

लेखक की ओर से

"हमारी सारी शिक्षा व्यर्थ है, हमारी पाठशालाओं, विद्यालयों आदि पर जो कुछ व्यय किया जा रहा है; हम अक्षर-ज्ञान में जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह सब व्यर्थ है, जबतक कि हमें अपने साधारण नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों की शिक्षा नहीं दी जाती। शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य यही है कि व्यक्ति अपने को अपने लिए, अपने कुटुम्ब के लिए, अपने समाज के लिए यथासम्भव उपयोगी बना सके और समाज में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त कर सके। सच्चा नागरिक ही वास्तविक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति है। मेरी तो यही आशा है, आकांक्षा है, यही अभिलाषा है। मैं तो उस दिन की उत्कण्ठा से प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब हमारे देश में सच्चे नागरिकों, वास्तव में कार्यकुशल नर-नारियों की हर प्रकार के कार्य में इतनी बहुतायत होगी कि हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर उसे निबाह सकेंगे, उसे स्थापित कर सकेंगे और अपने देश में उसी प्रकार से आत्मसम्मान-युक्त, स्वतंत्र-पुरुषोचित जीवन व्यतीत कर सकेंगे, जैसा अन्य देशों के स्त्री पुरुष कर रहे हैं।"

बाशी के सुप्रसिद्ध कर्मशील विद्वान् श्री श्रीप्रकाश एम एल ए. ने अपने एक लेख के अन्त में उपर्युक्त विचार प्रकट किये हैं। वास्तव में शिक्षा उस समय तक व्यर्थ है जबतक कि वह व्यक्ति का एक उपयोगी श्रेष्ठ नागरिक नहीं बनाती।

आज हम बड़े गौरव के साथ यह कहते हैं कि आर्य-संस्कृति सर्वोत्कृष्ट है, आर्य धर्म तथा आर्य-सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है। हम अपने ऐतिहासिक अतीत पर गर्व करते हैं। यह सब ठीक है और इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि गौरवमय अतीत उज्ज्वल भविष्य के लिए स्फूर्ति और बल प्रदान करता है। परन्तु जब हम अपने नागरिक जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो हमें घोर निराशा होती है यद्यपि जैसे जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय नवचेतना बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हमारे नेतागण में

नागरिक-जीवन के सर्वतोमुख गुधार के लिए तीव्र अभिलाषा तथा चेष्टा भी स्पष्ट दीव्य पड़नी है।

ससार वा इतिहास यह बतलाता है कि किसी देश ने अपनी जा उन्नति की उसका श्रेय वह कि नागरिकों के श्रेष्ठ और उच्चतम नागरिक जीवन को ही रहा है। किसी देश में किसी महात्मा या महान् उन्नायक के जन्म लेने मात्र से ही राष्ट्र में जीवन का संचार नहीं होने लगता। इसके लिए तो समूचे राष्ट्र की आत्मा में चेतना की आवश्यकता होती है। प्रत्येक देश में महान् धार्मिक तथा राजनीतिक नेता तथा महापुरुष पैदा हुए हैं, परन्तु वास्तव में उन्नति उन देशों ने ही की है जिनकी जनता ने बहु-संख्यक श्रेष्ठ नागरिकों को जन्म दिया।

नागरिक जीवन का श्रेष्ठ बनाने की अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या हमारे देश के सामने भी है। अभी तक हमारी शिक्षा प्रणाली में इस महत्वपूर्ण अंग की उपेक्षा की गयी है। नागरिक शास्त्र के ज्ञान के लिए कोई व्यावहारिक शिक्षा का प्रबंध हमारे विद्यालयों व विश्व विद्यालयों में नहीं किया गया। हमारी शिक्षा-संस्थाओं में नागरिक शास्त्र (Civics) की सामान्य शिक्षा का प्रबंध तो है, पर वह पहले तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य विषय नहीं है और जो है उससे उसे कोई उपयोगी व्यावहारिक लाभ नहीं मिलता। विद्यार्थियों को नागरिक-शास्त्र की केवल सैद्धान्तिक शिक्षा दी जाती है जिससे वे अपने जीवन में न कोई लाभ उठा सकते हैं और न वास्तविक भारतीय सांस्कृतिक एवं नागरिक जीवन से ही परिचय प्राप्त कर सकते हैं।

ससारभर के शिक्षा विशारद इससे सहमत हैं कि शिक्षा ही समाज के पुनर्निर्माण का आधार है। अतः हमें भारतीय शिक्षा-प्रणाली में ऐसे सुधार करने चाहिए जिससे हमारे भावी नर नारियों में अपनी सत्कृति, अपने आदर्शों, अपने विचारों एवं अपनी जीवनप्रणाली के प्रति अनुराग एवं श्रद्धा का भाव उदय हो और वे वास्तविक अर्थ में सच्चे उपयोगी नागरिक बन सकें। सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शब्दों में 'हमारा एक उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम भारत को संयुक्त, शांत और

गौरवपूर्ण देखें जिसमें हमें जीवन का एक नवीन दृश्य देखने को मिले । हमें आर्थिक न्याय, सामाजिक समता तथा राजनीतिक स्वाधीनता के महान् आदर्शों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

आज के युग में विज्ञान तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के चमत्कार ने सारे ससार को एक परिवार बना दिया है । आज हमने इनके प्रताप से समय तथा दूरी पर आश्चर्यजनक विजय प्राप्त कर ली है । इसलिए इस युग में हमारी नागरिकता केवल नगर या राष्ट्र तक ही परिमित नहीं रह सकती । वास्तव में मानव-संस्कृति का लक्ष्य तो मानव-एकता है । इसलिए मैं इस पुस्तक में नागरिकता पर व्यापक दृष्टि से विचार किया है और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीयता का नागरिक जीवन से जो घनिष्ठ सम्बन्ध है उसकी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के साथ-साथ नागरिकता के सिद्धान्तों की मीमांसा करते हुए नागरिक-जीवन के पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी पहलुओं पर सविस्तर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है ।

आर्य संस्कृति ही ससार की सबसे प्राचीन तथा महान् संस्कृति है । अर्य संस्कृतियाँ इससे पैंदा हुई हैं अथवा इसके विवृत्त रूप हैं । भारत में हिन्दू संस्कृति के रूप में यह संस्कृति आज भी विद्यमान है । परन्तु आज भारत में 'मुस्लिम संस्कृति' का भी अस्तित्व है । मैं इन दोनों संस्कृतियों को एक तो नहीं मानता क्योंकि दोनों में भारी मौलिक भेद हैं, ता भी मैं भारत में सांस्कृतिक एकता का समर्थन हूँ क्योंकि इस प्रकार के प्रयास से ही हमारे नागरिक-जीवन में समन्वय और सहकारिता की भावना जाग उठेगी और उससे समचे राष्ट्र का कल्याण होगा ।

सांस्कृतिक-जीवन अध्याय बड़ा होगा है । वह इस पुस्तक का मेरा दण्ड है । इसके अन्तर्गत शिक्षा, भाषा, राष्ट्रभाषा, लिपि, साहित्य कला और संस्कृतियों पर विचार किया गया है । जहाँ भारतीय साहित्य एवं कला के विषय में विवेचन है, वहाँ मेरा अभिप्राय उनकी विशेषताओं तथा आदर्शों एवं विचारधाराओं पर ही प्रकाश डालना रहा है । मैं भारतीय साहित्य तथा प्राचीन भाषाओं का श्रम बद्ध

विवेचन करना उचित नहीं समझा। इस कारण केवल हिन्दी-साहित्य को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके भारतीय साहित्य के आदर्शों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं प्रान्तीय भाषाओं और उनके साहित्य की आवश्यकता एवं महत्त्व को स्वीकार नहीं करता।

मैंने इस ग्रन्थ में प्रत्येक धर्म, मस्कृति और राजनीतिक विचार-धारा के मूल सिद्धान्तों एवं प्रवृत्तियों को जहाँतक हो सके सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है और प्रत्येक विषय का विवेचन इस ढंग से किया है कि कोई बात विवाद-ग्रस्त न बन जाये, परन्तु आवश्यकतानुसार कहीं-कहीं सिद्धान्तों व प्रवृत्तियों की आलोचना भी की गयी है।

इस ग्रन्थ द्वारा मैंने सांस्कृतिक प्रकाश में भारत के नागरिक-जीवन की एक झलक प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। इस प्रयास में मुझे कहीं-तक सफलता मिली है, इसका निर्णय मैं वित्त पाठकों तथा उदार-हृदय विद्वान् समालोचकों पर ही छोड़ता हूँ।

इस रचना में जो विचार तथा भाषा-सम्बन्धी त्रुटियाँ रह गयी हैं, मैं कृपालु पाठकों से विनम्रपूर्वक क्षमा चाहता हूँ। आगामी संस्करण में उन्हें दूर कर दिया जायेगा।

इस ग्रन्थ की रचना में मुझे जिन ग्रन्थों से सहायता मिली है उसे मैंने यथास्थान स्वीकार किया है और सहायक-ग्रन्थों की एक सूची भी अन्त में जोड़ दी है। मैं हृदय से उनके विद्वान् लेखकों एवं प्रकाशकों को धन्यवाद देता हूँ।

१५ दिसम्बर, १९४० }
राजामण्डी, आगरा }

रामनारायण यादवेन्दु

विषय-सूची

१. विषय-प्रवेश

राज्य—राज्य के आवश्यक अंग—राज्य और शासन में अन्तर—
राज्य और नागरिक—नागरिक शास्त्र क्या है ?—राजनीति-विज्ञान
और नागरिक शास्त्र में अन्तर । ३-१२

२. नागरिक-शिक्षा

नागरिक शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता—इतिहास का अध्ययन
और नागरिकता—सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य—नागरिक शास्त्र के
अध्ययन की पद्धति । १३-१६

३. मानव-समाज

मानव समाज का संगठन—सत्तार के महान् राज्य—सत्तार की
पराधीन जातियाँ—एशिया के पराधीन राष्ट्र—अफ्रीका के उपनिवेश—
अमरीका में मुनरो सिद्धान्त । २०-३०

४. साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ

आधिपत्य साम्राज्यवाद—राष्ट्रीय स्वाधीनता का सन्तु साम्राज्य
वाद—जनता का आधिक शोषण—राष्ट्रीय जागरण का दमन—विश्व
की अशान्ति का कारण । ३१-३६

५. अन्तर्राष्ट्रीयता

अन्तर्राष्ट्रीयता क्या है ?—राष्ट्रों की अन्योन्याश्रयता—प्रभुत्व का
निद्धान्त—अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ—राष्ट्रसंघ की विफलता और उसके
कारण—अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सहयोग । ३७-५१

६. भारतवर्ष और अन्तर्राष्ट्रीयता

भारत का विश्वप्रेम—विश्व-बन्धुत्व और सम्राट् अशोक—समारा
की स्थिति और भारतवर्ष—भारत का जग-भग—प्रवासी भारतीय—
साम्राज्य विरोधी संध—पी० ई० एन० और भारत । ५२-६७

७. राष्ट्रीयता

राष्ट्रीयता क्या है ?—राष्ट्रीयता के उदय के कारण—राष्ट्रीयता की भावनाएँ—भारतीय राष्ट्रीयता और ५० जवाहरलाल नेहरू ।

६८-८५

८. नागरिक-स्वाधीनता

अधिकार और कर्तव्य—नागरिक समानता—भारत का शासन-विधान और मौलिक अधिकार—आर्थिक समानता—वैयक्तिक स्वाधीनता—शरीर स्वाधीनता—विचार स्वाधीनता—गृह-विद्रोह या युद्ध-काल में नागरिक स्वाधीनता—समाचार पत्रों की स्वाधीनता—समासगठन की स्वाधीनता—धार्मिक स्वाधीनता—व्यावसायिक स्वाधीनता—अन्य नागरिक अधिकार—राजनीतिक अधिकार । ८६-११४

९. नागरिकों के कर्तव्य

अधिकार और कर्तव्य—कर्तव्य-परायणता की आवश्यकता—कर्तव्यों के प्रकार—शासन-प्रबन्ध में सहयोग—कानून-निर्माण में नागरिकों का योगदान—राज्यों के कानूनों का पालन—शान्ति-रक्षा में सहयोग—राज्य-कोष में कर तथा लगान आदि देना—स्वदेश-रक्षा—कर्तव्यावर्तव्य का निर्णय ।

११५-१२६

१०. प्रजातन्त्र

प्रजातन्त्र क्या है ?—प्रजातन्त्र के प्रकार—प्रजातन्त्र का आधार—प्रजातन्त्र के तत्त्व—प्रजातन्त्र शासन के गुण—प्रजातन्त्र शासन के दोष—भारतवर्ष और प्रजातन्त्र—पाकिस्तान ।

१३०-१३६

११. धार्मिक जीवन

नागरिक जीवन और धर्म—वैदिक धर्म—जैन-मत—बौद्धमत—सिख-मत—हिन्दू समाज के अन्य मत-मतान्तर—इस्लाम धर्म—ईसाई-धर्म—पारसी-धर्म ।

१४०-१४२

१२. सामाजिक जीवन

हिन्दू-जीवन—वैदिक वर्ण-व्यवस्था—वर्तमान-युग में वर्ण-

अवस्था—जाति-प्रथा—कुटुम्ब का प्रयोजन—संयुक्त-कुटुम्ब-प्रथा—
संयुक्त कुटुम्ब में स्त्री पुरुष के अधिकार—संयुक्त-कुटुम्ब-प्रथा का
भविष्य—आश्रम - व्यवस्था—अस्पृश्यता—मुस्लिम-जीवन—उत्तरा-
धिकार—विवाह—तलाक़ ।

१५३-१७२

१३. नागरिकों का स्वास्थ्य

स्त्री-पुरुषों की मृत्यु-संख्या का अनुपात—भारत की मृत्यु-संख्या—
भारत की जन-संख्या में वृद्धि—प्रसूति-काल में मृत्यु—जीवन-काल का
औसत—सक्रामक रोगों की वृद्धि और भीषणता—भारत के अपाहिज—
अस्वास्थ्य के कारण—स्वास्थ्य-सुधार के उपाय ।

१७३-१८७

१४. सांस्कृतिक जीवन

शिक्षा—प्राचीन काल में शिक्षा—स्त्रियों की शिक्षा—वर्तमान
शिक्षा-प्रणाली—अन्य शिक्षा संस्थाएँ—दलित जातियों में शिक्षा—
वर्षा-शिक्षा-पद्धति—भाषा और लिपि—हिन्दी-राष्ट्रभाषा—हिन्दी-भाषी
प्रान्त—अहिन्दी भाषी प्रान्त—हिन्दुस्तानी—हिन्दी-साहित्य सम्मेलन
और राष्ट्रभाषा—भारतीय साहित्य-परिषद और 'हिन्दी हिन्दुस्तानी'—
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और हिन्दुस्तानी—राष्ट्र-लिपि की समस्या—
साहित्य—हिन्दी-साहित्य—कला—भारतीय कला के आदर्श—मगीत-
कला—नृत्य कला—चित्र कला—वास्तु कला—मूर्ति-कला—नागरिक
जीवन और कला—संस्कृति—संस्कृति क्या है ?—आर्य संस्कृति के
आदर्श—आर्य-संस्कृति की प्रवृत्तियाँ—अरबी और मुस्लिम संस्कृति—
मुस्लिम संस्कृति में परिवर्तन—आर्य-संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति का
प्रभाव—मुस्लिम संस्कृति पर आर्य संस्कृति का प्रभाव—भारतीय-
संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव ।

१८८-२४५

१५. आर्थिक जीवन

आर्थिक स्थिति—औद्योगिक स्थिति—व्यापारिक स्थिति—भारत
में आर्थिक साधन—भारत का आर्थिक संगठन—भारत की गरीबी के
मूल कारण ।

२४६-२७६

कृषि—भूमि-प्रणालियाँ—बन्दोबस्त—लगान की दर—जमींदारी प्रथा की उत्पत्ति और विकास—संयुक्तप्रान्त में जमींदार और उनके अधिकार—संयुक्तप्रान्त में किसान और उनके अधिकार—किसानों का कर्जा—उद्योग-व्यवसाय—कारखाने—पैदावार—ज्वायंट स्टॉक कम्पनियों की पूंजी—मजदूरों की दशा—मजदूरों के हित के लिए कानून ।

१६. राष्ट्रीय जीवन

शासन-पद्धति—भारतीय संघ-शासन—प्रान्तीय शासन-प्रणाली—गवर्नरों के अधिकार—प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल—स्थानिक स्वायत्त शासन—म्यूनिसिपल बोर्ड—ज़िला-बोर्ड—ग्राम-पंचायतें ।

राष्ट्रीय नवजागरण—राष्ट्रीयता का उदय—राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना—राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) की स्थापना—वर्गभेद और स्वदेशी आन्दोलन—स्वराज की माँग ।

राष्ट्रीय आन्दोलन—गांधीयुग का आरम्भ—दमन तथा शासन-सुधार—असहयोग-आन्दोलन—स्वराज्य दल का जन्म—पूर्ण स्वराज की ओर—सत्याग्रह-आन्दोलन—गोलमेज-परिषद्—ऐतिहासिक उपवास—विधानवाद की ओर—नया शासन-विधान और कांग्रेस—कांग्रेस-मंत्रि मण्डलों का पदत्याग—युद्धविरोधी सत्याग्रह—मुस्लिम लीग की राजनीति—नरमदल की राजनीति—हिन्दू-महासभा की राजनीति—भारतीय ईमाई और राष्ट्रीयता—दलितवर्ग और उसकी राजनीति ।

२७६-३१४

भा र ती य सं स् कृ ति
और
नागरिक जीवन

विषय-प्रवेश

समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जिन्होंने व्यक्तिगत हितों की सार्वजनिक रक्षा के लिए, सार्वजनिक व्यवहार में समता उत्पन्न करने-वाले कुछ सामान्य नियमों से शासित होने का समझौता कर लिया है। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत विशेषताएँ होती हैं। इसी प्रकार समाज की भी विशेषताएँ होती हैं। समाज में व्यक्ति इन दोनों—व्यक्तिगत एवं समाजगत—विशेषताओं की रक्षा के लिए नियम बनाते हैं। समाज की प्रारम्भिक अवस्था में ये नियम अत्यन्त स्थूल और सामान्य होते हैं और जैसे-जैसे समाज विकसित और प्रगतिशील होता जाता है, वैसे-वैसे सामाजिक नियम अत्यन्त विस्तृत, विविध और जटिल होते जाते हैं। मानव-समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन करने से यह कथन भली भाँति प्रमाणित होता है।

अनेक भारतीय और यूरोपीय राजनीति-विज्ञान-विचारकों का यह मत है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले समाज में अराजकता थी। समाज में न्याय और व्यवस्था के स्थान में शक्ति का शासन था। शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति दुर्बल व्यक्तियों का दमन करते थे। इसलिए इस दशा से तग आकर सबने इकट्ठे होकर समझौता किया और उसके फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। यह सामाजिक समझौता ही राज्य की उत्पत्ति का मूल है। मध्यकालीन यूरोपीय विचारक हॉब्स के अनुसार भी राज्य की उत्पत्ति से पूर्व अराजक दशा थी। हॉब्स के कथनानुसार इस अराजक दशा में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से निरन्तर लड़ता था। यह निरन्तर संघर्ष की दशा थी। सब एक-दूसरे पर सन्देह और अविश्वास करते थे। जिस तरह गुस्मिल भेड़ों ने एक-दूसरे को मार खाने के लिए एक-दूसरे पर झगड़ते रहते हैं, उसी तरह मनुष्य भी आपस में एक-दूसरे का विनाश करने के लिए संघर्ष करते रहते थे। उस समय न्याय-अन्याय और

उचित अनुचित में कोई भेद नहीं था। उस समय शरीर पर ही सब-कुछ था। महाभारत में अनेक स्थान पर राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार के विचार मिलते हैं।

“अराजक राष्ट्रों में धर्म स्थिर नहीं रह सकता। अराजक अवस्था में लोग एक-दूसरे को खा जाते हैं। अराजक दशा में पापी लोग दूसरी का धन छीनने ही में आनन्द अनुभव करते हैं। पर जब दूसरे लोग इन पापियों को लूटने लगते हैं, सब दृष्टे राजा की आवश्यकता होती है। इस भयकर दशा में पापियों का भी तो भला नहीं होता, क्योंकि दो मिलकर एक को लूट खाते हैं और बहुत-से मिलकर दो को लूट लेते हैं। जो दास नहीं है, अराजक दशा में उन्हें दास बना लिया जाता है और स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण किया जाता है।

प्राचीन भारतीय विद्वान धर्म की स्थिति के लिए राजा को अनिवार्य समझते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि अराजक दशा में धर्म नहीं रह सकता। धर्म क्या सामान्य जीवन भी राजा के बिना नहीं रह सकता। पाण्ड्या का उत्पत्ति तम जारी रखने के लिए राजा चाहिए ही। धर्म, अर्थ, काम—इस त्रिवर्ग की प्राप्ति राज्य के बिना नहीं हो सकती। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह किसी नियामक के बिना नियंत्रण में रह ही नहीं सकता। समाज में जहाँ वहाँ भी सुव्यवस्था दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण नियामक की सत्ता है। यदि मनुष्य सामाजिक मर्यादाओं एवं वचनों के अधीन न रहती उसकी स्वच्छन्दता के फल-स्वरूप फिर अराजक दशा उत्पन्न हो जायगी। इस नियामक सत्ता के लिए महाभारत के शान्ति पर्व तथा अथर्वराज्य विज्ञान के ग्रन्थों में ‘दण्ड’ शब्द का प्रयोग किया गया है।

‘मनुष्य कहीं सम्मोह में पड़कर भट्ट न हो जायें, सम्पत्ति की रक्षा की जा सके, इसके लिए कोई मर्यादा चाहिए। इसी मर्यादा का नाम दण्ड है।’ १

१ महाभारत शान्तिपर्व, अध्याय १५, श्लोक ३

२ “ ” ” ” १५, श्लोक १०

महाभारत में मानव स्वभाव के सम्बन्ध में लिखा है—

‘वह (मनुष्य) यदि यज्ञ करता है या दूसरे को भलाई करता है, तो केवल दण्ड के भय से। यदि वह दान करता है, तो केवल दण्ड के भय से। मनुष्य जो ठोक रास्ते पर चलता है, अपने व्यवहार को स्थिर रखता है उसका एक मात्र कारण दण्ड है।’^१

इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई। भारतीय विचारका के मतानुसार राजा ही धर्म, अधर्म, न्याय की उत्पत्ति का मन्त्राधार है। प्राचीन काल में राजा की इस महत्ता के कारण ही कुछ विचारकाने राजा में दैवी शक्ति की कल्पना की। पद्म पुराण में लिखा है—‘राजा नारायण या परमेश्वर के अंग से उत्पन्न हुआ है, वह किसी भी अवस्था में मनुष्य नहीं है।’

यूरोप में मध्यकाल में यूरोपीय विचारक तथा राजा राज्य की उत्पत्ति के ईश्वरीय या दैवी अधिकार में विश्वास करते थे। इस मत का पूरा विकास इंग्लैंड में स्वयं शासक और फ्रांस में चौदहवें सदी के समय में हुआ। चौदहवीं सदी के अन्त में कहा करना था—‘म राजा हूँ। मेरी इच्छा राज्य की इच्छा है। मेरी आज्ञा राज्य का कानून है। इसी सिद्धान्त के आधार पर इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम और जेम्स अपने विरुद्ध आन्दोलन करनेवाला को ईश्वर का सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन करने का अनुराधी समझकर दण्ड दिया करते थे।

अद्यपि भारतवर्ष में राज्य का दैवी सिद्धान्त अत्यन्त प्राचीन काल में प्रचलित था तथापि उसका इतना विकास नहीं हुआ था। वैदिक काल में राजा का ईश्वर या ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं समझा जाता था। भारत में कुछ मध्यकालीन विचारका न राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण यह था कि व्यक्ति पारस्परिक लूटमार,

१ महाभारत शांतिपर्व, अध्याय १५ श्लोक १२ १३

२ वालोइवि नाथमतव्यो मनुष्य इति भूमिष ।

महती देवता ह्यमेषा नररूपेण निष्ठति ॥

अन्धकार और अव्यवस्था के परिणामस्वरूप दुःखी थे, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर यह निश्चय किया कि समाज में नियम और मर्यादा द्वारा शांति और सुव्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए राज्य की स्थापना की जाये।

राज्य के आवश्यक अंग

‘राज्य’ शब्द एक निश्चित प्रदेश में वैध ढंग से ऐसी सुव्यवस्थित प्रजा का बोधक है जिसकी सरया चाहे कम हो या अधिक, पर जहाँ स्थायी रूप से उस प्रदेश में रहनेवाली हो और बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। साथ ही जिसका अपना शासन हो और जो स्वभावन उसकी प्राणा पालन भी हो। राज्य के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं—

१ प्रजा—यह राज्य का प्रमुख और अनिवार्य अंग है। प्रजा के अभाव में राज्य की कल्पना सम्भव नहीं, पर राज्य के लिए प्रजा की संख्या निर्धारित नहीं है। प्राचीन युग में रोम और ग्रीस में नगर राज्य थे। परन्तु जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता गया युद्ध का भय अधिकाधिक बढ़ता गया तथा नवीन नूतन आधिपत्यारो की वृद्धि होती गयी, वैसे-वैसे राज्य बड़े-बड़े होने लगे और एक एक राज्य में ३० ३० और ४०-४० करोड़ की प्रजा रहने लगी।

२ भू-खण्ड—प्रजा की तरह भू-खण्ड—निश्चित भू-खण्ड भी आवश्यक अंग है। भू-खण्ड के बिना भी राज्य की कल्पना सम्भव नहीं। यदि कोई जन समुदाय समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करे भी और उसका एक प्रमुख भी हो, परन्तु यदि वह एक निश्चित भू-खण्ड में स्थायी रूप से निवास न करे तो वह राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। जन समुदाय राज्य का निर्माण उसी देश में कर सकता है, जब कि वह किसी प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करता हो। यह भू-खण्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसपर किसी बाहरी शक्ति का अधिकार या नियंत्रण न हो।

३ हित-एकता—राज्य के निर्माण के लिए एक निश्चित भू-खण्ड पर रहनेवाली प्रजा में हितों की एकता होना भी आवश्यक है। भाषा, संस्कृति, इतिहास और धर्म की दृष्टि से उनमें सामंजस्य होना जरूरी

है। जिस राज्य की प्रजा में स्वाभाविक रूप से धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐति-
हासिक एवं भाषा-सम्बन्धी एकता एवं सामाजिक नहीं होता, उस राज्य में
सामाजिक शांति स्थायी नहीं रहती। जातीय एकता भी अत्यन्त आवश्यक
है। राज्य की जनता में जाति, धर्म, सम्प्रदाय, सस्कृति और भाषा-सम्बन्धी
भेदभाव ऐसे न हो जो राज्य शासन और सामाजिक जीवन में अव्यवस्था
और अशांति पैदा कर दें।

४ शासन—शासन भी राज्य का प्रमुख अंग है। यदि किसी
निर्दिष्ट प्रदेश में जनता स्थायी रूप से रहती है और उसमें पारस्परिक
एकता भी है, परन्तु यदि वह किसी शासन के अधीन नहीं है, तो वह
राज्य नहीं कहला सकती। शासन के अभाव में प्रजा के ऐसे संगठन
धार्मिक, आर्थिक या साम्प्रदायिक ही हो सकते हैं—राजनीतिक नहीं
हो सकते।

५ प्रभुता—प्रभुता भी राज्य का प्रमुख और आवश्यक अंग है।
प्रभुता का अर्थ यह है कि वह निर्दिष्ट प्रदेश जिसपर प्रजा स्थायी रूप
से रहती है, और जिसका अपना शासन है, वह किसी बाह्य शक्ति के
नियन्त्रण में न हो। स्वाधीनता के बिना कोई ऐसा प्रदेश राज्य नहीं
कहला सकता। उदाहरण के लिए, भारतवर्ष में सन् १९३१ की जन-
गणना के अनुसार २५ करोड़ जन हैं। परन्तु भारत का शासन और
प्रभुता भारतीय प्रजा के हाथ में नहीं है। इसीलिए राजनीतिक परिभाषा
में भारत राज्य नहीं है।

राज्य और शासन में अन्तर

उपर्युक्त विवेचन से राज्य और शासन का अन्तर स्पष्ट है। सामान्यतया
राज्य और शासन को पर्याय या समानार्थक माना जाता है। परन्तु ऐसी
धारणा गलत है। राजनीतिक भाषा में राज्य और शासन में बड़ा भारी
अन्तर है। राज्य एक राजनीतिक समुदाय है और शासन उसका एक अंग है।
देश के सभी निवासी सामान्यतया राज्य के सदस्य होते हैं, परन्तु शासन-
यंत्र का संचालन अल्प-संख्यक प्रजा के हाथ में होता है। यह तो समय

है कि किसी राज्य की शासन-नीति में परिवर्तन करना समस्त जनता के हाथ में हो, परन्तु उस नीति के अनुसार शासन प्रबंध का कार्य एक विनिष्ट बग के हाथ में हाना है। शासन में परिवर्तन होते रहते हैं, एक शासन का स्थान दूसरा शासन लेता है। परन्तु राज्य में परिवर्तन नहीं होता वह स्थायी रूप से वैसा ही रहता है। शासन राज्य का अंग है और राज्य की मुख्यवस्था के लिए शासन अनिवार्य है। यही कारण है कि शासन का महत्त्व राज्य से अधिक है।

राज्य और नागरिक

राज्य के सदस्य का नागरिक कहा जाता है। इलाहाबाद विश्व विद्यालय के राजनीति के प्राफ़ेसर डा० श्री वेणीप्रसाद के मतानुसार प्राचीनकाल में रोम निवासी अधिकारों को ही नागरिकता समझते थे। जब रोम का साम्राज्य बढ़ा तब नागरिकता की नयी श्रेणियाँ हो गयीं। सबसे नीचे दर्जे की श्रेणी वह थी जिसमें लोग का केवल दो चार इने-गिने नागरिक अधिकार ही प्राप्त थे और सबसे ऊँची श्रेणी वह थी जिसके लोग को सभी नागरिक और सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। वहाँ नागरिकता षष्ठ ही प्रचलित था, क्योंकि एथेन्स तथा अन्य यूनानी वास्तवों की तरह रोम भी पहले पहल वास्तव में एक नगर राज्य ही था। अधिकारों का संग्रह, सिद्धान्त और व्यवहार दोनों में पहले केवल नागरिकता से था। बाद में एकान्तरूप से नागरिकता के साथ उनका संबंध केवल सिद्धान्त में ही रह गया। सिर्फ नगर में निवास करना ही नागरिक की योग्यता थी। जो नगर में रहता था वही नागरिक कहलाता था। बाद का उसका यह अर्थ नहीं रह गया। नागरिकता का सम्बन्ध मुख्यतः अधिकारों ही से रह गया। जो लोग नगर में रहते लेकिन अधिकारों से वंचित होते थे वे नागरिक नहीं कहलाते थे। उदाहरणस्वरूप ग्रीक नागरिक नहीं थे, यद्यपि कई पीढ़ियों तक उन्होंने नगर में निवास किया था। इसके विपरीत वे लोग, जो असल में नगर के अन्दर तो निवास नहीं करते थे, लेकिन नगर के सदस्य माने जाते और अधिकार-

युक्त होन ये, नागरिक कहलाने थे ।^१

राम और यूनान के नगर राज्या के निवासिया को 'नागरिक' कहा जाता था । उम समय नागरिकता म अभिप्राय नागरिक के अधिकारा म होना था और आधुनिक समय म नी नागरिकता से यही अभिप्राय है । परन्तु आधुनिक युग में नगर राज्य नहीं है । उनके स्थान पर राष्ट्र-राज्य है । कालान्तर में नागरिकता की भावना म भी परिवर्तन हुआ गया है । नागरिकता का उदय राम के छोटे-से नगर राज्य में हुआ, परन्तु आधुनिक युग म बहु समय दस राज्य और राष्ट्र राज्य में व्याप्त हो गयी है । प्रत्येक नागरिक, चाहे वह नगर निवासी हो चाहे ग्राम निवासी, समान रूप से नागरिक अधिकारा का उपयोग कर सकता है ।

प्राज्ञेनर डा० बनीप्रसाद का यह मत है कि

“अधिकारी के लिहाज से ग्रामवासी भी उसी प्रकार नागरिक है जिस प्रकार शहरवाले । यह बात जरूर है कि नगर राजनीतिक जीवन, घन सभ्यता और सस्कृति के केन्द्र है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि शहरवालों के हित के आगे हम गाँववालों के हित का विचार न करें । ग्रामवासियों के हित को नगरवासियों के हित के अधीन करना उचित नहीं है । दोनों के हितों पर बराबर ध्यान रखना चाहिए । इसी प्रकार सबसे काम करने की आशा भी करनी चाहिए । व्यवसाय सम्पत्ति-रक्षा, न्याय, कीटुम्बिक जीवन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सध-जनिक जीवन, तथा सध समिति के अधिकार और उनके साथ लगे हुए कर्तव्य गाँववालों से उतना ही सम्बन्ध रखते हैं जितना कि नगर-निवासियों से ।”^२

हिन्दी माहि्य म 'नागरिक' शब्द का प्रयोग नगर निवासी के अर्थ में प्राचीन समय से होता रहा है । हिन्दी म 'नागर' या 'नागरिक' शब्द का

१ डा० बनीप्रसाद नागरिक शास्त्र चौथा अध्याय, पृ० ७४-७५.
(सन् १९३७)

२ उपर्युक्त ।

अर्थ है नगर में रहनेवाला । प्राचीन-काल में 'नागरिक' शब्द चतुर, शिष्ट तथा सम्पत् के अर्थ में भी प्रयुक्त होता था । अंग्रेजी में 'सिटीजनशिप' का जो अर्थ है, वही अर्थ हिन्दी में 'नागरिकता' का भी है ।

इस सम्बन्ध में संक्षेप में यह जान लेना उचित होगा कि राजनीतिक भाषा में 'नागरिक' और 'प्रजा' इन दोनों में अन्तर है । स्वाधीन राज्य के निवासी नागरिक कहलाते हैं, और परतन्त्र, अर्द्धपरतन्त्र या एतन्त्र राज्य के निवासी 'प्रजा' कहलाते हैं, यद्यपि वैदिक और भारतीय साहित्य में 'प्रजा' शब्द का प्रयोग नागरिक के अर्थ में ही किया गया है । वेदों के अनेक मंत्रों में राजा-प्रजा के कर्त्तव्यों और अधिकारों का उल्लेख मिलता है । किन्तु आधुनिक समय में 'प्रजा' शब्द 'नागरिक' शब्द से हीन कोटि का है । 'प्रजा' से एक ऐसे जन-समुदाय का बोध होता है, जो ऐसे शासन के नियन्त्रण में रहता है, जिसके संचालन में उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में हाथ नहीं ।

परन्तु इस सम्बन्ध में एक अपवाद है । इंग्लैण्ड के नागरिक 'प्रजा' कहलाते हैं, यद्यपि वे नागरिकता के अधिकारों से युक्त हैं । दूसरी ओर भारत के निवासी भी प्रजा कहलाते हैं, नागरिक नहीं, यद्यपि भारतीयों को नागरिकता के पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हैं ।

नागरिक-शास्त्र क्या है ?

जिस समय यूनानियों ने अपने देश में नगर-राज्यों की स्थापना की उसी समय में रोमवासियों ने इटली में वैसे ही नगर-राज्य स्थापित किये । वे नगर को 'सिविटस' कहते थे । अंग्रेजी में 'सिटी'—नगर—शब्द की उत्पत्ति इसी शब्द से हुई है । लैटिन भाषा के 'सिविस' शब्द का अर्थ नागरिक है । प्राचीन समय में यूनान में 'पॉलिटिक्स' शब्द का प्रयोग नगर के मामलों के सम्बन्ध में किया जाता था । इसी प्रकार इटली में नगर के मामलों के सम्बन्ध में 'सिविक्स' शब्द का प्रयोग किया जाता था । इस प्रकार भाषा-विज्ञान के अनुसार पॉलिटिक्स, राजनीति, 'सिविक्स' और नागरिक-शास्त्र का एक-सा ही अर्थ है । रोम और यूनान की

सम्पत्ता का प्रभाव समस्त यूरोप के देशों पर पड़ा और नागरिकता, नागरिक सम्पत्ता आदि शब्दों का प्रयोग अन्य भाषाओं में भी होने लगा। यही कारण है कि राजनीति और नागरिक शास्त्र में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि उनके बीच विभाजक रेखा खींचना असम्भव नहीं तो कठिन जम्हा है।

राजनीति-विज्ञान और नागरिक-शास्त्र दोनों ही का राज्य के नागरिकों में सम्बन्ध है। वे मनुष्यों, मानव-समाज तथा राज्यों के पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन करते हैं। नागरिकों के अधिकारों और राज्य के प्रति उनके वस्तुस्थितियों का प्रतिपादन नागरिक-विज्ञान का विषय है। नागरिक-शास्त्र ऐसी अवस्थाओं और परिस्थितियों का निर्देश करता है जो नागरिकों के अनुकूल होनी हैं और जिनमें रहकर वे व्यक्तिगत एवं सामाजिक उत्थान कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र इस बातका विवेचन करता है कि नागरिक-जीवन किस प्रकार उत्तम और सुखी बनाया जा सकता है। नागरिक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए राज्य की ओर से क्या-क्या सुयोग, सुविधाएँ होनी आवश्यक हैं, किन-किन कार्यों में राज्य को व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा प्रत्येक नागरिकको यह विश्वास हो जाये कि वह शान्तिपूर्वक अपने धर्म के फल का उपयोग करना हुआ अपने राष्ट्र, नगर और विश्व में शान्ति स्थापित करने में योग दे सकेगा।

राजनीति-विज्ञान और नागरिक-शास्त्र में अन्तर

विषय की दृष्टि से इन दोनों में तनिक भी अन्तर नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि एक जिस बात पर अधिक जोर देता है दूसरा उसपर उतना जोर नहीं देता। निम्नलिखित तुलनात्मक वर्णन में यह सहज में जाना जा सकता है—

राजनीति-विज्ञान

नागरिक-शास्त्र

१ राजनीति विज्ञान विशेषतः राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विषयों

१ नागरिक-शास्त्र विशेषतः स्थानीय विषयों से सम्बन्ध रखता

का विवेचन करता है ।

है ।

२ राजनीति विज्ञान राजनीतिक
संस्थाओं और व्यवस्थाओं के विकास
का इतिहास बतलाता है ।

२ नागरिक-शास्त्र उस विकास
को पहले से ही मान लेता है ।

३ राजनीति-विज्ञान मुख्यतः
अधिकारों और उनकी प्राप्ति के
उपायों पर जोर देता है ।

३ नागरिक-शास्त्र मुख्यतः
कर्तव्यों और उनके सम्पादन के
लिए आवश्यक शिक्षा और आच-
रण पर जोर देता है ।

अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नागरिक-शास्त्र का विषय
समूचे नागरिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना है—उसकी उन्नति करना है ।
वह सामाजिक अवस्थाओं और परिस्थितियों की जाँच-पड़ताल करता
है, इसलिए विज्ञान है और अनुसंधान के परिणामों का उपयोग नागरिक
जीवन की उन्नति के लिए करता है, इसलिए वह कला भी है ।

नागरिक शिक्षा

नागरिक-शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता

नागरिक-शास्त्र का उद्देश्य नागरिक-जीवन को पूर्ण और श्रेष्ठ बनाना है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह नागरिक के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का यथावत् ज्ञान प्राप्त करके उनका पालन करे। यह ज्ञान सभी प्राप्त हो सकता है जब वह नागरिक-शास्त्र का भली भाँति अध्ययन करके उसके सिद्धान्तों, आदर्शों एवं नियमों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करे। भारत में स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों व छात्राओं को यह विषय पढ़ाया जाता है। परन्तु यह विषय वैज्ञानिक ही है। अभी तक नागरिक शास्त्र का अनिवार्य रूप से इन संस्थाओं में अध्ययन नहीं किया जाता। इस कारण अधिकांश छात्र नागरिक-शास्त्र के सिद्धान्तों व नियमों से अनभिज्ञ ही रहते हैं। इसका परिणाम प्रत्यक्षतः व्यावहारिक जीवन में देख पड़ता है। हममें नागरिक-भावना के अभाव का यह एक बड़ा कारण है।

प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य के नागरिकों को शासन-कार्यों के प्रति दिलचस्पी हो। जिस राज्य के नागरिक स्वदेश की राजनीति में अधिक दिलचस्पी लेते हैं, उसमें प्रजातन्त्र की सफलता की अधिक सम्भावना होती है। जबकि भारत के ११ प्रान्तों में 'प्रान्तीय स्वशासन' की स्थापना हुई है, तबसे शासन-कार्यों में जनता की दिलचस्पी पैदा होने लगी है। जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क होगयी है। यदि शासन नागरिकों के अधिकारों पर कुठाराघात करनेवाली किसी नीति या कार्य को करने का निश्चय करे, तो यदि नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हों, वे उसका विरोध करके सरकार को उसे बदल देने के लिए बाध्य कर सकते हैं।

भारत में शिक्षा-शास्त्री और लोक-ज्ज्ञा यह अनुभव करने

लगे हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण इस ढंग से किया जाये कि उसमें भारतीय संस्कृति का पूरा विचार रखते हुए नागरिकता के श्रेष्ठ आदर्शों को स्थान मिले जिससे शिक्षा जीवनोपयोगी बनने के साथ साथ जीवन को ऊँचा उठानेवाली भी बन सके। वर्षा शिक्षा कमेटी की रिपोर्ट में इसी मत का प्रकाशन किया गया है। इस रिपोर्ट के योग्य लेखका का यह मत विचारणीय है कि

‘हमारी यह आकांक्षा है कि वे अध्यापक और शिक्षा विशारद जो इस नवीन शिक्षा सम्बन्धी प्रयोग को अपने हाथों में ले, इस योजना में निहित नागरिकता के आदर्शों को भलीभाँति समझ लें। आधुनिक भारत में नागरिकता देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में अधिकाधिक प्रजातन्त्र हो जायगी। कम से कम नये युग की सन्तति को अपनी समस्याओं अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानने-समझने के लिए सुयोग मिलना चाहिए। नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों के विवेकपूर्ण उपभोग के लिए कम से कम शिक्षा प्राप्ति के निमित्त एक सर्वथा नयी प्रणाली की आवश्यकता है। दूसरे, आधुनिक समय में, विवेकशील नागरिक को समाज का सक्रिय सदस्य बनना चाहिए। उसमें इनकी समझ हो कि वह अपने समाज के सदस्य की हैसियत से किसी उपयोगी सेवा के रूप में समाज को प्रतिदान कर सके।’

इतिहास का अध्ययन और नागरिकता

इतिहास, भूगोल, समाज विज्ञान अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि सब विज्ञान सामाजिक विज्ञान हैं। इन विज्ञानों का मानव-समाज से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अथवा यों कहना अधिक उपयुक्त होगा कि मानव समाज के आधार पर ही इन विज्ञानों का विकास हुआ है। इन विज्ञानों का परस्पर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि हम उन्हें एक-दूसरे से अलग करके समझ नहीं सकते। वास्तव में वे मानव समाज

पर विचार करने के विभिन्न दृष्टिकोण हैं।

इतिहास मानव-समाज की अतीत काल की घटनाओं, कार्यों, ज्ञान और अनुभवों का वैज्ञानिक वर्णन है। प्राचीन युग के मानव-समाज के रीति नियमादि के अध्ययन के आधार पर ही सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ है। नागरिक शास्त्र के उपादान तो स्पष्टतः इतिहास से प्राप्त किये गये हैं। समाज की अवस्था के विकास के साथ-साथ, उसके आदर्श, नियमों एवं अवस्थाओं में भी परिवर्तन होने रहते हैं। इन परिवर्तनों और अनुभवों के प्रकाश में सामाजिक विज्ञान में भी परिवर्तन हो रहे हैं। अतः इतिहास के साथ-साथ नागरिक शास्त्र का भी अध्ययन जरूरी है।

सामाजिक विज्ञानों का उद्देश्य

सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का उद्देश्य यह है कि मानव-जाति के उत्थान और कल्याण के लिए नागरिकों में मानव हित का सम्यक् विज्ञान हो। समाज में जो अभाव और जो आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति के लिए नागरिकों को प्रेरणा व स्फूर्ति मिले। नागरिकों में मातृ-भूमि के लिए भक्ति भावना तथा मानव के प्रति अनुराग पैदा हो और वे सत्य न्याय, प्रेम के आधार पर समाज-रचना कर सकें। नागरिकों का अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का ज्ञान पैदा हो और वे अपने अधिकारों की प्राप्ति, रक्षा एवं भीग कर सकें। सारांश यह है कि मानवों के चरम उत्थान के लिए नागरिकों की सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करना अनिवार्य है। यदि मानव हित की भावना से इनका अध्ययन करके, उनके द्वारा प्रतिष्ठित मानवीय आदर्शों के अनुसार अपने जीवन का सुगम बनवाया जाय तो विश्व में महत्कारिता, न्याय, प्रेम और सत्य का राज्य स्थापित होना असंभव नहीं।

नागरिक शास्त्र के अध्ययन की पद्धति

नागरिक शास्त्र का अध्ययन केवल ज्ञान-वर्द्धन ही नहीं होना चाहिए

वरिक उसे शिक्षाप्रद और प्रयोगात्मक भी होना चाहिए। नागरिक शिक्षा ज्ञानवर्द्धक के साथ शिक्षाप्रद और प्रयोगात्मक होनी चाहिए। आज-कल स्कूलों व कालेजों में इस विषय की जो शिक्षा दी जाती है, वह केवल ज्ञानवर्द्धक ही है। व्यावहारिक न होने से वह जीवनोपयोगी नहीं है।

नागरिक शिक्षा ज्ञान वर्द्धक हो—इसका अभिप्राय यह है कि पाठक को नगर की, देश की और मसार की स्थिति और अवस्था का ज्ञान हो जाये। देश के राष्ट्रीय जीवन के विविध क्षेत्रों का ज्ञान जरूरी है। देश की नागरिक, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक एवं राजनीतिक अवस्था का ज्ञान प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए। इस आवश्यक ज्ञान के अभाव में वह अपने कर्त्तव्य कार्यों का यथाविध पालन नहीं कर सकता।

नागरिक शिक्षा शिक्षाप्रद भी हो—इसका मतलब यह है कि नागरिकों को शिक्षा ऐसे ढंग से दी जाये कि वे अपने परिवार, पाठशाला, बालेज, पढोस, वस्ती, ग्राम, नगर, समाज, राज्य और अन्य में विश्व के मानवों के प्रति सामाजिक व्यवहार के आधारभूत सिद्धान्तों को हृदयगत कर सकें। उन्हें अपना नागरिक जीवन सुखी और श्रेष्ठ बनाने के लिए पथ-प्रदर्शन मिले तथा उनमें सामाजिक संस्थाओं के प्रति आदर और श्रद्धा पैदा हो तथा वे उनके मंचालन एवं प्रबंध में सहयोगपूर्वक भाग ले सकें। नागरिकों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाये कि वे लोक-संग्रह, सामाजिक न्याय, सहकारिता, राष्ट्रीय एकता और अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता के सिद्धान्तों को भली भाँति समझ लें।

नागरिक-शिक्षा सैद्धान्तिक होने के साथ-साथ प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक भी हो। नागरिक शिक्षा और नागरिक जीवन में स्पष्ट संबंध होना चाहिए। जिस प्रकार रसायन या भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी अपनी प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं, उसी प्रकार नागरिक-शास्त्र के विद्यार्थियों को मानव-समाज की प्रयोग-शाला में प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए। स्वदेश और मसार के मानव समाज के संस्कारों, रीति-रिवाजों, सामाजिक दशाओं और नागरिक दशाओं का अध्ययन

और अन्वेषण करके नागरिक जीवन के अनेक तथ्या वा शास्त्र प्राप्त किया जा सकता है यही नागरिक शिक्षा की व्यावहारिकता है। अपने नगर या ग्राम के जन-समाज की सामाजिक स्थिति, जीवननैर्घा, आर्थिक जीवन आदि की जाँच-पड़ताल द्वारा प्रयोग शुरू किया जा सकता है और समय और सुविधा के अनुसार यह प्रयोग एक बड़े पैमाने पर भी किया जा सकता है।

नागरिक शिक्षा के लिए तीव्र बुद्धि, कल्पना शक्ति, सहानुभूति और सेवामय की बहुत जरूरत है। नागरिक-शास्त्र के विद्यार्थी को विचार-शक्ति से अधिक काम लेना चाहिए। अपने से अधिक श्रेष्ठ विद्वानों के विचारों, सिद्धान्तों और सम्मेलनों से प्रभावित होकर, तब की बसोटी पर उन्हें परमेश्वर के अग्रगण्य से उसका प्रयोग निष्पक्षता से पूरा नहीं हो सकता। विद्यार्थी को चाहिए कि यह देश या संसार के मानव समाज की स्थितियों और सामाजिक जीवन की जाँच-पड़ताल करते समय साम्प्रदायिक या सही मनीषा से काम न ले। उसमें कल्पना-शक्ति की भी आवश्यकता है। कल्पना-शक्ति के अभाव में उसका प्रयोग सफल हो नयेगा, इसमें सन्देह है। जब हम समाज के विभिन्न व्यवस्था, समुदाय और वर्गों की स्थितियों का निरीक्षण करते हैं, तो हम एक सीमा तक अपने को भी उन स्थितियों में अनुभव करते, उनकी दशा पर विचार करते हैं। उदाहरणार्थ, अगर प्रयाग विश्वविद्यालय का राजनीति का एक छात्र मयुक्तप्रान्त के किसी पूर्वी जिले के ग्राम-जीवन का अध्ययन और निरीक्षण करना चाहे तो उस अपने मानसिक दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस छात्र ने अपने जीवन का अधिक समय होस्टल में सुख और आनन्द के साथ बिताया है, जिसने नागरिक जीवन के लिए विज्ञान और आधुनिक आविष्कारों को सुविधाएँ और साधन प्रदान किये हैं, उनका उपभोग किया है, जिसने सिनेमा, गेटव, पिक्चर, संगीत तथा नृत्य का आनन्द उठाया है और जो हर समय 'निमित्त वातावरण में सोम लेता रहा है, ऐसा विद्यार्थी यदि सहसा ग्राम-जीवन के अध्ययन के लिए किसी गाँव का चयन करे तो उसकी सारी दुनिया ही

बदल जायेगी। वह अपने को एव सर्वथा नये और अपरिचित वातावरण में पायेगा। इस ग्राम-जगत की झाँकी के लिए उसे एक ग्रामीण बनना होगा और ग्रामीण बनकर ही वह उनके मनोभावों, विचारों, अभावों और आवश्यकताओं को जान और समझ सकेगा, अन्यथा नहीं। इसके लिए उसे कल्पना-शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें सेवा-भाव का भी होना जरूरी है। इसके बिना वह जीवन का अध्ययन सफलतापूर्वक नहीं कर सकेगा। सेवा-भाव सहानुभूति से उत्पन्न होता है। सहानुभूति का अर्थ है दूसरों के दुख-सुख की अनुभूति। विद्यार्थियों में नागरिक भावना का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि उनमें लोक-संग्रह की भावना जगायी जाये। समाज-सेवा के लिए विस्तृत क्षेत्र है। केवल जरूरत है विद्यार्थी-वर्ग में समाज-सेवा के लिए सच्ची लगन की, प्रदर्शन की नहीं।

अपने गाँव के किसानों, अपने नगर के मजदूरों तथा दूसरे शोषित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जाँच-पड़ताल की जा सकती है। इस प्रकार वे उनके जीवन को सुधारने के लिए उपाय सोच सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों से न केवल उनका ज्ञान ही बढ़ेगा बल्कि वे पीड़ित मानवता की सेवा भी कर सकेंगे।

विश्वविद्यालयों और कालेजों के छात्र एव छात्राएँ 'सेवासप्त' बनाकर निकटवर्ती गाँवों के निवासियों के सम्पर्क में आकर उनकी सामाजिक दशा का निरीक्षण कर सकते हैं। इन सेवा-सप्तों द्वारा ग्रामवासियों को स्वास्थ्य, ज्ञान और शक्ति का सन्देश दिया जा सकता है। साक्षरता के प्रसार के लिए प्रौढ-पाठशालाओं का संचालन, रोगियों की सेवा, जनता में स्वास्थ्य के सिद्धान्तों व सफाई के नियमों का प्रचार, किसानों को अपनी कृषि तथा घन्धों में सुधार करने के उपाय बतलाना, नगरों में मजदूरों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्रयत्न करना आदि आदि जन-सेवा के अनेक मार्ग हैं। इन साधनों द्वारा नागरिक शिक्षा का व्यावहारिक अध्ययन किया जा सकता है।

मंसूर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त-उत्सव में ६ अक्टूबर १९३८ को स्वर्गीय दीनबन्धु सी० एफ० एण्ड्रूज ने अपने दीक्षान्त भाषण में इसी प्रकार

के विचार व्यक्त किये थे

मेरा ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस विश्व-विद्यालय के विद्यार्थी गांवों में जाते हैं, और अपनी कल्पना के अनुरूप कार्य का प्रतीक मंने बगलौर में शुरू कर दिये गये काम में पा लिया है । लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि इस दिशा में इससे भी अधिक एकनिष्ठ प्रयत्न किया जाये । क्या कोई ऐसा आश्रम या बस्ती नहीं हो सकती, जिसका विश्वविद्यालय से सीधा सम्बन्ध हो, जिसकी अपनी इमारतें हों थीर जहाँ विश्वविद्यालय के वे स्नातक जा सकें जो दीन-दुष्टियों के दुःख में घुल मिल जाने का संकल्प कर चुके हैं ?

मानव-समाज

मानव-समाज का संगठन

मानव - समाज अर्थात् समस्त ससार के मनुष्य जाति, रंग, धर्म, सस्कृति, सभ्यता, राज्य शासन प्रणाली आदि कारणों से विविध समुदायों में बँटे हुए हैं। ससार की जनसंख्या १ अरब ९९ करोड़ २५ लाख है। परिवार या कुटुम्ब सबसे छोटा मानव समुदाय है। यह समुदाय सृष्टि के आदि से आज तक विद्यमान है और अन्त तक कायम रहेगा। परिवार ही वास्तव में मानव-संगठन का मूल आधार है। उसका कार्य सतान का पालन-पोषण और सृष्टि क्रम का संचालन है। यह कार्य मानव-जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मानव सदैव परिवार की रक्षा के लिए प्रयत्नशील और जागरूक रहा है। परिवार के विनाश से मानव-समाज की सभ्यता तथा सस्कृति पर बड़ा आघात होगा, इसकी कल्पना भयंकर है।

जातियों के आधार पर मानव समाज अनेक भागों में बँटा हुआ है। जैसे—आर्य, अनार्य, द्राविड, अरब पारसी नीग्रो, हूण, नॉर्डिक, स्लेव, कैल्ट, नार्मन, सेक्सन आदि। धर्म के आधार पर भी अनेक विभाग हैं—हिंदू, ईसाई, मुसलमान, बौद्ध कफूशियन, यहूदी आदि और इनके भी अनेक उप विभाग हैं। ऐसे भी जन समुदाय हैं, जो धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करने। वे निरीश्वरवादी हैं। वर्तमान समय में सोविट रूस ईश्वर-विरोधी है। वर्ग अर्थात् रंग की दृष्टि से भी मानव समाज कई भागों में विभाजित है—गोराग, पीताग, कृष्णाग इत्यादि। शीतप्रधान देशों में गोराग जन हैं। ये अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उष्ण देशों में कृष्णाग मिलते हैं। चीन-जापान में पीताग जन हैं। व्यावसायिक आधार पर भी मानव कई भागों में विभाजित है—वैज्ञानिक, मजदूर, व्यापारी, पूँजीपति आदि। इनके अतिरिक्त प्रत्येक देश में मास्कृतिक समुदाय भी हैं—विश्व-

विद्यालय, विद्वन्मण्डल, संगीत-परिषद्, नाट्य-परिषद्, साहित्य-परिषद् आदि । कुछ मानव-समुदाय स्वतन्त्र हैं, दुमरे परतन्त्र हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो स्वतन्त्र देशों के प्रभाव में हैं अथवा अर्द्ध-स्वतन्त्र हैं ।

इन समस्त समुदायों में राज्य, धर्म और ज्ञानि-सम्बन्धी समुदाय ही प्रमुख हैं । आज के मानव-समाज में ये तीन तत्त्व मानव-एकता, मानव-मगठन और विश्व-शान्ति के लिए महान् भव्य सिद्ध हो रहे हैं ।

संसार में प्रत्येक स्वतन्त्र राज्य उग्र राष्ट्रवादी है । वह संसार के दूसरे राष्ट्रों को अपने आधिपत्य, प्रभाव या अधिकार में लाना चाहता है । आज यूरोप, अमरीका, एशिया और अफ्रीका में इसका प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है । जर्मनी समस्त संसार में चक्रवर्ती राज्य की कामना करता है । इसी उद्देश्य से वह यूरोप में युद्ध में तल्लीन है । जापान एशिया का शिरोमणि होना चाहता है और इसलिए यह चीन और हिन्द-चीन को दबाता हुआ प्रह्ला की ओर पंर बढ़ा रहा है । इटली रोमराज्य का मधुर स्वप्न देख रहा है, इसलिए अफ्रीका में वह बमबर्षा कर रहा है । इस प्रकार ये स्वाधीन राष्ट्र-राज्य ममार की स्वाधीनता को कुचक रहे हैं ।

धर्म, जो वास्तव में मानव-समाज में एकता और आध्यात्मिक प्रेम तथा महवारिता पैदा करने के लिए है, आज उग्र राष्ट्रवादी देशों की साम्राज्य विस्तार की कामना की पूर्ति का साधन बन गया है । धर्म के नाम पर बड़े-से-बड़ा पाप किया जा रहा है और उसे पवित्र कृत्य सिद्ध कराने के लिए धर्माचार्यों तथा पोप-पादरियों को खरीदा जा रहा है ।

इसी प्रकार जाति (Race) की उग्र आत्म-चेतना आज संसार-सकट का कारण बन रही है । अनेक गरीब जातियाँ यह दावा करती रहीं कि हमें ईश्वर ने संसार की अन्य (वाली, पीली, भूरी) जातियों को सम्पत्ता का सन्देश देने के लिए पैदा किया है, हमें संसार पर आधिपत्य करने के योग्य है, परन्तु अब इस युग में जर्मनी में हेर हिटलर का यह दावा हो रहा है कि केवल जर्मन ही पवित्र आर्य जाति के हैं, शेष यूरोप की जातियाँ वर्ण-सकर हैं । इसी कारण जर्मन रक्त की पवित्रता की रक्षा करने

के लिए हिटलर ने अपने राज्य से यहूदिया को देस निबाला दे दिया ।

पिछले महायुद्ध (१९१४-१८) के बाद यूरोप के राष्ट्रा ने धर्म राज्य तथा जाति के बंधनों से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विकास के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना करने का प्रयत्न किया । परंतु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली ।

संसार के महान् राज्य

आधुनिक जाल में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियट रूस, जर्मनी फ्रांस जापान, इटली, चीन विश्व के महान् राज्य हैं । पृथ्वी पर चार बड़े-बड़े महाद्वीप हैं—एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमरीका (उत्तरी व दक्षिणी) । इनमें अमरीका की राजनीति की कुंजी संयुक्त राज्य अमरीका के हाथ में है । दक्षिणी अमरीका के राज्यों पर उसका प्रभाव और अधिकार है । प्रायः १०० वर्षों से संयुक्त राज्य मुनरो सिद्धांत के अनुसार यूरोपीय राष्ट्रों के हस्तक्षेप से दक्षिणी अमरीका को मुक्त रखे हुए हैं । इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वह ब्रिटिश राष्ट्र-समूह की धुरी है और उसके चारों ओर उपनिवेश तथा पराधीन देश हैं । दक्षिणी अफ्रीका आस्ट्रेलिया, 'यूजीलैण्ड कनाडा और आयरलैण्ड में ब्रिटेन का साम्राज्य है । भारतवर्ष भी १५० वर्षों से ब्रिटेन के आधिपत्य में है । इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य आज संसार में सबसे बड़ा राज्य है ।

विश्व राजनीति में यूरोप का स्थान अग्रतम है । यूरोप में ब्रिटेन फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस ये पांच बड़े राज्य हैं । आजतक यूरोप के इन देशों में शक्ति साम्य के लिए बराबर संघर्ष और विग्रह होते रहे हैं । कभी किसी देश का प्रभाव अधिक बढ़ गया तो दूसरे देश को उसका प्रभाव घटाने की चिन्ता हो गयी । इस प्रकार यूरोप सदैव युद्ध भूमि रहा है ।

पिछले महायुद्ध के बाद यूरोप में कई नये देश बनाये गये । इसके फल-स्वरूप यूरोप में इस समय ३४ राज्य हैं । इनमें केवल अभी कहे गये

पाँच राज्य बड़े हैं और वे शेष २९ राज्या पर अपना प्रभाव बनाये हुए हैं। जब उनको अपने किसी हित में बाधा आन पड़ती है तो वे दूसरे राष्ट्र में अपने अल्पमत की रक्षा के नाम पर युद्ध में प्रवृत्त हो जाते हैं। वर्तमान् यूरोपीय युद्ध का आरम्भ भी इसी बहाने हुआ है। जर्मनी का यह अनियोग था कि पोलैण्ड में बसनेवाले जर्मनों के साथ पोल (पोलैण्डवासी) बड़े नृशंस और भीषण अत्याचार करते हैं। उनकी रक्षा के लिए ही जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण किया, ऐसा हेर हिटलर का दावा है। यूरोप के इन बड़े राष्ट्रों के अफ्रीका और एशिया में साम्राज्य है—उपनिवेश हैं, प्रभाव क्षेत्र है। प्रत्येक महान् राष्ट्र का सदैव यही प्रयत्न रहा है कि वह अपने साम्राज्य, उपनिवेश तथा प्रभाव क्षेत्र को सुगन्धित रखे तथा उनमें वृद्धि करे।

संसार की पराधीन जातियों

एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमरीका में पराधीन और अर्द्ध-परतन्त्र जातियों की प्रधानता है। सन् १९२९ की जन-संख्या के अनुसार संसार के समस्त देशों की कुल जनसंख्या १,९९ २५ २९ ००० है।^१ एशिया, अफ्रीका और अमरीका में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, मयुक्त राष्ट्र, नैदरलैण्ड, पुर्तगाल आदि देशों के साम्राज्य और उपनिवेश हैं। सन् १९१४-१८ के यूरोपीय महायुद्ध के पहले अफ्रीका में जर्मनी के भी उपनिवेश थे, परन्तु वार्साई की संधि के अनुसार उनका अधिकार जर्मनी से ले लिया गया और वे मिन राष्ट्रों के नियंत्रण में आ गये। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत पराधीन जातियों की जन-संख्या ४० करोड़ ५८ लाख २४ हजार है। यह संसार में सबसे बड़ा साम्राज्य है। इसके बाद नैदरलैण्ड का स्थान है। इस देश के साम्राज्य के अन्तर्गत पराधीन जातियों की जनसंख्या ६ करोड़ २ लाख १९ हजार है। फ्रांस तीसरा साम्राज्यवादी राष्ट्र है। उसके साम्राज्य के अन्तर्गत पराधीन जातियों की आबादी

१ सीग ऑफ नेशन की 'स्टैटिस्टिकल ईयरबुक' १९३०-३१

५ करोड़ ७३ लाख २० हजार हैं। जापान का चौथा स्थान है। उसके साम्राज्य की जनसंख्या २ करोड़ ६९ लाख २० हजार है।^१ संयुक्तराज्य अमरीका का पांचवा स्थान है। इसके साम्राज्य की आबादी १ करोड़ ४२ लाख २८ हजार है। इटली का छठा स्थान है। अफ्रीका में अत्री-सीनिया उसका साम्राज्य है जिसकी जनसंख्या १ करोड़ ३० लाख १० हजार है। सातवां स्थान पुर्तगाल का है जिसके साम्राज्य की जनसंख्या ८० लाख ४ हजार है। वर्तमान यूरोपीय महापट्ट से पूर्व जर्मनी ने आस्ट्रिया व चेकोस्लोवाकिया को अपने राज्य में मिला लिया था।^२ इन पराधीन देशों के अतिरिक्त इरलैण्ड, फ्रांस, बेलजियम, दक्षिणी अफ्रीका यूनियन, न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया और जापान के अधिकार में राष्ट्रमण्डल द्वारा सीपे हुए वे देश भी हैं जिनका शासन-प्रबन्ध शासनादेन-प्रणाली से होता है। ऐसे प्रदेशों की कुल जनसंख्या २ करोड़ २८ हजार है। इस प्रकार ससार में प्रायः ६० $\frac{१}{३}$ करोड़ की विशाल जनसंख्या पराधीन है। इसमें ३५ करोड़ भारतीय भी शामिल हैं। इस प्रकार भारत की पराधीन जनसंख्या ससार की पराधीन जनसंख्या के आधे भाग से भी अधिक है।

१. जापान ने सन् १९३२ के बाद चीन पर आक्रमण करके जो उसके प्रदेश अपने अधिकार में ले लिये उनकी जनसंख्या इसमें शामिल नहीं है।

२. जर्मनी ने अप्रैल सन् १९३८ में आस्ट्रिया और सितम्बर १९३८ में चेकोस्लावाकिया को अपने राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार इटली ने अलबानिया को अपने अधीन कर लिया। इन प्रदेशों की संख्या निम्न प्रकार है

आस्ट्रिया	—	६८ लाख
चेकोस्लोवाकिया	—	५० लाख
अलबानिया	—	११ लाख

एशिया के पराधीन राष्ट्र

एशिया में केवल दो राष्ट्र ऐसे हैं जो पारिचाय्य देशों के साथ प्रतियोगिता में ठहर सकते हैं। वे हैं जापान और तुर्किस्तान। इन दोनों राष्ट्रों ने आधी सदी में ही अपने देशों में वायापलट कर दी। एशिया में जापान, चीन, ब्रह्मा, तुर्किस्तान, तिब्बत, नेपाल, भारत, लका, हिन्दचीन, स्याम, इन्डोनेशिया, फारस, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, कोरिया और फिलिपाइन द्वीप आदि राष्ट्र हैं। इनमें भारतवर्ष, ब्रह्मा, तथा लका ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हैं। फिलिस्तीन राष्ट्रमण्डल के शासनादेशों के अनुसार ब्रिटेन के नियन्त्रण में है। सीरिया पर फ्रांस का नियन्त्रण है। नेपाल स्वतन्त्र राज्य है, तो भी वह ब्रिटेन के प्रभाव में है। हिन्दचीन में फ्रांस का साम्राज्य है। इराक और सीरिया भी ब्रिटेन के वड्डों में हैं।

चीन यद्यपि स्वाधीन राष्ट्र है, ता भी उसकी दशा पराधीन राष्ट्र तक से गयी-बीती है। उसपर दस वर्षों से साम्राज्यवादी जापान की कोसदृष्टि है। उसने चीन के कई प्रान्तों का अपहरण कर लिया है और जब भी उसकी साम्राज्य-विषासा शान्त नहीं हुई है। जापान का सिद्धास्त है कि एशिया एशियायी लोगों के लिए है। उसपर गैर-एशियायी राष्ट्रों को आधिपत्य जमाने का कोई अधिकार नहीं है। जापान जो आज से ५० वर्ष पहले औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा देश था, आज यूरोप से बला कीशाल सीखकर न केवल विज्ञान और कला की नकल अपने देश में कर रहा है बल्कि वह यूरोप की जमी भयकर स्थिति एशिया में भी पैदा कर रहा है। उसने यूरोप के सैनिकवाद और साम्राज्यवाद की नकल करने में सफलता प्राप्त की है और आज एशिया जापान के साम्राज्यवाद से सहम रहा है।

चीन में आन्तरिक कलह वर्षों से है। राष्ट्रीय एकता के अभाव से जापान ने सन् १९३१ में चीन पर आक्रमण कर दिया और उसके कई प्रदेशों को हडप लिया। उस समय जापान राष्ट्रमण्डल का सदस्य था। चीन भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य था। जब चीन पर जापान का आक्रमण

हुआ तो उसने राष्ट्रसंघ से यह अनुरोध किया कि वह अपने विधान की १०वीं और १५वीं धारा के अनुसार जापान के विरुद्ध कार्रवाई करे। परन्तु राष्ट्रसंघ ने चीन की सहायता के लिए कुछ भी नहीं किया। इससे जापान का उत्साह बढ़ गया और उसने संघ के विधान को ठुकरा दिया। उसने मंचूरिया तथा मंगोलिया के प्रदेश हड़प लिये तथा मञ्चूको नामक एक नाममात्र का स्वतंत्र राज्य कायम कर दिया।

चीन में न केवल जापान का हित है, बल्कि ब्रिटेन और संयुक्त-राज्य अमरीका के भी हित हैं। चीन के आर्थिक जीवन पर इन साम्राज्यवादी राष्ट्रों का नियंत्रण है। यहाँ तक कि विदेशी राष्ट्रों की सेनाएँ भी चीन में हैं। चीन में विदेशी राष्ट्रों की जनता चीन के न्यायालय तथा पुलिस के नियंत्रण से भी मुक्त है। विदेशियों ने चीन में अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे हैं। उनकी चीन में स्थानीय सरकारें भी हैं और चीन के समुद्रमार्ग पर उनके बन्दरगाह भी हैं। ऐसा है स्वाधीन चीन जो पराधीनता का बुरी तरह शिकार बना हुआ है।^१

चीन के बाद दूसरा प्रमुख देश भारत है। भारत प्रायः १५० वर्षों से ब्रिटेन के आधिपत्य में है। इतने वर्षों तक पराधीनता की स्थिति में रहने से भारतीयों का न केवल राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पतन ही हुआ है बल्कि उनका नैतिक पतन भी हो गया है। पराधीनता शारीरिक बल ही नहीं है, वह तो आत्मा को भी गिरा देती है। परन्तु अब अर्द्ध-शताब्दी से भारत में राष्ट्रीय नवचेतन और राजनीतिक जागरण हो रहा है और सन् १९१४-१८ के यूरोपीय महायुद्ध के बाद नौ भारतीय राष्ट्र में नवचेतना इतनी अधिकता में आ गयी है कि उसके जीवन का कोई भी विभाग उसके आश्चर्यकारी प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में समस्त राष्ट्र की जनता में एक अभूतपूर्व जागरण के लक्षण दिखायी देने लगे हैं।

१ लिपोनाई वुल्फ : 'इंटेलिजेंट मैन के दृष्टि में भारत' (१९३३)

ब्रिटेन और फ्रांस के नियन्त्रण में हैं। सीरिया पर फ्रांस का नियन्त्रण है।

फिलिस्तीन अंग्रेजों के संरक्षण में है। वास्तव में यह अरबों का देश है। एक अंग्रेज हाई कमिश्नर उसका शासन-प्रबन्ध एक कमिटी की सलाह से करता है। अरब इस प्रकार के संरक्षण के सदा से विरोधी रहे हैं। जबसे जर्मनी ने यहूदियों को निकाल दिया है तबसे उनसे उपनिवेश के लिए तरह-तरह की योजनाएँ सोची जा रही हैं। यहूदी और अरब ये दो विभिन्न जातियाँ हैं। यहूदिया में बड़े-बड़े पूजापति हैं। उन्होंने फिलिस्तीन में बसकर उसे ज़मन बना दिया है। उनकी आधिपत्य दशा में बड़ा सुधार हो गया है। परन्तु इन दोनों में संघर्ष जारी है। अरब यह नहीं चाहते कि उनके देश का बँटवारा हो। दूसरी ओर यहूदियों की बढ़ती हुई संख्या के लिए प्रदेश की आवश्यकता है। यहूदी-अरब संघर्ष का अन्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक शाही कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि फिलिस्तीन को अरब और यहूदियों में बाँट दिया जाय। इस प्रकार अरबों में और भी असन्तोष पैदा हो गया है।

सीरिया फ्रांस के आधिपत्य में है। परन्तु सन् १९२८ में वहाँ उत्तर-दायी शासन की स्थापना कर दी गयी।

भारत के उत्तर में स्थित तिब्बत देश पर भी ब्रिटेन का प्रभुत्व है। इन्डोनेशिया डच (हालैण्ड के) साम्राज्यवाद का शिकार है। इस देश में सन् १९२७ से स्वाधीनता-प्राप्ति का आन्दोलन हो रहा है। परन्तु अभी तक उसे स्वतन्त्रता नहीं मिल पायी है।

हिन्द-चीन फ्रांस का उपनिवेश है। उसकी प्रजा विदेशी शासन के विरुद्ध है। वह भी विदेशी बन्धन से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील है। इस समय जापान इस देश पर आक्रमण कर रहा है।

फिलिपाइन द्वीप पर संयुक्तराज्य अमेरिका का आधिपत्य है। इस देश के निवासी वर्गों से स्वाधीनता प्राप्ति के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। परन्तु उन्हें आज तक स्वतन्त्रता नहीं मिली है।

अफ्रीका के उपनिवेश

१

अफ्रीका सबसे पिछड़ा हुआ देश है। मोरहवीं सदी में जब दास-व्यापार बड़े पैमाने पर चला रहा था, तब यूरोप की जातियाँ ने इस स्वर्ण-भूमि पर प्रवेश किया था। कई शताब्दियों तक सम्भ्रता का पाठ सिप्यानेवाले गोरा के सम्पर्क में रहते हुए भी आज अफ्रीका के असली निवासी सम्भ्रता और सस्कृति में बहुत पिछड़े हैं। यूरोपीय जातियाँ को अफ्रीका में अपना आधिपत्य जमाने के लिए अधिक संघर्ष या युद्ध नहीं करना पड़ा, बल्कि यहाँ की अधिकांश जातियाँ बन्ध और असम्भ्र थीं। उन्होंने विदेशियों के चरणों में आत्म-समर्पण कर दिया। पिछले महायुद्ध (१९११-१८) से पहले अफ्रीका में जर्मनी के कई उपनिवेश थे। परन्तु शान्ति-सन्धि के अनुसार ये उपनिवेश ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम के अधिकार में आगये।

टोगानिका ब्रिटेन के आधिपत्य में चला गया। इसका कुछ उत्तरी-पश्चिमी भाग बेल्जियम को मिला। जर्मन कैमरून का अधिकांश भाग फ्रांस के हस्त में आया। टोगालैण्ड फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बाँटा गया। 'वर्षिणी अफ्रीका यूनियन' ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश है। मिला पहले ब्रिटेन के अधीन था। परन्तु अब वह स्वतन्त्र राष्ट्र है। फिर भी ब्रिटेन का उसपर प्रभाव है। सन् १९३४ में इटली ने स्वतन्त्र राज्य अबीसीनिया को युद्ध में हराकर उसे अपने अधीन कर लिया। अब केवल लिबेरिया ही एकमात्र स्वतन्त्र राज्य है।

अमरीका में मुनरो-सिद्धान्त

संयुक्तराज्य अमरीका कई सदियों से यूरोप की राजनीति में अलग रहा है। वह यूरोप की मकटपूर्ण राजनीति की उत्पत्ति में अपने आपको सदैव बचाता रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति वाशिंगटन ने पहले-पहल १७ सितम्बर १७९६ को अपने भाषण में यह भावना व्यक्त की कि अमरीका की यूरोपीय बगड़ा ने अलग रहना चाहिए। इसके बाद सन् १८२३ में राष्ट्रपति मुनरो ने आने वाले समय में अमरीका की नीति का

स्पष्टीकरण किया। इस सन्दर्भ में मुनरो ने यह घोषणा की कि यूरोप के राष्ट्रा को अब अमरीका (उत्तरी व दक्षिणी) में अपने उपनिवेश स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यूरोपीय देशों के ऐसे युद्धों में, जिनसे अमरीका का कोई संबंध नहीं, वह भाग नहीं लगा और न ऐसा करना उसकी नीति के अनुकूल ही है। यूरोपीय देशों ने साम्राज्य-स्थापना की भावना से अमरीका महाद्वीप में प्रवेश किया तो उनका यह प्रयत्न अमरीका की शान्ति के लिए खतरा होगा। इस समय अमरीका में जो यूरोपीय उपनिवेश या पराधीन राज्य हैं, उनके साथ अमरीका का संबंध वैसा ही बना रहेगा और समुक्तराज्य अमरीका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सिद्धान्त 'मुनरो सिद्धान्त' के नाम से विख्यात है। इस सिद्धान्त या भविष्य में जो विश्वास हुआ उससे कारण समुक्तराज्य समूह अमरीका महाद्वीप का संरक्षक बन गया। इस समय समस्त अमरीका समुक्तराज्य के आधिक साम्राज्यवाद का शिकार है। उसका अमरीका तट के निकटवर्ती द्वीपों पर अधिकार है। यहाँ नहीं, सुदूर द्वीपों पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया है। हवाई और फिलिपाइन द्वीप समुक्त-राज्य अमरीका के आधिपत्य में है। इससे अतिरिक्त उसने क्यूबा, हैटी, साण्टो डोमीनगो के साथ सन्धि करके उनकी भी स्वाधीनता पर अनेक प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। पनामा और निकारागुआ राज्यों के चुनावों के समय समुक्तराज्य की सेनाओं का प्रबन्ध रहता है। इन सब राज्यों की वैदेशिक नीति पर भी उसका प्रभाव है।

साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ

साम्राज्यवाद क्या है—इसका स्मरस्पशी और वास्तविक विवरण एक भारतीय विद्वान के वाक्य में इस प्रकार है 'स्वाधीनता और मानवता की रास से साम्राज्यवाद का जन्म हुआ है। वरसों नर-नारिषी की आहो और अभिशापी से बना मुकुट साम्राज्य के सिर पर है। इसके कपड़े लाल रंग के हैं, इसके साथी अकाल, महामारी और भीषण रोग हैं। इसके आने के साथ भीषण आतंक छा जाता है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है। दूसरी भाषा, दूसरी सभ्यता और संस्कृति खदबंती से सार दी जाती है। अपनी इच्छा को दूसरे की इच्छा का अनुगामी बनना पड़ता है। क्या यह साम्राज्यवाद दुनिया के लिए सगलमय, सुखप्रद, और जीवनदाता हो सकता है ?'

यह है साम्राज्यवाद का सजीव स्वरूप। इससे अच्छी उसकी व्याख्या और क्या हो सकती है ? साम्राज्यवाद पूँजीवाद का अन्तिम और निखरा रूप है। पूँजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है। इसलिए साम्राज्यवाद भी आर्थिक है। आज का युग ही अर्थ-प्रधान है। राजनीति भी अर्थ-नीति की अनुचरी है। इसलिए आज के साम्राज्यवाद को आर्थिक साम्राज्यवाद कहा जाता है।

आर्थिक साम्राज्यवाद

आर्थिक साम्राज्यवाद का प्रादुर्भाव फ्रांस की राज्य क्रान्ति और औद्योगिक क्रान्ति के बाद हुआ। फ्रांस की राज्य-क्रान्ति का प्रभाव समस्त यूरोप पर पड़ा। फलस्वरूप यूरोप के अधिकांश देशों में प्रजातन्त्र का बोलबाला रहा। जनता ने स्वेच्छाचारी एकतन्त्र शासन का अन्त कर के शासन की धामदोर अपने हाथ में ली। इसने सारे यूरोप में समता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व के आदर्श की घूम मच गयी। प्रजातन्त्र के

प्रताप से राजसत्ता स्वेच्छाचारी राजाओं के हाथ से निकलकर उच्च मध्यमवर्ग के लोगों के हाथ में आ गयी। इससे मध्यमवर्ग ने लाभ उठाया। उद्योग धंधों में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। अब पूँजीपति वर्ग के सामने अपना तैयार माल बाहर के देशों में भोजन की समस्या उपस्थित हुई।

अब ऐसे देशों की खोज होने लगी जिनमें तैयार मात्र बेचा और उनसे कच्चा माल सस्त भाव में खरीदा जा सके। इसलिए उपनिवेशों की खोज के लिए साहसी नाविक निकल पड़े। रेल तार जहाज तथा मशीनों के आविष्कार ने उद्योग धंधों में आश्चर्यजनक उन्नति बढ़ा दी। सबसे पहले एशिया, अफ्रीका आदि के देशों में यूरोपियन जातिधर्मों ने प्रवेश किया। इनमें उद्योग धंधे बड़ी पिछड़ी दशा में थे। इसलिए उन्हें इन देशों में अपना माल रफ्तार और कच्चा माल खरीदने का एक बड़ा क्षेत्र और मुयाग हाथ लगा। इस उपनिवेश विजय में प्रतियोगिता भी बीज रूप में बिछमान थी। जब सबसे पहले यूरोप की विविध जातियाँ या देशवासी अफ्रीका और एशिया में आये तब उनका एकमात्र ध्येय व्यावसायिक ही था। वे इन महाद्वीपों के देशों में अपना व्यवसाय चाहते थे। परन्तु दूसरे देशवालों की प्रतिस्पर्धा से अपनी रक्षा करने के लिए हर एक की चेष्टा यह रही कि मेरा ही एकाधिकार कायम होजाये। इसीलिए प्रतियोगिता में संघर्ष चला। युद्ध लड़े गये। जब एक जाति का एकाधिकार इन महाद्वीपों में जम गया तब इस बात की चेष्टा होने लगी कि इनके देशों पर राजनीतिक प्रभुत्व भी कायम किया जाये। विदेशियों की प्रतिस्पर्धा से अपने आपको सुरक्षित करने के लिए राजनीतिक आधिपत्य कायम किया गया। इस प्रकार यूरोप के साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने एशिया और अफ्रीका में उद्योग धंधों में अपनी पूँजी लगाने के साथ साथ उसकी रक्षा के लिए राज सत्ता भी स्थापित की।

मुप्रसिद्ध लेखक श्री डाउट ने यूरोप और अफ्रीका की औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा के सम्बन्ध में लिखा है—

‘यूरोप और अफ्रीका ने हाल ही के कुछ वर्षों में चीन के सिवा सातार के सभी स्वतंत्र देशों पर आधिपत्य जमा लिया है। इस समय

में सब प्रकार के देशों पर आधिपत्य जमाने के लिए हुए । सभी देश जल्दी करना चाहते थे । जिन राष्ट्रों के पास उपनिवेश नहीं हैं उन्हें भविष्य में मिलने की आशा नहीं थी । यदि उन्हें उपनिवेश नहीं मिलेंगे, तो बीसवीं शताब्दी के होनेवाले आर्थिक शोषण में उनको सुयोग नहीं मिलेगा । यही कारण है जिससे यूरोपीय राष्ट्र साम्राज्यवादी नीति के कारण उत्पन्न हो गये हैं ।^१

राष्ट्रीय स्वाधीनता का शत्रु—साम्राज्यवाद

यद्यपि साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति मूलतः आर्थिक ही है, तो भी पूँजीपतियों का शासन पर प्रभुत्व होने के कारण साम्राज्यवाद अधिकृत देशों व उपनिवेशों में केवल जनता का आर्थिक शोषण ही नहीं करता बल्कि उनके शासन में भी सत्कारण करता है । इसलिए साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति राजनीतिक भी रही है । प्राचीन भारत और यूरोप में जो विनाश साम्राज्य स्थापित किये गये, उनका उद्देश्य राजनीतिक प्रभुता ही थी । आज भी इसी प्रभुता के लिए दूसरे देशों की स्वाधीनता का अपहरण किया जा रहा है ।

यूरोपीय तथा अमरीकन राष्ट्र जहाँ जहाँ अपने देशों की पताका लेकर गये वहाँ वहाँ की राष्ट्रीय स्वाधीनता का दमन करके उनकी जनता को उड़ोने पराधीन बनाया । उन्होंने वर्षों तक युद्ध जारी रखे, लाखों सैनिकों ने अपने जीवन की आहुतियाँ दी और अपार धन-सम्पत्ति युद्ध देवता के चरणों पर चढ़ायी । इस बलिदान के प्रभाव में उन्हें एशिया और अफ्रीका के देशों में 'राजनीतिक प्रभुता' प्राप्त हुई । यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि यह 'राजनीतिक प्रभुता' विजित देशों की स्वाधीनता के लिए घातक सिद्ध हुई । इस तरह साम्राज्यवाद ने अधिकृत देशों की जनता का आर्थिक शोषण करके ही विश्राम नहीं लिया, बल्कि उसको आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक पतन के लिए भी अचिराम प्रयत्न किया है ।

१. एड ड्राउट्ट 'सोशल एण्ड पोलिटिकल प्रॉब्लेम्स एंड द एण्ड ऑफ द नाइन्टीअथ सेन्चुरी' ।

जनता का आर्थिक शोषण

यह तो ऊपर कहा ना चुका है कि साम्राज्यवाद पूँजीवाद का अंतिम सोपान है। पूँजीवाद जब उस स्थिति में पहुँच जाता है जबकि किसी देश के पास अपार धन राशि और तैयार माल जमा हो जाता है जो स्वदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद भी बच रहता है तब तयार अधिक माल को बचने के लिए दूसरे देशों की खोज की जाता है। वस यही साम्राज्यवाद के उदय का कारण है। एक पूँजीवादी देश दूसरे पूँजीवादी देश में अपना तयार माल मुनाफे के साथ नहीं बेच सकता। इसीलिए वे ऐसे देशों की खोज करते हैं जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हों। ऐसे ही देशों में वे अपना तयार माल अधिक मुनाफे के साथ बेच सकते हैं और कच्चा माल सस्ते दामों में खरीद सकते हैं।

साम्राज्यवादी राष्ट्र अधीनस्थ देशों के उद्योग धंधों का नाश करके जनता को स्वदेशी धनोपाजन के साधनों से वंचित करता है तथा अपनी पूँजी से उस देश में उद्योग धंधे खड़ा करता है। इस प्रकार पिछड़े हुए देशों में बड़े बड़े कारखाने खुल जाते हैं और साम्राज्यवादी राष्ट्र पूर्णतया उसके आर्थिक जीवन का नियंत्रण करने लगता है। कागज़ पर अधिकृत देशों में भी पूँजीवाद का शासन स्थापित हो जाता है।

राष्ट्रीय जागरण का दमन

साम्राज्यवादी राष्ट्र का हित इस बात में है कि वह अपने अधिकृत देश या उपनिवेशों की प्रजा को सदैव प्रगति तथा प्रकाश से अलग रखे। वह उस नवयुग की नवीन विचारधारा संसार की सामाजिक शान्तियों के अमर सदेव तथा ज्ञान विज्ञान से वंचित रखकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। अधिकृत देश में नवीन प्रगतिशील विचारधाराओं का प्रतिपादन करनेवाले साहित्य और रचनाओं पर रोक लगायी जाती है समाचारपत्रों पर कड़ी नज़र रखी जाती है और जब जनता में विद्रोही बचन से मुक्ति पाने के लिए नवीन चेतना का जागरण होता है तब उसे कुचोट देने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि

साम्राज्यवादी राष्ट्र यह भलीभाँति अनुभव करता है कि राष्ट्रीय जागरण उसके हित के लिए घातक सिद्ध होगा। परन्तु सच तो यह है कि साम्राज्यवादी राष्ट्र अपने मुख्यवस्थित कड़े दासन, दमन और मोपण से भी राष्ट्रीय जागरण को रोक नहीं सकता। ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध राजनीतिक लेखक प्रोफेसर श्री हैरान्ड लास्की का कथन है कि "साम्राज्यवाद पराधीन राष्ट्र की जनता में राष्ट्रीयता को जन्म देता है।" राष्ट्रीय जागरण तो साम्राज्यवाद की एव स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जिसे रोकने की शक्ति स्वयं उसमें भी नहीं है।

भारत में राष्ट्रीयता का उदय बग-भग के साथ होता है। इसी समय स्ववशी आन्दोलन शुरू होजाता है। सन् १९१४ में जब यूरोपीय महायुद्ध शुरू हुआ, तब भारत में राष्ट्रीय असन्तोष अधिक बढ़ गया। इस असन्तोष को दवाने का ज्या-ज्यो प्रयत्न किया गया, त्यो-त्या वह उग्रतर होता गया। और जब युद्ध की समाप्ति पर भारत में रौन्ट बिल पास किया गया, तब भारतीय असन्तोष ने उग्रतम रूप धारण कर लिया। इसी समय महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुए। महान्मा गांधी ने दमन का विरोध करने के लिए जनता को अहिंसात्मक आन्दोलन का अस्त्र प्रदान किया। इसमें जनता में निभयता, साहस और बलिदान की भावना पैदा हुई।

सच तो यह है कि स्वाधीनता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। किसी भी राष्ट्र को किसी दूसरे राष्ट्र की जनता को इस मानवीय अधिकार से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। आजतक साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने इस सत्य को अनुभव नहीं किया। परन्तु इस बीसवीं सदी में यह प्रकाश के समान स्पष्ट है कि कोई भी राष्ट्र सदा के लिए गुलामी में नहीं रखा जा सकता। अधिकृत राष्ट्र में राष्ट्रीयता का विकास और उत्तरोत्तर यदि साम्राज्यवाद के जीवन के लिए सकट है।

विश्व की अशान्ति का कारण

उपर्युक्त विवचन से यह स्पष्ट है कि साम्राज्यवाद राष्ट्रीय स्वाधीनता

का शत्रु है। यही नहीं वह ससार में अशान्ति का जनक भी है। सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि आधुनिक काल में युद्धों का मूल कारण यही साम्राज्यवाद है। जिस देश के पास कोई उपनिवेश या साम्राज्य नहीं है वह उसकी प्राप्ति के लिए युद्ध पर उतारू होजाता है और जो देश स्वयं साम्राज्यवादी है वह अपने साम्राज्यवाद की रक्षा तथा उसकी वृद्धि के लिए युद्ध क्षेत्र में उतर आता है। इस प्रकार साम्राज्यवाद उन राष्ट्रा के लिए एक दूषित चीज है जो साम्राज्यवादी नहीं हैं। साम्राज्यवाद की प्रणाली में अशान्ति असंतोष और प्रतियोगिता तथा युद्ध के बीज मौजूद हैं। इसलिए यह ध्रुव सत्य है कि जब तक इस पृथ्वी पर साम्राज्यवाद, उसके अवशेष या साम्राज्यवादी भावना विद्यमान रहनी तबतक ससार में शांति का स्वप्न देखना भी संभव नहीं और न उस समय तक किसी भी सभाव्य उपाय से सदैव के लिए युद्धों की रोक ही की जा सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीयता

आधुनिक काल में नागरिक-जीवन का सबब केवल अपने नगर, ग्राम या राज्य से ही नहीं, बल्कि समस्त ससार से है। मानवता परिवार, नगर और मातृभूमि से भी महान् है। परन्तु जाति, धर्म, रंग एवं राष्ट्रीयता की उग्र भावना के कारण मानव-समाज कृत्रिम विभागों या समुदायों में विभाजित हो गया है। ससार में जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होना जा रहा है, वैसे-वैसे मानव जाति यह अनुभव करती जा रही है कि धर्म, जाति और रंग के भेद कृत्रिम हैं और मानव एकता में इन्हे बाधक नहीं होना चाहिए। अब ससार के मनुष्य यह अनुभव करने लगे हैं कि मानव-समाज का सगठन सत्य, न्याय और सहकारिता के आधार पर होना चाहिए। ससार के मानव हिंसापी वैज्ञानिकों ने जो लोकोपयोगी आविष्कार किये हैं, उनके द्वारा मानव-एकता की भावना अधिक दृढ़ होती जा रही है। बेतार के तार, रेडियो, दूर-दर्शन-यन्त्र आदि आविष्कारों ने मानव-एकता की स्थापना में बड़ा सहयोग दिया है। यही नहीं, प्रत्येक देश और प्रत्येक युग में ऐसे महापुरुष पैदा होते रहे हैं और आज भी ऐसे महापुरुष विद्यमान हैं जो सकीर्ण राष्ट्रीय बंधनों से मुक्त मानवता के पुजारी हैं। भारतवर्ष तो वैदिककाल से 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आदर्श का समर्थक रहा है। अशोक और बौद्धधर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने विश्ववन्द्यत्व के लिए क्रियान्वित प्रयत्न किया। आधुनिक युग में भी महात्मा गांधी, विश्वकवि डॉ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर और प० जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीयता के पुजारी होने के साथ साथ विश्व-नागरिक भी हैं। भारत की राष्ट्रीयता मानव हित विरोधी नहीं है, इसलिए वह अन्तर्राष्ट्रीयता को पोषक है।

अन्तर्राष्ट्रीयता क्या है ?

मानव-इतिहास में आदिम काल से हम मानव-सम्बन्धों में दो सिद्धांतों के आधार पर संघर्ष देखते आ रहे हैं ।

पहला सिद्धान्त है अराजकता और दूसरा है व्यवस्था । पहले सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य स्वच्छन्द वैयक्तिक स्वाधीनता का समर्थक रहा है । दूसरे सिद्धान्त के अनुसार वह समाज के हित और व्यक्तिगत हित के लिए व्यवस्था का समर्थक रहा है । आज संसार में जितनी संस्थाएँ मानव-कल्याण के कार्य में लगी हुई हैं, वे व्यवस्था के सिद्धान्त के अनुसार कार्य कर रही हैं । सदियों के कटु अनुभव के बाद मानव ने यह अनुभव किया कि संघर्ष और अराजकता नहीं, बल्कि पारस्परिक सहयोग और व्यवस्था ही समाज के कल्याण का श्रेष्ठ नियम है । यदि मानव-समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति किसी सर्वहितकारी नियम या मर्यादा का पालन न करके स्वच्छन्द रूप से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगे, तो वास्तव में ऐसे समुदाय में व्यक्तिगत स्वाधीनता की कल्पना तक संभव नहीं, क्योंकि जहाँ कोई नियम, मर्यादा या व्यवस्था नहीं है, वहाँ कौन किसके अधिकार का आदर करने की सोचेगा ? और जब ऐसा न होगा तो कोई व्यक्ति सच्ची स्वाधीनता का उपभोग नहीं कर सकता । इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । राज-मय का प्रयोग करनेवालों के लिए यह नियम समाज ने निर्धारित कर दिया है कि वे बायीं ओर रहे (Keep to the left) । अब यदि राज-मय का प्रयोग करनेवाले व्यक्ति, मोटर-कार चलातेवाले या ताँगे हाँकनेवाले इस नियम की अवहेलना करके स्वच्छन्दता से चले या हाँके तो इसका परिणाम यह होगा कि एक की स्वतंत्रता दूसरे के लिए बाधा सिद्ध होगी । उनमें परस्पर संघर्ष होगा और उमरा अन्तिम फल होगा विनाश ।

यदि हम सामाजिक संस्थाओं के विकास का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि मानव का प्रयत्न सहयोग और व्यवस्था की ओर अग्रसर रहा है । वह संघर्ष और अराजकता से बचने रहने के लिए प्रयत्नशील रहा है ।

प्रत्येक सम्य राष्ट्र का शासन प्रबंध जनता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा बनाये हुए कुछ मौलिक नियमों के द्वारा होता है, जिन्हें शासन विधान का नाम दिया गया है। इन नियमों में स्पष्ट रूप से राज्य, शासन और नागरिकों के परस्पर संबंधों और अधिकारों का उल्लेख होता है। इन नियमों के अनुसार शासन प्रबंध होने से नागरिकों की स्वाधीनता का उपभोग करता है। यदि कोई नागरिक किसी दूसरे के अधिकार पर आघात करता है अथवा अपने उत्तरदायित्व में त्रुटि करता है तो समाज या राज्य उसे दण्ड देता है।

हम व्यक्तिगत जीवन में भी इसी नियम का देखते हैं। यदि हमारे परिवार का कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य का कोई हानि पहुँचाता है तो परिवार के सब सदस्य उससे ऐसे कार्य की निन्दा करते हैं, उसका विरोध करते हैं और उसे अपनी त्रुटि का अनुभव कराने के लिए उससे असहयोग भी करते हैं।

जब एक परिवार, एक राज्य या एक राष्ट्र में हम यह व्यवस्था और नियम पाते हैं तब प्रत्येक राज्य के परस्पर संबंधों में इनका पालन क्या नहीं होना चाहिए? जब किसी राज्य का कोई व्यक्ति कानून के विरुद्ध कोई काम करता है तो समाज के हित के लिए राज्य उसे दण्ड देता है क्योंकि यदि राज्य में सभी व्यक्ति उसी प्रकार कानून के विरुद्ध काम करने लगेंगे, तो इससे समाज ने अपने कल्याण के लिए जो नियम बनाये हैं उनका उल्लंघन होगा और फलतः समाज का अहित होगा। परन्तु जब एक राज्य दूसरे राज्य पर अयोग्यपूर्वक आक्रमण करे, तब क्या विचारेंगे? क्या राज्य को इस प्रकार स्वच्छंद होकर निर्दोष राष्ट्र पर आक्रमण करने दिया जाये? जो राज्य को सर्वोपरि मानते हैं, वे यह कहेंगे कि राज्य पर किसीका नियंत्रण नहीं है, वह व्यक्तियों की भाँति नैतिक नियमों में बँधा नहीं है, इसलिए उस को रोक सक्ता है? परन्तु हम यह साफ तौर से देखते हैं कि इस बीसवीं सदी में यह कथन कुछ अप्रामाणिक-सा है। आज हम यह अनुभव करते हैं कि संसार का कोई देश अलग नहीं है सक्ता। आज पृथिवी सम्बन्धी

नहीं है। सब राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध इतने घनिष्ठ होगये हैं कि एक देश की आन्तरिक राजनीति का दूसरे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। तब यह कैसे संभव हो सकता है कि एक सबल राष्ट्र दूसरे पर अन्याय करता रहे और सब राज्य मिलकर उसका विरोध न करे ?

प्रोफेसर रामजे म्यूर ने अन्तर्राष्ट्रीयता के संबंध में लिखा है —

“अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर प्रगति का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों में कानून की सत्ता स्थापित करना है। किसी राज के पारस्परिक सम्बन्धों में कानून की सत्ता का स्पष्ट रूप उस प्रयत्न में दिखाई देता है जिसके द्वारा उनमें पारस्परिक संबंध का अवरोध होता है और शक्ति के निर्णय के स्थान में न्याय के निर्णय की स्थापना की जाती है। अतः अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर प्रगति का प्रयोजन अन्त में स्थायी शांति के लिए प्रगति ही है।”¹

राष्ट्रों की अन्योन्याश्रयता

इस युग में व्यवसाय और उद्योग ऊँची से-ऊँची स्थिति को पहुँच चुके हैं। एक प्रकार से इस पाश्चात्य उद्योगवाद ने ससार के राष्ट्रों को आत्म-निर्भरता से वंचित कर दिया है। किसी देश में कोयले की अधिकता है, किसी देश में लोहा अधिक है, तो दूसरे देश में पेट्रोल और तेल अधिक है। इसी प्रकार किसी देश में उद्योग बंधे अधिक हैं, तो कोई देश कृषि की पैदावार में अग्रगण्य है। वही रबड़ और लाख ज्यादा पायी जाती है, किसी देश में रई पैदा होती है, तो किसी देश में मशीनें अधिक बनती हैं, रई पैदा नहीं होती। इस प्रकार प्रकृति ने इन प्राकृतिक साधनों का वितरण सारे ससार में इस ढंग से किया है कि कोई भी एक देश दूसरे देश से संबंध स्थापित किये बिना उद्योग-व्यवसाय में उन्नति नहीं कर सकता। यही कारण है कि कोई राष्ट्र इस युग में आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त का प्रयोग नहीं कर सकता।

१. प्रोफे० रामजे म्यूर : 'नेशनलिज्म एण्ड इन्टरनेशनलिज्म' (१९१९) पृ० १३८

की पूर्ति के साधन-भाव हैं। यदि किसी राज्य में आर्थिक प्रक्रिया में कोई असमान हित होगा, तो राज्य की शक्ति उन लोगों के हाथ में होगी जो अधिक सत्ता के साधनों के स्वामी हैं। यदि इनका प्रयोग विशेष रूप से साम्राज्यवाद के लिए किया गया, तो उन उद्देश्यों की रक्षा के लिए प्रभुत्व का प्रयोग किया जायेगा। यदि किसी अन्तर्राष्ट्रीय सत्या ने ऐसे स्वतंत्र राज्य के अपने हितों के संरक्षण के प्रयत्न में बाधा उपस्थित की, तो वह उसके आवेश को ठुकरा देगा।”^१

प्रोफेसर लास्की के अनुसार प्रभुता प्राप्त राज्यों में ‘सत्तार के विभाजन का अर्थ है सत्तार की अन्तर्राष्ट्रीय आधिक्य अराजकता।’ ऐसी स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोई व्यवस्था कायम नहीं हो सकती।

अतः अन्तर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्य-राष्ट्र प्रभुता-हीन राज्य (Non Sovereign States) हों। जब तक राज्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने कार्यों का स्वयं निर्णायक बना रहेगा और जब तक वह उनका निर्णय किसी अन्तर्राष्ट्रीय समूह के हाथ में न सौंपेगा, तब तक वह स्वेच्छानुसार उन सम्मन्धों का निर्धारण करता रहेगा और इस प्रकार के कार्य से सत्तार की शान्ति के लिए खतरा बना रहेगा।

सारार्थ यह कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज के लिए एक निर्धारित आर्थिक योजना की आवश्यकता है, जिससे किसी भी राज्य की आर्थिक कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय मर्घ्य न करना पड़े।

अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाएँ

(१) राष्ट्रमण्डल ,

विगत महायुद्ध (१९१४-१८) के अन्त में जब शान्ति-सन्धि हुई तब सत्तार में युद्धों का अन्त करने के लिए राष्ट्रमण्डल की स्थापना का

१ हेराल्ड जे० लास्की : ‘इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ पीस इन ल्यो-
नार्ड वुल्फ्स वे टु प्रोवेण्ट वार’; पृ० ५३३

प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अमरीका के राष्ट्रपति विलसन ने राष्ट्रसंघ की कल्पना की और अन्य राजनीतिज्ञों के सहयोग से उसे एक अन्तर्राष्ट्रीय जीवन संस्था का रूप दिया गया। १० जनवरी १९२० को राष्ट्रसंघ की विधिवत स्थापना हो गयी।

राष्ट्रसंघ के विधान में उसकी सबसे प्रथम धारा में उसका लक्ष्य इस प्रकार घोषित किया गया —

प्रतिज्ञा करनेवाले राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए युद्ध न करने को भर्वादा को स्वीकार करके राष्ट्रों में परस्पर प्रकट रूप से व्यापपूर्ण और सम्माननीय सम्बन्धों को कायम रखते हुए विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय विधान को क्रियात्मक रूप देने और यह बात विश्वासपूर्वक ध्यान में रखकर सुसंगठित राष्ट्रों की पारस्परिक सन्धियों की प्रतिज्ञाओं का पूरा आदर करते हुए व्याप की रक्षा के लिए राष्ट्रसंघ के इस विधान को स्वीकार करते हैं।

विधान की इस प्रस्तावना में राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित सिद्धान्त स्पष्टनया निहित हैं—

- १ अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता शान्ति और सुरक्षा की स्थापना।
- २ युद्ध की रोक।
- ३ राष्ट्रों में परस्पर समुचित प्रवृत्ति और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों की स्थापना।
- ४ मसाल की सरकारों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार आचरण।
- ५ अन्तर्राष्ट्रीय धर्म-व्यवस्था की स्थापना।
- ६ सन्धियों की समस्त शर्तों का पालन।

इस विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रसंघ के दो मुख्य लक्ष्य हैं—
एक तो संसार में शान्ति की स्थापना और दूसरा युद्धों को रोकना। अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए राष्ट्रों में परस्पर सहकारिता और सुरक्षा आवश्यक है। राष्ट्रसंघ सामूहिक सुरक्षा में विश्वास करता है और कटनीति को शान्ति-स्थापना के लिए घातक मानता है। इसलिए

विधान में यह स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों में जो सन्धियाँ हाथी के प्रकट रूप में की जायेंगी। गुप्त रूप से कोई संधि नहीं होगी और उन सन्धियों की संघ के आफिस में रजिस्ट्री भी होगी। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता की वृद्धि के लिए अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ मनुष्या के कल्याणार्थ स्थापित की गयी। युद्ध रोकने की समस्या बड़ी विषट है। राष्ट्रसंघ ने इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया तथा निःशस्त्रीकरण के लिए योजना बनाने का विचार किया।

राष्ट्रसंघ के अन्तर्गत दो प्रमुख परिपद हैं। पहली असेम्बली कहलाती है और दूसरी कौंसिल। असेम्बली में प्रत्येक स्वतन्त्र राज्य को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। कौंसिल राष्ट्रसंघ की कार्य समिति है। सन् १९३२ में संसार के कुल ६६ राष्ट्रों में से ५५ राष्ट्र राष्ट्रसंघ के सदस्य थे।

संयुक्तराज्य अमरीका तो राष्ट्रसंघ के जन्म काल से ही अलग रहा है। सन् १९३२ के बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बिगड़ती गयी और पुन राजनीतिक क्षितिज पर युद्ध के बादल उमड़ने लगे। वस, साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने एक-एक करके राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया। सबसे पहले जापान ने राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इटली और जर्मनी ने भी उसे त्याग दिया। इस प्रकार सन् १९३२ के बाद राष्ट्रसंघ का प्रभाव धीरे-धीरे घटता गया और अन्त में वह एक निर्जीव और शक्तिहीन संस्था रह गयी। राष्ट्रसंघ की उपर्युक्त दोनों परिपदा के निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए जेनेवा (स्वीजरलैंड) में उसका एक विशाल अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय है। इसके अन्तर्गत १३ विभाग हैं जो अपने-अपने कार्य का चलाते हैं।

(२) अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ

शान्ति सन्धि के १३वें भाग में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-संघ के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है। इसमें लिखा है —

“राष्ट्रसंघ का उद्देश्य विश्व में शान्ति की स्थापना करना

है और शान्ति उसी समय स्थापित हो सकती है जबकि उसका आधार सामाजिक न्याय हो। आज मजदूरों की वर्तमान अवस्था इतनी अन्यायपूर्ण, कष्टमय और विकट है कि बहुतेरे मजदूरों के लिए मृत्यु ही हो रही है। इसीलिए ससार में इसनी अशान्ति बढ़ गयी है कि समूचे ससार की शान्ति और सामंजस्य ही संकट में है। इस परिस्थिति में शीघ्र ही सुधार होना चाहिए—जैसे मजदूरों के दैनिक कार्य के घण्टे कितने हों, कितने घण्टों का दिन माना जाये, कितने दिनों का एक सप्ताह माना जाये, मजदूरों की भरती का नियन्त्रण, बेकारी का निवारण, उचित वेतन निर्धारण करना, जब अधिक कार्य-काल में आहत होजायें या व्यथित हो तो उनकी रक्षा करना, बालकों, युवकों और स्त्रियों का संरक्षण, बुढ़ापे तथा शरीर से निवृत्त होनेपर जीविका की व्यवस्था, प्रवासी मजदूरों के हितों का संरक्षण, पारस्परिक सहयोग से सगठित कार्य करने की सुविधा, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध तथा अन्य सुविधाएँ।”

इस भूमिका से यह स्पष्ट है कि राजनीतिज्ञों को मजदूरों की अवस्था का अनुभव था और वे यह जानते थे कि यदि उनकी दशा में राज्यों ने सन्तोषप्रद सुधार नहीं किया तो इससे बड़ी अशान्ति होगी। अतः समस्त प्रमुख उद्योगवादी राष्ट्रों ने एक अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-न्याय की स्थापना की। इस सभ्य के सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

- (१) सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि श्रम को बाजार में बेचने-खरीदने की चीज न माना जाये।
- (२) मजदूरों व पूंजीपतियों को वेध उद्देश्यों के लिए सगठन करने का अधिकार है।
- (३) मजदूरों के पारिश्रमिक (मजदूरी) की दर इतनी पर्याप्त नियत की जाये जो उनके देश, काल और स्थिति के अनुकूल व उचित हो।
- (४) जिन देशों में मजदूरों के लिए ८ घंटे का दिन तथा ४८ घंटे का सप्ताह नहीं माना जाता, उन देशों में यही नियम प्रचलित कराने या प्रयत्न किया जाये।

- (५) प्रति सप्ताह मजदूरी को एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए और, जहाँतक सम्भव हो रविवार छुट्टी का दिन नियत किया जाये।
- (६) बालका स मजदूरी न ली जाय जिसमे वे उचित शिक्षा प्राप्त कर सक और उनका शारीरिक विकास हो सके।
- (७) पुरुषा और स्त्रियों को समान काय के लिए समान मजदूरी दी जाय।
- (८) मजदूरी के कार्य का जो तरीका कानून द्वारा निर्धारित किया गया है वह आर्थिक दृष्टि से न्यायसंगत है।
- (९) प्रत्येक राष्ट्र को अपने देश में ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि यह जाँच पड़ताल की जा सके कि उपयुक्त सिद्धांता का पालन ठीक ढंग से होता है या नहीं। इस जाँच में स्त्रियाँ भी भाग लें।

मजदूर सभ का संगठन भी राष्ट्र सभ जैसा ही है। उसकी अन्तर्राष्ट्रीय परिषद में प्रत्येक राष्ट्र को प्रतिनिधि भजने का अधिकार है। उसमें ५६ राज्यों के प्रतिनिधि हैं। अन्तर्राष्ट्रीय परिषद मजदूरों के कल्याण के लिए प्रस्ताव स्वीकार करती है और अपने सदस्य राष्ट्रों को यह आदेश करती है कि वे उसके अनुसार अपने अपने देश में कानून बनाकर उसे कार्यान्वित करें। परन्तु यदि कोई राष्ट्र इन प्रस्तावों के अनुसार काम न करे तो सभ उस ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-सभ का एक वायवहारिणी समिति है और उसका सचैट्रियट भी जेनेवा में स्थित है। इस वायवहारिणी में कुल ३२ सदस्य हैं। इनमें से ८ सदस्य ग्याया हैं। भारत भी एक ग्यायी सदस्य है।

(३) स्थायी

राष्ट्रसभ न हग में एक अन्तर्राष्ट्रीय की है, जो ३० जनवरी मत १०३ न्यायालय का उन विग्रही राष्ट्रों का अधिकार है जो न्यायालय को स्वीकार

राष्ट्रसंघ की विफलता और उसके कारण

कवर कहा गया है कि राष्ट्रसंघ अथवा एन.एन.ओ. निरर्थक और निष्प्रभावी सम्मेलन चुकी है, अतः उसकी असफलता के कारणों पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। अतएव इस सम्बंध में जो विवेचन किया गया है, उसमें यह भी माना जाना जा सकता है कि राष्ट्रसंघ की विफलता के मुख्य कारण यही हैं। फिर भी यहाँ मुख्य रूप से उक्त दो मुख्य कारणों पर ध्यान दिया जायेगा, जिससे पाठक आसानी से समझ सकें और जब भविष्य में विद्वत् लोग इसके लिए किसी विद्वत् सम्मेलन की स्थापना की जाय तो इन कारणों के निवारण के लिए प्रयत्न किया जाये।

- (१) राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद ही यू.एन.ओ. में उभरे प्रति विद्रोह उठ गया हुआ। राज्य-साम्राज्यवाद के नये में पागल होकर मानवता के आदर्शों को भूल गये और मानव एकता और विश्व-व्युत्थान के प्रति उत्तरी श्रद्धा कम होनी लगी। राष्ट्रसंघ प्रधान-संविधानमन्त्र और साम्राज्यवादी राष्ट्रों के हाथ में स्वायत्तता का अन्त कर दिया गया। यह राज्य के शासन के प्रतिनिधियों का एक ऐसा गुट बन गया, जो वास्तव में मानव-समाज का भगदोर करने के अयोग्य थे। राष्ट्रसंघ का राज्य के नागरिकों में कोई सम्बन्ध न रहा।
- (२) अक्षरशः का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है संविधानी राष्ट्रों की साम्राज्यवादी प्रवृत्तियाँ। राष्ट्रसंघ की स्थापना में इनमें प्रतिवन्धी भागीदारी नहीं हुई। प्रभुता के सिद्धांत को जो अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोधी है, सभी राष्ट्र मानते हैं और इस प्रकार राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों का राष्ट्रीय प्रभुत्व के नाम पर कोई मुल्त ही न रह गया।
- (३) विश्व-परा-सम्बन्धी-समर्थन भी राष्ट्रसंघ की विफलता के लिए उत्तरदायी है। यू.एन.ओ. के बाद कम से कम पाँच-छह के सम्बन्धित सम्मेलनवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। सम्मेलन के दौरान में सम्मेलनवाद का प्रचार हो गया। सम्मेलनवादी विचारधारा के प्रतिवन्धी देशों और जर्मनी में प्रतिनिधित्व उत्पन्न हुई, और उसके सम्बन्धित पाँचों और नवीन-दो नवीन विचारधाराओं का

विकास हुआ। इटली में मुसोलिनी ने मुस्लिमखुला शांतिवाद के सिंगफ बिद्रोह शुरू कर दिया। इटली के विश्व ज्ञान-कोष में मुसोलिनी ने लिखा है —

“फासिज्म का न तो शाश्वत ज्ञान्ति की आवश्यकता में विश्वास है और न उसकी उपयोगिता में। ज्ञान्तिवाद में सघर्ष से बचने की प्रवृत्ति छिपी हुई है। वह मूलनः कायरता ही है। इसलिए ‘फासिज्म’ खलिदान के मुकाबिले में ज्ञान्ति को ठुकराता है। युद्ध और सिर्फ युद्ध में ही मनुष्य की शक्तियों की अधिक से-अधिक परीक्षा होती है और उसे स्वीकार करने का साहस करनेवाली जातियों के सिर पर ही उच्चता का सेहरा घेंपता है। और सब तरह की परीक्षाएँ नकली हैं। ये मनुष्य के सामने जीवन या मरण के चुनाव का सवाल पेश नहीं करतीं।”

इसी प्रकार जर्मनी में हेर हिटलर ने जर्मनों की सोयी हुई हिंसा-वृत्तियाँ जगाने के लिए एक आत्मचरित लिखा और उसमें हिंसा, युद्ध और साम्राज्यवाद का यश गाया। उसमें लिखा —

“यदि कोई जीवित रहना चाहता है, तो उसे लड़ाई करनी चाहिए। और यदि कोई इस सतत सघर्षशील सतार में लड़ाई के प्रति उदासीन है, तो उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं।”

“ऐसा समझोता—गुटबन्दी—जिसका उद्देश्य युद्ध में पड़ना नहीं है, बेकार और व्यर्थ है।”

स्पष्ट है कि ये विचारधाराएँ शान्तिवाद और राष्ट्रसंघ के लक्ष्य के विरुद्ध हैं। जर्मनी और इटली आज १० वर्षों से भी अधिक समय से पूरे यूरोप में हिंसावाद, युद्ध और सघर्ष का प्रचार कर रहे हैं।

(४) राष्ट्रसंघ के आन्तरिक संगठन की ग्राटियाँ भी उसकी विफलता के लिए कम उत्तरदायी नहीं हैं। राष्ट्रसंघ स्वतन्त्र सदस्य-राष्ट्रों की सरकारों के प्रतिनिधियों की संस्था है। राष्ट्रसंघ की सत्ता

१-२. हेर हिटलर : ‘माइन कैंम्फ’ (मेरा सघर्ष) १८ वीं जर्मन संस्करण, पृष्ठ ३१७ और ७४९।

इसी प्रकार एशिया में किसी राष्ट्र पर कोई अन्यायपूर्ण आक्रमण होता है, तो यूरोप के बड़े राष्ट्रों को यह न सोचना चाहिए कि इससे यूरोप का कोई सम्बन्ध नहीं है। संसार के किसी भी भाग में होनेवाला छोटे-से-छोटा उपद्रव विश्व-शांति के लिए खतरा है, यह प्रत्येक राष्ट्र को भली-भाँति समझ लेना चाहिए।

संसार के एक बहुत बड़े भाग में ऐसे राष्ट्र एवं जातियाँ भी हैं जो राजनीतिक, आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टियों से पिछड़ी हुई हैं और जो इस समय साम्राज्यवादी राष्ट्रों की साम्राज्य-लालश की शिकार हैं। राष्ट्रसंघ ने ऐसे राष्ट्रों व पिछड़ी हुई जातियों का शासन-प्रबंध शासना-देश-प्रणाली के अन्तर्गत विगत युद्ध के विजेता राष्ट्रों के हाथ में देकर उन्हें उनका भाग्य-निर्णायक बना दिया। ऐसी पिछड़ी तथा पराधीन जातियाँ एशिया और अफ्रीका में अधिक हैं। अब समस्या यह है कि इनके संबंध में, अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिए क्या किया जाये? इसके लिए सबसे पहले अन्तर्राष्ट्रीय समाज को यह सिद्धान्त बिना किसी अपवाद के स्वीकार करना चाहिए कि प्रत्येक राष्ट्र को स्वभाष्य निर्णय का अधिकार है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पराधीन राष्ट्र को स्वाधीनता दी जाये तथा उनकी रक्षा के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन नियुक्त किया जाये। इस कमीशन का कार्य इस प्रकार स्वतंत्र किये गये राष्ट्रों को सबल राष्ट्रों की कोप-दृष्टि से बचाना हो।

इस प्रकार संसार के प्रत्येक राष्ट्र को, चाहे वह एशियाई राष्ट्र हो या अफ्रीकन, अन्तर्राष्ट्रीय जीवन में समानता का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार जातीय प्रश्न का एकदम ख़ात्मा होजाना ही श्रेयस्कर होगा।

राष्ट्रों के आपसी झगड़ों के फँसले के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का निर्णय किया जाये। प्रत्येक राष्ट्र को इस न्यायालय में ही अपने ऐसे विवाद का निर्णय कराने के लिए सन्नद्ध होना चाहिए। इस न्यायालय में सभी राष्ट्रों का विन्यास होना जरूरी है। कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न इस न्यायालय

की अधिकार-सीमा के बाहर न होना चाहिए और न किसी राष्ट्र का इस संबंध में कोई विशेष शिष्यायते दी जानी चाहिए ।

अन्तर्राष्ट्रीय मिशन का निर्माण किया जाना और प्रत्येक राष्ट्र स उमरा पालन कराने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ।

समस्त राष्ट्रों में पारस्परिक सहायता तथा विश्वशान्ति के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित जाना चाहिए । यह संगठन संधि के सिद्धान्त के आधार पर कार्यरत हो । प्रत्येक राष्ट्र को अपने सामान्य मामलों का नियंत्रण और प्रबंध इस संगठन का सौंप देना चाहिए ।

यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठन वैदणिक नीति, अन्तर्राष्ट्रीय सेना, आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रीय राजस्व, उपनिवेशों की समस्या, अन्तर्राष्ट्रीय यातायात, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा और प्रचल आदि मामलों का प्रबंध कर सक्ता है ।

हमन सन्धे में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धान्तों की रूपरेखा तथा मौलिक सिद्धान्तों का विवेचन किया है । इनपर विस्तृत रूप से विचार उची समय किया जा सकना है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की कोई व्यावहारिक और श्रेष्ठ योजना तैयार की जाये ।

संसार की एकमात्र अन्तर्राष्ट्रीय समस्या राष्ट्रसंधि के पतन के कारणों पर विचार करके उनका निवारण का प्रयत्न करना चाहिए । राष्ट्रसंधि के पतन से हमें यह न समझ लेना चाहिए कि संसार में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता संभव ही नहीं है बल्कि उसका लिए उचित तरीके से प्रयत्न करना चाहिए ।

भारतवर्ष और अन्तर्राष्ट्रीयता

अन्तर्राष्ट्रीय समाज में भारतवर्ष का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। यद्यपि भारतवर्ष इस समय अपनी राजनीतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए अग्रसर है, तो भी इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि भारत विश्व-शान्ति के लिए आज भी सर्वश्रेष्ठ देने देने की क्षमता रखता है। चाहे जिस दृष्टि से देखा जाये, भारत विश्व वन्धुत्व के आदर्श को कार्यरूप में परिणत करने में समर्थ है। भारत का प्राचीन इतिहास हमारे इस बयान की मनाई प्रकट करता है।

भारत का विश्व-प्रेम

संसार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान और पुण्यतत्त्ववेत्ता इस बात में एकमत हैं कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्थाएँ विश्व में प्राचीनतम हैं। जैसे-जैसे साहित्य, विज्ञान, राजनीति आदि के क्षेत्रों में अन्वेषण और अनुसंधान होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे यह प्रकट होता जा रहा है कि भारतवर्ष न केवल आध्यात्मिक जगत् में ही धिरोमणि रहा है, प्रत्युत साहित्य, कला-कौशल, ज्ञान-विज्ञान, समाज नीति और राजनीति में भी किसी सभ्य राष्ट्र से पीछे नहीं रहा। कुछ ही समय पहले पश्चिम्य यूरोपीय विद्वानों की दृष्टि में भारत एक ऐसा 'दार्शनिकों का देश' था, जहाँ केवल माधु-महामाया की ही पूजा होती हो। परन्तु राजनीति और इतिहास के सुविशार भारतीय विद्वान प्रो० येनीप्रसाद ने अपने खोजपूर्ण ग्रन्थ 'प्राचीन भारत में राज्य की स्थिति' और 'प्राचीन भारत में शासन का सिद्धान्त' तथा भारत विख्यात इतिहासवेत्ता स्व०

१ 'द स्टेट इन ऐशियन इण्डिया'।

२ 'पिअरी और गवर्नमेण्ट इन ऐशियन इण्डिया'।

डा० वाणीप्रसाद जायसवाल ने अपने सुविख्यात ग्रन्थ 'हिन्दू राजतन्त्र' द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि भारतवर्ष केवल आध्यात्मिक जगत् में ही शिरोमणि नहीं रहा है प्रत्युत राजनीति में भी अग्रगण्य रहा है। कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' इस विषय का अनुपम ग्रन्थ है।

समस्त भारतीय साहित्य विद्वत्-संस्कृति और विश्व प्रेम की विचार-धारा से ओतप्रोत है। वैदिक संस्कृति की मर्ममे यही विशेषता यही है कि वह लोकमग्न अर्थात् मानव-समाज के कल्याण की प्रमुख और ऊँचा म्यान देती है। वैदिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोकसंग्रह का सिद्धान्त अन्तर्भूत है। इसी विशेषता का फल है कि भारत-भूमि में सदैव से विद्वत्-भावना की पूजा होती रही है। आज भी भारत में जिस राष्ट्रीयता का यशोगान हो रहा है, उनका भी आधार विद्वत् प्रेम और लोकसंग्रह ही है।

'वैदिक' संस्कृति के अनुसार विश्व प्रेम और दान प्रेम एक-दूसरे का विरोधी नहीं है प्रत्युत पूरक भाव है। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने कुटुम्ब से अनुराग रखता हुआ भी दानभक्ति से मुक्त नहीं मोंडता, राष्ट्र-हित में अपने व्यक्तिगत हित का बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है, उसी प्रकार एक सच्चा दानभक्त भी विश्व हित के लिए अपना सब-कुछ अर्पण कर सपता है। जिन विचारका वा यह कथन है कि राष्ट्रीयता (दशमन्ति) विश्व प्रेम के लिए घातक है, उन्हें अपना यह कथन आधुनिक उग्र राष्ट्रीयता के लिए ही सीमित रखना चाहिए। जो राष्ट्रीयता हमें दूसरी से द्वेष करना नहीं सिखलाती, वह हमारे विश्व के लिए अवाञ्छनीय किस प्रकार हो सकती है ? २

आयुर्वेद के पृथिवी-सूक्त अ० १२-१ में ऐसे ही भाव मिलते हैं—

‘हे पृथिवी ! मरणधर्मा यदायं अयवा मनुष्य तुल्यो उत्पन्न होते हैं और तुल्य ही विचरण करते हैं—निवास करते हैं, तू द्विपद (मनुष्य)

१ 'हिन्दू पॉजिटी'।

२ रामनारायण यादवेन्द्र 'राष्ट्रताम्र और विश्व-शान्ति', पृ० २३५

और क्षुत्पद (चीपायो आदि) का पालन-पोषण करती है । जिन मनुष्यों के लिए उदय होता हुआ सूर्य किरणों के द्वारा अमृत, जीवन-प्रद प्रकाश भली प्रकार देता है, फँलाता है, वे पाँचो मानव जातियाँ (गौर, लाल, धूसर, पीत और कृष्ण) तेरी ही हैं । '

[पृ० सू० - अध्याय १२-१ १५ वाँ श्लोक]

"वे सब प्रजाएँ हमें मिलकर—इकट्ठी होकर—भरपूर करें और हे पृथ्वी ! तू घापी की मधुरता मुझे दे ।

[पृ० सू० अ० १२-१ : १६ वाँ श्लोक]

"हे मातृभूमि ! तू इकट्ठा रहने का महत् स्थल है अतएव तू महती पूजनीया है । तेरा वेग, गति, एव कम्पन महान् है और महिमा-सम्पन्न, महत्त्वशाली, सूर्य, परमात्मा अथवा ऐश्वर्य सम्पन्न राजा प्रमादरहित होकर तेरी रक्षा करता है । ऐसी तू भूमि प्रकाश की चमक की भाँति हमें उत्तम रीति से चमका, प्रवृत्त कर, जिससे हमसे कोई द्वेष-स्पृहा न करे ।"

[पृ० सू० अ० १२-१ १६ वाँ श्लोक]

अन्यत्र लिखा है —

"यथास्थान अथवा एक गृह के सदृश नाना भाषाएँ बोलनेवाले और अनेक व्यवसायवाले जनों को धारण करती हुई यह पृथिवी निश्चेष्ट तथा निश्चल गो की भाँति मुझे धन की हजारों धाराएँ बहावे ।

[पृ० सू० अ० १२-१ : ४५ वाँ श्लोक]

वैदिक संस्कृति में समस्त मानव समाज एक परिवार है, परन्तु विविध भाषा, रंग रूप, व्यवसाय आदि के कारण वह अनेक भागों में बँट गया है । जिस प्रकार एक परिवार के सदस्य विविध भाषा, साहित्य और व्यवसाय से अनुराग रखते हुए भी परिवार बंधन में ग्रथित रहते हैं उसी प्रकार समस्त मानव समाज भी एकता के मूत्र में बँधा रह सकता है ।

पृथिवी-सूक्त के उक्त १५ वं श्लोक में विश्व प्रेम का आदर्श वितनी उत्तमता से वर्णित हुआ है । पृथ्वी पर निवास करनेवाली पाँचो मानव-जातियाँ का समानता का अधिकार है । पाश्चात्य जातियाँ की यह भावना रही है कि ईश्वर ने गौर वर्ण की जातियाँ को ही ससार म

शासन करने के लिए पैदा किया है और पीत तथा कृष्ण वर्ण की जातियाँ तो शासित होने के लिए ही पैदा हुई हैं । इसे यूरोपीय 'गौर जातियाँ का भार' (White man's Burden) कहते हैं । यूरोपीय जातिप्राप्त जातीयता की भावना इतनी उग्र है कि वे सारे ससार में गौरा का प्रभुत्व चाहती हैं । आज यूरोप इसीके अभिगाप से पीड़ित है ।

विश्व-व्युत्पत्ति और सम्राट् अशोक

भारत में विश्व प्रेम के सिद्धान्त केवल साहित्य और धर्म-ग्रन्थों तक ही सीमित नहीं रहे हैं, प्रत्युन् जीवन में—व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों में—उनकी चरितार्थ किया गया है । व्यक्तिगत जीवन के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । किन्तु हम यहाँ अहिंसा, प्रेम और विश्व-व्युत्पत्ति का एक ऐसा उदाहरण देना चाहते हैं, जैसा ससार के इतिहास में दूसरा नही मिलेगा ।

मानवता को एक मूल में बाँधने एवं ससार में प्रेम या साम्राज्य स्थापित करने में सम्राट् अशोक ने जो प्रयत्न किया वह वास्तव में स्वर्णचरित्रों में लिखे जाने योग्य है । राष्ट्रपति विल्यम प्रियन्ड, अमरीका के गान्धिवादी निकीत्स बटलर मरे (जिन्हें गत वर्ष गान्धि का नोबल पुरस्कार मिला है), रोबिन्स, रोम्या रोण और महात्मा गाँधी आदि महापुरुषों के सामूहिक प्रयत्न अशोक के काय की ही परम्परा हैं । प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास-लेखक श्री० एच० जी बेंत्स ने अशोक के सम्बन्ध में लिखा है—

‘अशोक पहला सम्राट है, जिसने मनुष्यों के सच्चे उद्देश्य और जीवन-पथ को लक्ष्य में रखकर मनुष्य जाति को शिक्षित किया । उसने विनाश सेना और बड़ी भारी शक्ति के होते हुए भी, सैनिक और राजनीतिक विजय नहीं की । उसने अपने शौर्य, पराक्रम और घोरता को दिखाने के लिए किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया, किसी देश का सवनाश करने के लिए किसी राष्ट्र की गुलाम बनाने के लिए, सुंदर नगरों को धूल में मिलाने के लिए, बाहूतों, घोड़ों और बुद्धिमानों के अभिगाप से, हाहा

कार से और आँसुओं से भरी पृथ्वी को अधिक बोझिल तथा दुःसित मानव समाज को अधिक दुःखी नहीं किया। उसने धर्म विजय की, धर्म-भिक्षुको द्वारा अतृप्त और सतृप्त ससार को प्रेम और धर्म का अमृत-पान कराया।”

अपने चतुर्दश शिला लब्ध म अशोक ने लिखवाया है —

“धर्म विजय को ही ‘देवताओं के प्रिय’ प्रियदर्शी मह्यत विजय मानत ह। इस धर्म विजय को ‘देवताओं के प्रिय’ ने यहाँ (अपने राज्य में) तथा एतद्दूरी योजन दूर पड़ोसी राज्या में प्राप्त किया है जहाँ अन्तर्गोक नामक पवन राजा राज्य करता है, और अन्तर्गोक के बाद तुरन्त, अलिकिति, यक और अलिकमुन्दर नाम के चार राजा राज्य करते हैं और उन्होंने अपने राज्य के नीचे (दक्षिण में) चील, पाण्ड्य तथा ताम्रपर्णि में भी धर्म विजय प्राप्त की है। उसी प्रकार हिंदुराजा के राज्य में तथा विषयजिह्वा में यवनों में, कम्बोजों में, नामक नाम पक्षियों में, भोजों में, पितृ निकाय आश्रमों में और पुलिन्दों में सब जगह लोग देवताओं के प्रिय का धर्मानुशासन अनुसरण करते हैं और अनुसरण करेंगे। जहाँ जहाँ ‘देवताओं के प्रिय’ के वृत्त नहीं पहुँच सकते, वहाँ वहाँ लोग ‘देवताओं के प्रिय’ का धर्माचरण, धर्म विधान और धर्मानुशासन सुनकर धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। इस प्रकार सर्वत्र जो विजय हुई है, वह विजय वास्तव में सर्वत्र आनन्द देनेवाली है। धर्म विजय में जो आनन्द है, यह बहुत प्रगाढ़ है, पर वह आनन्द क्षुद्र वस्तु है। ‘देवताओं के प्रिय’ पारलौकिक कल्याण को ही बड़ी भारी वस्तु समझते हैं। इसलिए यह धर्म लेख लिखा गया है कि मेरे पुत्र और पौत्र जो हों, वे नया देश विजय करना अपना कर्त्तव्य न समझें। यदि कभी वे नया देश विजय करने में प्रवृत्त हों तो उन्हें शांति और नम्रता से काम लेना चाहिए और धर्म-विजय को ही सच्ची विजय मानना चाहिए। उससे इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख-लभ होता है। उद्योग ही उसके आनन्द का कारण हो, क्योंकि उससे इहलोक और परलोक दोनों सिद्ध होते हैं।

अथाक् क मग्निं के शिला जग में लिखा है —

“ ‘सब मनुष्य मेरे पुत्र हैं, और जिस प्रकार मैं चाहता हूँ कि मेरे पुत्रगण सब तरह के हित और सुख को प्राप्त करें, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि सब मनुष्य ऐहिक और पारलौकिक सब तरह के हित और सुख का लाभ उठावें। आप लोग इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि यह नीति श्रेष्ठ है।’

‘अशोक ने २८ वर्षों तक मनुष्यों की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए कार्य किया। इतिहास के पन्नों में जिन हजारों सम्राटों, राजा-महाराजों आदि का उल्लेख है, उनमें केवल अशोक का नाम आकाश में तारे के समान जगमगाता है। योलगा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर के साथ लिया जाता है। चीन, तिब्बत और भारत में भी (यद्यपि उन्होंने अशोक के सिद्धान्तों का परित्याग कर दिया है) उसकी महानता की परम्परा सुरक्षित है। आज भी जीवित मनुष्यों में अशोक की स्मृति कागस्टेनटाइन या चार्ल्समैगन की यादगार से कहीं अधिक जाग्रत है।’ ये हैं असाव व प्रणि विद्वत् व एक महान् इतिहास वेत्ता श्री एच० जी० वैंस के विचार। श्री वैंस के इस कथन की सवाई में सम्मति करना अगता हागी, परन्तु भारत के सम्बन्ध में उन्होंने जो जो कहा है उसके सम्बन्ध में इनका और कहना पर्याप्त होगा कि प्राधुनिक काल में भी भारत ने अशोक की परम्परा का त्याग नहीं किया है। आजके युग में महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आन्दोलन अशोक की सिद्धान्तों का प्रतीक है।

हमारे कथन का सार यह है कि भारत प्राचीन समय में ही विश्व-प्रेम, विद्वत् व धृष्ट और अन्तर्राष्ट्रीयता का पुजारी रहा है। आज भारत अपनी स्वाधीनता की मिट्टि में लगा हुआ है और हमारा यह ध्रुव विचार है कि स्वाधीन भारत विद्वत् में मन्वी अन्तर्राष्ट्रीयता को जन्म देने में सफल होगा।

समाप्त की स्थिति और भारतवर्ष

आत्मशास्त्र विद्वत्विद्यालय के गवर्नरी के प्रोफेसर श्री एच० ड० जेम्स

ने भारत के सम्बन्ध में अपने एक विचार-पूर्ण निबन्ध में लिखा है —

“...आनेवाले युग में भारत विश्व-राजनीति का प्रधान-अंग बनेगा। अधिक स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ यह है कि यदि भारत ब्रिटिश-कॉमनवेल्थ से अपना सम्पर्क बनाये रखेगा और दूसरी ओर कॉमनवेल्थ भी भारत को अपने सफटन में समुचित पद प्रदान करेगा तो विश्व शांति और मानव-समाज के अभ्युदय का मार्ग अत्यधिक प्रशस्त हो जायेगा। यदि भारत और दूसरे ब्रिटिश उपनियेता के बीच समानता के आधार पर सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न विफल रहा, तो उसका परिणाम न केवल कॉमनवेल्थ पर प्रत्युत समग्र मानव-समाज पर पड़ेगा। अन्तर्जातीय मध्यम के लिए एक विशाल रणमञ्च तैयार होजायेगा।”^१

प्रोफेसर जिमर्न के पथन में यह स्पष्ट होजाना है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज में भारत का स्थान अद्वितीय है। परन्तु भारत के पराधीन देश होने से मानव समाज की उन्नति में बड़ी अड़चन होरही है। राष्ट्रसंघ में या विश्व की राजनीति में अधीनस्थ राज्यों का कोई स्थान नहीं है। जैसे भारतवर्ष राष्ट्रसंघ के जन्म-काल में ही उसका मौलिक सदस्य रहा है, परन्तु उसकी मदम्यता के कारण उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और न विश्व-शांति की समस्या के समाधान में ही कोई योग मिला है। भारत का राष्ट्रीय लोकमत प्रारम्भ से ही राष्ट्रसंघ की सदस्यता का विरोधी रहा है। यह इसलिए नहीं कि भारत राष्ट्रसंघ के आदर्शों में विश्वास नहीं करता, बल्कि इसका कारण यह है कि वर्तमान परिस्थिति में, जबकि राष्ट्रसंघ यूरोप के महान् राष्ट्रों के घूटनीतिज्ञों का एक गुप्त मण्डल बन गया है, भारत का राष्ट्रसंघ से सम्बन्ध रहना विभीषिके लिए हितकर नहीं होसकता।

या प्रतिवर्ष सितम्बर मास में भारत की ओर से राष्ट्रसंघ की असेम्बली के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए प्रतिनिधि मण्डल जेनेवा को जाता है, परन्तु यह प्रतिनिधि-मण्डल सच्चे अर्थों में भारत

का नहीं होना, क्योंकि इन प्रतिनिधियों की नियुक्ति या निर्वाचन में भारतीय नागरिकों का हाथ नहीं है और न भारतीय व्यवस्थापिका समा ही इन्हें चुनकर भेजती है। इन प्रतिनिधियों का चुनाव भारत-मन्त्री के हाथों में है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ की असेम्बली के अधिवेशन में भारत का प्रतिनिधि-मण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक अपने हितों की रक्षा के लिए कोई कार्य नहीं कर सकता; वह ब्रिटिश-प्रतिनिधि-मण्डल के राकेट पर ही अपने विचार प्रकट कर सकता है।

सन् १९३२ में राष्ट्रसंघ की आय (जो राष्ट्रों के चन्दे से प्राप्त हुई थी) १३ लाख ४७ हजार ५२० पाँड थी। भारत ने प्रतिवर्ष ७५ हजार ४९९ पाँड अर्थात् १० लाख ५ हजार ८० रु० के हिसाब से अबतक १९ वर्षों में १ करोड़ ९१ लाख ६ हजार ५२० (अर्थात् २ करोड़ के लगभग) रुपये राष्ट्रसंघ की भेंट चढ़ाये हैं। भारत की गरीबी तथा राष्ट्रसंघ में उसकी स्थिति को देखने हुए यह धन-राशि बहुत अधिक है। राष्ट्रसंघ के लिए सबसे अधिक धन इंग्लैंड देता है। उसके बाद फ्रांस। फ्रांस के बाद जापान का और चीन नम्बर भारत का है। जापान ने राष्ट्रसंघ छोड़ दिया है। इसलिए सबसे अधिक ख़ाद देनेवाली में अब भारत का तीसरा स्थान है। इतना धन व्यय करने पर भी भारत का राष्ट्रसंघ की कौंसिल में कोई वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं है।

कौंसिल में केवल बड़े-बड़े राष्ट्रों का ही प्रभुत्व है। सितम्बर १९३८ के असेम्बली-अधिवेशन में मुसलमानों के नेता और धार्मिक प्रमुख श्री आगाख़ा को राष्ट्रसंघ की असेम्बली का प्रधान निर्वाचन करके इंग्लैंड ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया है। पर अशक्त, दुर्बल और अपने श्रेष्ठ में पतित राष्ट्रसंघ की अच्युतता भारतीय को प्रदाल पर इंग्लैंड ने कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं किया। इस समय भारे मगार को यह ज्ञान हो गया है कि राष्ट्रसंघ मण्डल पावण्ड के सिवा और कुछ नहीं है।

भारत का श्रंगमंग

इस समय जहाँ भारत मगार के गमन देशों के साथ सहयोग और

भ्रष्टता का सम्बन्ध बनाने में प्रयत्नशील है वहाँ ब्रिटिश शासन की नीति इसमें सर्वथा विपरीत चली आ रही है और दूसरे देशों से भारत का सम्बन्ध दृढ़ करना तो दूर उसके अपने अगा—ग्रह्या, लका आदि—को ही उससे विच्छिन्न किया जा रहा है।

१ अप्रैल १९३७ तक ग्रह्या भारत का ही एक प्रांत था। परन्तु इसके बाद से ग्रह्या को भारत से पृथक् करके एक स्वतन्त्र ब्रिटेन सरकार के अधीन देश बना दिया गया है। यही नहीं, ग्रह्या के लिए अलग शासन-विधान भी बनाया गया है जिसके अनुसार उसका शासन हो रहा है। ग्रह्या में १० लाख भारतीय निवास करते हैं। वहाँके व्यवसाय और कृषि में १० करोड़ रुपये की भारतीय पूँजी लगी हुई है। वहाँ मद्रास के बहु-संख्यक महाजन, बिहार-बंगाल के मजदूर और भारतीय सरकारी नौकर तथा वकील आदि हैं। अब इनमें और ग्रह्या के लोगों में प्रतिस्पर्धा बनी रहने लगी। इस प्रतिस्पर्धा और भारतीयों के प्रति ग्रह्या लोगों की घृणा का दुष्परिणाम यह हुआ है कि भारतीय ग्रह्या के चावल, लकड़ी और तेल का बहिष्कार कर रहे हैं।

लका में भी भारतीय मजदूरों की संख्या ६ लाख है। वहाँ भारतीय पूँजी और भारतीय शिक्षितों का अभाव है। भारतीय मजदूरों के साथ भेदभाव किया जाता है। स्थानीय मस्याओं के चुनावों में ग्राम्य मत-धिवार के सम्बन्ध में भी भारतीयों के साथ भेदभाव से व्यवहार किया जाता है। इसका भी दुष्परिणाम यह हुआ कि भारतवर्सी लका के नारियल तथा दूसरी चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं।

प्रवासी भारतीय

प्रवासी भारतीयों की समस्या के विशेषज्ञ स्वामी भवानीदयाल सन्यासी ने अपने एक लेख में प्रवासियों की स्थिति के सम्बन्ध में लिखा है —

“इस समय सप्ताह में भिन्न-भिन्न देशों और उपनिवेशों में प्रवासी भारतीयों की जन-संख्या लगभग २५ लाख है। जहाँ-जहाँ वे बसे हुए

है, वहाँ-वहाँ उनको अपने देश की पराधीनता के कारण अपमान का कड़वा घूँट पीना पड़ता है। चीन सदों तक जारी रहनेवाली शतवर्षी प्रया का इतिहास यास्तव में भारतीयों की अपकीर्ति का ही इतिहास है और उसमें विशेषतः अन्यायो, अत्याचारों और अपमानों के ही अध्याय मिलेंगे। यद्यपि अनेक सहृदय महानुभावों के उद्योग से अब इस प्रया का अन्त हो गया है, तो भी इससे उत्पन्न स्थिति की सीमा अभी अगोचर है। इतने आन्दोलनों और बलिदानों के बाद भी न तो प्रवासियों के संकट का अन्त हुआ है और न उनकी अवस्था में आशा-जनक अन्तर ही पड़ा है। मखा तो यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत उपनिवेशों में उन्हें सबसे अधिक अपमान के घबके सहने पड़ते हैं।”

दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के बप्टों की कहानी बहुत मन्वी पुरानी और चिरपिचिन्त है। महात्मा गांधी ने यह सारी कथा ‘दक्षिण अफ्रीका का न्यायग्रह’ के रूप में लिखी है, बिस्मर से जानने के लिए पाठनगण उसे पढ़ें।

अफ्रीका के उन प्रदेशों में जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य है प्रवासी भारतीयों की स्थिति समस्त के शब्दों में इस प्रकार है —

“... दक्षिण अफ्रीका में हम रंगीन जातियों को गोरों के साथ समानता का पद नहीं दे सकते। हमारी समानता मौलिक रूप से इस सिद्धांत पर आश्रित है कि धर्म और राज्य में गोरों और रंगीन जातियों के बीच कोई समानता नहीं हो सकती।”

ये शब्द दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्स के प्रधान-मंत्री और राष्ट्रमन्त्री के मुख-विधाता के हैं। जातीयता की यह भावना निरन्तर उग्र है।

दक्षिण-अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों की परिस्थिति चम्पुन अत्यन्त शोचनीय है। वहाँ आनीयता का सबसे उग्र रूप देखने को मिलता है। यहाँ भारतीय ‘कुली’ समझे जाते हैं और उनका भाव वैसा ही व्यरहा

गिया जाना है । वहाँ स्वामी भवानीदयाल सन्यामी के दण्ड में—

“आज भी भारतीयों के लिए ट्रामों और ट्रेनों में अलग डिब्बे हैं । डाकघरों, स्टेशनों और बस्तरों में रंग-भेद का गान प्रदर्शन है । होटलो और थियेटरो के दरवाजे उनके लिए बंद हैं । न उन्हें पार्लमेण्टरी सभाधिकार हैं और न म्यूनिसिपल । कुलीगिरी के सिवा उन्हें और कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती । जो भाई खेतों और रोजगार करते हैं उनकी राह में इतने कांटे बिखेर दिये गये हैं कि वे पाग-पाग पर चुभते हैं । राम और कृष्ण के बराबर एव बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, शंकर और इवान्गेल के अनुयायी यहाँ असंख्य हस्तियों से भी निम्नतर समझे जाते हैं ।”

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रवादी श्वेतांगों की परिपक्व ने हाल में जो प्रस्ताव पास किया है वह यह है —

‘यूरोपीय ईसाई संसृति की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि यूरोपीयों और अयूरोपीयों में घषासम्भव अन्तर रखा जाये; उनका विवाह-समर्थ कानून से जुर्म ठहराया जाये, अयूरोपीय स्कूलों में अन्य वर्गों के साथ गौरीग अध्यापक की नियुक्ति रोकी जाये, कोई भी श्वेतांग किसी अश्वेतांग से नौकरी में नीचे के ओहदे पर न रखा जाये और गौरी स्त्रियाँ अयूरोपीयों के यहाँ नौकरी करने से रोकी जायें ।’

नेटाल तथा ट्रान्सवाल (दक्षिण अफ्रीका) में श्वेतांगों ने स्वतः भारतीयाँ को बसाया था, पर उनके साथ बीभत्स पाप और अन्याचार किये गये । उनपर व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाये गये और ऐसे कानून बनाये गये जिससे वे भूमि के स्वामी न बन सकें । उनके लिए यूरोपिया से पृथक् मुहल्ले बनाये गये । सन् १९२४ में जनरल स्मट्स की सरकार के पतन के बाद नयी सरकार ने प्रवासी भारतीयों के साथ और भी संसृति से व्यवहार किया । यह अत्याचार यही तक समाप्त नहीं हुआ । रंग प्रतिबन्ध कानून (Colour Bar Bill) के जो वाद में कानून के रूप में बदल गया, अनुसार सरकार भारतीयों को दूसरे अयूरोपीयों की भाँति दक्षतापूर्वक किये जानेवाले काम धन्धा (skilled occupations) से

वर्चन कर सकती है ।

केनिया और युगाण्डा की अवस्था भी करणाजनक और शोचनीय है । यद्यपि केनिया की व्यवस्थापिका सभा में प्रवासी भारतीयों के पाँच प्रतिनिधि हैं, तो भी अल्पसंख्यक होने के कारण उनकी आवाज में कुछ बल नहीं है । केनिया के पठार (Highland areas) श्वेतानों के लिए सुरक्षित हैं । केनिया के निकट टेंगेनिका प्रदेश है । पहले यह जर्मनी का उपनिवेश था । परन्तु यूरोपीय महायुद्ध के बाद सन् १९२० से इसका शासन-प्रबन्ध राष्ट्रसंघ की आसनादेश-प्रणाली (Mandate System) के अन्तर्गत अंग्रेजों द्वारा किया जाता है । यहाँ भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है ।

ऑस्ट्रेलिया में एक समय की कॉमनवेल्थ ने भारतीयों का प्रवास सर्वथा रोक दिया था । इस रोक के प्रमुख कारण जातीयता के उग्र भाव और अर्थ-शीपण ही थे । और तो और, उन भारतीयों का प्रवेश भी रोक दिया जो केवल भ्रमण के ही लिए—बसने के लिए नहीं—जाना चाहते थे । प्रवासियों की स्थिति में मुघार के लिए प्रायः ७५ वर्षों से लगातार आदोलन हो रहा है । इसीके फलस्वरूप सन् १९०४ में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीयों के प्रवेश पर से यह रोक हटाली और भारतीय भ्रमणकारियों के लिए वहाँ जाने का द्वार खुल गया ।

न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ, भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी थी । सन् १९१९ में भारतीयों के लिए न्यूजीलैंड में प्रवास-सम्बन्धी कड़े-से-कड़े नियम बनाये गये । सन् १९२० में प्रवास-प्रतिबन्ध-कानून के द्वारा समस्त प्रवासियों पर कड़े नियम लगाये गये । जो न्यूजीलैंड जाना चाहता उसे पहले से आज्ञा प्राप्त करना जरूरी होता था ।

कनाडा में भी प्रवासी भारतीयों को कड़े-कड़े अत्याचार और अपमान सहने पड़े हैं । भारतीयों के सिवा चीनी और जापानी लोगों पर भी प्रवास-सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये गये । सन् १९१० में कनाडा की सरकार ने प्रवास-सम्बन्धी जो नियम बनाने के जापानियों की अपेक्षा भारतीयों के लिए

अधिक अपमानजनक और प्रतिबन्धकारी थे। सन् १९१४ में सरदार गुहदत्तासह क नेतृत्व में भारतीया (विशेषतः मिक्त्रा) का एक दल जापानी जहाज 'कोमागाता मार्' में कनाडा के त्रिप्त गया। परन्तु वह जहाज बन्दर पर लगाना तीन मास तक लगा रहा। कनाडा की सरकार ने उनके यात्रियों को कनाडा में प्रवेश करने में रोक दिया। अन्त में दस जहाज को घापस लौटना पड़ा। कनाडा की फेडरल सरकार के आग्रह पर भी ब्रिटिश बोलम्बिया के प्रवासी भारतीया को अबतक सत्ताधिकार में बचिन रखा गया है।

दक्षिणी रोडेसिया में भारतीया के साथ बहुत पुरा बर्ताव किया जाना है। परन्तु वहाँ प्रवासिया की संख्या बहुत कम है।

फिजी और मॉरिशस में सन्-१९२० में भारतीय प्रवासियों की जनसंख्या क्रमशः ७६,७०० और २५,७९६ थी। ये अंग्रेजा की ब्राउन कॉलोनी है। इनको आबाद करने में भारतीया ने अपना बलिदान किया और पुरस्कार में उन्हें अपमान और दमन मिला। फिजी की व्यवस्थापिका परिषद् में अब पाँच प्रतिनिधि लिये जाते हैं। तीन भारतीय प्रतिनिधि निर्वाचित और दो मनोनीत होते हैं। मॉरिशस की जनसंख्या में तीन हिस्से भारतीया की आबादी हैं। परन्तु इसपर भी राजनीतिक दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। मेडागास्कर फ्रांस के अधीन है। वहाँ प्रवासी भारतीया के साथ अपमानजनक व्यवहार तो नहीं होता, फिर भी उनकी वह स्थिति नहीं है जो होनी चाहिए। जो उपनिवेश डच तथा पुर्तगाली लोग के अधीन हैं, उनमें भी भारतीया की स्थिति मन्तोपप्रद नहीं है। जर्जियार नाममान के लिए सुलतान के हाथों में है, उसके शासन प्रबंध में अंग्रेजा का प्रभाव है। हाल में जर्जियार में लीग व्यापार के संबंध में जो नया कानून बना था, उससे भारतीया में बड़ा असन्तोष पैदा होगया। भारतीय राष्ट्रीय महासभा—कांग्रेस—ने भारत में इसी कारण लीग का बहिष्कार किया था।

प्रवासी भारतीया की समस्या सचमुच बड़ी विकट है। प्रारम्भ में जिन भारतीयों ने अपनी पूँजी और धन में ब्रिटिश उपनिवेशों को इस

योग्य बनाया कि वे मनुष्या ने रहने योग्य उन सब और उन्हें व्यापारिक दृष्टि में उन्नत बनाने में पूरा योग दिया, आज उन्हीं भारतीयों को स्वेतांग यह कहते हैं कि उन्हें उपनिवेशों में प्रवास का कोई अधिकार नहीं है। प्रवासियों की इस दयापूर्ण दगावा एका मात्र कारण है भारत की परतन्त्रता। परन्तु स्वाधीनता-प्राप्ति के साथ प्रवासियों के वे भवट दूर हो जायेंगे।

साम्राज्य-विरोधी मंच

मसार भर में साम्राज्यवाद का अन्त डलना उठ गया है कि उसका विरोध करने के लिए सन् १९२७ ई० में ब्रिटेन में अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्य विरोधी मंच (League Against Imperialism) की स्थापना की गयी। संस्था का मूल उद्देश्य साम्राज्यवाद की सभी विरोधी शक्तियों को एक मूत्र में बाँधना है क्योंकि साम्राज्यवादियों से भय के लिए यह आवश्यक है कि उम्मी विरोधी शक्ति का संगठन किया जाये। उक्त संस्था का कार्य उपनिवेशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध होरह युद्ध को चलाये रखना है। भारतीय राष्ट्रीय महामन्त्र (कांग्रेस) और भारतीय स्वतन्त्रता-मंच का इस सम्बन्ध में सहमति है।

प्रिन्स (जर्मनी) में जो स्थायी मंच स्थापित किया गया उसका महापणित्व हर्नर के प्रसिद्ध मजदूर नेता जार्ज लेन्सवरी ने ग्रहण किया था। ५० जवाहरलाल नेहरू प्रिन्स की साम्राज्य विरोधी परिषद में सम्मिलित हुए थे। इसके सम्बन्ध में उन्होंने मेरी कहानी में लिखा है —

“काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति साम्राज्य विरोधी लीग के संरक्षक हैं। उनमें एक तो मि० आइन्स्टीन हैं और दूसरी थोमस सनघातसेन और मेरा जगजगत्तु हैं रोमियाँ रोमियाँ भी। कई महीने बाद आइन्स्टीन ने हस्तियों दे दिया, क्योंकि फिलिस्तीन में अरबों और यहूदियों के जो झगड़े हो रहे थे उनमें लीग ने अरबों का पक्ष लिया था और यह खान उन्हें नापसन्द थी।”

१० जवाहरलाल नेहरू का इस सघ से पहले सम्पर्क था, परन्तु सन् १९३१ से कांग्रेस और सरकार के बीच दिल्ली में जो समझौता हुआ और उसमें नेहरूजी ने जो भाग लिखा उसपर साम्राज्यवाद-विरोधी सघ उनसे नाराज होगया और उसने उन्हें अपनी सदस्यता से अलग करने के लिए प्रस्ताव भी पास किया ।

पी० ई० एन० और भारत

पी० ई० एन० का बलब कवियों, पत्रकारों, नाटककारों, संपादकों और उपन्यास लेखकों की एक अन्तर्राष्ट्रीय-संस्था है । इंग्लैंड की प्रसिद्ध विदुषी लेखिका थीमती केयरिन ए० डायसन स्कॉट ने लन्दन में अक्टूबर १९२१ में इसकी स्थापना की थी । पर इस समय इस संस्था की समस्त ससारा में ४० देशों में शाखाएँ हैं । सुविख्यात अंग्रेजी उपन्यास-लेखक जॉन गैरस-वर्दी प्रारम्भ से अपनी मृत्यु तक इस संस्था के प्रधान रहे । उसके बाद यह सम्मान सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासवेत्ता श्री एच० जी० विल्स को दिया गया । इस समय वही इस संस्था के प्रधान हैं । पी० ई० एन० का उद्देश प्रत्येक स्थान के लेखकों में पारस्परिक सद्भावना और सहानुभूति पैदा करना है । पी० ई० एन० वास्तविक अर्थ में एक विश्व-संस्था है । यह उन लेखकों के विरुद्ध नहीं है जो उनके सदस्य नहीं हैं । उसमें जाति, रंग, राजनीति तथा राष्ट्रीयता के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं है । ससारा के प्रमुख लेखक चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, श्वेतांग हा या पीतांग, जवान हो या बूढ़ गरीब हा या धनी, अथवा चाहे जिस धर्म, जाति या राष्ट्र के हों, इस संस्था के सदस्य हो सकते हैं—

भारत में भी पी० ई० एन० की शाखा सन् १९३३ ई० में बम्बई में स्थापित हो चुकी है । जब पी० ई० एन० की तेरहवीं अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस मई १९३५ में वार्सिलोना नगर में हुई थी तो उसमें भारत की ओर से

P=Poets Playwrights (कवि, नाटककार), E=Editors
Essayist (सम्पादक निबंधकार), N=Novelists (उपन्यासकार)

श्रीमती साफिया वाडिया प्रतिनिधि की हैसियत से सम्मिलित हुई थी। इस मस्या के द्वारा समस्त प्रसिद्ध भारतीय लेखकों का परस्पर एक दूसरे को जानने और समझने का ही भुयोग नहीं मिलता, प्रत्युत उनका अन्तर्प्रान्तीय साहित्यिक सम्पर्क भी होता है। यह मस्या दो दिशाओं में भारत में साहित्य की प्रगति के लिए कार्य करती है —

(१) अपने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सदस्य लेखकों को अंग्रेजी रचनाओं को ससार भर में प्रसिद्ध करना।

(२) अपने सदस्यों की भारतीय भाषाओं में लिखी गयी रचनाओं को समस्त भारत में प्रसिद्ध करना और भारत की विविध भाषा सबकी मस्वृतियों के सबंध में ज्ञान का प्रसार करना। इसी उद्देश से एक असिल भारतवर्षीय भाषा-समिति भी स्थापित की गयी है जिसमें अनेक भारतीय भाषाओं के प्रमुख प्रतिनिधि हैं।

इस गाम्या की ओर स 'इण्डियन पी० ई० एन०' नामक एक मासिक पत्रिका भी निकल रही है जिसमें मस्या की गतिविधि और अन्य प्रकाशित होने रहते हैं।

भारतीय गाम्या की प्रवर्धन समिति इस प्रकार है —

(१) डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर		प्रधान
(२) श्री० रामानन्द चट्टोपाध्याय	}	उपप्रधान
(३) श्रीमती सुरोजिनी नायडू		
(४) सर स० सधाकृष्णन्		
(५) श्रीमती सोफिया वाडिया		संगठनकर्त्री

राष्ट्रीयता

राष्ट्रीयता क्या है ?

राष्ट्रीयता पर विजद रूप से विचार करने से पहले यह जान लेना उचित होगा कि राष्ट्रीयता है क्या ? 'राष्ट्रीयता' शब्द की उत्पत्ति 'राष्ट्र' शब्द से हुई है। राजनीतिक भाषा में राष्ट्र, राज्य और जाति इन तीनों में अन्तर है। 'राज्य' के कई आवश्यक तत्त्वों में से 'राष्ट्र' भी एक है, परन्तु 'राष्ट्र' को हम 'राज्य' नहीं कह सकते। 'राज्य' में 'राष्ट्र' शामिल है, क्योंकि वह उसका एक अंग है। जाति को भी हम राष्ट्र नहीं कह सकते। हाँ, हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि एक ही जाति से बना कोई राष्ट्र हो। ससार में ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जो कई जातियों के समूह से बने हैं। जैसे ब्रिटेन में दो जातियाँ—फ़ार्मीसी और अंग्रेज़—हैं। स्वीडन में तीन जातियाँ हैं—जर्मन, डेनिसन और फ़ार्मीसी। भारतवर्ष में मुख्यतया दो जातियाँ हैं—हिन्दू और मुसलमान। परन्तु हिन्दू या मुसलमान स्वयं कोई राष्ट्र नहीं हैं। आजकल ऐसा प्रचार हो रहा है कि हिन्दू हिन्दू-समाज को, मुसलमान मुसलमानों को मुस्लिम-राष्ट्र कहते हैं। परन्तु यह धर्मपूर्ण और युक्तिहीन है।

उमके लिए बड़े-स-बड़ा बलिदान करने में तत्पर रहता है।

वे सम्बन्ध, जिनके कारण एक जन-समूह राष्ट्र कहलाता है, कई प्रकार के हैं— भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, धार्मिक और जातीय। इनमें सबसे प्रमुख भौगोलिक सम्बन्ध है। एक देश में रहने के कारण व्यक्तिगत म देशभक्ति की भावना पैदा होजाती है और वे उसे अपनी मातृभूमि समझते हैं। एक ही संस्कृति एवं ऐतिहासिक परम्परा भी व्यक्ति-समूह के पारस्परिक बन्धन को मजबूत बनाती है। एक धर्म के अनुयायियों में भी एक प्रकार का बन्धुत्व स्थापित होजाता है। आर्थिक हितों की समानता भी ऐसे सम्बन्धों को पैदा करने में सहायक है। अन्त में जातीय एकरा—रक्त सम्बन्ध—भी राष्ट्र का एक बन्धन है। परन्तु उसपर अधिक जोर देने आवश्यकता नहीं है। सच तो यह है कि आज मसार की कोई भी जाति अपने रक्त की पवित्रता का दावा नहीं कर सकती। परन्तु तो भी यूरोपियन जानियाँ अपनी जातीय भावना के कारण ससार में अन्याय और अत्याचार कर रही हैं। अमरीका जैसे सभ्य और सुमस्तुन देश में हत्या पर भीषण अत्याचार किये जा रहे हैं। उनका 'लिचिंग' किया जाता है। अफ्रीका में भी बाली जातियों के साथ गोरो के बर्बरतापूर्ण अत्याचार आज भी हो रहे हैं। जर्मनी में जातीय पवित्रता की भावना ने ऐसा छत्र और भयकर रूप धारण किया कि हिटलर ने अपने देश से यहूदियों को निवार दिया। हिटलर की यह धारणा है कि केवल जर्मन ही पवित्र आर्य हैं। यहूदियों के ससर्ग में रहने से जर्मन का आर्यत्व नष्ट होजायेगा इसलिए उन्हें जर्मनी में न रहने दिया जाये। विदेशों में गोरी जानियाँ प्रवासी भारतीयों को 'कुली' कहकर उनके साथ बंसा अन्याय करती हैं यह तो सबकी भगोभीति विदित ही है।

प्रोफेसर रामजे म्यूर ने सिद्ध किया है कि जातीयता की भावना (अर्थात् यह विश्वास कि हमारी जाति ही मसार में सर्वश्रेष्ठ है और दूसरी जानियाँ अपवित्र या वर्ण-मकर हैं) ससार की जानियाँ में घृणा, रग-र्रेष, प्रतियोगिता और अशांति पैदा करनेवाली है।

राष्ट्रीयता

राष्ट्रीयता क्या है ?

राष्ट्रीयता पर विचार रूप से विचार करने ॥ पहले यह जान लेना उचित होगा कि राष्ट्रीयता है क्या ? 'राष्ट्रीयता' शब्द की उत्पत्ति 'राष्ट्र' शब्द से हुई है। राजनीतिक भाषा में राष्ट्र, राज्य और जाति इन तीनों में अन्तर है। 'राज्य' के कई आवश्यक तत्वों में से 'राष्ट्र' भी एक है, परन्तु राष्ट्र को हम 'राज्य' नहीं कह सकते। 'राज्य' में 'राष्ट्र' शामिल है क्योंकि वह उसका एक अंग है। जाति को भी हम राष्ट्र नहीं कह सकते। हाँ हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि एक ही जाति से बना कोई राष्ट्र हो। ससार में ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जो कई जातियों के समूह से बने हैं। जैसे कनाडा में दो जातियाँ—फ्रांसीसी और अंग्रेज—हैं। स्वीजरलैंड में तीन जातियाँ हैं—जर्मन, इटेलियन और फ्रांसीसी। भारतवर्ष में मुख्यतया दो जातियाँ हैं हिन्दू और मुसलमान। परन्तु हिन्दू या मुसलमान स्वयं कोई राष्ट्र नहीं हैं। आजकल ऐसा प्रचार हो रहा है कि हिन्दू हिन्दू समाज को हिन्दू-राष्ट्र और मुसलमानों को मुस्लिम-राष्ट्र कहते हैं। परन्तु वास्तव में यह धारणा अमपूर्ण और युक्तिहीन है।

राष्ट्र एक ऐसा जन समुदाय है जो विशिष्ट सम्बन्धों से बंधा हुआ है और ये सम्बन्ध इतने शक्तिशाली और मजबूत हैं कि जिनके कारण वह सामूहिक रूप से सुखी रह सक्ता है और जब उसके सम्बन्ध अस्त-व्यस्त कर दिये जाते हैं तब वह असन्तोष और अशान्ति का अनुभव करता है। ऐसे जन-समूह का प्रत्येक व्यक्ति परस्पर एकता का अनुभव करता है और वह जिस दश में रहता है उसे अपनी मातृभूमि मानता है। ये सम्बन्ध वास्तव में उसी मातृभूमि के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न करते हैं और वह इस भक्ति भावना के कारण

उमके लिए बड़े-से-बड़ा बलिदान करने में तत्पर रहता है।

वे सम्बन्ध, जिनके कारण एक जन-समूह राष्ट्र कहलाता है, कई प्रकार के हैं— भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, धार्मिक और जातीय। इनमें सबसे प्रमुख भौगोलिक सम्बन्ध है। एक देश में रहने के कारण व्यक्तिगत या देशभक्ति की भावना पैदा होती है और वे उसे अपनी मातृभूमि समझते हैं। एक ही संस्कृति एवं ऐतिहासिक परम्परा भी व्यक्ति-समूह के पारस्परिक बन्धनों को मजबूत बनाती है। एक धर्म के अनुयायियों में भी एक प्रकार का बन्धुत्व स्थापित होता है। आर्थिक हितों की समानता भी ऐसे सम्बन्धों को पैदा करने में सहायक है। अन्त में जातीय एकता—एक-सम्बन्ध—भी राष्ट्र का एक बन्धन है। परन्तु उसपर अधिक जोर देने आवश्यकता नहीं है। सब तो यह है कि आज ससार की कोई भी जाति अपने रक्त की पवित्रता का दावा नहीं कर सकती। परन्तु तो भी यूरोपियन जातियाँ अपनी जातीय भावना के कारण ससार में अन्याय और अत्याचार कर रही हैं। अमरीका जैसे सभ्य और मुसलमान देश में इन्धियों पर भीषण अत्याचार किये जा रहे हैं। उनका 'लिविंग' बिया जाता है। अफ्रीका में भी काली जातियों के साथ गोरो के बर्बरतापूर्ण अत्याचार आज भी हो रहे हैं। जर्मनी में जातीय पवित्रता की भावना ने ऐसा छत्र और भयंकर रूप धारण किया कि हिटलर ने अपने देश से यहूदियों को निकाल दिया। हिटलर की यह धारणा है कि केवल जर्मन ही पवित्र आर्य हैं। यहूदियों के सत्कार में रहने से जर्मनों का आर्यत्व नष्ट होजायेगा, इसलिए उन्हें जर्मनी में न रहने दिया जाये। विदेशों में गोरी जातियाँ प्रवासी भारतीयों का 'कुली' कहकर उनके साथ बर्मा अन्याय करती हैं, यह तो सबको भलीभाँति विदित ही है।

प्रोफेसर रामजे म्यूर ने सिद्ध किया है कि जातीयता की भावना (अर्थात् यह विश्वास कि हमारी जाति ही ससार में सर्वश्रेष्ठ है और दूसरी जातियाँ अपवित्र या वर्ण-भेदक हैं) ससार की जातियों में घृणा, रग-द्वेष, प्रतियोगिता और अमान्ति पैदा करनेवाली है।

संसार में राष्ट्रीयता ने इतनी अगानि पैदा नही की जिनकी बि जातायता की भावना ने की है ।^१

राष्ट्र के लिए भाषा की एकता भी जरूरी है । जबतक जनसमूह में भाव प्रकाशन सामान्य भाषा द्वारा न होगा तबतक उसमें विचार की एकता भी पैदा नहीं होसकती और जब विचार एकता पैदा नही होगी तो उसमें सांस्कृतिक एकता पैदा नहीं हो सकती । भारत में राष्ट्रीय नेताओं ने इस आवश्यकता को अनुभव किया है और इसी लिए सामान्य भाषा—राष्ट्रभाषा—के निर्माण के लिए प्रयत्न होरहा है ।

राष्ट्र की ऐतिहासिक परम्परा ने सबंध में प्रोफेसर रामजै म्यूर का मत है —

‘ धीरों के महान वृत्त्य और धीरता के साथ किया गया बलिदान ऐसा खेठ और पीछिक भोजन है जिससे राष्ट्र की आत्मा को शक्ति और स्फूर्ति मिलती है । इसीसे अमर और पावन परम्परा और इतिहास का निर्माण होता है, और फलतः राष्ट्र निर्माण का माग भी साफ होता है । इनके मुकाबिले धन सम्पदा, जन और भूमि हेतु प्रतीत होती है । जिस राष्ट्र के पास ऐसी स्मृतियों का अक्षय भण्डार है, उसके देश के आस-पास रहनेवाले लोग, जिनका उससे न कोई जाति सबंध है और न धर्म तथा भाव का सबंध उसमें मिल जाने में आत्मगौरव अनुभव करेंगे ।’

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता एक भावना है । जिस देश की जनता में सामान्य भावना हो वही राष्ट्रीयता का पीग पनपने लगता है ।

राष्ट्रीयता के उदय के कारण

आज हम राष्ट्रीयता का उदय उन सभी देशों में देख रहे हैं जो विदेशी शासन के नियंत्रण में हैं और जो देश स्वाधीन हैं उनमें तो राष्ट्रीयता का विकास ऐसी भयंकर दिशा में हुआ है कि आज विद्वानों

१ रामजै म्यूर ‘नेशनलिज्म एण्ड इम्प्रेनेशनलिज्म’ (१९१९)

या यह मन है कि राष्ट्रीयता ही मसार में अज्ञानि का मूल है। स्वाधीन और पराधीन दोनों प्रकार के देशों में राष्ट्रीयता के विराम के भिन्न-भिन्न कारण हैं।

स्वाधीन देशों में विज्ञान, आविष्कार और औद्योगिकरण ने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया। पाश्चात्य देशों में औद्योगिक शान्ति ने जनता के सामाजिक जीवन में आश्चर्यजनक शान्ति पंदा बन्दी। पहले लोग छोटे-छोटे साधारण बम्बों और ग्रामों में रहते थे। अधिकांश लोग मेहनत-मजदूरी करके अपना पेट पालने थे। कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय था। यातायात तथा पत्र-सम्बन्ध के माध्यम वैज्ञानिक टग के न होने से परस्पर मेल-मिलाप भी कम होता था। साक्षरता एवं शिक्षा का बड़ा अभाव था। इन कारणों से उनमें राष्ट्र-भावना का विकास नहीं हो सता। यदि आप ३० वर्ष पूर्व की रूस, चीन, ब्रह्मा तथा भारत की स्थिति का अध्ययन कर तो आपको यह स्पष्ट होजायेगा कि भारत में भी पहले राष्ट्र-भावना नहीं थी। परन्तु जब उद्योग-धन्धा का विस्तार हुआ, नवीन आविष्कारों के कारण नयी-नयी मशीन, यंत्र तथा औजार तैयार किये गये, तब उद्योगवाद का जन्म हुआ। उद्योगवाद ने पूँजीवाद को विरसित किया। पूँजीवाद ने अपनी रक्षा और वृद्धि के लिए देश में राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया और उनका मनमाना उपयोग किया।

आज सम्य तथा स्वाधीन देशों में शिक्षा तथा समाचारपत्रों द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार किया जा रहा है। स्कूली और कॉलेजों में प्रत्येक राष्ट्र ऐसी शिक्षा की योजना काम में ला रहा है जिससे अपने राष्ट्र की भव्यश्रेष्ठता की छात्र छात्रा के हृदय पर पड़े। पूँजीपतियों द्वारा संचालित समाचारपत्र भी राष्ट्रीयता का प्रचार कर रहे हैं।

जो देश पराधीन हैं, उनमें राष्ट्रीयता के उदय के कारण इनमें भिन्न हैं। पराधीन राष्ट्रों में साम्राज्यवादी राष्ट्रों के द्वारा जो आर्थिक

शोषण किया जाता है तथा उनके आर्थिक जीवन को नष्ट कर दिया जाता है, उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अर्थात् अपने आर्थिक सर्वनाश से रक्षा पाने के लिए, राष्ट्रीय भावना पैदा होती है। समस्त दलित और पीड़ित जनता में वैदेशिक नियन्त्रण से मुक्ति पाने के लिए एवता का भाव पैदा होता है और वह इस आधार पर आन्दोलन उठाती है कि विदेशी वन्दन से मुक्त होजाने पर समस्त जनता का बन्धन होगा। वरन् इस प्रकार राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होजानी है।

राष्ट्रीयता की भावनाएँ

आज के युग में हम राष्ट्रीयता की तीन भावनाएँ मुख्य रूप में पाते हैं। जनतन्त्रीय देशों में पूँजीवादी राष्ट्रीयता अपनी घरम-सीमा को पहुँच चुकी है। अधिनायकतन्त्रवाले राज्यों में फैंसिस्ट राष्ट्रीयता हिंसा और युद्ध का प्रचार ही नहीं कर रही है बल्कि यूरोप की सम्मता और स्वाधीनता के नाश के लिए युद्ध क्षेत्र में सलग्न है। एक तीसरी राष्ट्रीयता की भावना का उदय स्वाधीनता के साधक भारत में ही रहा है, जिसके प्रयत्न मसाल के अद्वितीय शान्तिवादी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसे हम मानववादी राष्ट्रीयता या नया नाम देंगे।

(१) पूँजीवादी राष्ट्रीयता

फ्रांस की राज्यक्रान्ति के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, बेलजियम तथा अन्य देशों में प्रजातन्त्र का उदय हुआ। स्वाधीनता, समता तथा बन्धुता के भावों का जनता में बड़ा प्रचार हुआ। सबसे पहली बार जनता ने एकतन्त्र-शासन से मुक्ति पायी और प्रजा की स्वाधीनता की स्थापना की। इस क्रान्ति के बाद प्रजातन्त्र के नाम पर व्यक्ति स्वातन्त्र्य का घोर प्रचार किया गया। इसका परिणाम यह निकला कि प्रसिद्ध अफ्रेञ्च राजनीतिज्ञ मिल, स्पेसर सिज्विक, ग्रीन और बोलाववट ने मुल्लमगुल्ला व्यक्तिवाद का समर्थन किया।

व्यक्तिवाद का मतलब यह है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की

उत्पत्ति उसकी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के सत्र व्यक्तिता के लिए एक-सा कानून बनाना ठीक न होगा। सरकार का व्यक्तिता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वतन्त्र रीति से अपनी उत्पत्ति और विधान का अवसर देना चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिवाद सरकार के कार्यों की बहुत ही मर्यादित मानता है। ग्रीन ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि सरकार दमन या सुशासन के द्वारा समाज के आम निर्णय के अधिकार में कोई दावा न करे। सब लोग का अपने-अपने रास्ते से चलन देना उचित है।

व्यक्तिवाद का विकास डनीसवा मदी में यहाँ तक हुआ कि व्यक्तिता को कानून की दृष्टि में समान समझा जान लगा। प्रत्येक (बालिग) व्यक्ति को समान मताधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र में समता का मिथ्यात्व स्थिर किया गया।

राजनीतिक समता के कारण नागरिका का अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार मिला। प्रतिनिधि-संस्थाओं का विकास हुआ। प्रतिनिधि-संस्थाओं की यह विशेषता है कि राज्य का शासन जनता-द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों के हाथ में होता है। अतः इस प्रणाली के अन्तर्गत निर्वाचकों का अधिक महत्त्व है। जिस दल का पार्लमण्ट में बहुमत होता है उसी दल का नेता मन्त्रिमण्डल बनता है और इस तरह वह सारे देश का शासन करता है। परन्तु पूँजीवाद के प्रभाव के कारण निर्वाचक स्वतन्त्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करत। चुनाव पूँजी पतियों के हाथ में होता है। वे जिसे ठीक समझते हैं, उसीको चुनाव में सटा करत हैं और उस कायदा बनाने के लिए निर्वाचकों का तरह-तरह के प्रयत्न दत है। इस प्रकार निर्वाचकों और प्रतिनिधियों का पतन किया जाता है। देश के बड़े-बड़े प्रभावशाली पत्रा के स्वामी भी पूँजीपति ही हान हैं, जिससे समाचारपत्र भी ऐसे ही उम्मीदवारों का समर्थन करत है। अतः घोषित समाज के लिए राजनीतिक समता अथ सिद्ध होती है। यह स्वतन्त्रता न अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता।

इस तरह, ऐसे चुनावों के फलस्वरूप, पार्लमेण्ट में पूँजीपतियों का बोलबाला होता है और वे अपनी सरकार बनाने हैं । फिर शासन-सत्ता हाथ में आजाते से पूँजीपति स्वच्छन्दता से अपने स्वाधियों की मिद्धि करते हैं । अपने तैयार माल की बिक्री के लिए वे दूसरे देशों में बाजारों की खोज करते हैं, पिछड़े देशों में अपना आधिपत्य जमाने हैं, नये उपनिवेश बसाने हैं, और इन कामों में पूँजीवादी राष्ट्रीय सरकार उनकी पूरी मदद करती हैं । सरकार की पूरी ध्वनि—पुलिस, फौज और बैंक आदि—इन पूँजीपतियों के पीछे रहती हैं । पूँजीपति अपने वर्गीय स्वार्थों की 'राष्ट्रीयता' का रंग देकर अपने देशव्युत्थों को धोखा देने हैं । उनके सामने अपने स्वाधियों को 'राष्ट्रीय हित' के नाम से पुराते हैं । ये पूँजीवादी अपने देश में यह आन्दोलन करते हैं कि हमारे देश की जन-मन्या में वृद्धि हो गयी है, देश में स्थान की कमी है । इसलिए हमें और देश चाहिए । हमारे देश में बेकारी है, आर्थिक मन्दता है, इसलिए हमें अपने उद्योग-धंधों की वृद्धि करनी चाहिए । हमें दूसरे देशों से खतरा है; इसलिए हमें अपने देश में साम्राज्य तथा युद्ध-सामग्री की वृद्धि करनी चाहिए ।

(२) फासिस्ट राष्ट्रीयता

फासिज्म मूलरूप में इटली का राष्ट्रवादी आन्दोलन है, जिसका प्रवर्तन १९१९ में इटली के अधिनायक (डिक्टेटर) बेनिटो मुसोलिनी ने किया था । इस आन्दोलन का कार्यक्रम राष्ट्रवादी, प्रभुतावादी, साम्यवाद-विरोधी और पार्लमेण्ट-विरोधी था । फासिज्म दावा करता है कि न तो वह पूँजीवादी है न समाजवादी । उसकी भावना और मगठन सैनिक ढंग का है ।

इस समय यूरोप में फासिस्ट राष्ट्रीयता का घोर आतक है । फासिस्ट राष्ट्रीयता ने यूरोप में उग्र राष्ट्रीयता का विकास इस सीमा तक किया है कि यूरोप के वर्तमान युद्ध में आज सारी यूरोपीय सभ्यता, संस्कृति और स्वाधीनता नष्ट हुई जा रही है ।

वेनितो मुसोलिनी ने उच्च राष्ट्रीयता का प्रचार बारम्ब से ही किया है। मुसोलिनी ने अपने एक लेख में लिखा है—

“ फासिज्म जितना अधिक सामयिक राजनीतिक दृष्टिकोण को अलग रखकर, मानवता के भविष्य और उसके विकास पर विचार एयुचितन करता है, उतना अधिक न तो बहु स्यायी शान्ति की उपयोगिता में विश्वास करता है और न ऐसा सम्भव ही है। इस प्रकार यह शांतिवाद के उस सिद्धान्त को अस्वीकार करता है जिसकी उत्पत्ति सघर्ष के परिस्थान और आत्मत्याग के सामने कायरता से हुई है।

‘सिर्फ युद्ध ही मानवीय शक्तियों को सबसे अधिक उत्तेजना प्रदान करता है और मानवों के हृदय पर खेळता की छाप लगाता है। अतः जो सिद्धान्त शान्ति की इस हानिप्रद कल्पना पर स्थिर है, वह फासिज्म का विरोधी है।

‘यह (फासिज्म) मानव-समाज की भाविकाल के कबीले के जीवन से ऊँचा उठाकर मानव शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति की ओर ले जाता है—जिसे साम्राज्य कहते हैं।

‘फासिज्म के लिए साम्राज्य का विकास—अर्थात् राष्ट्र का विस्तार—शक्ति का आवश्यक प्रदर्शन है और इसका विपरीत अथ पतन का लक्षण है। जो जातिवाँ उठ रही है, वे सदैव साम्राज्यवादी ही होती हैं। इसका परिस्थान ही पतन और मृत्यु का लक्षण है।”

हिटलर की ओर से भी एक दगाव्दी से जमनी म हिसा, युद्ध और दूसरे राज्यों के प्रति घृणा तथा विद्वेष का प्रचार हो रहा है। उन्होंने भी अपने आत्मचरित मेरा सघर्ष में लिखा है—

“यथाथ में शांतिवादी-मानववादी भावना पूर्णतः अच्छी है परंतु इस शत पर कि सबसे पहले सर्वोच्च मानव वर्ण ने ससार को इस सीमा तक जीत लिया हो कि वह ससार का एकमात्र स्वामी बन जाये।

१ सी-योर मुसोलिनी ‘द पोलिटिकल एण्ड सोशल थ्योरीन आव फासिज्म इन इन्साइक्लोपीडिया इटैलियाना’ (१९३२)

इसलिए हमें पहले युद्ध करना चाहिए—शान्तिवाद शायद भविष्य में देखा जायगा ।’

हिटलर ने जर्मन जनता में सामरिक भावना पैदा करने के लिए ही लिखा है —

“जर्मनी की सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए तुम्हें यह न पूछना चाहिए कि ‘हम किस तरह शस्त्रास्त्र बनावें ?’ बल्कि वह भावना पैदा करनी चाहिए जिससे मनुष्यों में शस्त्र-धारण की क्षमता प्राप्त हो जाये । यदि ऐसी भावना लोगों में पैदा होजाये, तो उनकी इच्छा-शक्ति सहजों ढंग से प्रकट होसकेगी, जो उनमें से किसी को भी शस्त्रीकरण की ओर ले जायेगी । यो एक कायर व्यक्ति को १० पिस्तील दे दिये जायें, तो भी जब उसपर आक्रमण होगा तो वह एक गोली भी न छोड़ सकेगा ।”

‘ऐसे राष्ट्रीय समाजवादी आन्दोलन की धिक्कार है, जो केवल विरोध पर निर्भर रहता है और युद्ध की तैयारी नहीं करता ।”

उपर्युक्त अवतरणों से यह स्पष्ट है कि ‘राष्ट्रीय समाजवाद’ का आधार सैनिकवाद और हिंसा है । इस फासिस्ट राष्ट्रीयता का जर्मनी में समाचारपत्रों और स्कूलों द्वारा भी प्रचार किया जाता है । जर्मनी में हेर हिटलर ने उग्र राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए हर उपाय से काम लिया है । साहित्य, कला, काव्य, संगीत, सिनेमा, रेडियो आदि सबका उपयोग युद्ध और हिंसा के भाव को जगाने के लिए किया गया है ।

जर्मनी में प्रचलित गीतों में भी फास, रूस और यहूदिया के प्रति जर्मनों के हृदय में पाशविक, घृणापूर्ण और प्रतिहिंसा के भावों को वाक्य-मयी भाषा में जगाने की प्रबल चेष्टा है ।

यहूदियों पर जो भयंकर और हतकम्पनकारी अत्याचार जर्मनों द्वारा किये गये हैं उनसे द्रवित होकर अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने लिखा है —

“जर्मनों ने यहूदियों पर जो अत्याचार किये हैं, उनकी कहानी इतिहास में दर्ज है । प्राचीन काल के अत्याचारी इतने पागल नहीं हो

गये थे जितने कि हिटलर पागल होगये प्रतीत होते हैं। वह ऐसा धार्मिक जोश के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वह उग्र राष्ट्रीयता के नवीन धर्म का विकास कर रहे हैं जिसके नाम पर किया गया कोई भी अमानवीय कार्य मानवीय बन सकता है। और जिसके लिए इहलोक और परलोक में पुरस्कार मिलेगा।”

यह है इस उग्र राष्ट्रीयता का स्वरूप। इसका अधिक उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं कि फासिज्म सत्कार में स्थायी शान्ति का विरोधी है। वह अन्तर्राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करता। उनका आधार उग्र राष्ट्रवाद, सैनिकवाद और साम्राज्यवाद है। फासिज्म स्वदेश के अभ्युदय के लिए अन्य देशों पर आधिपत्य को मानवना की धर्म का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मानता है। यह युद्ध को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि साम्राज्य-विस्तार युद्ध के बिना सम्भव नहीं है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि वर्तमान युद्ध यूरोप में घटती हुई पूँजीवादी और फासिस्ट राष्ट्रीयता का ही भयकर परिणाम है।

(१) मानववादी राष्ट्रीयता

महात्मा गांधी की राष्ट्रीयता अहिंसा और विश्व-प्रेम पर स्थिर है। यह सबसे पहले मानव है और अन्त में भी मानव है। उनके हृदय में मानव-मान के लिए प्रेम है, आदर है और मनुचित जातीयता को वह घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अहिंसा के अनन्य पुजारी होने के कारण वह किसी भी राष्ट्र की जनता को किसी प्रकार की हानि पहुँचाने की भावना को अपने सिद्धान्त के विरुद्ध मानते हैं। वह वास्तव में एक आदर्श मानव-वादी हैं।

गांधीजी स्वदेश के नागरिका में एकता चाहते हैं—समन्वय चाहते हैं—सघर्ष नहीं। भारत में उनका लक्ष्य यह है कि उससे आन्तरिक मतभेदों और विवादों को मिटाकर जनता को स्वराज्य के लिए संगठित किया जाये, स्त्रियों को उठाकर पुरुषों के सम्पन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक धरातल पर प्रिठाया जाये राष्ट्र को विभक्त करनेवाले धार्मिक

घृणा-द्वेषों का अन्त कर दिया जाये, और हिन्दू धर्म की अस्पृश्यता के सामाजिक बलंक से मुक्त कर दिया जाये ।^१ गांधीजी की यह धारणा है कि 'यदि मेरा पुनर्जन्म हो, तो मैं अछूत होकर अगमना चाहूंगा, ताकि मैं उनके दुःख-बुद और अपमान में भाग ले सकूँ और अपने-आपको तथा उनको उस दमनीय बशा से छुड़ाने का प्रयत्न कर सकूँ ।'^२

उनकी दृष्टि में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि में कोई भेद नहीं है । वह यद्यपि हिन्दू-धर्म का पालन करते हैं और हिन्दू होने का उन्हें गर्व है, तथापि ससार के अन्य धर्मों के प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा है । इसका कारण यह है कि गांधीजी धर्मों की एकरता में विश्वास करते हैं । उनका विचार है कि ससार के सब धर्मों में तात्त्विक एकरता है—उनके मूल सिद्धान्त एव-से हैं । गांधीजी नागरिक समानता को भारत में स्थापित करना चाहते हैं । उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है—

"जब घुड़ के बादल बिखर जायेंगे और भारत अपनी स्वाधीनता का अधिकार पा लेगा, तब मुझे शक नहीं कि कांग्रेसी लोग किसी मुसलमान, सिक्ख, ईसाई या पारसी को अपने प्रधान-मंत्री के तौर पर वैसे ही सहर्ष स्वीकार करेंगे जैसे कि एक हिन्दू को । इतना ही नहीं, वह कांग्रेसी न भी हो, तो भी वैसे ही और किसी प्रकार के धर्म या वर्ण के भेद बिना उसे अधिकार देंगे ।"^३

महात्मा गांधी प्रजातन्त्र के प्रबल समर्थक हैं । वह राष्ट्र के विविध वर्गों, हिंदी और समुदायों में सहयोग और एकरता चाहते हैं । वह किसी एक वर्ग का शासन नहीं चाहते । बहुमत के निर्णय में उनका विश्वास है । फासिज्म और नाजीवाद की उन्होंने सदैव निंदा की है और उन्हें सम्म्यता एव संस्कृति का शत्रु कहा है ।

१. गांधी-अभिनन्दन-ग्रन्थ : सम्पादक—श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन (१९३९) पृ० १०

२-३. 'हरिजन-सेवक' (पूना) : 'मेरा अन्याय' (गांधीजी) २८ सितम्बर १९४०

वह मानव-सेवा के सबसे महान् समर्थक हैं। सार्वजनिक जीवन में सुद्धि तथा सदाचार पर वह जोर देते हैं। उनमें मातृभूमि के लिए बड़े-से-बड़ा त्याग और बलिदान करने की शक्ति है। परन्तु उनकी देशभक्ति उग्र एवं दूसरे राष्ट्र के लिए विधातिनी नहीं है। वह अपनी जन्म-भूमि के प्रति अनुराग रखते हुए भी मानवता-प्रेमी हैं, विश्व-शान्ति के समर्थक हैं।^१

गांधीजी का विश्वास है कि भारत की प्राचीन सभ्यता से सत्सार के विवास में सहायता मिल सकती है। नीचे गिरा हुआ भारत मानव-जाति का आशा का सन्दरा नहीं दे सकता। जगत् स्वयं भारत ही पीड़ित सत्सार की सहायता कर सकता है। गांधीजी कहते हैं कि यदि अमेश लोग न्याय, शान्ति और व्यवस्था की अपनी भावना में सच्चे हों, तो आक्रान्ता शक्तियों को दबा देना और वर्तमान परिस्थिति को ही कायम रखना उचित नहीं है। हमारे माने हुए आदर्शों के विपरीत जो परिस्थिति हो उसे सुधारने से इन्कार करना भी हिंसा है। न्याय और स्वतन्त्रता के हमारे प्रेम में इस निष्क्रिय हिंसा से बचने का बल होना चाहिए। यदि साम्राज्य का निर्माण मनुष्य की तृष्णा, क्रूरता और घृणा ने किया है, तो सत्सार का न्याय तथा स्वतन्त्रता की शक्तियाँ का साथ देने के लिए कहने से पहले हमें उनको बदलना होगा। हिंसा या तो सक्रिय होगी या निष्क्रिय। आक्रान्ता शक्तियाँ इस समय सक्रिय हिंसा कर रही हैं, वे साम्राज्यवादी शक्तियाँ भी हिंसा की उतनी ही अपराधिनी और स्वातन्त्र्य-

१ My patriotism is both exclusive and inclusive. It is exclusive in the sense that in all humility I confine my attention to the land of my birth, but it is inclusive in the sense that my service is not of a competitive or antagonistic nature.

—‘महात्मा गांधीज स्पेचिज एण्ड राइटिंग्स (चतुर्थ संस्करण) : जी० ए० नटेशन क०, मद्रास

नया प्रजातन्त्र की विरोधिनी है, जो भूत-काल की हिंसा द्वारा प्राप्त अ-यायपूर्ण कामों का उपयोग करने में आज भी सलग्न है। जबतक हम इस मामले में ईमानदारी से काम न लेंगे, तबतक हम सबसे अच्छी विदेश-व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकेंगे, और संसार में युद्ध तथा युद्धों का भय जारी रहकर, अनिश्चय की व्यवस्था स्थायी होजायेगी। भारत को स्वतंत्र कर देना ब्रिटिश ईमानदारी की अग्नि परीक्षा है।^१

मार्च १९३९ के विश्व-संकटकाल में 'न्यूयार्क टाइम्स' के एक सदाब-दाता ने गांधीजी से संसार के लिए सन्देश माँगा, तब उन्होंने कहा कि सब प्रजातन्त्रों को एकदम निःशस्त्र होजाना चाहिए। उन्होंने बतलाया कि इसी एकमात्र हल से युद्धों का अन्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा— 'मुझे यहाँ बैठे-बैठे ही निश्चय है कि इससे हिटलर की आँखें खुल जायेंगी और वह आप निःशस्त्र होजायेंगे।'

सदाब-दाता ने पूछा—क्या यह चमत्कार नहीं है ?

गांधीजी ने जवाब दिया—शायद। परन्तु इससे संसार की उस रक्तपात से रक्षा होजायेगी जो अब सामने खींच रहा है। कठोरतम धातु काफी आँच से नरम होजाती है, इसी प्रकार कठोरतम हृदय भी अहिंसा की पर्याप्त आँच लगने से पिघल जाना चाहिए और अहिंसा कितनी आँच पैदा कर सकती है उसकी कोई सीमा नहीं। अपने आधी शताब्दी के अनुभव में मेरे सामने एक भी ऐसी परिस्थिति नहीं आयी जब मुझे यह कहना पड़ा हो कि मैं असहाय हूँ और मेरी अहिंसा निरुपाय होगी।^२

गांधीजी का अहिंसा की शक्ति में कितना गहरा विश्वास है यह उनके उपयुक्त कथन से साफ प्रकट होजाता है। यह सन्देश उन्होंने वर्तमान यूरोपीय युद्ध के प्रारम्भ होने से पहले दिया था जबकि संसार

१ सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 'गांधी अभिनन्दन ग्रन्थ' (१९४१)

रे गण्टो का सम्प्रीकरण प्रेहद वर बुका था और युद्ध के बादत आवाश में भँटरा रहे थे ।

वर्तमान यूरोपीय युद्ध नुरू होने पर भारत में उसको स्वाधीन राष्ट्र घोषित करने की राष्ट्रीय मांग कांग्रेस की ओर से ब्रिटिश सरकार के सामने रखी गयी । आज दो वर्ष से अधिक समय बीत गया, परन्तु ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय मांग को स्वीकार नहीं किया । एवं और तो ब्रिटिश सरकार की यह धृति है, दूसरी ओर महात्मा गांधी भारत की स्वाधीनता के लिए युद्ध-काल में कोई ऐसा उपाय करना अहिंसा के सिद्धान्त के विरुद्ध समझत है जिससे अंग्रेज जाति सबट में पड जाये । गांधीजी परावर सम्मग्रह के प्रदन को इसी दृष्टि से टाकते रहे थे । उनका कहना है कि अंग्रेजों की सबट-पूर्ण स्थिति से लाभ उठाकर हमें स्वाधीनता प्राप्त करना सोभा नहीं देता । ऐसा करना भारतीय आर्थ-मर्यादा के विरुद्ध है ।

गांधीजी को वर्तमान युद्ध में इतनी दारुण ध्यथा पहुँची कि उन्होंने घोर युद्ध काल में, जयति प्रिटेन के लिए जीवन मरण का मन्त्र था— अंग्रेजों से यह अपील की थी —

“राष्ट्रों के परस्पर के सम्बन्ध और दूसरे मामलों का निर्णय करने के लिए युद्ध का मार्ग छोड़कर अहिंसा का मार्ग स्वीकार करें । मैं आपसे यह कहता हूँ कि इस युद्ध के समाप्त होने पर बिजय चाहें जिस पक्ष की हो, प्रजातन्त्र का वहीं मामोनिजान भी नहीं मिलेगा । यह युद्ध मनुष्य जाति पर एक अभिशाप और चेतावनी के रूप में उतरा है । यह युद्ध शापवर्ष है, क्योंकि आज तक कभी मानव मानवता को इस तद्वर नहीं भूला था, जिनका कि यह इस युद्ध के असर के नीचे भूल रहा है ।”

यद्यपि महात्मा गांधी भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलन के मन्त्राव और कांग्रेस के प्रधान नेता हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मन्त्र

विराधी हूँ तो भी वह एक आदर्श मानववादी हूँ। आज भी गांधीजी ग्रिटन के प्रति मंत्री का निर्वाह कर रहे हैं— 'मैं दावा करता हूँ कि मैं ग्रिटन का आजीवन और निस्वार्थ मित्र रहा हूँ।' एक वक्त ऐसा था कि मैं आपके साम्राज्य पर भी आश्रित था। मैं समझता था कि आपका राज्य भारत को फायदा पहुँचा रहा है। मगर जब मैंने देखा कि वस्तुस्थिति तो दूसरी ही है, इस रास्ते से भारत की भलाई नहीं हो सकती, तब मैंने अहिंसक तरीके से साम्राज्यवाद का सामना करना शुरू किया और आज भी कर रहा हूँ। मेरे देश के भाग्य में आखिर कुछ भी लिखा हो, आप लोगों के प्रति मेरा प्रेम वैसे ही कायम है और रहेगा। मेरी अहिंसा सारे जगत के प्रति प्रेम मागती है और आप उस जगत के कोई छोटा हिस्से नहीं हैं। आप लोगों के प्रति मेरे उस प्रेम ने ही मुझसे यह निवेदन लिखाया है।”

यह है गांधीजी की फलसफाई राष्ट्रीयता। वह भारत के लिए स्वाधीनता चाहत है परन्तु वह यह स्वाधीनता किसी दुबले राष्ट्र का शोषण करने या साम्राज्य की स्थापना करने के लिए नहीं चाहत।

यूरोप में युद्ध आरम्भ होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का कार्य-समिति ने १४ सितम्बर १९३९ का भारतीय माँग के सम्बन्ध में अपना जा एतिहासिक वक्तव्य प्रकाशित किया। यह स्वाकार किया गया है कि सत्ता के वारण और गिरावट के लिए।

स्थापित स्वार्थों की वस्तुस्थिति को कायम रखना है, तो भारत को ऐसे युद्ध से कोई सरोकार नहीं है। अगर सवाल प्रजातन्त्र और प्रजातन्त्र के आधार पर स्थान समाज की व्यवस्था का है, तो भारत की उसमें बड़ी दिलचस्पी है। "यदि ब्रिटेन प्रजातन्त्र की रक्षा और विस्तार के लिए युद्ध में लड़ रहा है, तो उसे अपने अधिकृत देशों में से साम्राज्यवाद का अन्त कर देना चाहिए और भारत में पूर्ण प्रजातन्त्र की स्थापना करनी चाहिए। अतएव भारत की जनता को बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपनी निर्वाचित विधान-निर्मात्री परिषद् से अपना शासन-विधान बनाने का अधिकार मिलना चाहिए और स्वयं ही अपनी नीति का संचालन करना चाहिए।

"स्वतन्त्र प्रजातन्त्रवादी भारत दूसरे स्वतन्त्र राष्ट्रों के साथ भाग-मण के बिल्कुल पारस्परिक रक्षा तथा आर्थिक सहकारिता के लिए खुशी से सहयोग करेगा। हम एक सच्ची विश्व-व्यवस्था की स्थापना के लिए काम करेंगे जिसका आधार स्वाधीनता और प्रजातन्त्र होगा और संसार के शासक-विशाल और साधनों की मान्यता के विकास और प्रगति में उपयोग किया जायेगा।"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय संघटन के विरुद्ध नहीं है। यह उसमें पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रस्तुत है। परन्तु ऐसा करना उसी समय मफज हो सक्ता है जब पहले यह साम्राज्यवाद के वग्नन में मुक्ति पा ले।

भारतीय राष्ट्रीयता और पण्डित जवाहरलाल नेहरू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीयता की अन्तर्राष्ट्रीय रंग में रंगकर वास्तव में राष्ट्र की एक महान् सेवा की है। आज भारत में नेहरूजी में ब्रह्मकार कोई अन्तर्राष्ट्रीयता का समर्थक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीयता की उम्र और मकुचिन हो जाने में बचाने में नेहरूजी ने जो योग दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पूर्णतः समाजवादी है, परन्तु उनपर महात्मा गांधी के मिथान्तों और विशेषण से उनके

स्थापित स्वार्थों की वस्तुस्थिति को त्रायम रखना है, तो भारत को ऐसे युद्ध से कोई सरोकार नहीं है। अगर सवाल प्रजातन्त्र और प्रजातन्त्र के आधार पर स्थित समाज की व्यवस्था का है, तो भारत की उसमें बड़ी दिलचस्पी है। 'यदि ब्रिटेन प्रजातन्त्र की रक्षा और विस्तार के लिए युद्ध में लड़ रहा है तो उसे अपने अधिकृत देशों में से साम्राज्यवाद का अन्त कर देना चाहिए और भारत में पूर्ण प्रजातन्त्र की स्थापना करनी चाहिए। अतएव भारत की जनता को बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपनी निर्वाचित विधाननिर्मात्री परिषद् से अपना शासन विधान बनाने का अधिकार मिलना चाहिए और स्वयं ही अपनी नीति का संचालन करना चाहिए।

"स्वतन्त्र प्रजातन्त्रवादी भारत दूसरे स्वतन्त्र राष्ट्रों के साथ आत्म-मण के विरुद्ध पारस्परिक रक्षा तथा आर्थिक सहकारिता के लिए खुशी से सहयोग करेगा। हम एक सच्ची दिव्य व्यवस्था की स्थापना के लिए काम करेंगे जिसका आधार स्वाधीनता और प्रजातन्त्र होगा और सत्ता के ज्ञान वितरण और साधना को मानवता के विकास और प्रगति में उपयोग किया जायेगा।"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत अन्तराष्ट्रीय मंच पर विरुद्ध नहीं है। यह उसमें पूरा सहयोग देने के लिए प्रस्तुत है। परन्तु ऐसा करना उसी समय संभव है। सच है जब पढ़ें यह साम्राज्यवाद के बन्धन न मुक्ति पा ले।

भारतीय राष्ट्रीयता और पण्डित जवाहरलाल नेहरू

पण्डित जवाहरलाल नेहरू न भारतीय राष्ट्रीयता का अन्तराष्ट्रीय रंग में रंगकर साम्प्रदायिक राष्ट्र की एक महान सेवा की है। आज भारत में नेहरूजी ने बख्तर कोई अन्तराष्ट्रीयता का समर्थक नहीं है। भारतीय राष्ट्रीयता का उग्र और सन्तुष्ट हो जाने से बचाने में नेहरूजी ने जा मान दिया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा पूर्णतः समानवादी है, परन्तु ऊपर महात्मा गांधी के सिद्धान्तों और विचारों से उनका

अहिंसा-सिद्धान्त का गहरा प्रभाव पड़ा है। महात्माजी की अहिंसा में उनका पूरा विश्वास है। वह साम्राज्यवाद के बटुर विरोधी है और फासिज्म की साम्राज्यवाद का ही भयंकर रूप मानते हैं। उनकी यह धारणा है कि भारत का बन्धन समाजवादी व्यवस्था से होगा। वह शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीयता के सपने बड़े समर्थक में हैं। उन्होंने स्वयम् अपने सम्बन्ध में लिखा है—

“फासिज्म और साम्यवाद इन दोनों में से मेरी सहानुभूति बिल्कुल साम्यवाद की ओर है। इस पुस्तक के इन्हीं पृष्ठों से यह मालूम हो जायेगा कि मैं साम्यवादी होने से बहुत दूर हूँ। मेरे संस्कार शायद एक हद तक अब भी उन्नीसवीं सदी के हैं और मानववाद की उदार परंपरा का मुझपर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि मैं उससे बिल्कुल बचकर निकल नहीं सकता।”^१

अन्तर्राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है—

“मैं नहीं जानता कि हिन्दुस्तान जब राजनीतिक दृष्टि से आजाद हो जायेगा, तो किस तरह का होगा और वह क्या करेगा? लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उसके लोग जो आज राष्ट्रीय स्वाधीनता के समर्थक हैं, व्यापक से व्यापक अन्तर्राष्ट्रीयता के भी समर्थक हैं। एक समाजवादी के लिए राष्ट्रीयता का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन बहुतों के लिए, जो समाजवादी नहीं हैं, लेकिन आगे बढ़े हुए हैं, वे सच्ची अन्तर्राष्ट्रीयता में पुजारी हैं। स्वाधीनता हम इसलिए नहीं चाहते कि हमें सबसे अलग होकर रहने की इच्छा है। इसके विपरीत हम तो इस घात के लिए बिल्कुल राजी हैं कि दूसरे देशों के साथ साथ अपनी स्वाधीनता का भी कुछ अंश छोड़ दें कि जिससे अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम हो सके। कोई भी साम्राज्य-प्रणाली, चाहे उसका नाम कितना ही बड़ा रख दिया जाये, ऐसी व्यवस्था की शत्रु है और ऐसी प्रणाली के द्वारा विश्वव्यापी सहयोग या शान्ति कभी स्थापित नहीं हो सकती।”^२

१ ‘मेरी कहानी’ (१९४१) पण्डित जवाहरलाल नेहरू, पृ० ९३६

२ उपर्युक्त, पृष्ठ ६६२

प० जवाहरलाल नेहरू ममार में सच्ची और स्थायी शान्ति चाहते हैं। उनकी यह ध्रुवधारणा है कि साम्राज्यवादी राष्ट्रों द्वारा शान्ति-व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। शान्ति-व्यवस्था के लिए सबसे पहले साम्राज्यवाद का जन्त कर देना जरूरी है। इसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय सघटन के लिए प्रत्येक स्वाधीन राज्य को अपनी प्रभुता का कुछ अंग छोड़ना पड़ेगा। जबतक मसार में राष्ट्रीय राज्य कायम रहेंगे तबतक कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय सघटन सफल नहीं हो सकता। नेहरूजी इसे भली भाँति अनुभव करते हैं।

नवी समाज की स्वरूपा खींचने हुए नेहरूजी लिखते हैं—

“हमारा अन्तिम ध्येय तो यह हो सकता है कि समान ग्वाय और समान सुविधापूर्ण एक वर्ग-रहित समाज हो, ऐसा समाज जिसका निर्माण मानव-समाज को भौतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ऊँचा उठाने और उसमें सहयोग, निःस्वार्थ सेवाभाव, सत्य-निष्ठा, सद्भाव और प्रेम के आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि करने के सुनिश्चित आधार पर हुआ हो, और अन्त में एक ऐसी संसार-व्यापी व्यवस्था हो जाये।”

यह है भारतीय राष्ट्रीयता का समुज्ज्वल स्वरूप और उसके उच्च मानवीय आदर्श जिनपर वास्तव में सच्ची अन्तर्राष्ट्रीयता की आधार-मिला रखी जा सकती है।

नागरिक-स्वाधीनता

मसार व सत्र विद्वाना का यह मत है कि नागरिक जीवन का विकास और उत्कर्ष केवल स्वतन्त्र वातावरण में ही हो सकता है । नागरिक-स्वाधीनता मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है । स्वाधीनता के बिना मानव न तो अपना आत्म विकास कर सकता है, और न दूसरों की भलाई ही । राज्य सुमगडित नागरिकों की एक संस्था ही है । उसका बिना नागरिकों के हित ही के लिए है । नागरिकों से रहित राज्य की चलना संभव नहीं । राज्य की उत्पत्ति इसी कारण हुई कि सत्र नागरिक निर्वाध रूप से स्वाधीनता का लाभ उठा सकें, क्योंकि अराजक दशा में मनुष्य-माय का आश्रय न लेकर प्रतिन के चल पर शासन करने लगते हैं ।

राज्य मानवों के हित के लिए है । अतः राज्य की ओर से प्रत्येक व्यक्ति अथवा नागरिक की सुख-सुविधा के लिए समान रूप से सम्यक् व्यवस्था होनी चाहिए । नागरिक स्वाधीनता के उपभोग के लिए राज्य ने नागरिकों को विशिष्ट और निर्धारित अधिकारों की व्यवस्था की है । प्रोफेसर हंटर लॉन्ग के अनुसार 'नागरिक स्वाधीनता ऐसे अधिकार हैं जो सामाजिक जीवन की उन अवस्थाओं की रक्षा के लिए जरूरी हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी मानव अपना आत्म-विकास नहीं कर सकता । सुप्रसिद्ध समाज विज्ञानवेत्ता श्री हॉब्सबॉस के मतानुसार 'सच्चा अधिकार उसके अधिकारों के वास्तविक मंगल का एक तत्त्व है स्थिति है जो सामंजस्य के सिद्धान्त के आधार पर सार्वजनिक मंगल का ही एक प्रमुख अंग है ।'

इटली व महापुरुष और वीर दशभक्त मेज़िनी नागरिक स्वाधीनता को सर्वोच्च पालन के लिए अत्यन्त आवश्यक मानते थे । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है—

“स्वाधीनता के बिना आप अपने किसी भी कर्तव्य को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्वाधीनता का अधिकार है और आपका यह कर्तव्य है कि जो कोई सत्ता स्वाधीनता का नियंत्रण करती हो, उससे उसे किसी भी उपाय से प्राप्त कर लो।”

राज्य और विशेषतः प्रजातन्त्र-राज्य का लक्ष्य है नागरिकों के जीवन-विभास तथा उत्कर्ष के लिए सामान्य सुयोग एवं सुविधाएँ प्रदान करना। राज्य नागरिकों के प्रति इस महान् कर्तव्य का पालन समीक्षा में कर सकता है जब कि उसे नागरिकों की स्थिति, अभाव एवं आवश्यकताओं का पूर्ण और सच्चा ज्ञान हो। राज्य को नागरिक-जीवन की अवस्थाओं का पूर्ण और सच्चा ज्ञान समीक्षा हो सचना है जब कि नागरिकों को अपनी आवश्यकताओं के अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो। जन्म-समय नागरिकों को किसी प्रकार के भेद-भाव के बिना अपने मनोभाव एवं विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होना, तबतक राज्य उनकी आवश्यकताओं का सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार सामान्य जीवन में स्वाधीनता का मूल्य सुस्पष्ट है। उदाहरणार्थ, किसी राज्य में किसानों को बड़ा कष्ट है, उनसे बेगार ली जाती है, जमींदार अधिक लगान वसूल करते हैं चाहे जब मनमाने ढंग से उन्हें जमीन में बेदखल कर दिया जाता है और उनकी मवेशी को चारा नहीं मिलता क्योंकि चरागाहों पर भी जमींदार खेती कराते हैं। अब यदि राज्य शासन की ओर से कृषि सुधार के लिए कोई योजना या कानून बनाया जाये और उसके सम्बन्ध में किसानों को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार न दिया जाये, सिर्फ जमींदारों की सम्मति से ही योजना या कानून बना लिया जाये, तो इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे नियम या योजना से किसान-समाज का हित नहीं होगा। इसी प्रकार धारा-सभा में यदि कोई मन्त्रिणयोगी कानून बनने जा रहा है, और उससे पहले में राष्ट्र की मन्त्रियों के लोकमत को जानने का प्रयत्न नहीं किया जाता, तो ऐसे कानून के बन जाने में मन्त्रियों का क्या हित-साधन होगा? मन तो पर है कि किम व्यक्ति को कोई अमान या आवश्यकता

है, वही भलोभानि अपनी आवश्यकता प्रकट कर सकता है।

अधिकार और कर्त्तव्य

नागरिकता एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक अधिकार है। वह किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति-समूह की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं है। नागरिक समाज का एक अंग है और उसे जो नागरिक-अधिकार प्राप्त हैं, वे केवल इसलिए कि वह उनका प्रयोग इस ढंग से करे कि जिससे अपना हित-साधन करते हुए वह समाज के अन्य सदस्यों को हानि न पहुँचा सके। यदि किसी मनुष्य के नागरिक अधिकारों के प्रयोग से दूसरे को हानि पहुँचती तो उससे समाज का कल्याण नहीं हो सकता और जिस लोक सभ्यता की दृष्टि से राज्य ने नागरिक स्वाधीनता प्रदान की है, उसका अभिप्राय भी सिद्ध नहीं होना।

इससे यह सिद्ध होता है कि समाज में अधिकारों के साथ-साथ कर्त्तव्यों का भी उतना ही मूल्य है। यदि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार राज्य ने दिया है, तो दूसरे व्यक्तियों के लिए वही अधिकार कर्त्तव्य बन जाता है। उदाहरणार्थ, एक नागरिक अपने भाषण-स्वाधीनता के अधिकार का प्रयोग करता है, तो ऐसी दशा में दूसरे नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि वह उसकी इस स्वाधीनता में बाधा न डाले जबतक कि उनका भाषण कानून-विरुद्ध अथवा मानहानिकर न हो।

वास्तव में नागरिकों की पारस्परिक सहयोग की भावना और कर्त्तव्य-परायणता ने ही नागरिक-अधिकारों को जन्म दिया है। यदि नागरिक सहयोगपूर्वक नागरिक-स्वाधीनता की रक्षा व उसका उपभोग न करें और उन अधिकारों द्वारा जो कर्त्तव्य निर्धारित हुए हैं, उनका तत्पन्ता से पालन न करें, तो हम समाज में अधिकारों की कल्पना नहीं कर सकते।

डॉ० बेनीप्रसाद का यह मत उचित है कि अगर उपयुक्त जीवन-निर्वाह की अवस्थाओं को सबसे लिए सुरक्षित रखना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को उनके उपयोग की आशा करनी चाहिए और साथ-ही-साथ ह्मएक

आदमी को इस प्रकार काम करना उचित है कि दूसरे लोगों के उपभाग में किसी प्रकार की बाधा न पड़े। यही नहीं प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि ऐसी परिस्थितियों को सबके लिए सुलभ करने में निश्चित रूप से प्रोत्साहन दे। एक व्यक्ति के सम्बन्ध में जो अधिकार हैं, वह दूसरों के लिए कर्तव्य हैं। इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के आधिन हैं। वे एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। अगर कोई उनको अपने दृष्टिकोण से देखता है तो वे अधिकार हैं और अगर दूसरों के दृष्टिकोण से देखता है तो वे कर्तव्य हैं। दोनों सामाजिक हैं और दोनों असल में उपयुक्त प्रकार के जीवन की अवस्थाएँ हैं, जिन्हें समाज के सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना चाहिए।^१

नागरिक समानता

इंग्लैण्ड के मुख्यमन्त्र राजनीतिशास्त्री श्री हेरल्ड लाम्बी ने लिखा है —

“जिस राज्य में नागरिक स्वाधीनता को अपने निदिष्ट लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है वहाँ समानता होना भी जरूरी है।” “राज्य में नागरिकों में जितनी अधिक समानता होगी सामान्यतया उतना ही अधिक वे अपनी स्वाधीनता का उपयोग कर सकेंगे।”^२

नागरिक-स्वाधीनता और समानता एक ही वस्तु नहीं है। दोनों में अन्तर है। यदि राज्य में कुछ निश्चित समानताएँ प्राप्त न हों तो यह संभव नहीं कि हम नागरिक-स्वाधीनता का उपयोग कर सकें।

समानता और असमानता के संबंध में यह स्पष्ट रूप से जान लेना आवश्यक है कि विश्व में प्राकृतिक समानता का कहीं भी अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक वस्तु में रचना, आकृति और रंग-रूप के कारण भिन्नता होना स्वाभाविक है। एक पिता को दो सन्तानों में भी आकृति, रंग-रंग,

१ डॉ० बेनीप्रसाद, ‘नागरिक-शास्त्र’; पृ० ४१

२. लारकी ‘लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट’ (१९३०); पृ० १६-१७

स्वाधीनता, सङ्घति और भाषा की रक्षा, कानून की दृष्टि में सभी नागरिकों की समानता और इसी प्रकार शासनाधिकार में, व्यवसाय-व्यापार में धर्म, जाति या 'सेक्स' के भेदभाव के बिना समानता और इसी प्रकार के अधिकार ।'

“हमारी यह धारणा है कि देश में समस्त अल्प-संख्यक जातियों के आवासन के लिए भारतीय शासन-विधान में इन मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में एक मारटो होनी चाहिए ।

“इसके लिए कांग्रेस का कराची-प्रस्ताव और पाश्चात्य शासन-विधानों की नागरिक स्वाधीनता सम्बन्धी धाराएँ नमूने के तौर पर ली जा सकती हैं ।”^१

वर्तमान शासन विधान की धारा २९८ में नागरिकों का यह अधिकार तो स्वीकार किया गया है कि सरकारी पदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में या किसी सम्पत्ति के प्राप्त करने या बेचने अथवा व्यवसाय-व्यापार करने में केवल धर्म, जाति, जन्म स्थान, रंग या इनमें से किसी के कारण कोई भी नागरिक अयोग्य न माना जायेगा ।

विधान की धारा २७५ में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति लिंग भेद के कारण ब्रिटिश भारत में किसी 'सिविल सर्विस' या 'सिविल पोस्ट' पर नियुक्त होने के अधिकार से वंचित न किया जायेगा । परन्तु गवर्नर जनरल, गवर्नर और भारत मन्त्री अपने विशेष आर्डर द्वारा स्त्रियाँ का सरकारी पदा पर नियुक्त होने के अधिकार से वंचित कर सकेंगे ।

शासन विधान की २९८ वीं धारा के होते हुए भी भारत में ऐसे अनेक वर्ग हैं, जिन्हें जातिभेद के कारण शासनाधिकार में व्यावहारिक समानता प्राप्त नहीं है । 'दलितवर्ग' या हिन्दू समाज का ही अंग है, आज भी उच्च सरकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता । यही नहीं इस वर्ग के सदस्यों को व्यापार व्यवसाय में भी समानता प्राप्त नहीं

है। इस वग के लग वाजारा में कोई ऐसी इवान नहीं खोल सकते जिसमें खाने-पीने की चीज बिकती है।

भारत में पदाधिकार के सम्बन्ध में लिंग भेद का व्यवस्था गुप्त स कायम है। आज भी विधान की २७५ वा धारा के हाने हुए महिलाओं को इंडियन सिविल सर्विस, प्रान्तीय सिविल सर्विस आदि की प्रति योगिताओं में बैठन की आज्ञा नहीं है। सेना में तो उनके लिए बाबून प्रतिक्रम है। यह वास्तव में विधान का एक बड़ा दाप है।

आर्थिक समानता

यदि राज्य में नागरिकों को आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त है और आर्थिक समानता नहीं है, तो इसका परिणाम यह होगा कि समाज में आर्थिक विषमता पैदा हो जायगी और ऐसे वातावरण में सच्ची आर्थिक स्वाधीनता का उपभोग भी नहीं किया जा सकेगा।

जबकि आर्थिक समता की स्थापना नहीं हो जाती तबतक राज नीतिव समता—नागरिकों का समान भताधिकार—अव्य है। उससे व आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकते। आधुनिक राज्य का केवल इतना यही नाम नहीं है कि यह चार और टाकुभा में नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की और इस प्रकार नागरिक-स्वाधीनता की रक्षा कर, उनके लिए प्रजातन्त्र-दान-पद्धति तथा अन्य नाना प्रकार के नागरिक सुखा के लिए मुविषाएँ प्रदान करे। आज के युग में इन नरस नागरिक-जीवन का उत्थप सम्भव नहीं। यह आर्थिक युग है। इसलिए राज्य का ऐसी आर्थिक व्यवस्था भी स्थापित करनी चाहिए जिसमें सभी नागरिक पूरी तरह सुखी रह सक और अपने जीवन को ऊँचा बना सक। यदि राज्य में अगकर बेकारी होगी बेहद गरीबी होगी कुछ मुठठी भर लोग न्यमपति और करोड़पति मिला और कम्पनिया के मालिक तथा भूमि के स्वामी होंगे और शेष विपणन जन-समुदाय को नागरिक जीवन की सम्पन्न मुविषाएँ तो दूर भरोपेन जन भी नोना बकन न मिनेगा, तो क्या यह आशा की जा सकती

हैं कि अधभूखे और अर्द्धनग्न जन आर्थिक स्वाधीनता भाग सकें ?

आज संसार के सभी प्रजातन्त्रों में अधिकांश नागरिक आर्थिक दृष्टि से दुर्मी हैं। वहाँ भयंकर बकारी गरीबी बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन पाश्चात्य प्रजातन्त्रों ने आज तक आर्थिक याद या आर्थिक समता की स्थापना के लिए ईमानदारी से कोई प्रयत्न नहीं किया। संसार में साविट्ट हस ही एक ऐसा राष्ट्र है जिसने अपने शासन विधान के मौलिक अधिकारों की धारणा में यह स्वीकार किया है कि "सोविट्ट हस के नागरिकों को परिश्रम करने का अधिकार है अर्थात् उन्हें काम के परिमाण तथा उसकी किस्म के अनुसार अपने परिश्रम के लिए नियत वेतन पर पारिश्रमिक का अधिकार है।"

साविट्ट हस में राज्य की ओर से प्रत्येक नागरिक का अपनी योग्यतानुसार काम माँगने का अधिकार है और उसके लिए नियत वेतन भी।

आर्थिक समता की स्थापना के लिए समान को आर्थिक ढाँचा नये ढंग से खड़ा करना होगा। इसमें मौलिक परिवर्तन की जरूरत है। समस्त व्यवसायों, कम्पनियों, कारखानों, रेलों बैंकों आदि पर राज्य का नियंत्रण या अधिकार होना चाहिए। श्री श्रीनिवास अयंगर ने लिखा है —

‘संसार की आर्थिक व्यवस्था में सबसे अधिक सकट ज्यादा हटाकर कम्पनियों ने पैदा किया है, इसलिए इनका पूर्णतः परिचालन किया जाये, साझेदारी भी मर्यादित कर दी जाये, उसके साझेदारों की संख्या कम कर दी जाये तथा उसका क्षेत्र भी सीमित कर दिया जाये। बैंक, बीमा जहाज तथा यातायात आदि राज्य के अधिकार में हों। नहर आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर राज्य की ओर से किया जाये। नहरादि बनानेवाली कम्पनियाँ का नियंत्रण भी राज्य के अधिकार में हो। इस प्रकार राज्य की ओर से राष्ट्रीय व्यवसाय धन्यों को इतना प्रोत्साहन दिया जाये कि जिससे बेकारी व गरीबी दूर हो जाये और वेतन तथा पारिश्रमिक का मान-दण्ड बढ़ जाये। संक्षेप में, एक नियोजित

आर्थिक योजना, जो जनता की समस्त श्रेणियों की मौलिक माननीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके, आज भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए सबसे पहली शर्त है; क्योंकि वह (प्रजातंत्र) उसी सीमा तक स्थायी होगा जिस सीमा तक वह जनता को यह गारण्टी दे सके कि जनता की आर्थिक उन्नति उसका प्रमुख लक्ष्य है ।^१

वैयक्तिक स्वाधीनता

वैयक्तिक स्वाधीनता या अर्थ है व्यक्ति की स्वाधीनता । प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी रक्षा करे । आत्म-रक्षा का नियम भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक फलितार्थ है । समाज या राज्य के निर्माण में नागरिकों का योगदान होता है, इसलिए नागरिकों की वैयक्तिक स्वाधीनता सामाजिक जीवन के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है । यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास न हो सके कि वह राज्य में वैयक्तिक स्वाधीनता का उपभोग कर सकता है तो वास्तव में उसका जीवन दुम्भर हो जायगा ।

मनुष्य का जीवन वैयक्तिक दृष्टि से ही मूल्यवान् नहीं है, बल्कि समाज और राज्य के दृष्टिकोण से भी वह बहुमूल्य है । यही कारण है कि राज्य मानव-जीवन की रक्षा को अपना पवित्र कर्तव्य समझता है । मानव-जीवन की रक्षा के लिए सेना और पुलिस का राज्य की ओर से प्रबन्ध जरूर होता है । परन्तु पुलिस के लिए हर समय और हर स्थान में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना सम्भव नहीं है । इसलिए राज्य ने प्रत्येक व्यक्ति को आत्म-रक्षा का अधिकार दे रखा है । यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने के प्रयोजन से उसपर सापात्रित्व गांधपण करे, तो वह अपनी रक्षा के लिए प्रत्येक सम्भाव्य साधन को काम में ला सकता है । यहाँ नव कि यदि वह आक्रमणकारी के

१ श्री श्रीनिवास अयंगर : 'ग्रॉन्लैंड्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इण्डिया' (१९३९), पृ० ६९

जीवन का अन्त भी कर दे तो राज्य उसे इसके लिए दण्ड नहीं देगा। प्रत्येक देश में आत्म-रक्षा के लिए नागरिकों को अस्त्र शस्त्र धारण करने का भी अधिकार है।

माय ही चूँकि राज्य का यह परम वस्तु है कि वह ममस्त नागरिकों और व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करे, इसलिए यदि कोई व्यक्ति आमयाम द्वारा अपने जीवन का अन्त करने का प्रयत्न करे, तो राज्य उसे इसके लिए दण्ड देगा।

शरीर-स्वाधीनता

शरीर-स्वाधीनता का अन्विष्ट यह है कि वह राज्य में अपने गृह में स्वतंत्रता से रह सके। उसकी स्वीकृति, इच्छा या आज्ञा के बिना कोई व्यक्ति उसके गृह में प्रवेश न कर सके और जबतक कि राज्य के कानून के अनुसार मजिस्ट्रेट न उसकी गिरफ्तारी के लिए वारण्ट न जारी किया हो अथवा पुलिस को यह सन्देश न हो कि उसने राज्य के कानून के विरुद्ध ऐसा अपराध किया है जिसमें वह बिना वारण्ट के भी गिरफ्तार किया जा सके तबतक राज्य भी उसे गिरफ्तार न कर सके। जबतक कोई भी नागरिक कानून के अनुसार न्यायालय में दायी प्रमाणित न हो जाये और वह निस्सन्देह सिद्ध न हो जाये कि उसने वह अपराध ऐसे समय किया था जबकि वह कानूनन अपराध था, तबतक केवल सन्देह के आधार पर कोई भी व्यक्ति अनिश्चित बाल के लिए नजरबन्द नहीं किया जा सकता और न हवालात में २४ घंटे से ज्यादा रखा जा सकता है। जबतक वह दायी प्रमाणित न हो जाये, तबतक उसे कोई शारीरिक दण्ड नहीं दिया जा सकता।

भारतवर्ष में नागरिकों को शरीर-स्वाधीनता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। यहाँ आज भी ऐसे दमनकारी कानून, मौजूद हैं जिनमें अस्तित्व में उन्हें शरीर-स्वाधीनता नहीं है। मद्रास, कोलकाता में आज से एक आन्दोलन से भी अधिक घुसने के हैं। आज भी प्रचलित हैं, जिन्हें अनुसार किसी भी व्यक्ति

में शोषी प्रमाणित किये वर्षों तक राजबन्दी बनाकर रखा जा सकता है। सन् १९३१ के सत्याग्रह आन्दोलन में महात्मा गांधी को बम्बई रेग्यूलेशन (१८१८) के अनुसार राजबन्दी बनाकर पूना-जेन्ट में रखा गया। जनवरी सन् १९३२ में श्री मुभाषचन्द्र वसु को डंगी रेग्यूलेशन के अनुसार राजबन्दी बनाकर रखा गया था।

भारत के हर एक प्रान्त में मिनिमल एमेण्डमेट एक्ट जारी है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को मदेह में गिरफ्तार करके राजबन्दी बनाया जा सकता है। पंजाब और बंगाल प्रान्त में राष्ट्रीय जागरण को दबाने के लिए घोर-से घोर दमनकारी कानून आज भी प्रचलित हैं। वर्तमान युद्ध के कारण तो यह दमन अपनी चरम-सीमा को पार कर चुका है। सन् १९३७ में बंगाल के आगवधारी-दमन कानून के अनुसार यहाँ १६ हजार व्यक्ति नजरबन्द थे। बाद में महात्मा गांधी के प्रयत्न में कुछ नजरबन्द रिहा कर दिये गये।

नागरिकता का मौखिक सिद्धान्त यह है कि जबतक कोई व्यक्ति शोषी सिद्ध न हो जाये तबतक उसे दण्ड नहीं दिया जा सकता। केवल सन्नेह में किसी को बन्दी बनाकर रखना तो कानून की दृष्टि में भी बन्धाप है। ऐसा करने का अर्थ तो यह हुआ कि जिन लोगों के ह्रास में पार्यवारिणी सत्ता है, वे ही न्यायाधीन बन गये।

विचार-स्वाधीनता

विचार-स्वाधीनता नागरिक-जीवन के विकास और उन्नति के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण है। जिस राज्य के नागरिक विचार स्वाधीनता (अर्थात् मन प्रकाशन की स्वाधीनता) का बेरोक-टोक उपयोग करने हैं, उसमें साहित्य, कला, ज्ञान-विज्ञान की आदिव्यजनक प्रगति और प्रसार होता है। विचार चिया जाये तो वास्तव में विचार ही मनोमात्र प्रकट करने का अमोघ साधन है। जिन देशों में विचार-स्वाधीनता नहीं उन देशों में न विचार मौलिकता को प्रोत्साहन मिलता है और न विचार शान्ति के लिए उपयुक्त क्षेत्र ही मिलता है। जिस प्रकार तालाब का रूका हुआ जल मड़

‘अभिज्ञात व्यक्ति जिन्हें निजी अनुभव के आधार पर विचार-मग्न करने की सुविधा नहीं मिलती, विचार करना ही बंद कर देते हैं। जो व्यक्ति विचार करना बन्द कर देते हैं, वे सच्चे अर्थ में नागरिक नहीं रहते।’

अतः यह निर्विवाद है कि व्यक्तित्व के विकास, समाज के उत्कर्ष और राज्य की समृद्धि के लिए विचार और मत प्रकाशन की स्वाधीनता अत्यन्त आवश्यक है।

मनुष्य अपने विचार मुख्यतः दो रूपों में प्रकट करता है—भाषण और लेखन। भाषण स्वाधीनता का समा-संगठन की स्वाधीनता से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनके अतिरिक्त मनुष्य अपने विचार समाचार-पत्र, पुस्तक, चित्र, संगीत, सकेन, कार्टून (व्यंग्यचित्र), रेडियो, चित्रपट आदि द्वारा व्यक्त करता है।

राज्य में प्रत्येक नागरिक को भाषण और लेखन की पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट करने एवं आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में भी उसे अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। परन्तु इस सम्बन्ध में इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसने सम्बन्ध में केवल ऐसे विचार ही व्यक्त किये जायें जो सार्वजनिक महत्त्व के हों। किसी नागरिक या व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन को संश्लेषण के सामने केवल सामाजिक हित की दृष्टि से ही प्रकट करना उचित है। यदि उससे समाज का हित नहीं होना तो ऐसा मत प्रकाशन व्यर्थ है।

नागरिक के मत प्रकाशन के अधिकार पर राज्य की त्रार से कुछ प्रतिबन्ध भी लगाये जाते हैं। उन्हें ऐसे विचार प्रकट करने का अधिकार नहीं है, जो ईश्वर या किसी धर्म के अनुयायियों की धर्म मानना पर आघात करें, उत्पीड़न हों, अपमान-जनक हों, राजद्रोह-मक हों अथवा हिंसा, अशान्ति या उपद्रव का उत्तेजन दें।

नागरिकों को धर्म के सम्बन्ध में स्वाधीनता है। वे दूसरे धर्म के

सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, परन्तु उन्हें किसी के धर्म की चोट पहुँचाने का अधिकार नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई धर्म-सुधारक धर्म के नाम पर प्रचलित अध-परम्परा एवं अधविश्वासों को दूर करने का प्रयत्न न करे। यदि स्वतन्त्र रीति से धर्म पर विचार-विनिमय न किया जाये या प्रचलित अध-विश्वासों का मिटाने का उपाय न किया जाये, तो इसका भी परिणाम अत्यन्त भयकर होगा। जनता में धर्म के नाम पर अनाचार, अन्याय और भ्रष्टाचार होने लगेगा।

अश्लील भाषण या लेख भी समाज के लिए हानिप्रद हैं। इनसे जनता का नैतिक पतन ही नहीं होता, बल्कि स्वास्थ्य पर भी घातक प्रभाव पड़ता है। अश्लील से तात्पर्य यह है कि कोई विचार या भाव अथवा लेख ऐसा हो जिससे श्रोता या पाठक के मन पर बुरा असर पड़े—विकार उत्पन्न हो जाये। यदि विचार मानव के मन में विमल और विशुद्ध भावा को जाग्रत नहीं कर सकते, तो उनसे समाज के उत्कर्ष में क्या सहायता मिल सकती है? हाँ, प्रत्येक देश और समाज का नीति शास्त्र भिन्न होता है—जो काम किसी देश में अश्लीलता की कोटि में माना जाता है, वही कार्य दूसरे देश में श्लीलता में गिना जाता है। उदाहरणार्थ, भारत में काम-विज्ञान जनता में अश्लील माना जाता है, इस विषय की सार्वजनिक चर्चा असभ्यता या अशिष्टता मानी जाती है पर भारत में अब एक ऐसा वर्ग पैदा होता जा रहा है जो काम-विज्ञान की शिक्षा को आवश्यक समझता है। तो भी यह वर्ग अल्पसंख्यक में है और नवीन संस्कृति के उपासक जना तक ही सीमित है। यूरोप और अमरीका के देशों में तो काम विज्ञान एक लोकप्रिय विषय है। वस्तुतः दाम्पत्य-विज्ञान मानव-जीवन की सुखी बनाने के लिए परम आवश्यक है। इसमें वैज्ञानिक विवेचन में विवाह, काम, प्रेम, सुहागरान, मन्नति निरोध, तलाक आदि की समस्याएँ आ जाती हैं। परन्तु इनका विवेचन ऐसे ढंग से होना चाहिए कि उससे मुरचिप्रिय व्यक्ति के हृदय में रगति का भाव पैदा न हो।

विचार-स्वाधीनता या मत-प्रकाशन की स्वाधीनता पर एक प्रति-
बन्ध और भी है—किसी व्यक्ति के लिए कोई अपमानजनक वचन न
कहा जाये और न लिखा जाये। जवनक अपमानजनक भाषण या लेख
समय न हो और उसकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता न हो, तबतक
उसका प्रकाशन अनुचित है। यदि कोई व्यक्ति दुराचारी, भ्रष्टाचारी
और पतित है और उसका सार्वजनिक जीवन में प्रमुख स्थान है, तो
उसके भ्रष्टाचार को, यदि वह समय है तो, जनता के सामने प्रकट करना
सार्वजनिक हित में होगा। इसलिए ऐसा मत-प्रकाशन अपमानजनक
नहीं कहा जा सकता।

विचार-स्वाधीनता और मत-प्रकाशन पर एक बड़ा प्रतिबन्ध यह है
कि भाषण या लेख राजद्रोहात्मक न हो। सामाजिक संगठन अथवा
शासन-पद्धति के सम्बन्ध में प्रत्येक नागरिक को अपना मत प्रकट करने
का अधिकार है। भारत में सरकार के किसी कार्य की आलोचना तथा
नीति की निन्दा भी राजद्रोह माना जाता है। यहाँ राजद्रोह सबसे बड़ा
राजनीतिक अपराध है। भारतीय-दण्ड-विधान की धारा १२४ अ का
प्रयोग सदैव भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का दमन करने के लिए किया
जाता रहा है। जुलाई सन् १९३७ में जब भारत के मातृ प्रांतों—मद्रास,
बम्बई, संयुक्तप्रान्त बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त, सीमा प्रान्त और आसाम
में कांग्रेस-दल के मन्त्रि-मण्डलों की स्थापना हुई, तो जनता ने सबसे
पहले अंग्रेजी राज्य में नागरिक-स्वाधीनता का अनुभव किया। किसी भी
व्यक्ति पर राजद्रोह का अपराध लगाना बन्द कर दिया गया। बम्बई-
सरकार के तत्कालीन गृह-मंत्री श्री कन्हैयालाल मुन्शी ने बम्बई-असेम्बली
में अपने (१५ सितम्बर १९३७ के) एक भाषण में कहा था—

“कांग्रेस व्यक्ति की स्वाधीनता का समर्थन करती है, क्योंकि उसका
अहिंसा और प्रजातन्त्र में अटल विश्वास है। हमारे लिए स्वाधीनता
केवल भौतिक लाभ की चीज नहीं है। इसे हम इतिहास की भौतिकवादो
व्याख्या की तुलना में नहीं सोल सकते। स्वाधीनता हमारे लिए एक
अपने दग का चमत्कार है। ईश्वर और कानून के राज्य में बोलना, काम

करना और साँस लेना एक पवित्र विशेषाधिकार है। उसके साथ ही विचार किये बिना ही उसमें हमारा विश्वास है। अन्तिम समय तक प्रत्येक कांग्रेसवादी जिसकी प्रज्ञानत्रय में श्रद्धा है, स्वाधीनता का समर्पण करेगा।

“नागरिक-स्वाधीनता प्रज्ञातत्रयी का वास्तविक आधार-शिला है। प्रज्ञातत्रयी का मतलब है एक ऐसा धर्म जिसका समाज ज्ञान-दान विचार-विनिमय और आपस द्वारा विकास कर सकता है—एक दूसरे का तिर सोडकर नहीं। किन्तु नागरिक-स्वाधीनता के लिए अहिंसक आतावरण आवश्यक है जिसमें नागरिक वैयक्तिक हिंसा, दबाव या सामूहिक हिंसा या दबाव से निर्भय रहते हुए परस्पर विचार-विनिमय कर सके। नागरिक-स्वाधीनता की यह एक मौलिक मर्यादा है। हिंसापूर्ण और उत्तेजित आतावरण में आप नागरिक-स्वाधीनता का उपभोग नहीं कर सकते।”

हम इसका उल्लेख कर चुके हैं कि प्रज्ञातत्रय में प्रत्येक नागरिक का शासनाधिकार प्राप्त होता है। प्रज्ञातत्रय का अर्थ ही है जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक है कि जनता को शासन पर अपना प्रभाव डालने का अधिकार हो। शासन की नीति एवं कार्यों की स्वनियंत्रण रूप से आलोचना करना जनता का और एक मूल्यवान् अधिकार है। इससे एक बड़ा लाभ यह है कि शासन को जनता के मनोभाव व विचार विदित होने रहने हैं और उसे अपनी नीति और कार्यों में उचित संशोधन या परिवर्तन करने में सुगमता होती रहती है।

गृह-विद्रोह या युद्ध-काल में नागरिक-स्वाधीनता

यदि राज्य में विद्रोह पैदा हो जाये अथवा राज्य किसी दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो, तो ऐसे असाधारण अवसरों पर भी नागरिक स्वाधीनता की रक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है। जो व्यक्ति राज्य विद्रोह में भाग ले, उन्हीं देश के सामान्य कानून के अनुसार दण्ड देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि किसी भाग में विद्रोह या

आन्दोलन शुरू हो जाने पर सम्मले प्रान्त की नजरबन्द-शिविर बना दिया जाय या फौजी कानून (मागैल लॉ) जारी कर दिया जाये। भाग्य म मन् १९१९ में अमृतसर, गद्दीर, कमूर, गुजरावाला, बीर शेखपुरा में फौजी कानून जारी किया गया। इस प्रकार नागरिक-स्वाधीनता का बुरी तरह दमन किया गया। मन् १९३० में मोलापुर और पेगावर में फौजी कानून का शासन रहा।

वर्तमान युद्ध ने प्रारम्भ होने के बाद तुरन्त ही भारत के गवर्नर-जनरल ने भारत-रक्षा-कानून जारी कर दिया। इस कानून का श्रेय इतना व्यापक है कि आज भारे देश की स्वाधीनता का दमन इसीके द्वारा हो रहा है जबकि भारत-रक्षा-कानून का लक्ष्य है ब्रिटिश भारत की रक्षा, सार्व-जनिक व्यवस्था की रक्षा, युगान्तापूर्वक युद्ध-मचारण, अथवा समाज के जीवन के लिए आवश्यक चीजा और सेवाओं की व्यवस्था।

सरकार ऐसा क्यों बिना करती है? इसका उत्तर देने हुए प्रोफेसर लाय्की ने लिखा है—

“...जब व्याव-व्यवस्था का कार्य सामान्य न्यायालयों में लेकर शासन के किमी दूसरे अंग को सौंप दिया जाता है, तो उसका सदैव दुर्बलपण होना है। व्यक्ति की समुचित रक्षा के प्रश्न को इस विश्वास पर विस्मृत कर दिया जाता है कि आतंक के शासन से जनता की अश्रद्धा (Disaffection) कम हो जायेगी। इसका कोई प्रमाण नहीं कि ऐसा हो जाता है। यदि ऐसा हो सकता, तो रूसी क्रांति ही न होनी और आज भारतीय स्वायत्त शासन के लिए कोई आन्दोलन न हुआ होता।”

भारत में समाचार-पत्रों की स्वाधीनता पर भी कुदारापान हो रहा है। नये-नये बाउंड जारी किये जा रहे हैं। इन सबके ऊपर सेंसर का एक-छत्र गम्य है। समाज और सम्मेलन पर प्रतिबंध लगा दिये गये हैं। पुलिस के अधिकारियों में पूर्व आज्ञा प्राप्त किये बिना कोई गिराफ्तारी नहीं की जा सकती, चाहे उस गिराफ्तारी का मुद्दा ने कोई सम्बन्ध ही न हो।

जुलूसों पर भी इसी प्रकार का प्रतिवध है। भारत-रक्षा कानून के अन्तर्गत नियम ५८ के अनुसार मृत्यु सवका, सवा-दला तथा वाग्गियर-दला का प्रदर्शन करने तथा परेड करने से रोक दिया गया है। प्रेस तथा समाचार-पत्र जलन किये जा रहे हैं। समस्त भारत में हजारों पुस्तकें और समाचार पत्रों की जलनी हो चुकी है। राष्ट्रीय एवं समाजवादी साहित्य जिसका वर्तमान युद्ध के संचालन से तनिक भी सम्बन्ध नहीं, जलन किया जा रहा है। इस प्रकार भारत की नागरिक स्वाधीनता इस समय अत्यन्त संकट में है।

युद्ध-काल में नागरिक-स्वाधीनता पर सिर्फ इतना प्रतिवध होना चाहिए कि जिससे नागरिक शत्रु को कोई सहायता न दे सके या कोई ऐसा कार्य न करे जिससे युद्ध-संचालन में बाधा पड़े। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि नागरिकों का मत प्रकाशन की भी स्वाधीनता न दी जाये। युद्ध-काल में शांति काल की अपेक्षा नागरिकों को मत प्रकाशन की अधिक स्वाधीनता मिलनी चाहिए, क्योंकि युद्ध में नागरिक देश रक्षा के लिए न केवल धन और सम्पत्ति से ही सहायता देते हैं बल्कि अपने प्राणा का भी होम करते हैं। इसलिए नागरिकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ही उन्हें अपने विचार स्वतन्त्रता में प्रकट करने का अधिकार मिलना आवश्यक है।

समाचार-पत्रों की स्वाधीनता

समाचार-पत्रों की स्वाधीनता का अभिप्राय यह है कि समाचार-पत्र बिना किसी पूरे आज्ञा के समाचारों को वास्तविक रूप में प्रकाशित कर तथा घटनाओं पर अपने विचार स्वतन्त्र रीति से प्रकट कर। वास्तव में प्रजातन्त्र में समाचार पत्रों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वे केवल जनता को देश विदेश की स्थिति से परिचित ही नहीं कराते बल्कि किसी भी सार्वजनिक प्रश्न पर लोकमत तैयार करने में बड़ा प्रभाव डालते हैं।

समाचार पत्र केवल लोकमत का प्रकट करने का साधन ही नहीं है,

प्रत्युत वह स्नेहमय बनाने का भी उतना ही शक्तिशाली साधन है। वास्तव में प्रजातन्त्र की सफलता के लिए प्रगतिशील लोकमत की आवश्यकता है। उसके अभाव में उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। शान्ति-काल में समाचार-पत्र स्वराष्ट्र की सरकारी नीति तथा कर्मों की आलोचना करते हैं जिससे जनता को सरकारी कार्यों का स्यावत् ज्ञान हो सके। व किसी भी सार्वजनिक प्रश्न को सरकार तक पहुँचाने के साधन हैं। परन्तु युद्ध-काल में तो समाचार-पत्रों का उत्तरदायित्व और भी महान् एवं गंभीर हो जाता है। युद्ध के कारण देश में जो भय और आतंक एवं गलतफहमियाँ तरह-तरह की अफवाहों के कारण पैदा हो जाती हैं, उनके दूर करने में समाचार-पत्र बड़ी सहायता करते हैं। युद्ध मंचालन तथा देश-रक्षा के प्रयत्नों के सम्बन्ध में प्रचार के लिए समाचार-पत्र से बड़ कर कोई साधन नहीं है।

भारतवर्ष में सरकार समाचार-पत्रों की स्वाधीनता का सदैव दमन करती रही है। इसका कारण यह है कि भारत के अधिकांश लावप्रिय और प्रभावशाली अंग्रेजी तथा प्रान्तीय भाषाओं के पत्र राष्ट्रीय हैं अथवा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सहानुभूति रखते हैं। उन्हें भारत में अंग्रेजी सरकार की नीति की आलोचना करनी पड़ती है इसलिए उनके सिर पर भी हर समय 'प्रेस एक्ट' सवार रहता है।

सन् १९३१ में इंडियन प्रेस (इमर्जेंसी पॉवर) एक्ट आतंकवाद का नाश करने के लिए बनाया गया। वह उसी समय की विशेष परिस्थिति के कारण बनाया गया था। परन्तु वह आज तक मौजूद है। अब समाचार-पत्रों को इसी कानून के अनुसार राजद्रोह, जातीय या वर्गीय द्रोह, फौजी-भर्ती-विरोध तथा सैनिकों को उत्तेजना देने आदि के लिए दण्ड दिया जाता है। इस कानून के अनुसार समाचार-पत्रों में जमानत माँगी जाती है। जब कोई नया समाचार-पत्र शुरू किया जाता है तो उसके प्रकाशन से पहले ही जमानत माँग ली जाती है। ये जमानत नकद होती है और ५०० रुपये से लेकर १० या १५ हजार तक की होती है। जमानत देने के बाद यदि समाचार-पत्र सरकारी नीति के विरुद्ध

कुछ लिखें तो जमाने जय्य कर ली जाती है । कानून-विज्ञान के अनुसार न्याय तो यह है कि सम्पादक, प्रकाशक या मुद्रक को पहले न्यायालय में अपराधी प्रमाणित कर दिया जाये, तब उसे दण्ड दिया जाये । परन्तु आज अंग्रेजी राज में उसका अग्रगण्य प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं समझी जाती और उसे पहले से ही दण्ड दे दिया जाता है ।

भारतवर्ष में, जबसे युद्ध आरम्भ हुआ है तबसे तो भारत-रक्षा कानून के अन्तर्गत नियम ३८ व ४१ का प्रयोग समाचार-पत्रों की स्वाधीनता का नाश करने के लिए खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है ।

कुछ महीने हुए भारत रक्षा कानून के नियम ४१ के अन्तर्गत २५ अक्टूबर १९४० को सरकार ने निम्न लिखित आशय की आज्ञा प्रत्येक सम्पादक के पास भेजी —

“भारत-रक्षा कानून के नियमों की सध्या ४१ (१-ब) द्वारा प्रदत्त अधिकार से केन्द्रीय सरकार ने भारत में किसी भी मुद्रक, प्रकाशक या संपादक द्वारा ब्रिटिश भारत में किसी भी ऐसे विषय का प्रकाशन निषिद्ध कर दिया है जो युद्ध-संचालन के प्रति विरोध उत्पन्न करेगा, चाहे ऐसा प्रत्यक्ष रूप से किया गया हो या परोक्ष रूप में, या ऐसे विषय के प्रकाशन या मुद्रण को निषिद्ध किया गया है जो इस प्रकार युद्ध-विरोध के लिए की गयी किसी सभा के भाषण से सम्बन्धित हो ।”

इससे बड़ी हलचल मच गयी । महात्मा गांधी ने युद्ध के विरुद्ध प्रचार करने के लिए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया था, उसी के दमन के लिए ऐसी आज्ञा निकाली गयी थी । इसके फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने तीनों साप्ताहिक पत्रों ‘हरिजन’, ‘हरिजन-सेवक’, ‘हरिजन-चन्बु’ का प्रकाशन स्थगित कर दिया । साथ ही अधिकांश संपादकों ने भी अपने समाचार-पत्रों में अग्रलेख तथा सम्पादकीय विचार लिखना बन्द कर दिया ।

बाद में १० नवम्बर १९४० को अखिल भारतवर्षीय सम्पादक-सम्मेलन हुआ जिसमें देश के सभी प्रमुख अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, गुजराती, अंग्रेजी, तमिल, मराठी पत्रों के संपादकों ने भाग लिया और प्रेस की

स्वाधीनता पर विरोध करने वाले नये नार का विरोध किया। पञ्चकारा और केन्द्रीय सरकार के बीच पारस्परिक विचार-विनिमय के बाद सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि उपर्युक्त आर्डर रद्द कर दिया गया है। इस प्रकार समाचार-पत्रों की स्वाधीनता पर आया हुआ मण्ड एक सीमा तक दूर होगया।

सभा-संगठन की स्वाधीनता

विचार-स्वाधीनता के उपभोग के लिए यह आवश्यक है कि विचारों के विनिमय तथा उनकी आलोचना के लिए भी स्वाधीनता हो। यदि एक व्यक्ति एकान्त में बैठकर विचार करता रहे, और उसे अपने किसी मित्र के साथ या देहावासियों के साथ वार्तालाप करके भाषण द्वारा अपने विचारों को उन्तक पहुँचाने की छूट न दी जाये, तो उसके विचारों से समाज कोई लाभ नहीं उठा सकता।

सामाजिक उत्थान के लिए समाज को संगठन और सभा की जरूरत है। जहाँ व्यक्ति सभाओं में परस्पर मिलते-जुलते हैं, तब उन्हें अपनी विविध समस्याओं पर विचार और निर्णय करने का अवसर मिलता है। प्रत्येक देश में नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए तरह-तरह की राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, कला और नाट्य विषयक मण्डियाँ होती हैं। भारत में भी ऐसी मण्डियाँ बहुत हैं। इन्हें अपने कार्य-मन्त्रालयों की आवश्यकता होगी चाहिए। इनमें ने धार्मिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक मण्डियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परन्तु राष्ट्रीय, राजनीतिक तथा व्यावसायिक मण्डियों पर सरकार की कड़ी दृष्टि रहती है। अराष्ट्रीय सरकार द्वारा ऐसी मण्डियों को रजिस्ट्रार-नियुक्त घोषित कर दिया जाता है अथवा उनकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाता है। इनके द्वारा जो विचार सभाओं और जुलूसों का आयोजन किया जाता है, उनपर भी प्रतिबंध लगाये जाते हैं।

जो बालू एक सामान्य नागरिक के लिए है, वही इन सभाओं के लिए भी होना चाहिए। सरकार को किसी भी मण्ड या सम्मेलन को

राकने या उसपर प्रतिबंध लगाने का उस समय तक कोई अधिकार नहीं है जबतक कि ऐसी सभा का उद्देश्य गैर कानूनी न हो अथवा उससे शान्ति भंग की आशंका न हो।

हाँ, यदि सभा के संयोजक शान्ति-पूर्वक कानून के अनुसार किसी सभा का आयोजन करें और कुछ उपद्रवी लोग उसमें आकर अनुचित रीति से व्यवहार करें, जिससे शान्तिभंग होने की आशंका हो तो पुलिस का यह कर्तव्य है कि सभा की स्वाधीनता के अधिकार पर इस प्रकार अघात करनेवाला का गिरफ्तार करके उचित दण्ड दिलाने का उद्योग करे। सभा के संचालकों का भी यह सामान्य कर्तव्य है कि वे शान्ति पूर्वक कानून के अनुसार अपना कार्य करें। सभा में भाषण देनेवालों का भी यह कर्तव्य है कि वे कोई ऐसा भाषण न दें जो न्याय (कानून) के विरुद्ध हो। मजदूर सभा का यह अधिकार है कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए बारबाना या मिला में काम करने की हड़ताल कर सकते हैं। मजदूरों का यह भी अधिकार है कि वह अपने सहयोगियों से शान्ति-पूर्वक हड़ताल करने का अनुरोध करें।

धार्मिक स्वाधीनता

धर्म का समाज और सामाजिक जीवन में एक विशेष स्थान है। इसलिए धार्मिक स्वाधीनता भी नागरिकों के लिए जरूरी है। धार्मिक स्वाधीनता का अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक का अपने विश्वास के अनुसार अपने धर्म पालन का अधिकार है।

वह चाहे तो अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण कर सकता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वाधीनता का सुयाग दे। धर्म का सम्बन्ध आत्मा और ईश्वर से है। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को अपनी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए समान रूप से सुविधाएँ एवं सुयोग प्रदान करे। ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जबकि राज्य की ओर से प्रत्येक धर्म के अनुयायी के लिए उचित धार्मिक शिक्षा का भी प्रबन्ध हो।

इसके साथ ही-साथ राज्य का यह भी तत्त्व है कि वह धर्म के नाम पर उसकी आड में हानिवाला सामाजिक पाप न निवारण का प्रयत्न करे। हिन्दू-समाज में धर्म के नाम पर ऐसी अनेक कुप्रथाएँ प्रचलित हैं जो समाज के लिए हानिकारक हैं—जैसे, बाल विवाह, बाल-हत्या, सती-प्रथा, तरमेव, धार्मिक अंध विश्वास, अस्पृश्यता, जानपान आदि। समाज न्याय के लिए इनके निवारण का भी राज्य की ओर स अधिक प्रयत्न होना चाहिए। ऐसे प्रयास का धार्मिक हस्तक्षेप का नाम देना अविवेक है।

धर्म के सम्बन्ध में राज्य की निष्पक्षता का मतलब यह है कि राज्य का किसी एक धर्म के साथ अपनी विशेष सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए और न उसे राज्य-कोष से विशेष मदद ही देनी चाहिए। राज्य के द्वारा सत्र धर्मों और उनके अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। जब 'धर्म' नागरिक जीवन की दृष्टि में बाधक हो अथवा किसी धर्म के अनुयायियों की ओर से सरकार के सामने ऐसी माँगें रखी जायें जिनका मौलिक नागरिक अधिकारों से धर्षण हो तो राज्य को सार्वजनिक हितों का पूरा ध्यान रखते हुए ऐसे सधर्मों का निवारण करना चाहिए।

भारत में गांधी, मसजिद के सामने राजा बजाने, लाजिया और आरती आदि प्रदत्ता की लेकर हिन्दू मुसलमानों में विशेष रूप से स्वीटारा के समय बड़े दंगे हो जाया करते हैं। प्रत्येक नागरिक को राज पथ का प्रयोग करने का अधिकार है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को अपने धर्म या समाज के जुगूस में भी शामिल होने का अधिकार है। हिंदुओं का मन्दिरा में पूजा-पाठ और आरती करने का उनका ही अधिकार है जितना कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने का। अब यदि मुसलमानों का यह आरोप है कि नमाज के वक्त सड़का पर बाजा न बजाया जाये या आरती न की जाये, तो क्या कभी मुसलमान भी यह माचने का प्रयत्न करेंगे कि यदि इसी प्रकार हिंदू भी यह आरोप कर कि आरती के समय कोई - नमाज न पढ़े या मुहर्रम के दिना में डोल न पीटे जायें क्याकि इससे मन्दिरा के दवना अप्रमन होत है अथवा नागरिकों को नौद में खलल

पड़ता है, तो मुसलमान क्या करेंगे ? इस प्रकार का अविवेकपूर्ण और धार्मिकता कट्टरताभर आक्षेप का तो अंत ही नहीं आयेगा । इसलिए सामाजिक शांति के लिए सहनशीलता और बहुभाव की आवश्यकता है ।

प्रत्येक धर्म के अनुयायी को यह भी अधिकार है कि वह अपने धर्म का जनता में प्रचार करे और दूसरे धर्मवाला को अपने धर्म में दीक्षित करे । इस प्रकार यह धर्म प्रचार और धर्म-परिवर्तन का कार्य शान्तिपूर्वक होना चाहिए । बलपूर्वक किसी को धर्म में मिलाना उचित नहीं है । अनाथों, नाबालिगों और विधवाओं का धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्हें प्रायः प्रशोभन दखर विधर्मी बना लिया जाता है ।

व्यावसायिक स्वाधीनता

व्यवसाय का वैयक्तिक जीवन में ही नहीं बरकरा सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण स्थान है । व्यावसायिक स्वाधीनता का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति, योग्यता और स्थिति के अनुसार व्यवसाय स्वीकार करने का अधिकार । जिस मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार काम मिल जाता है, वह उसे बड़ी उत्तमता से करता है । इसीलिए प्रत्येक को अपने मन का व्यवसाय पसंद करने का अधिकार होना चाहिए । कोई भी व्यक्ति अपनी जाति धर्म या समुदाय के कारण किसी भी व्यवसाय या सरकारी पद से वंचित न किया जाये । यदि वह उसके योग्य न होगा तो स्वयं ही असफल होगा । इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यवसाय को अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन करने का पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए ।

अन्य नागरिक अधिकार

उपयुक्त मौखिक अधिकारों के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकार भी मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए जरूरी हैं—

प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा

राज्य की ओर से समस्त नागरिकों के बालक बालिकाओं की प्राथ-

मित्र शिक्षा नि शुल्क हो, ऐसा प्रवृत्त होना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी राज्य को प्रोत्साहन देना चाहिए। जा जातियाँ शिक्षा में पिछड़ी हैं उनके लिए शिक्षा का विशेष प्रयत्न होना चाहिए जिससे वे शीघ्र से शीघ्र दूसरी शिक्षित जातियों के समान बन सकें। छानबूतियाँ आदि द्वारा विश्वविद्यालयों में उनके लिए सब प्रकार की सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

आवागमन की स्वतन्त्रता

प्रत्येक नागरिक को राज्य की सीमा में भ्रमण तथा प्रवास का अधिकार होना चाहिए। यदि राज्य की सीमा से बाहर जाना हो तो पासपोर्ट की सुविधा प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए।

सम्पत्ति का अधिकार

प्रत्येक नागरिक का अपनी अर्जित या प्राप्त सम्पत्ति और निजी आवश्यकता की चीज़ों पर व्यक्तिगत स्वामित्व होना जरूरी है क्योंकि इसके बिना उसका जीवन कठिन हो जायगा। परन्तु बड़े-बड़े व्यवसायों, कारखानों, कंपनियों, बैंकों, रेलों, खानों, भूमि आदि पर राज्य या समाज का अधिकार होना चाहिए जिससे उत्पत्ति तथा वितरण की साधना से समस्त समाज लाभ उठा सके और वे किसी व्यक्ति विशेष या समूह की ही वैयक्तिक सम्पत्ति न रहें।

न्याय प्राप्ति

प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि में समान है। इसका अर्थ यह है कानून धनी निर्धन, मजदूर मालिक, शिक्षित अशिक्षित में भेद नहीं मानता। वह सबों के लिए एक-सा है। यदि कोई पूँजीपति भी हत्या का अपराधी है, तो कानून उसे प्राणदण्ड देगा और यदि कोई ग्रेजुएट भी चोरी का अपराधी है तो कानून उस कैद की सजा देगा। किसी साधु राज-

नीतिक दृष्टि से सम्भव है कि वह अपने माता-पिता को उससे माय बाई किया जा सकता है।

भाषा, संस्कृति तथा साहित्य

प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, मातृभाषा, तथा संस्कृति के विनाश के प्रयोग का अधिकार है। वह चाहे तो अन्य भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें उसका बाधा नहीं दी जानी चाहिए।

आहार विहार और आचार विचार की स्वाधीनता

प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि यदि समाज के प्रति नैतिक या दूसरे प्रकार का अपराध न होना हो तो वह अपनी इच्छानुसार भोजन करे, वस्त्रालंकार धारण करे, खेल बूढ़ तथा मनोरंजन करे, तथा अपना रहन सहन रखे। वह अपनी इच्छानुसार विवाह शादी, सन्तान पालन तथा सामाजिक जीवन का पूर्णतया उपयोग कर सकता है।

सार्वजनिक स्थानों और सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार

प्रत्येक नागरिक को सामाजिक नियमों का उल्लंघन न करत हुए सार्वजनिक पार्क, शिक्षणालय, विद्यालय, मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, नदी, तालाब, बाटिका, पार्क, कुआँ, ममस्त सरकारी भवन, म्यूनिसिपल बोर्ड, जिला बोर्ड के दफ्तर आदि के प्रयोग का अधिकार है। किसी भी नागरिक को अपनी जाति, धर्म या रंग के कारण उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति के उपयोग में बाधा नहीं रखनी चाहिए।

समाचारों की गोपनीयता

प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि डाक, तार या फोन द्वारा वह जो पत्र, समाद या समाचार भेजे, वह गुप्त रहे। अर्थात् राज्य की ओर से डाक-तार-विभाग को प्रत्येक नागरिक के पत्र-व्यवहार की गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए। परन्तु युद्ध काल में 'सुरक्षा विभाग' के मामले इस गोपनीयता की रक्षा सम्भव नहीं।

राजनीतिक अधिकार

नागरिक-स्वाधीनता के अन्तर्गत नागरिकों के लिए राजनीतिक अधिकार भी आवश्यक हैं। राजनीतिक अधिकारों और नागरिक-अधिकारों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है क्योंकि दोनों की उत्पत्ति इसी सिद्धान्त के आधार पर हुई है कि राज्य नागरिकों को अपना जीवन सुखी बनाने के लिए समान मुविधाएँ प्रदान करे। राजनीतिक अधिकार मुख्यतः तीन प्रकार के हैं—

(१) मताधिकार (२) प्रतिनिधित्व का अधिकार (३) पदाधिकार

(१) मताधिकार

प्रजातन्त्र राज्य में प्रतिनिधि-संस्थाओं का सबसे अधिक महत्त्व है एक प्रकार से प्रतिनिधि-संस्थाएँ ही प्रजातन्त्र का आधार हैं। इन संस्थाओं का निर्वाचन होता है। इन निर्वाचनों के लिए जो निर्वाचक होते हैं, उनकी योग्यताएँ कानून द्वारा निर्धारित होती हैं। जो निर्वाचक की योग्यता रखते हैं, उन्हें ही मताधिकार प्राप्त होता है। जिन वर्गों में प्रजातन्त्र का अधिक विकास हो चुका है, उनमें प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को मताधिकार प्राप्त है। केवल नाबालिग और उमरत व्यक्ति ही मताधिकार से वंचित रखे जाते हैं क्योंकि वे अपने अधिकार का समुचित प्रयोग नहीं कर सकते।

भारतवर्ष में प्रांतीय एवं वैद्रीय व्यवस्थापक संस्था के लिए कुल ३६ करोड़ स्त्री-पुरुष मतदाता हैं। इस समय भारत की कुल जनसंख्या लगभग ४० करोड़ है। इस प्रकार ३६६ करोड़ जनता को यह महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान् राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में मताधिकार सम्पत्ति और शिक्षा के आधार पर है। यही कारण है कि मतदाताओं की संख्या इतनी कम है।

(२) प्रतिनिधित्व का अधिकार

प्रत्येक निर्वाचक, जिसकी आयु २५ और ३० वर्ष से अधिक हो,

क्रमशः प्रान्तीय असेम्बली और कौंसिल के लिए होनेवाले चुनावों में उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। केन्द्रीय असेम्बली व राज्य परिषद के लिए भी सदस्य की आयु क्रमशः २५ और ३० वर्ष होनी चाहिए।

प्रतिनिधि के लिए शिक्षा सम्बन्धी योग्यता का कोई नियम नहीं है। यही कारण है कि इन राज्य संस्थाओं में पिछले प्रान्तीय चुनावों द्वारा ऐसे भी प्रतिनिधि चुने जाकर गए जो नाममात्र के साक्षर कहे जा सकते हैं।

भारतवर्ष में अब दल की ओर से चुनाव लड़ जाने लगे हैं। भारत में कांग्रेस-दल ही सबसे सुसंगठित और शक्तिशाली है और उसका सम दल दल-ब्यापी है ग्राम-ग्राम में उसके कार्यकर्त्ता मौजूद हैं। यही चुनावों में कांग्रेस की विजय का रहस्य है।

(३) पदाधिकार

प्रान्तीय तथा केन्द्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का जो बहुमत-दल के होते हैं अपना मंत्रिमण्डल बनाने का अधिकार है। भारत में अभी केवल प्रान्तीय क्षेत्र में ही यह अधिकार मिला है। केन्द्रीय शासन तो आज भी सन १९१९ के शासन विधान के अनुसार जारी है।

इसके अतिरिक्त नागरिकों का राज्य की समस्त नौकरियों में नियुक्ति पाने का अधिकार है। प्रत्येक नौकरी के लिए सरकार ने योग्यताएँ निर्धारित कर दी हैं और जब उसे नियुक्ति नहीं करती होती है तब वह प्रान्तीय सर्विस के लिए प्रान्तीय पब्लिक सर्विस कमिशन तथा भारतीय सर्विस के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन की नियोजित की हुई प्रतिपाणिता-परीक्षाओं द्वारा नियुक्ति करती है। प्रत्येक सर्विस में साम्प्रदायिक ढंग पर प्रतिनिधित्व की पद्धति प्रचलित है।

नागरिकों के कर्तव्य

अधिकार और कर्तव्य

पिछले अध्याय में नागरिकों के अधिकारों के संघर्ष में हम विचार कर चुके हैं। परन्तु अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि बिना कर्तव्य-पालन के अधिकारों का उपभोग सम्भव और समुचित नहीं है।

प्रत्येक राज्य या राष्ट्र में नागरिकों का भाषण-स्वाधीनता का अधिकार होता है। वह देश के कानून के अनुसार मर्यादा का पालन करते हुए अपनी इच्छानुसार विचार प्रकट करने में स्वतन्त्र है। परन्तु उसने इस अधिकार के उपभोग के लिए यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि और दूसरे नागरिक उसकी विचार-स्वाधीनता में बाधा न डालें। उनपर किसी बाधा को उपस्थित न होने देने का उत्तरदायित्व ही उस नागरिक के लिए विचार-स्वाधीनता तथा भाषण-स्वाधीनता के अधिकार को जन्म देता है। यदि एक नागरिक एक सभा में या किसी जन-समुदाय में या अपने ग्राम की पंचायत के सदस्य के बीच अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न करे और उसी समय दूसरे नागरिक उसने इस अधिकार के उपभोग में बाधा पहुँचाने के लिए किसी प्रकार से शान्तिभंग कर दें तो यह नागरिक अपने अधिकार का सभी उपभोग नहीं कर सकेगा।

इसने यह सिद्ध है कि जब किसी नागरिक को नागरिकता का कोई अधिकार प्राप्त होता है, तो यह अधिकार ही दूसरों के लिए कर्तव्य बन जाता है। दूसरा का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे उसने प्रयोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न करें।

इस प्रश्न पर एक दूसरे पहलू से भी विचार किया जा सकता है। यदि समाज के सभी सदस्य केवल अधिकारों पर तो और दे पर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करें, तो इसका परिणाम होगा उनके अधिकार-प्रयोग

में सघर्ष । इसके फलस्वरूप समाज का कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक अपने अधिकार का प्रयोग न कर सकेगा ।

भारतीय कर्तव्य शास्त्र में कर्त्तव्यों के साथ-साथ अधिकारों पर भी जोर दिया गया है । जब नागरिक अपने कर्त्तव्यों का सन्घर्ष के साथ पालन करते हैं तभी वे ऐसा वातावरण पैदा करने में सफल हो सकते हैं जिसमें वे अधिकारों का प्रयोग स्वतन्त्र रीति से कर सकें ।

कर्त्तव्य-परायणता की आवश्यकता

समाज सार्वजनिक कल्याण के लिए संगठित जन-समुदाय का नाम है । समाज का निर्माण सब व्यक्तियों के कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हुआ है । अतः यदि समाज का कल्याण वाछनीय और अभिप्रेत है, तो व्यक्तियों को इसके लिए उद्योग करना होगा और समाज के अस्तित्व के लिए व्यक्तियों का जो उत्तरदायित्व है, वही उनका कर्त्तव्य है ।

यदि समाज के व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों का पालन न करें तो समाज का संगठन बना नहीं रह सकेगा । इसी प्रकार यदि किसी नगर या ग्राम के निवासी अपने ग्राम या नगर की व्यवस्था के लिए संगठित होकर अपने कर्त्तव्य का पालन न करें तो उसकी स्थिति बड़ी खराब हो जायेगी ।

समाज में जबतक सब व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का पालन करते रहते हैं, तबतक समाज के लोग सभी प्रकार से सुखी और प्रसन्न रहते हैं और समाज भी उन्नतिशील बनता है । परन्तु जब समाज के व्यक्ति अपने दायित्वों और कर्त्तव्यों के पालन की अवहेलना करके केवल अधिकारों पर ही जोर देते हैं, तब उनका पतन शुरू हो जाता है और अन्त में समूचे समाज की अधोगति हो जाती है ।

भारत में हिंदू-जाति के पनन और परामर्श का कारण भी उसकी कर्त्तव्य परायणता के प्रति उपेक्षा भावना ही है । प्राचीन काल में वैदिक वर्ग व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों के लिए ये कर्त्तव्य निर्धारित किये गये थे —
(१) वेद पढ़ना तथा पढ़ाना—अर्थात् गुरुकुलों द्वारा समाज में विद्या का प्रचार करना ।

- (२) यज्ञ करना तथा करना—अर्थात् समाज के कल्याण के लिए उत्तम और शुभ कर्म करना ।
- (३) दान देना—अर्थात् ब्राह्मण ने अपनी साधना तथा तपस्या से जो ज्ञान सचय विद्या है, उसे जनता को देना । विद्या-दान सर्वोत्तम दान माना गया है ।

इन कर्तव्यों के साथ-साथ ब्राह्मण को यह अधिकार प्राप्त था कि वह दान स्वीकार करे । जनता उसकी सेवाओं के पुरस्कार में अपने श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण को दान-दक्षिणा दे, उसकी भेंट-पूजा करे, उसका आदर जातिधर्म करे । ब्राह्मण अपने इन सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कर्तव्यों के पालन करने पर ही इनसे सम्बन्धित अधिकारों के भोग का अधिकारी बन सकता था । परन्तु जब ब्राह्मणों ने अपने इन कर्तव्यों की उपेक्षा करके सिर्फ दान-दक्षिणा ग्रहण करने पर ही खीर दिया, तब समाज का पतन हो गया । आज यह स्थिति है कि एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय या वैश्य अपने अधिकारों के निमित्त तो सदैव मग्न रहने के लिए सन्नद्ध है, परन्तु अपने कर्तव्यों के बारे में वह कुछ भी नहीं सोचता । इसीलिए तो आज समाज में न नागरिकों को अपने अधिकारों का उपभोग करने की म्यादीनता है और न समाज में मगठन तथा सामंजस्य है ।

कर्तव्यों के प्रकार

कर्तव्य अनेक प्रकार के हैं । उनका वर्गीकरण भी कई प्रकार से किया जा सकता है । हम यहाँ कर्तव्यों को पाँच भागों में विभक्त करते हैं—

- (१) अपने प्रति कर्तव्य,
- (२) अपने परिवार के प्रति कर्तव्य,
- (३) नागरिकों के प्रति कर्तव्य,
- (४) समाज के प्रति कर्तव्य,
- (५) राज्य के प्रति कर्तव्य ।

(१) अपने प्रति कर्तव्य

प्रत्येक नागरिक का सबसे पहले अपने प्रति कर्तव्य है । यह वाक्य

कुछ विचित्र-सा प्रतीत होता है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने प्रति भी कर्तव्य है। वह नागरिक और समाज के प्रति कर्तव्य का पालन ही उसी समय कर सकता है जबकि उसने अपने प्रति कर्तव्यों का पालन कर लिया हो।

प्रत्येक नागरिक को श्रेष्ठ नागरिक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यही उसका निजी कर्तव्य है। श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए आवश्यक है कि वह अपनी शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक शक्तियों के सामंजस्य और पूर्ण विकास के लिए प्रयत्न करे। इसके लिए उसे अपने शरीर का विकास करने की आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ बनाते तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने चरित्र का निर्माण करना है। मानसिक शक्तियों के विकास के लिए उसे विविध ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और आत्मिक विकास के लिए आध्यात्मिक साधना तथा ध्यान एवं चिन्तन की आवश्यकता है।

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि श्रेष्ठ नागरिक ही समाज का एक उपयोगी अंग है, क्योंकि वही समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने में समर्थ हो सकता है।

(२) अपने परिवार के प्रति कर्तव्य

समाज की इकाई व्यक्ति है और यदि समाज के संगठन पर विचार किया जाये तो यह स्पष्ट प्रकट होगा कि समाज का आधार परिवार-समूह है। प्रत्येक व्यक्ति का परिवार में जन्म होता है और परिवार में ही वह पालन-पोषण पाता है तथा उसी में रहकर उसके विचारों का निर्माण होता है तथा वह अपने परिजन की विचारधारा तथा सत्कारों को ग्रहण करके समाज में उपस्थित होता है। इसप्रकार व्यक्ति के निर्माण में परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने माता-पिता के प्रति विशेष कर्तव्य है। हिंदू विधान के अनुसार प्रत्येक पुत्र का यह कर्तव्य है कि वह बचस्क होने पर अपने माता-पिता का भरण पोषण कर, उनका यथावत् सत्कार करे तथा उनकी धर्म सम्मत आज्ञाओं

नहीं हो जाती। उसके अपने पड़ोसिया, बस्ती के वासियो, नगर-निवासियो, ग्रामवासियो तथा देश वासिया के प्रति भी कई कर्त्तव्य हैं।

इनके साथ उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए—किन किन परिस्थितियाँ एवं अवसरों पर उसे कैसा-कैसा व्यवहार करना चाहिए—इसका पूर्ण विवेचन तो कर्त्तव्य-शास्त्र का विषय है। यहाँ इसका पूरा विवेचन सम्भव नहीं है। अतः हम यहाँ केवल उन सामान्य और आधार-भूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में ही विचार करने का प्रयत्न करेंगे जिनके आधार पर इन नागरिकों के साथ सम्बन्ध स्थिर करना उचित है।

समाज में समता, प्रेम तथा सहानुभूति की प्रतिष्ठा के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक नागरिक दूसरे नागरिकों के साथ भाई के समान व्यवहार करे। दूसरे शब्दों में उसे भ्रातृभाव की वृद्धि के लिए उद्योग करना चाहिए। भ्रातृभाव के साथ-साथ नागरिक में सेवा की भावना का होना भी उचित है। कोई भी कार्य इस भावना से नहीं करना चाहिए कि वह किसी दूसरे के साथ उपचार कर रहा है। ऐसा विचार ही मिथ्या अहंकार का जन्मदाता है और अहंकार सच्ची सेवा के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। प्रत्येक नागरिक को अपनी योग्यता के अनुसार अपनी सेवा का क्षेत्र चुनने की सुविधा होनी चाहिए। नागरिक के व्यवहार में शिष्टता तथा सहानुभूति का होना परम आवश्यक है। सहानुभूति के द्वारा ही वह नागरिक व समाज की सेवा करने में समर्थ हो सकता है। सेवा के लिए सहानुभूति एक प्रकार की मार्ग-प्रदर्शिका है। प्रत्येक नागरिक को ग्राम, नगर तथा अपने मुहल्ले में शान्ति तथा एकाग्रता बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। साधारण-सी गलत-फहमियाँ तथा घटनाओं को लेकर साम्प्रदायिक उपद्रव हो जाते हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इन उपद्रवों से समाज की वित्तीय हानि होती है। नागरिकों का यह कर्त्तव्य है कि वे ऐसी गलतफहमियों को दूर करने का संगठित रूप से उद्योग करें तथा मामूली विवादों को शीघ्र ही आपसी समझौते द्वारा तय कर दें जिससे वे भयंकर उपद्रवों का रूप ग्रहण न करें। यदि नागरिक सहनशीलता से काम ले तो ऐसे झगड़े

और उपद्रव बड़ी आसानी से घान्त किये जा सकते हैं। सहनशीलता वास्तव में मानवता का एक अमूल्य रत्न है। इसके अभाव में मानवीय सुगुणों का विकास होना सम्भव नहीं और न इससे समाज का संगठन ही कायम रह सकता है। नागरिक का यह भी कर्तव्य है कि वह दूसरे नागरिकों के जीवन तथा सम्पत्ति का भी वैसा ही आदर करे जैसा कि अपने जीवन व सम्पत्ति का करता है।

राज्य ने प्रत्येक नागरिक को आत्म-रक्षा (Self defence) का अधिकार दिया है। परन्तु उस अधिकार के साथ यह कर्तव्य लगा हुआ है कि वह दूसरे के जीवन व सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा भी करे। जनता की जा सार्वजनिक सम्पत्ति हो—जैसे बाग, पार्क, तालाब, कूप पाठशाला, धर्मशाला—उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

जीवन में इस महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धान्त का सदा, सर्वथा, सर्वत्र पालन होना आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को दूसरे नागरिकों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे व्यवहार की वह अपने प्रति उनसे आशा रखता है। इस नियम पर चलने से समाज के व्यक्तियों में कभी किसी विषय पर संघर्ष नहीं हो सकता और जीवन के सब काम बड़ी सरलता से चलते रह सकन हैं।

(४) समाज के प्रति कर्तव्य

हमने नागरिकों के कर्तव्यों के सबन्ध में ऊपर जो निवेदन किया है, वह केवल व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक नागरिक के ही लिए है। नागरिक के कुछ कर्तव्य ऐसे भी हैं जिन्हें वह दूसरों के सहयोग से पूरा कर सकता है। ऐसे कर्तव्य समाजात होते हैं। इनके पालन से समूचे समाज का कल्याण होता है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह दूसरे नागरिकों के साथ सहयोग-पूर्वक समाज के संगठन में भाग ले। समाज के उत्कर्ष के लिए उसे राज्य की ओर से कई प्रकार के संगठन निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार का प्रयोग वह समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, व्यापारिक,

बीजोगिक, आर्थिक, मानसिक, स्वास्थ्य-विषयक आदि अनेक प्रकार की उन्नति के लिए कर सकता है।

नागरिकों का वर्तव्य है कि वे विविध उन्नति के लिए समाज-सघ, स्वास्थ्य-सघ, साहित्य परिषद्, नाट्य-परिषद्, शिक्षा-परिषद्, विज्ञान-परिषद्, व्यवसाय-परिषद्, उद्योग-सघ, नगर-सघ, ग्राम-सुधार सघ, मनोरंजन-गृह, महिला-सघ, राजनीतिक परिषद् और आध्यात्मिक परिषद् आदि सगठनों की स्थापना करे। इनमें उन्हें समान रूप से भाग लेना चाहिए और यथाशक्ति उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी योग्यतानुसार प्रयत्न करना चाहिए।

(५) राज्य के प्रति कर्तव्य

जिस प्रकार राज्य ने नागरिकों की सुख-सुविधा के लिए उन्हें अधिकार प्रदान किये हैं, उसी प्रकार नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि वे उसके प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने का प्रयत्न करें। राज्य और नागरिकों का सवन्ध पारस्परिक सहकारिता की भावना पर ही निर्भर है। राज्य का आविर्भाव ही इसलिए हुआ है कि नागरिक सुख और शान्ति से जीवन व्यतीत कर सकें। राज्य का विकास, इस प्रकार, नागरिकों के सहयोग तथा सामाजिक कल्याण की भावना का ही फल है।

राज्य में शासन और नागरिक उसके सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। शासन का आविर्भाव भी इसी कारण हुआ है कि नागरिकों की सामाजिक व्यवस्था का उचित रीति से नियमन और संचालन हो सके। प्रजातन्त्र-शासन-प्रणाली के अन्तर्गत शासन का निर्माण नागरिकों की आपाधा के अनुसार होता है। इसी आपाधा की अभिव्यक्ति के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रणाली का विकास हुआ।

प्रतिनिधियों का चुनाव

प्रजातन्त्र-शासन-प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक वयस्क स्त्री-पुरुष को, जिसकी आयु १८ वर्ष या इससे अधिक हो, शासन-संस्थाओं के लिए प्रतिनिधि

चुनने का अधिकार प्राप्त है। ससार के अनेक देशों में जनता को वयस्क-मताधिकार प्राप्त है, परन्तु भारतवर्ष में ४० करोड़ की जन-संख्या में सिर्फ ३-४ करोड़ नागरिकों को मताधिकार प्राप्त है।

मताधिकार एक बहुमूल्य अधिकार है, परन्तु अज्ञान के कारण नागरिक इसके महत्त्व को नहीं समझते। जो लोग वयस्क नहीं हैं, उन्हें यह अधिकार इसलिए नहीं दिया गया है कि उनकी विवेक-बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि वे अपने कर्तव्य का उचित रीति में पालन कर सकें। अतः वयस्क मतदाताओं का यह कर्तव्य है कि वे लोगों की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए ऐसे किसी उम्मीदवार को मन न दें, जो उसके अधिकारी नहीं है।

मतदाताओं का कर्तव्य है कि वे ऐसे देशभक्त, देश-हितैषी, विचारवान्, विद्वान्, सदाचारी जनसेवक को अपना मत दें जो वास्तव में उनके सामूहिक हित के लिए कार्य करने में समर्थ हो। चुनावों के समय नागरिक इस अवधि में जैसा व्यवहार करते हैं उसी का यह दुष्परिणाम है कि योग्य, विद्वान् और सच्चे सेवक बहुत कम प्रतिनिधि चुने जाते हैं। देखने में आता है कि स्वार्थी, चरित्रहीन या सामाजिक हितों के विरोधी उम्मीदवार प्रतिनिधि-संस्थाओं में चुन लिये जाते हैं। चुनावों के समय उम्मीदवारों की ओर से बल-प्रयोग किया जाता है और मत-दानाओं की तरह-तरह के प्रलीभन दिये जाते हैं। इस प्रकार उम्मीदवार तो भ्रष्ट होने ही हैं, वे अपना दूष्प्रभाव मतदाताओं पर भी डालते हैं।

प्रतिनिधियों के कर्तव्य

प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे शासन-परिषदों तथा प्रतिनिधि-सभाओं में जाकर समाज के हित के लिए उपयोगी कार्य करें। उन्हें अपने क्षणिक व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए सामाजिक हितों पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। प्रतिनिधियों का यह भी कर्तव्य है कि वे अपने-अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में समय-समय पर भ्रमण किया करें और अपने मतदाताओं ही नहीं प्रत्युत सभी नागरिकों की असुविधाओं, कष्टों

तथा शिकायतों की जाँच करके उनके निवारण का उचित प्रबंध करे। इसप्रकार मतदाताओं तथा नागरिकों के साथ सम्पर्क स्थापित करके वे वास्तव में उनकी आकांक्षाओं को जान सकेंगे और तदनुसार धारासभाओं में कार्य भी कर सकेंगे।

प्रतिनिधियों का मुख्य कर्तव्य तो यह है ही कि वे नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक और औद्योगिक उन्नति के लिए उपयोगी कानून बनवाने के लिए प्रयत्न करे।

शासन-प्रबंध में सहयोग

प्रजासत्त-शासन-प्रणाली के अन्तर्गत शासन-प्रबन्ध नागरिकों के लिए, नागरिकों की इच्छा से, नागरिकों द्वारा होता है। इसलिए प्रजासत्त में प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है और इसीलिए उसका यह कर्तव्य भी है कि वह शासन-प्रबन्ध के कार्य में योग दे। शासन-प्रबन्ध के कार्य में तीन प्रकार से सहयोग दिया जा सकता है—

- (१) प्रतिनिधि के रूप में धारासभाओं में भाग लेकर और मन्त्रि-मण्डल का सदस्य बनकर शासनकार्य में प्रत्यक्ष भाग लिया जा सकता है। धारासभा का सदस्य बनकर उपयोगी कानून बनाकर सहयोग किया जा सकता है।
- (२) शासन-प्रबन्ध के विविध विभागों—शिक्षा-विभाग, स्वास्थ्य-विभाग, स्थानीय स्वायत्त विभाग, अर्थ-विभाग, ग्राम-सुधार विभाग, पुलिस-विभाग आदि—में पदाधिकार प्राप्त करके शासन-संचालन के कार्य में योग दिया जा सकता है।
- (३) सामान्य नागरिकों को चाहिए कि वे उपर्युक्त प्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों के वैध कार्यों में योग दें।

कानून-निर्माण में नागरिकों का योगदान

कानून धारासभाओं में बनाये जाते हैं। इन सभाओं में नागरिकों के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। परन्तु प्रजासत्त-प्रणाली के अन्तर्गत

मतदान-नागरिकों को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसे अंग्रेजी में Initiative कहते हैं और धारासभाओं द्वारा स्वीकृत कानूनों पर भी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है। स्वीजरलैण्ड तथा अमरीका में नागरिकों को ये दोनों अधिकार प्राप्त हैं।

राज्य के कानूनों का पालन

नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे राज्य के शासन-विधान के तथा दूसरे कानूनों का पालन कर। प्रजातन्त्र-राज्य में बहुमत द्वारा शासन होता है और धारासभा में भी प्रत्येक कानून बहुमत की राय से बनाया जाता है। इसलिए समस्त देश उस कानून से बाध्य हो जाता है। जब कानून बन चुकता है तब समस्त जनता का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उसका सद्भावना के साथ पालन करे।

अब प्रश्न यह है कि यदि धारासभाओं और सरकार द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो समाज के लिए या उसके किसी वर्ग के लिए घातक है, तो क्या उस कानून के विरोधियों का यह कर्तव्य है कि वे कानून की अवज्ञा कर? इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रत्येक प्रजातन्त्र राज्य में नागरिकों को यह अधिकार है कि वे किसी भी कानून तथा सरकार के कार्य की आलोचना कर सकते हैं और उसके प्रति विरोध-प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन बंध (न्यायोचित) माने जाते हैं। इन प्रदर्शनों का उद्देश्य है लोकमत द्वारा सरकार को यह बताना कि उसने जो कानून बनाया है वह समाज या किसी विशेष वर्ग के लिए घातक है जिससे सरकार उसमें संशोधन का प्रयत्न कर सके।

परन्तु कानून की अवज्ञा करना तो देश के विधान के अनुसार अपराध है। सत्तार के किसी भी सम्य राज्य के विधान ने नागरिकों को यह अधिकार नहीं दिया है। सोवियत प्रजातन्त्र-संघ के शासन-विधान में भी संघ नागरिक-संघ के विधान और उसके कानूनों को मानते, थम के अनुशासन को कायम रखने, सार्वजनिक कर्तव्य का आदर करने और समाजवादी सत्ता (सोसाइटी) के नियमों का पालन

करने के लिए बाध्य है ।^१

परन्तु भारतवर्ष की स्थिति दूसरे प्रजातन्त्र राज्यों से भिन्न है । न तो भारत में पूर्ण प्रजातन्त्र राज्य है और न यहाँ नागरिकों की आकांक्षा के अनुसार शासन ही होता है । इसलिए यह कहना कठिन है कि सरकार द्वारा जो कानून प्रचलित हैं वे प्रजा की आकांक्षा को अभिव्यक्त करते हैं ।

इसीलिए महात्मा गांधी भारतवर्ष में २२ वर्ष से सविनय अवज्ञा (Civil Disobedience) आन्दोलन का संचालन कर रहे हैं । उनका यह मत है कि यदि कोई कानून अनैतिक है, तो प्रजा की यह अधिकार है कि वह उसकी अवज्ञा करे । परन्तु अवज्ञा अहिंसात्मक होनी चाहिए । सन् १९१९ में गांधीजी ने रोलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह—सविनय अवज्ञा—आन्दोलन किया और सन् १९३० में नमक कानून जंगल कानून आदि के विरोध में । इस समय वह भारत रक्षा कानून (Defence of India Act) के विरोध में युद्ध विरोधी सत्याग्रह का संचालन कर रहे हैं । महात्मा गांधी ने लिखा है—

‘यह तो हम अधम बंश में पड़े हुए हैं इससे मान लेते हैं कि कानून में जो कुछ हो उसे मानना हमारा कर्तव्य है । अगर मनुष्य एक बार इस बात को महसूस करले कि अनुचित ज्ञान पढ़नेवाले कानूनों का पालन करना नामर्बी है, तो फिर किसी का जुल्म उसे सजबूर नहीं कर सकता । यही स्वराज्य की कुञ्जी है ।’

शान्ति-रक्षा में सहयोग

प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की शान्ति की रक्षा में राज्य के अधिकारियों की सहायता करे और उन्हें सहयोग दे । सरकार ने शान्ति रक्षा तथा अपराधों के अवरोध तथा अपराधों की

१ सोवियट प्रजातन्त्र संघ का विधान

२ महात्मा गांधी, ‘हिंद स्वराज्य’ (हिंदी संस्करण १९३९) पृ० १४८

१. जाँच के लिए पुलिस-विभाग की स्थापना की है। समस्त देश में प्रत्येक जिले तथा तहसील और यहाँ तक कि ग्राम में भी पुलिस के कर्मचारी होते हैं। परन्तु पुलिस के कर्मचारी नागरिकों की सहायता के अभाव में न तो शान्ति-रक्षा ही कर सकते हैं और न अपराधों की जाँच ही कर सकते हैं। अतः नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे शान्ति की रक्षा तथा राजद्रोह, घड़मूढ, हत्या, छूटमार, डकैती, चोरी, आग लगाना तथा अन्य अपराधों उनके अपराधियों की जाँच के मन्त्र में पुलिस का सहायता दें।

राज्य-कोष में कर तथा लगान आदि देना

राज्य के शासन का संचालन प्रजा द्वारा दिये गये कर, लगान आदि के रूप में आये हुए धन से ही होना है। यदि राज्य के पास इन साधनों के द्वारा पर्याप्त कोष प्राप्त नहीं होता तो वह लोकप्रयोगी धारों की ठीक प्रकार से करने में असमर्थ रहता है। इसलिए नागरिकों का कर्तव्य है कि वे ठीक समय पर निर्धारित टैक्स, माँगुजारी आदि सरकार को देत रहें। यदि सरकार कोई ऐसा कर लगाती है जो प्रजा पर भार है अथवा जो उचित नहीं है तो प्रजा का यह कर्तव्य है कि वह उसका विरोध करे।

स्वदेश-रक्षा

प्रत्येक देश के नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे वाह्य आक्रमणा से स्वदेश की रक्षा के कार्य में अपने देश की सरकार की धन, जन आदि से पूरी सहायता करें। इसीलिए बहुत से देशों में नागरिक सेनाएँ होती हैं। सोवियट राज्य में अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम है। इसी प्रकार मुद्र काल में प्रत्येक विग्रही राष्ट्र में अनिवार्य सैनिक सेवा का नियम प्रचलित हो जाता है। इस सम्बन्ध में मतभेद पाया जाता है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि अनिवार्य सैनिक-सेवा का नियम नैतिकता और नागरिक स्वाधीनता की भावना के विरुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है और

उमसे जबरदस्ती फौज में सैनिक का काम कराना उचित नहीं।

दूसरा मत यह है कि देश की स्वाधीनता की रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को सैनिक सेवा करनी चाहिए। ऐसा करना उसका कर्तव्य ही नहीं धर्म भी है। यदि अनिवार्य सेवा का नियम न रखा जाये तो नागरिक रक्षा के कार्य में सक्रिय भाग न लेना चाहेंगे।

इस सम्बन्ध में हमारा मत यह है कि नागरिकों में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वे स्वदेश के लिए सदैव प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर रहें। ऐसी दशा में वे स्वयं-सेवक सेना तैयार करने का प्रयत्न स्वयं ही करेंगे।

कर्त्तव्यकर्त्तव्य का निर्णय

व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब नागरिकों को यह निर्णय करना बड़ा कठिन जान पड़ता है कि क्या कर्त्तव्य है और क्या अकर्त्तव्य है? ऐसे अवसरों पर उन्हें क्या करना चाहिए—यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है।

जब कभी इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाये तब उन्हें यह विचार करना चाहिए कि जिस कार्य के करने से अधिक हित साधन हो, समाज का लाभ हो, यही करना उचित है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि इस प्रकार के निर्णय में त्याग तथा बलिदान की भावना का प्राधान्य होगा।

श्री भगवानदास केला ने इस सम्बन्ध में लिखा है —

“जिन कार्यों में भेदभाव न रखकर, समता का आदर्श रखा जाता है, जिनमें हम अपनी आत्मा की विशालता का अनुभव करते हैं, जिनमें स्वार्थ-परार्थ का प्रश्न नहीं उठता वे ही कर्त्तव्य हैं। इसके विपरीत जिन कार्यों से भेदभाव की उत्पत्ति होती है, अपने परार्थ का विचार होता है, अपना सुख दुःख मुख्य समझा जाता है, जिनमें आत्मा के विस्तार की भावना न रख कर, उसे परिवार या नगर आदि के सीमित क्षेत्र में परिमित रखा जाता है, वे अकर्त्तव्य हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि

हमारा अपने परिवार या नगर आदि के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। नहीं नहीं जैसा कि अन्यत्र बताया गया है, हमारा कर्तव्य तो स्वयं अपने प्रति भी है। हाँ हमें दूसरों के हित को न भूलना चाहिए।^१

श्री के.जी. ने जो सिद्धान्त उपर्युक्त अवतरण में स्थिर किया है, वह वास्तव में नागरिक जीवन के लिए एक उच्च मानवीय आदर्श है। इस सिद्धान्त के समुच्चय प्रकाश में नागरिकगण कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय यही आसानी के साथ कर सकेंगे।

१ श्री भगवानदास के.जी. 'नागरिक-शास्त्र' (१९३२) पृ० ३१४

प्रजातन्त्र

प्रजातन्त्र क्या है ?

प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्व यह भली भाँति जान लेना चाहिए कि प्रजातन्त्र केवल राजनीतिक सिद्धान्त एवं पद्धति ही नहीं है बल्कि वह एक सामाजिक सिद्धान्त और प्रणाली भी है। प्रजातन्त्र का अर्थ है वह सिद्धान्त या शासन प्रणाली जिसके अनुसार राज्य की शासन मत्ता उसने किसी एक व्यक्ति या वर्ग में निहित न होकर समाज के प्रत्येक सदस्य में निहित होनी है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का शासन सम्पूर्ण समाज के सदस्यों की सम्मति से होता चाहिए। प्रसिद्ध राजनीतिक लेखक श्री जम्स ब्राइस का कथन है कि सरकारी या संचालन लोकमत द्वारा होता है। चाहे शासन प्रणाली प्रजातन्त्र हो अथवा एक-तन्त्र या अभिजात-तन्त्र अथवा अधिनायक-तन्त्र सभी प्रकार की शासन-पद्धतियाँ में शासन जनता की इच्छा से ही होता है।

प्रजातन्त्र और स्वेच्छाचारी शासन-तन्त्र में अंतर यही होता है कि पहली प्रणाली के अंतर्गत प्रजा यह अनुभव करती है कि सत्ता उसके पास है सरकार का निर्माण उसी ने किया है और शासक प्रजा के आदेश का पालन करते हैं—अर्थात् शासन प्रजा की इच्छा के अनुसार होता है। दूसरी प्रणाली में प्रजा शासक की आज्ञा का पालन करती है, वह यह अनुभव नहीं करती कि उसका निर्माण उसी ने किया है। इस प्रकार वह शासक की आज्ञा का पालन करती है। दोनों में लोकमत की इच्छा से ही शासन होता है। अंतर केवल इतना है कि प्रजातन्त्र में लोकमत स्वतन्त्र होता है और वह अपनी इच्छा से शासन का निर्माण करता है, दूसरी ओर एक-तन्त्र या अधिनायक-तन्त्र में लोकमत अधिनायक या स्वेच्छाचारी शासक की सत्ता के भय या आतंक से उसका समर्थन करता है।

प्रजातन्त्र भारत के लिए नयी वस्तु नहीं है। यद्यपि प्राचीन भारत में आधुनिक ढंग की प्रजातन्त्र-प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, तो भी यह प्रमाणित हो चुका है कि वैदिक राजा या हिन्दू नरेश स्वेच्छा-चारी शासक नहीं होता था। प्राचीन काल में राजा का प्रजा की राज्य-समिति द्वारा चुनाव होता था।^१ राजा को मन्त्रि-परिषद् की सम्मति से शासन संचालन करना पड़ता था। मन्त्रि-परिषद् के बहुमत का राजा आदर करता था।^२ राजा के कर्तव्यों का विधान धर्म-शास्त्रों में प्रति-पादित होता था और उसके अनुसार ही उसे कार्य करना पड़ता था। प्रजा राजा की केवल धर्मपुत्र भाज्याओं को ही मानने के लिए बाध्य थी।^३ प्रजा को राजा के चुनने का अधिकार था परन्तु वह उसे अधि-कार-व्युत् भी कर सकती थी। राजा को प्रजा की सम्मति से कर मसूल करने का अधिकार था और वह पुलिस, सेना, सिविल सर्विस तथा राज्य के अन्य कार्यों का संचालन जाति मन्त्र, परिषदों या पंचायतों द्वारा करता था। उस समय आज जैसी वैधानिक परम्परा, पार्लियमेंटरी प्रणाली और उत्तरदायी शासन नहीं था। परन्तु ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिनसे यह सिद्ध है कि प्राचीन काल में भारत में प्रजातन्त्र संस्थाएँ मौजूद थीं और मन्त्र-शासन प्रणाली का भी विकास हो चुका था।^४

प्रजातन्त्र के प्रकार

आधुनिक काल में प्रजातन्त्र के दो प्रकार हैं। एक प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र और दूसरा परोक्ष प्रजातन्त्र। प्राचीन यूनान और रोम में राज्य छोटे

१. 'अथर्व वेद' हर्षद्वं ओरियण्टल सीरीज।

२. आत्मधिके कार्ये मन्त्रिणो मन्त्रिपरिषद् चाहूय ब्रूयात्। ६३

तत्र यद्भूमिष्ठा कार्यसिद्धिकरवा ब्रूयुस्तत्कुर्यात्। ६४

—कीटल्य अर्थशास्त्र अधिकरण १; अ० १५

३. 'हिन्दू राजनीति'. स्व० काशीप्रसाद जायसवाल।

छोटे नगरों के रूप में होने थे, इसलिए उन युग में यह संभव था कि राज्य के समस्त नागरिक स्वयं शासन प्रणाली में भाग ले सकें। परन्तु आज के राष्ट्र-राज्य में जिनकी जनसंख्या ६ करोड़ से ३५ और ४० करोड़ तक होती है, प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेना सब नागरिकों के लिए संभव नहीं। इसीलिए सदियों पूर्व प्रतिनिधि या परोक्ष-प्रजातन्त्र का विकास किया गया था।

प्रतिनिधि-प्रजातन्त्र का अर्थ यह है कि नागरिक अपने प्रतिनिधियों को अपना शासनाधिकार सौंप देते हैं और प्रतिनिधि अपने निर्वाचनों द्वारा सौंपे गये अधिकार का प्रयोग उनकी इच्छानुसार करते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि प्रजातन्त्र में प्रजा की इच्छा से शासन होता है। निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य की धारासमाओं में शासन-विधान का निर्माण करते हैं और फिर उसी के द्वारा राज्य का शासन होता है।

आधुनिक काल में प्रजातन्त्र के दो मुख्य उदाहरण विद्यमान हैं—अंग्रेजी प्रजातन्त्र और अमरीकन प्रजातन्त्र। अंग्रेजी प्रजातन्त्र को पार्लिमेंटरी या उत्तरदायी शासन-प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत दल द्वारा शासन का निर्माण होता है। जो पार्लिमेंट में बहुमत का नेता होता है, उसे सरकार बनाने का अधिकार होता है। अतः सरकार बहुमत के द्वारा पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी होती है। संयुक्त राज्य अमरीका में प्रमुख शासक (Chief Executive) ममस्त राज्या के निर्वाचकों द्वारा चुना जाता है। उसे संयुक्तराज्य अमरीका की धारा मभा (कांग्रेस) द्वारा सामायतया पद-च्युत नहीं किया जा सकता।

प्रजातन्त्र का आधार

प्रजातन्त्र का आधार क्या है? ईश्वर ने मनुष्यों को स्वतन्त्र पैदा किया है। वे किसी बंधन में नहीं हैं। ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान पैदा किया है। सभी मनुष्यों को पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ

दी है। उन्हें मस्तिष्क और हृदय भी दिया है। वे अपनी मानसिक एवं शारीरिक शक्तियाँ के विवास से अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। यह तो स्वयंसिद्ध है कि मनुष्य अपनी समस्त शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियाँ का सामञ्जस्यपूर्ण विवास केवल स्वाधीन दशा में ही कर सकता है। यदि वे बंधन में रहे, तो उनका विकास स्वाभाविक ढंग से न हो सकेगा। यह भी स्वयंसिद्ध है कि मानव जीवन का लक्ष्य शांति और आनन्द की प्राप्ति है। अतः राज्य और समाज को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें रहकर समस्त मानव अपने इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरस्कार्य कर सकें। जिस समाज में कानून की व्यवस्था एवं नियमन ही सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होगी, उसमें जैसा जनता आनन्द-प्राप्ति के प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। अतः इसका निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने समाज, राष्ट्र या राज्य की नीतियों के निर्माण में भोग देना आवश्यक है, क्योंकि जबरनक सभी मनुष्यों को अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का सुयोग नहीं मिलेगा, तबतक समाज या राज्य यह निर्णय नहीं कर सकेगा कि समाज या राज्य के लिए कौनसे नियम हितकारी हैं अथवा किन नियमों के पालन न करने से समाज को हानि है? यत्, प्रजातन्त्र का यही आधार है।^१

अमरीका की स्वाधीनता की घोषणा में जो सन् १७७६ ई० में की गयी थी यह घोषित किया गया था—

“हम इन सरपों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा किये गये हैं। सृष्टिकर्ता ने उन्हें कुछ जन्म सिद्ध अधिकार प्रदान किये हैं। इन अधिकारों में जीवन-स्वाधीनता और आनन्द प्राप्ति के अधिकार शामिल हैं। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकारों की स्थापना की गयी है। इन सरकारों को जो सत्ता प्राप्त है उसका आदि-भूत जनता ही है।”

१ 'प्रजातन्त्र के मौलिक तत्त्व': रामनारायण 'यादवेन्दु' - 'विदर्भमित्र'
मासिक, अगस्त १९४०

अगस्त सन् १७९१ ई० में फ्रांस की राष्ट्रीय परिषद् ने मानव-अधिकारों की घोषणा इस प्रकार की—

“अपने अधिकारों के सम्बन्ध में मनुष्य समान पैदा हुए है।” राजनीतिक समाज का उद्देश्य मनुष्य के जन्मसिद्ध तथा प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। ये अधिकार हैं नागरिक-स्वाधीनता, सम्पत्ति की सुरक्षा और व्यत्याचारों का विरोध।”

“समस्त प्रभुता का सिद्धांत राष्ट्र में निहित है। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता जो स्पष्ट रूप से राष्ट्र से प्राप्त न हुई हो।” समस्त नागरिकों को व्यवस्थित रूप से या प्रतिनिधियों द्वारा कानून बनाने के लिए इकट्ठे होने का अधिकार है। कानून की दृष्टि में बराबर होने के कारण वे समान हैं। वे उन समस्त पदों व सम्मानों के अधिकारी हैं।”

प्रजातन्त्र के तत्त्व

प्रजातन्त्र के तीन मूल सिद्धान्त हैं—नागरिक-स्वाधीनता, समानता, और बहुत्व। वास्तव में नागरिक-स्वाधीनता प्रजातन्त्र का प्राण है। इसके बिना प्रजातन्त्र की कल्पना संभव नहीं है। प्रजातन्त्र-राज्य में नागरिक-स्वाधीनता को इतना अधिक महत्त्व प्राप्त है कि उसके शासन-विधान में सबसे प्रमुख स्थान नागरिकता के मौलिक अधिकारों की घोषणा को दिया जाता है। नागरिक-स्वाधीनता में निम्न-लिखित तत्त्व शामिल हैं—विचार-स्वाधीनता, मत-प्रकाशन की स्वाधीनता, भाषण-स्वाधीनता, समा-संगठन की स्वाधीनता, व्यक्तित्व की स्वाधीनता, शरीर स्वाधीनता, धार्मिक स्वाधीनता, आर्थिक स्वाधीनता, राजनीतिक स्वाधीनता। इनका विस्तृत विवेचन आठवें अध्याय में किया जा चुका है।

प्रजातन्त्र का दूसरा प्रमुख तत्त्व है समानता। सब मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं। इसलिए राज्य को चाहिए कि वह भी कानून की दृष्टि में सबको समान माने और उनके साथ समानता का व्यवहार करे।

होना चाहिए और नागरिका को प्रजातंत्र के आदर्शों एवं व्यवहारों का ज्ञान कराया जाये।

इस प्रकार का प्रजातंत्रवादी समाज ही सच्चे प्रजातंत्र राज्य का विकास सफलतापूर्वक कर सकता है।

प्रजातन्त्र शासन के गुण

(१) प्रजातन्त्र शासन का सबसे बड़ा गुण तो यह है कि जनता या शासन जनता की इच्छा से उसके चुने हुए प्रतिनिधियों की राज्य सभाओं द्वारा होता है। इस प्रकार राज्य प्रबंध पर लोकमत का नियंत्रण रहता है। राज्य के बहुमत दल का शासन होता है और यह दल पालमट के द्वारा प्रजा के प्रति उत्तरदायी होता है।

(२) प्रजा की इच्छानुसार शासन होने के कारण यह शासन-प्रणति स्थायी है राजतंत्र या अधिनायक-तंत्र की भाँति अस्थायी नहीं।

(३) प्रजातंत्र में जनता यह अनुभव करती है कि उसी ने शासन की रचना की है और जो कानून शासन सभाओं द्वारा बनाये जाते हैं वे उसी की इच्छा से बनाये जाते हैं। इसलिए जनता राज्य के कानून का स्वेच्छा से पालन करती है।

(४) जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा होता है। स्वराष्ट्र की रक्षा के लिए नागरिक स्वेच्छा से बड़ से बड़ा बलिदान करने को उद्यत रहते हैं।

(५) प्रजातंत्र राज्य में विविध राजनीतिक या सामाजिक वर्गों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। अतः वे परस्पर भयर्ष नहीं करते।

(६) प्रजातंत्र में जनता की इच्छा से शासन होना है इसलिए भीषण राज्यत्रान्ति की समाप्ति कम होती है। रक्तपातपूर्ण नान्तिर्या सदैव ऐसे राज्यों में होती है जिनमें लोकमत का दमन करके शासन चलाया जाता है।

(७) प्रजातंत्र में शासन वर्त्ता स्वेच्छाचारिता का प्रदर्शन नहीं कर सकते और न वे 'यापालय' के बापों को छीनकर स्वयं 'याय' की व्यवस्था कर सकते हैं।

(८) प्रजातन्त्र में जनता की नागरिक-शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग मिला है। वह सार्वजनिक प्रश्नों के सचय में दिलचस्पी लेती है। उसमें सार्वजनिक हित के प्रश्न पर अपना स्वतन्त्र मत प्रकट करने की क्षमता होती है।

प्रजातन्त्र-शासन के दोष

प्रजातन्त्र-शासन में जहाँ इतने गुण हैं वहाँ उसमें—ससकी प्रणाली कुछ दोष भी हैं जिनमें से निम्नलिखित विशेष उल्लेखनीय हैं—

- १) प्रजातन्त्र की शासन-संस्थाएँ मन्द गति से ही अपना कार्य-संचालन कर सकती हैं। किसी प्रश्न पर, आवश्यकता के समय, शीघ्रता से निर्णय करने की सुविधा कम होती है।
- २) लोकमत की प्रगतिशीलता के कारण जनता के विचारों में परिवर्तन होता रहता है। किसी भी सार्वजनिक प्रश्न पर मन्त्रि-मण्डल में अथवा पार्लिमेंट में मतभेद होजाने से सरकारें त्यागपत्र दे देती हैं। फिर नये चुनाव होते हैं। इस प्रकार शासन कार्य में अव्यवस्था बहुत होती रहती है।
- ३) प्रजातन्त्र-प्रणाली में बहुमत जब अल्पमत के विचारों का आदर नहीं करता तब अल्पमत अनेक प्रकार के विवाद तथा उपद्रव पैदा करता है। यह विवाद और सभ्य पार्लिमेंट या धारासभा के सदस्यों तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि अल्पमत जनता पर भी अपना प्रभाव डालता है और जनता में उपद्रव और विद्रोह खड़े हो जाते हैं।
- ४) प्रजातन्त्र में जनता में नवीन आदर्शों, नवीन भावनाओं तथा नयी विचारधाराओं के कारण नवीनता के प्रति विशेष आकर्षण हो जाता है। इस प्रकार जनता में प्राचीन संस्थाओं को नष्ट करने और उनकी जगह नयी संस्थाएँ खड़ी करने का एक रिवाज-सा चल पड़ता है।
- ५) प्रजातन्त्र में प्रचार या प्रोपेगन्डा एक महान् शक्ति है। प्रत्येक

राजनीतिक दल नियमित रूप से अपने सिद्धांतों एवं कार्यों का जनता में प्रचार करता है। जिस दल के पास प्रचार का अच्छा साधन होता है, वह चाहे प्रजा का उनका हितपी दल न हो, तब भी अपने प्रापेण्डा की बढ़ती चुनावों में विजय प्राप्त कर लेता है। प्रापेण्डा से जहाँ लाभ है, वहाँ हानियाँ भी अनेक हैं। प्रापेण्डा की अधिकता का जनता पर घुरा प्रभाव पड़ता है। वह किसी भी प्रश्न को स्वतंत्र बुद्धि से माचने की क्षमता खो बैठती है।

(६) प्रजातंत्र में शिक्षा के अभाव के कारण जब अधिकांश जनता अज्ञानी और अशिक्षित होती है तब अयोग्य, स्वार्थी तथा अवसरवादी व्यक्ति नेता बन बैठते हैं। जब ऐसे लोगो के हाथ में शासन सत्ता आ जाती है तब वे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्वाचनों में रिश्वतखोरी का बड़ा आतंक रहता है।

(७) प्रजातंत्र राज्य प्रणाली के साथ सारी जनता सहयोग करने को प्रस्तुत रहती है तो भी अत्यन्त विचारशील पुरुष, तत्पक्षेता, महान् धर्मात्मा अथवा अत्यन्त उच्च श्रेणी के महापुरुषों के लिए प्रजातंत्र में कोई खास आकर्षक या उत्तेजक बात नहीं होती।

प्रजातंत्र में जो उपर्युक्त दोष बतलाये गये हैं वे उसकी उस प्रणाली में हैं जो पश्चात्य देशों में स्थापित है। प्रजातंत्र के आदर्शों में कोई दोष नहीं है। ये दोष व्यवहार के हैं जो प्रयत्न करने पर दूर भी हो सकते हैं।

भारतवर्ष और प्रजातंत्र

भारत के सभी विद्वान और राजनीतिक दल इस विषय में एक मत हैं कि भारत के लिए प्रजातंत्र राज्यप्रणाली ही सबसे श्रेष्ठ और उपर्युक्त है। भारत राष्ट्रीय महासभा का लक्ष्य भारत में स्वाधीन प्रजातंत्र-राज्य की स्थापना है। मुस्लिम लीग ने जब अपने लखनऊ अधिवेशन

(अक्टूबर, १९३७) में अपना लक्ष्य 'पूर्ण स्वाधीनता' को पाना मजूर किया तब उसके अध्यक्ष श्री मुहम्मदअली जिन्ना ने बड़े ओजस्वी शब्दों में लीग के ध्येय की घोषणा करते हुए कहा—'मुस्लिम लीग भारत के लिए पूर्ण राष्ट्रीय प्रजातन्त्रात्मक स्वराज्य चाहती है।' सिक्ख, भारतीय ईसाई, दलितगर्भ, लिबरलदल, हिन्दू महासभा आदि सभी दल प्रजातन्त्र के आदर्श में विश्वास करते हैं।

पाकिस्तान

विगत लाहौर अधिवेशन (मार्च, १९४०) से मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके यह बुझावा दिया शुरू कर दिया है कि भारत में दो राष्ट्र हैं—हिन्दू और मुसलमान। इसलिए भारत में प्रजातन्त्र-प्रणाली उपयुक्त नहीं है। हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिए अलग-अलग राज्य होने चाहिए। मुसलमानों का राज्य—पाकिस्तान—उत्तर-भारत में रहे जिसमें सीमा-प्रान्त, ब्रिलोचिस्तान, पंजाब, सिन्ध, बंगाल आदि शामिल हों। शेष भारत में हिन्दू-राज्य कायम किया जाये। मुसलिम लीग के नेता श्री जिन्ना ने यह पाकिस्तान की नयी योजना तैयार की है। परन्तु इस योजना को भारत के समस्त मुसलमानों ने तो कहा उनके बहुमत ने भी स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस, हिन्दू महासभा, सिक्ख, ईसाई तथा लिबरल सभी इस योजना का घोर विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार भारत में पाकिस्तान की स्थापना राष्ट्र के लिए खतरनाक है। और इसकी स्थापना का स्वप्न भी पूरा नहीं हो सकता।

धार्मिक जीवन

नागरिक-जीवन और धर्म

मानव-जीवन में धर्म का स्थान सदैव अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। ससार में कोई भी ऐसा देश नहीं जहाँ किसी-न-किसी धर्म के अनुयायी न हों किन्तु भारत तो धर्म-अधान देश ही कहलाता है। भारतीय जीवन के सत्र अंगों—राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक—पर धर्म का प्रभाव है। यही 'धर्म' की परिभाषा है—यतोऽभ्युदयनिश्चेयससिद्धिः। स धर्म — जिससे अभ्युदय और निश्चेयस की सिद्धि हो वही धर्म है। वह मत मशहूफ या 'रिलीजन' के समुचित अर्थोंवाला नहीं रहा। धर्म केवल योगियों या धर्माचार्यों की साधना की वस्तु नहीं है। वह जीवन के प्रत्येक अंग को स्पर्श करता है। हिन्दुओं के धर्म षण् वेद हैं। उनमें मानव-जीवन की पूर्णता के लिए नियम और साधन बतलाये गये हैं। वे केवल आध्यात्मिक ज्ञान के कोष ही नहीं हैं, भौतिक ज्ञान के भी अक्षय भांडार हैं। सभी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि भारत की संस्कृति आध्यात्मिक है और भारतीय जनता की धर्म में बड़ी श्रद्धा है। यहाँ धर्म ने ही मानव-जीवन को सुन्दर, श्रेष्ठ और पूर्ण बनाने और धर्म भावना ने मानव के नैतिक धरातल को ऊँचा उठाने में विशेष योग दिया है। धर्म हमें सामाजिक उत्कर्ष के लिए ही प्रेरित नहीं करता बल्कि हमारे वैयक्तिक जीवन में भी आनन्द और शांति का सृजन करता है।

(१) वैदिक धर्म

हिन्दूधर्म ससार का सबसे प्राचीन धर्म है। इसी का वास्तविक नाम वैदिक धर्म है, परन्तु भारतवर्ष में विदेशियों के आगमन के बाद इस धर्म को हिन्दू धर्म कहने लगे। यह नाम विदेशियों का रखा हुआ है। वेद, उपनिषद्, दर्शन तथा मनुस्मृति में 'हिन्दू' नाम का वही भी उल्लेख

नहीं मिलता। धार्मिक ग्रन्थों में इस धर्म का नाम 'आर्य्य धर्म' लिखा है।

उत्तर भारत प्राचीन समय में 'आर्यवर्त' के नाम से प्रसिद्ध था और उसके निवासियों को 'आर्य्य' कहा जाता था। 'आर्य्य' का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, मान्य पुरुष।

चारों वेद (ऋक्, यजु, साम, अथर्व) संसार के सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं और वैदिक धर्म संसार का आदि धर्म है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की तो सबसे पहले उन्होंने चार ऋषियों को ज्ञान दिया। यही ईश्वरीय ज्ञान 'वेद' है जो उन ऋषियों के द्वारा मानव समाज के लिए मुलभ हो सका।

उपनिषद् वेदा की व्याख्याएँ हैं जो बाद में ऋषियों ने की। इसी प्रकार दर्शनशास्त्र भी मुनियों द्वारा प्रणीत हैं। स्मृतियों में धर्म के नियम हैं। वे एष प्रकार से बानन-संग्रह हैं। सबसे प्राचीन स्मृति मानवधर्म-संग्रह है। यह 'मनुस्मृति' के नाम से भी प्रसिद्ध है।

वेद, उपनिषद्, ब्राह्मण, शास्त्र, और मनुस्मृति सब सस्कृत भाषा में हैं। योगदर्शन के अनुसार वैदिक धर्मानुयायी को निम्न लिखित दस नियमों का पालन करना चाहिए। ये यम नियम इस प्रकार हैं —

- (१) अहिंसा—मन, वचन और ब्रह्म से प्राणी-मात्र से प्रेम करना तथा किसी भी प्राणी का हानि न पहुँचाना।
- (२) सत्य—मन, वचन कर्म से सत्य का पालन करना।
- (३) अस्तेय—मन, वचन, कर्म से चोरी का त्याग।
- (४) ब्रह्मचर्य्य—वीर्य रक्षा करते और समयपूर्ण जीवन बिताते हुए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म प्राप्ति की राचना करना।
- (५) अपरिग्रह—आवश्यकता से अधिक का संग्रह न करना तथा स्वाभिमान रहित रहना।
- (६) शौच—जलादि से शरीर तथा वस्त्रा की शुद्धि, पवित्र विचारों से मन की शुद्धि तथा ब्रह्म-ज्ञान से आत्मा की शुद्धि करना।
- (७) तपोय—पुरुषार्थ करना तथा हानि लाभ में शोक न करना।

(८) तप—कष्ट सहन करते हुए भी धर्मसम्मत कार्यों का अनुष्ठान करना ।

(९) स्वाध्याय—स्वयं पढ़ना तथा दूसरा को पढ़ाना ।

(१०) ईश्वर प्रणिधान—ईश्वर की भक्ति में आत्म-समर्पण ।

इस प्रकार संक्षेप में, सूत्ररूप में योगदर्शन का ने धर्म के दस नियम बता दिये हैं । इनके अनुसार आचरण करके मनुष्य न केवल लौकिक सुख ही प्राप्त कर सकता है, प्रत्युत मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है ।

वैदिक धर्म के मौलिक सिद्धान्त इस प्रकार हैं

- (१) एकेश्वरवाद—इस विश्व और ब्रह्माण्ड का कर्त्ता केवल एक ईश्वर है । वह सर्वशक्तिमान्, निर्विकार, अजन्म, अनादि, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ आदि है ।
- (२) जीव चेतन है और अनन्त है । वह अमर है, अजन्म है और अनादि है । जीव में इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न होता है । जीव जैसे काम करता है, वैसा ही उसे फल मिलता है । जब जीव थोड़ा कर्म करता है और उसे मोक्ष मिल जाता है तब वह १५ सत्रह, ५१ अरब, २० करोड़ वर्ष बाद पुनः शरीर धारण करता है ।
- (३) जीव एक शरीर का त्याग करके दूसरी योगि में जाता है । इस प्रकार पुर्नजन्म में विश्वास वैदिक सिद्धान्त है ।
- (४) यह सृष्टि-रचना प्रकृति और जीव से हुई है । प्रकृति जड़ है । उसमें चेतनता का अभाव है । प्रकृति का कभी नाश नहीं होता । इसलिए वह अनादि है, अनन्त है ।
- (५) वैदिक धर्म के अनुसार मानव-जीवन चार आश्रमों में विभाजित है—ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ।
- (६) इसी प्रकार मानव समाज गुण वम और स्वभाव के आधार पर चार वर्णों में विभाजित है—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ।
- (७) वैदिक धर्म मूर्तिपूजा और अवतारवाद में विश्वास नहीं करता ।
- (८) वैदिक धर्म जात-पात और अस्पृश्यता की भी आज्ञा नहीं देता ।

आज भारतवर्ष में वैदिक धर्म के इस स्वरूप की झलक आर्य-समाज में ही विद्यमान है परन्तु वह भी पूर्णतया इसका पालन नहीं करता ।

शेष हिन्दू-समाज में आज वैदिक धर्म का केवल विकृत रूप ही रह गया है। वैदिक धर्म के अनुयायियों में अनेक धार्मिक पथ और प्रचलित हैं। हिन्दू समाज के अन्तर्गत विविध प्रमुख मत इस प्रकार हैं—

(२) जैन मत

ईसा से ६ शताब्दियों पहले महावीर ने जैन मत की स्थापना की थी। जैन मत वैदिक धर्म की प्रतिप्रिया के रूप में उदय हुआ था। वह वैदिक धर्म के कुछ सिद्धान्तों को स्वीकार करता है। वस्तुतः यह हिन्दू धर्म का ही एक रूप है।

जैन मत जगत की उत्पत्ति का कर्त्ता ईश्वर को नहीं मानता और न वह वैदिक वर्ण-व्यवस्था को मानता है। जैन मत शरीर और मन की शुद्धता पर जोर देता है। इस मत के तीन मूल तत्त्व हैं—ज्ञान, भक्ति और सदाचार। इन तीनों के द्वारा मोक्ष प्राप्त हो सकती है।

विश्व में दो शक्तियाँ हैं—प्रकृति और आत्मा। विशुद्ध आत्मा जब भौतिक शरीर में आजाता है तब वह दुःख का कारण बन जाता है। इसलिए तपस्या द्वारा इस शरीर को कष्ट देना चाहिए जिससे आत्मा इसका परित्याग करके मोक्ष का आनन्द भोग सके। निर्वाण में अतीत के कर्मों का नाश हो जाता है और आत्मा शरीर बन्धन से मुक्त हो जाता है। जैन मत के अनुसार श्रेष्ठ आचरण के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए—(१) अहिंसा (२) सत्य (३) अस्तेय (४) अचीन (५) त्याग।

जैन मत की पुस्तकें 'आगम' कहलाती हैं। जैनों में दो सम्प्रदाय हैं—श्वेताम्बर और दिगम्बर। श्वेताम्बर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगम्बर वस्त्र धारण नहीं करते नग्न रहते हैं। यद्यपि जैनमत के प्रवर्तक महावीर नास्तिक और मूर्तिपूजा के विरोधी थे, तो भी आजकल जैन मतावलम्बी महावीर की मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा करते हैं। अहमदाबाद, इलोरा अजमेर, आनूप और काठियावाड़ में जैन-मन्दिरों की प्रधानता है। ये जैना के तीर्थ-स्थान हैं। सन् १९३३

की जनगणना के अनुसार भारत में १२ लाख ५१ हजार १०५ जैन हैं।

यद्यपि हिन्दू धर्म जैन धर्म से भिन्न है परन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जैन अपने को हिन्दू ही मानते हैं और हिन्दू भी जैन धर्मावलम्बियों को हिन्दू मानते हैं। वे भी पूजा करने हैं, हिन्दू देव-मन्दिरों में जाते हैं, हिन्दू उत्तराधिवार कानून को मानते हैं, हिन्दू पर्वों और उत्सवों को मानते हैं और भाषा और संस्कृति की दृष्टि से भी वे हिन्दू ही हैं।

(३) बौद्ध मत

बौद्ध मत की प्रतिष्ठा ईसा से पूर्व पाँचवीं शताब्दी में गौतम बुद्ध ने की थी। महात्मा बुद्ध के मतानुसार जीवन दुःखमय है; समस्त दुःखों का कारण मोह और तृष्णा है। अतः इच्छाओं के दमन द्वारा ही दुःखों का परिहार हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बुद्ध ने निम्नलिखित नियमों के पालन पर जोर दिया है—(१) अहिंसा (२) अस्तेय, (३) ब्रह्मचर्य (४) सत्य (५) ईर्ष्या-त्याग (६) शिष्ट भाषण (७) प्रलोभन-त्याग (८) घृणा-परित्याग (९) अज्ञान-निवारण

बौद्ध मत में मुक्ति के लिए ईश्वर-भक्ति और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसमें नीति-मार्ग पर अधिक जोर दिया गया है। उसकी दृष्टि में आत्म-सयम ही मोक्ष का साधन है। बौद्ध मत में अहिंसा को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। इस धर्म का प्रचार एशिया में खूब हुआ। यद्यपि भारत में तो बौद्ध-मतानुयायियों की संख्या बहुत ही कम है, परन्तु ब्रह्मा, लका, तिब्बत, मंगोलिया, चीन और जापान में बौद्ध मत का ही प्रचार अधिक है क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध मत का अनुयायी बनकर उसके विस्तार के लिए इन देशों में महान् उद्योग किया था।

बौद्धमत के अन्तर्गत दो बड़े सम्प्रदाय हैं—हीनयान और महायान। हीनयान सम्प्रदाय के अनुयायी बुद्ध के उपदेशों में श्रद्धा रखते हैं, वे बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में मानते हैं जिसने दुःखों से मुक्ति पाने का मार्ग बतलाया। महायान सम्प्रदाय के अनुयायी

बुद्ध को भगवान् मानते हैं और उन्हें सर्वज्ञ एवं अमर मानकर उनकी पूजा करते हैं ।

बुद्ध हिन्दुत्व के पुजारी थे । वह वास्तव में हिंदू-समाज के एक महान् प्रतिकारी सुधारक थे । उनके महान् कार्य की विशेषता यह है कि उन्होंने उपनिषद् के सिद्धान्तों और वेद के उपदेशों की व्यावहारिक जीवन में ओसप्रोस कर उनकी सत्यता सिद्ध की । बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा के संबंध पर भी उतना अधिक जोर नहीं दिया जितना सात्विक-प्राण और मेधा धर्म पर । उन्होंने भारत में प्रचलित जाति-प्रथा की निस्तारना की सिद्ध करके मानव-बन्धुत्व की स्थापना की । उन्होंने स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार किया । वास्तव में बुद्ध विश्व-प्रेम के मानवीय उच्चादर्श को जीवा में चरितार्थ करनेवाले मानवता के महान् पुजारी थे । परन्तु आज रीढ़मत्तानुयायी बुद्ध के आदर्शों व सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत आवरण कर रहे हैं ।

सिक्ख मत

सिक्ख मत नवीन मत है । यह हिन्दू समाज में सुधार करने के लिए एक ऐसे युग में प्रचलित हुआ था जबकि हिन्दुत्व पतन की चरम सीमा की पहुँच चुका था । जब हिन्दुत्व पर विज्ञानीय शास्त्रों द्वारा आक्रमण हो रहा था तब गुरु नानक (सं० १४६९-१५३८) ने सिक्ख मत की स्थापना की थी । गुरु नानक ने दश में भ्रमण कर लाया की यह सन्देश दिया कि सत्रको ईश्वर की सत्ता में विश्वास करना चाहिए । कहा जाता है कि हिंदुओं के अनिश्चित मुसद्मान भी नानक के भ्रमण बन गये । गुरु नानक का जातपूजन और अत्युपस्था में विश्वास नहीं था । सत्र मनुष्य समान है—यही उनका मात्र सिद्धान्त था । निश्चय था धर्म अन्य 'आदि ग्रन्थ' है । सिक्खमतानुसार ईश्वर एक और सर्वज्ञात्मा है, वह अमर, अमर, अजन्म, स्वयम्भू, महान् और दयालु है । वह सत्य था सत्य है और गर्व सत्य रहेगा । उससे सिवा दूसरा कोई नहीं । अनेक गुणा के कारण ईश्वर के अनेक नाम हैं पर उमा गुरु नाम

सतनाम है। सिक्ख मत में इस जगत को अनित्य माना गया है और कहा गया है कि ईश्वर के ज्ञान से ही माध मिल सकता है, अतः उसी का ध्यान करना चाहिए और उससे ही चरणा में आत्म समर्पण करना चाहिए। सिक्ख मत मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता और न बलि देने में ही उसका विश्वास है। सिक्ख गुरु परम्परा का मानते हैं। उनके दस गुरु हुए हैं—(१) नानक (२) अंगद (३) अमरदास (४) राम दास (५) अर्जुन (६) हर्गोविन्द (७) हरराम (८) हरविन्द (९) तेगबहादुर (१०) गोविन्दसिंह। नानक के स्वर्गवास के बाद सिक्ख मत में एक नया सम्प्रदाय का उदय हुआ जो दसवें गुरु के जीवन काल में पूर्णतया सुमग्नित हो चुका था। सिक्खों को हिन्दुत्व की रक्षा के लिए विजातीय शासकों से लोहा लेना पड़ा इसलिए सिक्ख मत सैनिक संगठन में परिणत हो गया। यह नवीन सम्प्रदाय खालसा पथ कहलाता है। इसके धारिता जो नानक के शान्ति के उपदेशों में विश्वास करते हैं वे नानक-पथी कहलाते हैं।

भारत में सिक्खों की सबसे अधिक संख्या पंजाब में है। भारत में कुल सिक्ख ४३ लाख २५ हजार ७७१ हैं। सिक्ख पंच बकार धारण करते हैं—केश, कच्छ कड़ा कृपाण और कथा।

हिन्दू समाज के अन्य मत मतान्तर

उपर्युक्त प्रमुख मतों के अतिरिक्त हिन्दू समाज में और भी विविध मत एवं पथ हैं। हम संक्षेप में इनका उल्लेख करते हैं।

हिन्दू समाज में अगणित मतों के प्रादुर्भाव का कारण यह है कि भिन्न भिन्न देवताओं को ईश्वर का प्रतीक माना गया है—जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि।

अज्ञानवश लोगो ने अपने दृष्ट देवता को ही सर्वोपरि प्रधानता देकर विविध पथों की कल्पना कर डाली। उन्होंने अपने दृष्ट देवता को ईश्वर का अवतार माना और उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। विष्णु के माननेवाले वैष्णव और शिव के माननेवाले शैव कहलाये। यही

नहीं, लोगों ने देवियों की भी कल्पना की—जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती आदि। ब्रह्मा की देवी सरस्वती, विष्णु की देवी लक्ष्मी और शिव की देवी पार्वती या दुर्गा मानी गयी। इन तीनों देवियों को आदिशक्ति माना गया है और इनके उपासक शक्ति कहलाते हैं। इनके अन्वावा हिन्दू-समाज में कबीर-पथ, दादू-पथ, गोसाईं सम्प्रदाय, माधव और नारायण सम्प्रदाय और वाममार्ग आदि अनेक पथ और सम्प्रदाय प्रचलित हैं जो किसी सत अथवा आचार्य के नाम पर कायम हुए हैं।

आर्यसमाज

अन्तीसवीं सदी में जब भारत में वैदिक धर्म के प्रति हिन्दुओं की श्रद्धा गट्ट हो रही थी, धार्मिक क्षेत्र में पातण्ड और दम्भ का जोर बढ़ रहा था और समाज नैतिक पतन की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा था, तब धार्मिक हिन्दू जाति के अन्धविश्वास, और अज्ञान को दूर करने के लिए स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना की। उन्होंने ममस्त भारत में भ्रमण करके वैदिक-धर्म-विरोधी मत-मतान्तरों का खण्डन किया और वैदिक धर्म के सच्चे रहस्य की अनन्ता के सापने प्रस्तुत किया। स्वामी दयानन्द ने आर्यसमाज के १० नियम निर्धारित किये जो इस प्रकार हैं—

- (१) सब सत्य विद्या या और उसके समस्त जानेवाले सब पदार्थों का आविर्भूत परमात्मा है।
- (२) ईश्वर सच्चिदानन्द वस्तु, निराकार, सर्वसक्तिमान्, न्यायकारी, दयालु, अगन्ता, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर सर्वव्यापक, सर्वात्मामी, अजर, अमर, अमय, नित्य, पवित्र और मूर्तिवर्ती है। उसी की उपासना करना उचित है।
- (३) वेद सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना आर्यों का परम धर्म है।
- (४) सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने की सदा उद्यत रहना चाहिए।
- (५) भक्त कर्म धर्मनिष्ठ सत्य और असत्य का विचार करके करना चाहिए।

- (६) ससार का उपकार अर्थात् आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य है।
- (७) सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मनिसार यथायोग्य आचरण करना चाहिए।
- (८) अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
- (९) प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सरसी उन्नति में अन्तरे उन्नति सनञ्जनी चाहिए।
- (१०) सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतत्र और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतन्त्र रहना चाहिए।

आर्यसमाज के द्वारा हिन्दू-समाज में अनेक धर्मों में सुधार हुए। उसने वेद-कालीन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की स्थापना की तथा कन्याओं की शिक्षा के लिए अलग कन्या-गुरुकुल खोले। ग्रामों में शिक्षा-प्रचार और परदा प्रथा निवारण के लिए खास तौर से काम किया। बाल-विवाह तथा पैदाहिब कुरीतियों के निवारण के लिए भी महान् प्रयत्न किया गया। भादव द्रव्य-निषेध, हिन्दी भाषा प्रचार मिथवा विवाह, कन्याओं की रक्षा तथा शुद्धि-भगटन - ये आर्य-समाज के मुख्य अन्दोलन हैं। आर्यसमाज ने ऐसी सर्वतोमुखी क्रान्ति का प्रादुर्भाव किया कि जिससे मूलतः हिन्दू-जीवन में जागरण शक्ति और स्फूर्ति का संचार हो गया। भारतवर्ष में आज भी प्रत्येक नगर और जिले में आर्य समाज कार्य पर रहा है। भारत के बाहर भी यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में जहाँ भारतीय प्रवासी रहते हैं, आर्यसमाज की सम्पाएँ हैं।

ब्राह्म-समाज

सन् १८०८ में बंगाल में राजा राममोहन राय ने उपनिषदों के ग्रन्थों की उपासना के लिए ब्राह्मसमाज की स्थापना की। सन् १९३० में सबसे पहले उमाता मन्दिर स्थापित किया गया जिसमें सबको प्रवेश की आज्ञा दी गयी। ब्राह्मसमाजी मूर्तिपूजा, जानपात, अस्पृश्यता आदि कुप्रथाओं को नहीं मानते। इस प्रकार ब्राह्म-समाज ने हिन्दुओं की विचर्या होने से बचाया।

रामकृष्ण-मिरान

सन् १८३३ में बंगाल में रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। वे ईश्वर के अनन्य भक्त थे। सासारिक सुखों को त्याग कर उन्होंने पयास-व्रत लिया और योग-मयाधि द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना की। उन्होंने यह अनुभव किया कि सब धर्मों में एवता है। इसलिए उन्होंने किसी धर्म का लण्डन नहीं किया। भ्रामी विवेकानन्द, जो रामकृष्ण के महान् शिष्यों में से थे, वेदांत के प्रकाण्ड गण्डित थे। उन्होंने वेदान्त का प्रचार विदेशों में भी किया। स्वामी रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करनेवाली संस्था 'रामकृष्ण मिशन' नाम से प्रसिद्ध है।

इस्लाम धर्म

इस्लाम या मुसलमान धर्म ससार के प्रमुख धर्मों में से है। इसके संस्थापक हजरत मुहम्मद की जन्म-भूमि एशिया महाद्वीप के अरब देश में है। अरबवासियों के द्वारा ही यह धर्म भारत, अफगानिस्तान, मिथ्र, तुर्की आदि देशों में फैलाया गया। मुहम्मद साहब के उपदेशों का सग्रह 'कुरान' में है। जब मुसलमानों का राज्य हिन्दुस्तान में हुआ तो उन्होंने भी अपना धर्म यहाँ प्रचलित किया। कई मुसलमान बादशाहों ने धर्मप्रचार के लिए हिन्दु जनता पर बड़े अत्याचार किये, किन्तु अकबर आदि ने जनता को पूर्ण स्वतन्त्रता दी। मुहम्मद साहब के उपदेशों का सार यह है —

- (१) एक ईश्वर में विश्वास करो।
- (२) कुरान में विश्वास करो।
- (३) छुदाई निर्णय, स्वर्ग और नर्क में विश्वास करो।
- (४) पैगम्बरों में भक्तिभाव रखो।
- (५) प्रतिदिन यह पाठ करना चाहिए कि "अल्लाह के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मुहम्मद अल्लाह का पैगम्बर है।"
- (६) मक्का की ओर मुहूर्त करके दिन में ३ से ५ बार सब नमाज पढ़नी चाहिए।

(७) दान-दक्षिणा देनी चाहिए ।

(८) रमजान के दिनों में व्रत रक्खना चाहिए ।

(९) मक्का की तीर्थ-यात्रा करनी चाहिए ।

इस्लाम का मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं है । उसका भातृभाव और समानता का सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और उसका द्वार सब मनुष्यों के लिए खुला हुआ है । मुहम्मद साहब ने बर्ग पर अधिक धोर दिया है । उन्होंने लिखा है—

“ओ सच्चाई के साथ अपनी जीविका कमाते हैं, उन्हें ईश्वर प्रेम करता है ।”

“ईश्वर उन लोगों पर कृपा करता है जो अपनी मेहनत से कमाते हैं और भिक्षावृत्ति पर निर्भर नहीं रहते ।”

दान-दक्षिणा के सम्बन्ध में मुहम्मद साहब ने लिखा है—

‘दान देना प्रत्येक मुसलमान का धर्म है । जिसके पास दान देने के लिए कुछ नहीं, उसे चाहिए कि वह दूसरों के साथ भलाई करे और बुराई से अलग रहे । यही दान है ।

‘भूखों को भोजन दो; रोगियों की सेवा करो । अल्पसि प्रसन्न व्यक्ति को (चाहे वह मुसलमान हो या गैर-मुसलमान) मदद करो ।”

सहनशीलता की भावना के सन्ध में मुहम्मद साहब का आदेश है—

‘पूरा मुसलमान वही है जिसके वचन और कर्म से मानव जाति सुरक्षित रहे । सख्तधान रहो । वह मुसलमान नहीं जो व्यवहार करता है चारी करता है, मदिरा-पान करता है या जो किसी के धन का अपहरण करता है ।’

“ओ एन्डरवादी है और जो परलोक में विश्वास करता है, उसे अपने पडासियों को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए ।”

‘यदि तुम सृष्टि-रचयिता को प्रेम करते हो, तो पहले अपने सहयोगियों को प्रेम करो ।’

‘ईश्वर उनके लिए दयालु नहीं जो मानव-जाति के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करता ।’

भारत में मुसलमानों के दो मुख्य सम्प्रदाय हैं—शिया और सुन्नी। दोनों में सबसे अधिक संख्या सुन्नी मुसलमानों की है। शिया बहुत ही कम हैं। अरब तथा दूसरे देशों से भारत में आये हुए मुसलमानों तथा उनके वंशजों की संख्या भी बहुत कम है। शताब्दियों तक हिन्दू और मुसलमानों के साथ रहने से एक दूसरे पर आचार विचार का भी बहुत प्रभाव पड़ा है। कई मुसलमान और हिन्दू वेशभूषा, मापा आदि की समीपता से बहुत दूर हैं।

अधिकांश मुसलमानों के तो पूर्वज हिन्दू ही हैं। बम्बई में खोजा, गुजरात (पाठियावाड) में पच्छी ममन हराई मैमन और घाहुरा तथा मलकाने आदि पहले हिन्दू थे। आज भी उनके उत्तराधिकार तथा विरासत और वसीयत के मामले हिन्दू विधान के अनुसार तय होते हैं।

सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की जनसंख्या ७ करोड़ ७६ लाख ७८ हजार है।

ईसाई धर्म

ईसाई धर्म भी मत्तार के प्रमुख धर्मों में से है। इसके प्रवर्तन महात्मा ईसा एशिया महाद्वीप में गेलिली में पैदा हुए थे पन्तु उनका धर्म पहले यूरोप में फैला। जब यूरोप के निवासी वाणिज्य-व्यापार करने या उपनिवेश बनाने के लिए दूसरे महाद्वीपों, देशों या टापुओं में पहुँचे तो अपने धर्म को वहाँ लेगये और उसे वहाँ प्रचलित किया।

ईसा ने धर्म के मूलतत्त्वों के रूप में नीचे लिखे आदेश दिये थे—
किसी और देवता को मत मानो जल, धूल और आमाश की किसी वस्तु की प्रतिमा या चित्र मत बनाओ, लोगों के आगे सिर न झुकाओ, न उनकी पूजा करो, सबके प्रति दया दिखाओ, अपने प्रभु का नाम बेकार मत लो, ६ दिन काम करके रविवार को पवित्रता से बिताओ, अपने माता-पिता का आदर करो। व्यक्तिचार मन करो, चोरी मत करो, अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दो और न उसको किसी चीज पर जी ललचाओ।

भारत में पुर्तगाल देशवासी व्यापार के लिए आये, तब उन्होंने यहाँ ईसाई-धर्म का सूत्रपात किया। बाद में यहाँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज्य उसके शासकता द्वारा फैलाया जाने लगा और अंग्रेजी राज्य की स्थापना होजाने के बाद तो राजसत्ता की सहायता से यहाँ ईसाई धर्म का जोरो से प्रचार किया गया। फलस्वरूप भारत में एक नया सम्प्रदाय पैदा हो गया जो 'इण्डियन क्रिश्चियन' कहलाता है। आजतक भारत में यूरोप और अमरीका के विदेशी मिशन ईसाई धर्म का प्रचार करते आ रहे हैं। नगर-नगर में ईसाई और उनके पादरी और मिरजे दिखायी देते हैं। आरण्याक जातियो (जैसे भील, गोंड, सयाल, कोल आदि) में ईसाई धर्म प्रचारकों के विशेषरूप से वेद्व घने हुए हैं, और उनमें नियमित रूप से प्रचार हा रहा है। ईसाई पादरी व प्रचारक शिक्षा, चिकित्सा आदि अनेक प्रकार से प्रलोभन भी देते हैं। सन् १९३१ में भारत में ईसाइया की आबादी ६२ लाख ९७ हजार ७ थी।

पारसी धर्म

ईसा से पूर्व ८ वीं सदी में फारस में पारसी मत की स्थापना हुई। जरथुस्त्र ने इस धर्म की प्रतिष्ठा की। यह फारस का राष्ट्रीय धर्म था। और समस्त फारस में इस धर्म के अनुयायी थे। परन्तु जब सन् ५३७ में मुसलमानों ने फारस पर आक्रमण किया तो उन्होंने बहुत-से पारसियों को मुसलमान बना लिया। जरथुस्त्र के कुछ अनुयायी भारत में आकर बस गये। अब इस सम्प्रदाय के लोग केवल भारत में ही मिलते हैं। पारसी धर्म का आधार नीति-शास्त्र है। ये अहिंसा, दान, पवित्रता और परोपकार में पूरा विश्वास रखते हैं। ये अग्निपूजक हैं। तपस्या और तपस्वी जीवन के लिए पारसी धर्म में कोई स्थान नहीं है। इनकी धर्म-पुस्तक 'अवेस्ता' है। पारसियों में कोई जाति-भेद नहीं है। वे धर्मान्धता और प्रचार में विश्वास नहीं करते। पारसियों में विद्या वैभव और विद्वत्ता अधिक है। पारसी अधिवास में बम्बई प्रान्त में है। भारत में इनकी संख्या ११ लाख के लगभग है।

सामाजिक जीवन

भारत के सामाजिक जीवन में एकता का अभाव है। हिन्दू, मुसलमान ईसाई, पारसी, सिख आदि सममान ही नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक जीवन की भी व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक धर्म के धार्मिक सिद्धान्त ही भिन्न नहीं होते प्रभुत उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्थाएँ, आदर्श और सस्थाएँ भी भिन्न होती हैं। सामाजिक जीवन में रीति रिवाज का बड़ा महत्त्व है। सब तो यह है कि सामाजिक जीवन इन रीतियों के आधार पर ही स्थिर है। यूरोप के देशों में विविध धर्मों का पालन करते हुए भी लोग सामाजिक जीवन में समता के आदर्श को स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत भारत में प्रत्येक धर्म और मत ने अपना समाज शास्त्र अपने ही ढंग का गढ़ लिया है। एक हिन्दू का सामाजिक जीवन एक मुसलमान या ईसाई के सामाजिक जीवन से भिन्न है। यद्यपि इनमें परस्पर समन्वय करनेवाली प्रवृत्तियाँ भी काम कर रही हैं। भारतीय सामाजिक जीवन के प्रधान प्रधान अंगों की रूपरेखा यों है—

हिन्दू जीवन

हिन्दू-समाज की मुख्य विशेषता है संयुक्त परिवार तथा जाति प्रथा। आर्यसमाज सैद्धान्तिक रूप में जातिवाद को नहीं मानता, परन्तु व्यावहारिक रूप में इसका घातक प्रभाव आर्यसमाज पर भी पड़े बिना नहीं रह सका। आर्यसमाज भारत में पुनः वैदिक वंश व्यवस्था की स्थापना करना चाहता है। अतः सबसे पूर्व प्राचीन वंश-व्यवस्था पर व्यावहारिक दृष्टि से विचार करना उपयोग्य होगा।

वैदिक वर्ण-व्यवस्था

‘वर्ण’ शब्द के अर्थ हैं रूप, भेद, प्रकार, रंग आदि। परन्तु इसका वैदिक अर्थ है श्रम विभाजन।

ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में वर्ण-व्यवस्था का विधान है। यजुर्वेद में लिखा है—

“जो पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मूल के समान सर्वोत्तम हो वह ब्राह्मण, जो बाहु की भाँति बलवीर्यवान् हो वह क्षत्रिय, जो उरु की भाँति अन्य सब अर्गा का पोषण करे वह वैश्य और जो पाँवों की भाँति सेवा करे वह शूद्र है।”

इस वेद-भ्रम में सम्पूर्ण मानव-समाज को वर्णों एवं योग्यता के आधार पर चार भागों में विभाजित किया गया है—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की उपमा मस्तिष्क से दी गयी है। जिस प्रकार शरीर में मस्तिष्क का स्थान सर्वोच्च है, उसी प्रकार समाज में ब्राह्मण का स्थान है। वह जैसे शरीर के कार्य का संचालक है, उसी प्रकार ब्राह्मण भी समाज का नियामक है। क्षत्रिय की उपमा बाहु से दी गयी है। जिस प्रकार बाहु शरीर में बल का सूचक है और शरीर की रक्षा करता है उसी प्रकार क्षत्रिय अपने बल से समाज की रक्षा करता है। उरु का कार्य है भोजन के पाचन आदि से शरीर का पोषण। उसी प्रकार वैश्य का भी कार्य पोषण करना है। वह धन धान्य से समाज का पालन करता है। पाँव जिस प्रकार शरीर की सेवा करते हैं—उसी प्रकार शूद्र भी सारे समाज की सेवा करते हैं।

वर्ण व्यवस्था के सिद्धान्त में यह कार्य विभाजन बड़ी उत्तमता से किया गया है। समाज की वृद्धि बल, पोषण और सेवा इन चार की श्रृंखला है ही। जबतक इनमें से एक का भी अभाव होगा समाज की व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती। ब्राह्मण वृद्धि का प्रतीक है, क्षत्रिय बल का, वैश्य पोषण का और शूद्र सेवा का। यह वर्ण व्यवस्था व्यक्तिगत गुण, कर्म और स्वभाव पर निर्भर है। जन्म के कारण ही न कोई ब्राह्मण हो सकता है न क्षत्रिय और न वैश्य। यही कारण है कि सामाजिक जीवन में संस्कार का विशेष महत्त्व है। संस्कार से ही एक शूद्र ब्राह्मण

१ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदबाहु राजन्य कृत

उरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥ यजुर्वेद ३१-११

का पद या सक्ता है एक वैश्य क्षत्रिय वन सक्ता है । यदि ब्राह्मण में उसके वर्ण के अनुसार गुण-कर्म न हों तो वह गिर जाता है ।

(१) ब्राह्मण के कर्त्तव्य—वेद-शास्त्रों तथा समस्त ज्ञान-विज्ञान का अध्ययन करना, उनकी जनता को शिक्षा देना, शुभ कर्म करना, तथा यज्ञ करना, समाज को श्रियादि शुभ गुणों का दान देना और गृहस्थों से अपनी जीविका के लिए दान-दक्षिणा प्राप्त करना । गीता के अनुसार ब्राह्मण में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है—शम, दम, उप, मोक्ष, क्षमा, निरभिमान, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिकता ।

(२) क्षत्रिय के कर्त्तव्य—वेद-शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ तथा शुभ कर्म करना, सुत्राओं को दान तथा प्रजा को अभयदान, प्रजा की रक्षा, त्रिनेन्द्रिय रहना, वीरता के काम करना, तेजस्वी होना, आपत्ति के समय धैर्य से काम लेना, सैन्य-विद्या में निपुणता, युद्ध-कौशल, ईश्वर-भक्ति तथा प्रजा की पुत्र के समान मानना ।

(३) वैश्य के कर्त्तव्य—वेद-शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ करना, दान देना, पशु-पालन, वाणिज्य-व्यापार करना, श्राजलेना तथा कृषि करना ।

(४) शूद्र के कर्त्तव्य—मनुस्मृति के अनुसार परमेश्वर ने जो पिताहीन हो जिसको पढ़ने में भी विद्या न आ सके, जो शरीर से पुष्ट, सेवा में पुगल हो उस शूद्र के लिए अन्य वर्गों की निश से रहित प्रीति-पूर्वक सेवा करना, यही एक कर्म करने की आज्ञा दी गयी है ।

इन वर्गों का आधार व्यक्ति के गुण, कर्म एवं स्वभाव हैं—इसके लिए मनुस्मृति का निम्नलिखित प्रमाण दिया जाता है—

“जो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाववाला हो वह ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो जाता है वैसे ही जो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ और उसके गुण, कर्म और स्वभाव शूद्र के सदृश हों, तो वह शूद्र हो जाता है ।”

१ शूद्रो ब्राह्मणनामेति ब्राह्मणदर्शेन शूद्रताम् ।

क्षत्रियाञ्जातमेवन्तु विद्याद्वैश्यास्तथैव च ॥ मनु० अ० १० श्लो० ६५

आपस्तम्ब सूत्र में लिखा है—

“धर्मावरण से निवृष्ट वण अपने से उत्तम वण को प्राप्त होता है ।

दुःस्वर्णीति वा अध्याय १ द्वाक ३८ भी यही कहता है—

‘जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या मलेच्छ नहीं किन्तु सारे वण भेद का आधार गुण-कर्म पर है ।’

वर्तमान युग में वर्ण व्यवस्था

वैदिक युग में या उसके बाद किसी अन्य युग में यह वर्ण-व्यवस्था, जिसका ऊपर वर्णन किया गया है समाज में बनी रही हो परन्तु यह तो निर्विवाद है कि आज भारत में वर्ण-व्यवस्था का पूर्ण विनाश हो चुका है । आज न कोई ब्राह्मण वर्ण है, न क्षत्रिय वर्ण और न वैश्य वर्ण । महात्मा गांधी के शब्दों में आज सब ‘शूद्र’ हैं । सम्भव है, कुछ व्यक्ति ऐसे निकल आये जा वैदिक परिभाषा के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हो, परन्तु इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि आज वर्ण वास्तविक रूप में नहीं मिल सकते ।

वर्ण-व्यवस्था आर्य-सभ्यता के विकास-काल में किसी अवस्था के लिए उपयुक्त रही होगी, परन्तु आज के सामाजिक जीवन में, जो पूर्व-कालीन जीवन से सबधा भिन्न है वर्ण-व्यवस्था विकृत हो गयी है और श्रेय की ओर ले जाने के बदले हमें ह्रास की ओर ही ले जा रही है ।

जाति प्रथा

आज के हिन्दू-जीवन की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं—जाति और परिवार । आज भारत में ३००० से भी अधिक जातियाँ हैं और उनकी भी हजारों उपजातियाँ हैं । इस तरह हिन्दू समाज जातियों के छोटे-छोटे दायरों में बँटा हुआ है । वेदों में ऐसा एक भी मंत्र नहीं है जो जाति-प्रथा को सिद्ध करता हो । इस प्रकार यह तो सिद्ध है कि यह संस्था वेदविहित नहीं है और न धार्मिक ही है ।

मनुस्मृति में भी चार वर्णों का विधान है । यदि उसमें जातियों का

उल्टेसा है तो यह यह सिद्ध नह। वगता कि जानियाँ घाबिक सस्याएँ है । स्मृनियाँ ता युग विशेष के सामाजिक निधमा के मशह है । उनम समय समय पर परिवर्तन होना स्वाभाविक है ।

जातियों की उत्पत्ति वस्तुन हि दू सामाजिक जीवन में अराजकता के फलस हा हुडे है । हिन्दू समाज में, जो हजारों उगजातियों ह वे हिन्दू ज वन की अथ विनिष्पत्ताआ म सम्बधित है । इन विनिष्पत्ताआ में स एक है सम्पत्तिन परिवार ।^१

जानि की तीन मुख्य बिगेरनाएँ है । वे इस प्रकार है —

(१) जन्मपरक अवस्थितनशास विषमता

इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह आजन्म उसी में मिया जाता है । वह अपनी जाति का यदल मही सरता । यदि वह 'महत्तर' के पुत्र में पैदा हुआ है तो वह चाहे जैसा विद्वान और पणित क्या न हा जाये, उसकी जानि 'महत्तर' ही रहगी और समाज उसका साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा ।

(२) व्यवसाय व उद्योगों का जाति के आधार पर वर्गीकरण और उनकी विषमता

प्रत्येक जाति के लिए जो व्यवसाय या पैगा निर्धारित है वह उनी की बरती है और अपनी सन्तान का भी वही काम मियाती है । एक ब्राह्मण पढ़ानवाक व्यक्ति पुराहित का काम करके अपनी जीविका कमाना है, यह अन पुत्र की भी वही काम मियाता है । इसी प्रकार जो व्यक्ति सफाई का काम करता है, वह अपनी सन्तान स भी वही काम करेगा है ।

(३) विवाह सम्बन्ध तथा सानपान —

जाति की तीसरी विशेषता यह है कि वह विवाह-सम्बन्ध तथा सानपान अपनी ही जानि तक परिमित रखती है । इस प्रकार जानि रक्त की पवित्रता पर अधिक जोर देती है ।

यह जाति-प्रथा हिन्दू-संघठन और एकता में सबसे अधिक बाधक रही है। सभी समाज-सुधारकों ने यह स्वाकार किया है कि जाति-प्रथा सामाजिक संघठन के लिए एक विकट बाधा है। आश्चर्य की बात है कि हिन्दू-महासभा, जो हिन्दू-संघठन पर जोर देता है, हिन्दू-समाज के इन अगणित विभागों के नाश के लिए कोई योजना नहीं सोचती। प्रोफेसर वाडिया ने जाति-प्रथा के सम्बन्ध में लिखा है—

“उपनिषदों की उच्च काटि की आध्यात्मिकता और गीता का नीति-शास्त्र जाति के अत्याचार के कारण जोरे शब्द मात्र रह गये हैं। जिस भारत ने चेतन और जड़ जगत की एकता का संदेश दिया उसी ने एक ऐसे सामाजिक विधान को जन्म दिया जिसने अपनी सन्तति को छोटे-छोटे दायरों में बाँट दिया। उसी ने विदेशी सत्ता को यहाँ विजय प्राप्त करने का सुपाग दिया जिसके कारण वह न केवल गरीब और कमज़ोर ही हो गया है बल्कि अछूतपन का आगार बन गया है।”

हिन्दू-समाज में प्रचलित जात-पात की कुप्रथा का जो कुप्रभाव समाज के आचार पर पड़ा है उसके विषय में विद्वान् बैरिस्टर डा० भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है —

“जाति ने सार्वजनिक भावना का नाश कर दिया है। जाति ने सार्वजनिक दान-दक्षिणा की भावना का विनाश कर दिया है। जाति ने लोकमत को अमभव बना दिया है। एक हिन्दू की जनता उसकी जाति ही है। उसकी जिम्मेदारी केवल उसकी जाति के प्रति है। उसकी भक्ति केवल उसकी जाति तक ही परिमित है। सदाचार पर जाति का ध्यान है और नैतिकता भी जति से प्रभावित है।”

जाति-प्रथा ने वास्तव में हिन्दू-समाज का बड़ा अनिष्ट और अनर्थ किया है और वह उसके पतन के कारणों में से एक है। परन्तु हमें की बात है कि विचारशील मनीषियों के द्वारा जात-पात प्रथा में अब परिवर्तन किया

१. प्रो० वाडिया : ‘कटेम्पोररी इण्डियन फिलॉसफी’, पृ० ३६८

२. डा० भीमराव अम्बेडकर : ‘एनिहिलेशन ऑव कास्ट’, पृ० २४

जा रहे हैं और जाति-धर्म भी ढीला होना जा रहा है। हिन्दू-समाज के नेता यह अनुभव कर रहे हैं कि हिन्दुत्व की रक्षा के लिए हिन्दू-मगलन जरूरी है। हिन्दुओं में एकता पैदा करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता को अब वे अनुभव करने लगे हैं। अब जानि-प्रया एक सामाजिक सस्था बन गयी है और उसका धर्म से तनिक भी संबंध नहीं है, इस तत्त्व को सभी हिन्दू नेता स्वीकार करने हैं। आजकल भारत में केन्द्रीय और प्रांतीय धारासभाओं के रूप में एक ऐसी सत्ता मौजूद है जो सामाजिक सुधार कर सकती है। इन्हें हिन्दू-विज्ञान में परिवर्तन एवं सुशोधन करने का अधिकार मिला हुआ है। जनता के इन प्रतिनिधियों को 'स्मृति' बनाने का अधिकार है। इसलिए हिन्दू-समाज में जातिधारी परिवर्तन के लिए इस सत्ता का प्रयोग किया जा सकता है और धारासभा द्वारा एक नयी स्मृति बनायी जा सकती है जो सब प्रकार से इस बीसवीं सदी के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सके।

हिन्दू-समाज की सभी जातियों को राजनीतिक सत्ता मिली हुई है और वे सभी राज्य-संघटन पर अपना प्रभाव डाल सकती हैं। जिन जातियों को प्राचीन काल में कोई व्यवस्था देने का अधिकार नहीं था वे भी आज धारासभा में जाकर देश के लिए उपयोगी कानून बनाने में हाथ बँटा रही हैं। तब तो केवल ब्राह्मणों ही को व्यवस्था देने का अधिकार था, परन्तु आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा दलित जातियों और स्त्रियों तथा वे इन धारा-सभाओं में जाकर कानून बनाने का अधिकार है।

इस जमाने में देश में जो राष्ट्रीय आन्दोलन चल रहा है उसका भी जाति पर स्वास्थ्यकर प्रभाव पड़ रहा है। राष्ट्रीय आन्दोलन दो प्रकार से पुरातन हिंदू-भावना पर कुठाराघात कर रहा है। उसके द्वारा राजनीतिक सत्ता को अधिक महत्त्व दिया जा रहा है और धार्मिक सत्ता तथा वट्टरता का राजनीतिक जीवन में कोई महत्त्व का स्थान नहीं है। दूसरा प्रभाव यह पड़ रहा है कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन यह सिद्ध कर रहा है कि समाज के निर्माता स्वयं मानव हैं।

वह कोई देवी विधान नहीं है जिसे ईश्वर ने हमपर लाद दिया हो। इस प्रकार यह भावना जाग्रत होती जा रही है कि मनुष्य ही समाज-व्यवस्था के निर्माता है।

कुटुम्ब का प्रयोजन

‘कुटुम्ब वह छोटे से-छोटा मानव समुदाय है जिसमें केवल पति-पत्नी और उनकी सन्तान हों अतः विवाह के बाद ही कुटुम्ब का प्रादुर्भाव होता है।

कुटुम्ब मानव के जन्म के साथ ही पैदा हुआ और आज भी यह विद्यमान है। वास्तव में कुटुम्ब उतना ही प्राचीन है जितनी कि मानव-जाति। मानव के कुटुम्बिक जीवन का समाज से गहरा सम्बन्ध है। वास्तव में मानव सभ्यता का आधार कुटुम्ब ही है। इसमें तनिका भी सन्देह नहीं कि कुटुम्ब के नाश होने ही मानव सभ्यता भी नष्ट होकर फिर उसी बर्बर दशा को प्राप्त हो जायेगी। विवाह, उत्तर विचार, दत्त-विधान आदि सबका कुटुम्ब से सम्बन्ध है। कुटुम्ब और विशेष रूप से समुक्त कुटुम्ब का आय-संरूप में बड़ा महत्त्व है।

भारतवर्ष में प्रारम्भ से ही समुक्त कुटुम्ब प्रथा पायी जाती है। भारत के अधिकांश में पितृकुल ही है। दक्षिण में कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जिनमें मातृकुल भी पाये जाते हैं। कुटुम्ब-प्रथा के पीछे दो विचार प्रमुख हैं—मित्रा पवित्र और साध्वी रहे और उत्तराधिकार का नियंत्रण पुरुषों के हाथ में हो। जबतक समाज में इन दोनों विचारों का आदर होता रहेगा, तबतक कुटुम्ब कायम रहेगा।

समुक्त कुटुम्ब-अथवा

समुक्त कुटुम्ब की प्रथा बहुत प्राचीन है। इसमें पति, पत्नी, पिता, माता, पितामह, पितामही, बहन, भाई, पुत्र, पुत्री, दत्तक पुत्र आदि शामिल हैं। कुटुम्ब के विशेष नियम होते हैं। इन्हें कुल-आचार कहते हैं। जन्मोत्सव, उपनयन, विवाह, खान-पान, सामाजिक रीति रिवाज, उत्तराधिकार और

सदाचार आदि इन कुलाचारों ही पर निर्भर होने हैं । संयुक्त-कुटुम्ब में गृहपति का स्थान सर्वोच्च है और बृहिणी उसके अधीन रहती है ।

हिन्दू-विधान के अनुसार आजकल कुटुम्ब के निम्नलिखित सदस्यों को सम्पत्ति के अधिकार विरासत में मिलते हैं—

(१) पुत्र (२) पौत्र (३) प्रपौत्र (४) पत्नी (५) पुत्री (६) नाती (धेवता) (७) मा (८) पिता (९) भ्राता (१०) भतीजा आदि । दायभाग-कानून के अनुसार वगाल में यदि कोई हिन्दू किसी भी सम्पत्ति को छोड़कर मर जाये या मिताक्षरा कानून के अनुसार कोई हिन्दू अपनी पूरक सम्पत्ति छोड़कर मर जाये तो उसकी एक या सब विधवा स्त्रियों को मिश्रकर उसके पुत्र के बराबर भाग मिलेगा । परन्तु उसका या उनका सम्पत्ति पर वैसा अधिकार न होगा जैसा स्त्री-धन पर होता है ।

संयुक्त कुटुम्ब में स्त्री-पुरुष के अधिकार

संयुक्त-कुटुम्ब में पुरुष को कुटुम्ब में सबसे अधिक अधिकार प्राप्त है । पुत्र का अपने पिता की आधी सम्पत्ति पर अधिकार होता है । वह उसे अपने पिता के जीवन में विभाजित करा सकता है । जबकि वह जीविरोपार्जन के योग्य नहीं हो जाता तबतक पिता से उसे भरण-पोषण का अधिकार है । पिता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या भर्जित सम्पूर्ण सम्पत्ति पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है । वह उसे वसीयत में दे सकता है, बेच सकता है या रहन रह सकता है । उसे सम्पत्ति क्रय करने या भी अधिकार है । वह उसे दान अथवा वहेज में दे सकता है । उसके अधिकार पर बन्धन नहीं है । परन्तु यदि उसके कोई पुत्र है तो उसे उसके अधिकार पर आघात करने का अधिकार नहीं है । यदि पुत्र के आगे हिस्से की उसने भ्रष्ट कर दिया या उसे अनायक्यक दण से खर्च बिचा तो पुत्र को उसे पुनः प्राप्त करने का अधिकार है । पुरुष, सलोप में, गृहस्वामी है । वह वास्तविक अर्थ में गृह का स्वामी है, स्त्री गृह-स्वामिनी है । परन्तु उसके गृह में अधिकार बहुत सीमित है । कुटुम्ब में स्त्रियों में केवल निम्नलिखित स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त है—

(१) विधवा पत्नी (२) पुत्र की विधवा पत्नी (३) पौत्र की विधवा पत्नी (४) पुत्री (५) मा (६) पितामही (७) बहन (८) पौत्री (९) पुत्र की पुत्री ।

स्त्रियों के सम्पत्त्याधिकार दो प्रकार के हैं । एक को हम स्त्री-अधिकार (Woman's Estate) कहते हैं और दूसरे को स्त्री-धन । पुरुष से जो सम्पत्ति विरासत में प्राप्त होती है, वह स्त्री-अधिकार है । उस सम्पत्ति को केवल भोगने का ही उस अधिकार है । उस पर उसका पूर्ण स्वामित्व नहीं होता ।

स्त्री धन पर स्त्री का पूर्ण अधिकार होता है । यहाँ स्त्री-धन का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया है । विशिष्ट स्त्री-धन में निम्नलिखित सम्पत्ति सम्मिलित है—

१ सम्बन्धियों से प्राप्त दान या वसीयत ।

२ वस्त्राभूषण ।

३ विवाह सस्कार के अवसर पर या उससे पूर्व अन्य पुरुषों से प्राप्त दान ।

४ गैर सम्बन्धियों से प्राप्त दान ।

५ कुमारावस्था या विधवावस्था में कश-कौशल द्वारा अर्जित सम्पत्ति ।

६ बम्बई प्रान्त में जो सम्पत्ति स्त्री अपने पितृ-कुल में वसीयत में प्राप्त करती है, यह चाहे पुरुष से प्राप्त की गयी हो या स्त्री से, स्त्री-धन है ।

७ वृत्ति के बदले में मिली सम्पत्ति ।

८ विपरीत कब्जे द्वारा प्राप्त सम्पत्ति ।

९ ग्राट, दान, समझौते या विभाजन द्वारा प्राप्त सम्पत्ति, यदि दाता का उद्देश्य स्त्री को पूर्ण अधिकार देने का हो ।

१० स्त्री धन द्वारा क्रय की हुई सम्पत्ति ।

पुत्रियों के पालन पोषण का भार कुटुम्ब पर होता है । सपुक्त कुटुम्ब के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्रों के पालन-पोषण, उपनयन-सस्कार तथा विवाह का भार भी कुटुम्ब पर होता है । पुत्रियों व बहनों का विवाह भी कुटुम्ब

का करना पड़ता है। विधवा पुत्र बचू का मरक्षक स्वभुर होता है। उसका धर्म है कि वह उसका पालन पोषण करे। यदि कोई स्त्री पति से अलग हो जाये तो उस विधवा अवस्थाका में दृष्टि पान का भी अधिकार है।

मनुस्मृति व अनुसार स्त्री का वात्स्यकाय में माता पिता, सधवावस्था में पति और विधवावस्था में पुत्र के निपणण में रहना चाहिए। हिन्दू कुटुम्ब में स्त्री का मुख्य काम सन्तानोत्पत्ति तथा सन्तान पालन के सिवा गृह काम का प्रबंध करना है। पुण्य घर के बाहर जीविकाप्राप्तन में मग्न रहता है और स्त्रियाँ घर का काम काज करती हैं।^१ गृह की व्यवस्था में स्त्रियाँ का पूरा हाथ होता है। विवाह तथा जन्मोत्सव आदि अवसरों पर उनकी इच्छानुसार ही कार्य होता है।

हिन्दू पति का यह विवाह का अधिकार है। वह एक ही समय में एक से अधिक स्त्रियाँ से विवाह-सम्बन्ध कर सकता है। परन्तु इसका उपयोग प्रायः बहुत कम करते हैं क्योंकि इसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। विधवा विवाह की प्रथा अब पुनः प्रचलित हो गयी है। पर फिर भी ब्राह्मण आदि जातियों में जो बहुत-ही कट्टर हैं अपनी विधवा पुत्रियाँ को मुश्किल होने पर भी अविवाहित रखते हैं, उनका पुनर्विवाह नहीं करते जबकि पुरुषों को पुनर्विवाह का अधिकार है। सती प्रथा तो बहुत पहले से गैर-वातनी घोषित हो चुकी है। फिर भी आजकल कभी-कभी हिन्दू विधवाएँ सती हो जाती हैं। सती होने में मदद करना आज दण्डनीय अपराध है। यह विवाह व रोक्ने के लिए जुलाई १९३८ में क्रमशः बहुविवाह अवरोध कानून तथा यह विवाह नियमन कानून के अन्तर्गत भारतीय राज्यपरिषद् (कांसिल आफ स्टेट) में प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु अभी तक इनके सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं हो सका।

हिन्दू-समाज में बाल विवाह का भी अधिक प्रचार है। यद्यपि रान्

१. ग्रन्थ देश में पति को विवाहोपरांत ससुराल में रहना पड़ता है। पत्नी बाहर जीविकोपार्जन करती है बाजारी में दुकान पर बैठती है और पति गृह के काम काज करते हैं।

१९३० से बाल विवाह अवरोध कानून 'शारदा एक्ट' के नाम से भारत में प्रचलित है जिसके अनुसार १४ वर्ष से कम आयु की कन्या और १८ वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह करना दण्डनीय है। तोभी बाल-विवाह प्रतिवर्ष जहाँ तहाँ होत सुने जाते हैं।

विवाह बहुधा स्वजाति में ही कुल या गोत्र बचाकर किया जाता है। विवाह में दहेज देने का भी अधिक प्रचार है। इसके विरुद्ध कई जातियों में आन्दोलन चल रहा है। आर्यसमाज ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। राष्ट्रीय विचारों के युवक भी इसके समर्थक हैं। लाहौर का जात पाँत तोड़क मण्डल भी अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देता है। इन सब विचारधाराओं के फलस्वरूप सुसंस्कृत तथा शिक्षित युवक-युवतियाँ प्रायः जात-पाँत के बन्धनों को तोड़कर विवाह करने में कोई घुराई नहीं मानते। परन्तु ऐसा 'स्पेशल मैरिज ऐक्ट' के अनुसार ही किया जा सकता है। स्पेशल मैरिज सशोधन ऐक्ट (१९२३) के अनुसार हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख तथा जैन जातपाँत को तोड़कर विवाह कर सकते हैं। उहे अब यह घोषणा करने की जरूरत नहीं कि वे हिन्दू धर्म को नहीं मानते। ऐसा विवाह रजिस्ट्रार के सामने होता है। बाद में धार्मिक संस्कार भी किया जा सकता है। इस विवाह का प्रभाव यह होता है कि पति-पत्नी सयुक्त-कुटुम्ब के सदस्य नहीं रहते। उनका उत्तराधिकार तथा विरासत हिन्दू-विधान के अनुसार नहीं बल्कि भारतीय उत्तराधिकार-कानून के अनुसार होता है। वह किसीका गोद नहीं ले सकता। उसका पिता चाहे तो गोद ले सकता है, मानो उसका यह पुत्र काल-कवलित हो गया हो।

आर्य विवाह-कानून (Arya Marriage Validation Act) के अनुसार अब प्रत्येक आर्यसमाजी को यह अधिकार है कि वह जातपाँत तोड़कर विवाह कर सकता है। यह विवाह वैदिक रीति के अनुसार किया जा सकता है। विवाह की रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं है।

हिन्दू-कानून के अनुसार स्त्री पति को तलाक नहीं दे सकती। केवल प्रथा के अनुसार ही कुछ जानियाँ में स्त्री को तलाक का अधिकार है।

समुक्त कुटुम्ब-प्रथा का भविष्य

हिन्दू-जीवन पर पाश्चात्य ममृति तथा सम्यता का भयंकर प्रभाव पड़ा है। पाश्चात्य देशों में समुक्त कुटुम्ब की प्रथा नहीं है। वहाँ कुटुम्ब में पति-पत्नी होने हैं और जवनाक उनके पुत्रा व पुत्रिया का विवाह नहीं होता तबतक ये भी उनके साथ रहते हैं। बाद में वे अलग रहते हैं। पाश्चात्य देशों में स्त्री-स्वातन्त्र्य तथा व्यक्तिवाद की भावना के कारण समुक्त कुटुम्ब का रिवाज नहीं है। आज भारत में नवीन सम्यता के उपासन पुरुष और पुरुषियाँ भी स्वतन्त्र जीवन चिताने के लिए समुक्त-कुटुम्ब का त्याग कर देत हैं। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। देश के आर्थिक जीवन और औद्योगीकरण का भी समुक्त कुटुम्ब पर प्रभाव पड़ रहा है।

अब जीवन निर्वाह की समस्या इतनी जटिल हो गयी है कि एक व्यक्ति बड़े-बड़े कुटुम्ब का पालन करने में असमर्थ-सा रहता है। गाँवों के लोग शहरों में बाहर बस जाते हैं और भिला तथा कारखाना में मजदूरी करते हैं। शहरों में जीवन चिताना बड़ा क्लिप्तता पड़ता है। इसलिए ये मजदूर घाम से अकेले आत है या अपनी स्त्री-बच्चा को साथ ले आते हैं। इस प्रकार समुक्त कुटुम्ब की प्रथा टूटती जा रही है।

आश्रम-व्यवस्था

पुराने समय में भारतीय श्रमिया ने जिस प्रकार सामाजिक जीवन को चार वर्गों में बाँटा था, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन को भी चार आश्रमा में बाँटा हुआ था। मनुष्य की औसत आयु १०० वर्ष मानी गयी है। इसीके आधार पर मानव-जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया था—ब्रह्मचर्य्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सबने पहले २५ वर्ष तक मनुष्य को ब्रह्मचर्य्य का पालन करना चाहिए। इसके बाद विवाह करके अपनी सत्समिणी के साथ समाज-सवा में रत रहना चाहिए। ५० वर्ष की आयु तक गृहस्थ-जीवन चिताना चाहिए। बाद में वानप्रस्थी बनकर वन में योग-साधना और स्वाध्याय करना चाहिए।

इसकी अवधि ७५ वर्ष की आयु तक है। इसके बाद १०० वर्ष अर्थात् मृत्यु पर्यन्त सन्यासी रहना चाहिए।

परन्तु आज वर्ण-व्यवस्था के साथ यह आश्रम व्यवस्था भी नष्ट हो चुकी है। आज का हिन्दू जीवन वैदिक-जीवन नहीं रहा। उसमें मौलिक परिवर्तन हो गया है। आज सिवा आर्य समाज के गुरुकुलों के और कहीं 'ब्रह्मचारी' नहीं मिलेंगे। गुरुकुलों में २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है।

सन्यासियों का हिन्दू समाज में बड़ा महत्त्व है। उनकी बड़ी 'पूजा' की जाती है। आज भारत में ५२ लाख से भी ज्यादा साधु और सन्त हैं जो हिन्दू गृहस्थों के ७१ करोड़ से भी अधिक रुपये प्रतिवर्ष खाने-पीने नशे, कपड़े लस्ते और भोग विलास में व्यय करते हैं। जिस देश में रात-दिन मेहनत करनेवाले मजदूर दो वस्त्र मामूली खाना भी नहीं खा सकते, उस देश में भारत के २३६ करोड़ हिन्दुओं के पसीने की कमाई पर ५० लाख साधु महत्त और सन्तों का खाना, पीना और मौज उड़ाना हिन्दू समाज की अध-थड़ा का एक ज्वलन्त प्रमाण है।

अस्पृश्यता

'अस्पृश्यता' हिन्दू धर्म का महान् पाप है उसपर लगी हुई जग है। भयजो का तिरस्कार करना मनुष्यता को खो देता है।^१

'अस्पृश्यता' नाम का रोग हिन्दू समाज की ही एक विशेषता है। हिन्दू शास्त्रों में छत्राछूत पर धार्मिक आवरण डाल दिया जाने से वह बद्धमूल हो गया है। यह वास्तव में एक महान् सामाजिक पाप है जो हिन्दुओं ने अपने ही धर्म ग्रन्थों के साथ किया है। किसी वर्ग को अस्पृश्य घोषित कर देना वास्तव में मानवता का अपमान ही है। आज भारत में ६ करोड़ से भी अधिक हिन्दू नर-नारी अस्पृश्यता के अभिशाप का दुःख भोग रहे हैं। उन्हें हिन्दू समाज में रहते हुए न धार्मिक अधिकार है, न

सामाजिक अधिकार और न राजनैतिक अधिकार ही प्राप्त ह । व अपने ग्राम व नगर के सार्वजनिक स्थानों, सस्थाओं, स्कूला, मन्दिरों, नदी, तालाब तथा कुओं का प्रयोग स्वतन्त्रता से नहीं कर सकत ।

महात्मा गांधी ने सबसे पहले हिन्दू-समाज के इस पाप व निन्दित सन् १९३२ में देशव्यापी आन्दोलन चला किया । उनसे पूर्व भी आर्यसमाज के प्रसिद्ध नेता स्वामी श्रद्धानन्द ने दक्षिण भारत-आन्दोलन और पंजाब के प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय ने अछूतों-आन्दोलन चला दिया । अनेक समय में इन आन्दोलनों का एक सीमा तक सफलता भी मिली । परन्तु महात्मा गांधी ने जो आन्दोलन सन् १९३० में 'साम्प्रदायिक' निर्णय के विरोध में यरवदा-जेल में बन्दी की दशा में शुरू किया, वह कई दृष्टियों में सबसे महत्त्वपूर्ण है ।

महात्माजी ने सबसे गहरा प्रहार अस्पृश्यता की धार्मिकता पर किया । उन्होंने ससार और हिन्दू-समाज का यह चुनौती दी कि वह यह सिद्ध करे कि क्या या जात्रा में अस्पृश्यता का विधान है । उन्होंने यह घोषणा की कि अस्पृश्यता धार्मिक नहीं है । वह एक सामाजिक पीढ़ है । उसका निर्माण समाज ने किया है अतः उसका नाश भी समाज के उद्योग से ही संभव है ।

साम्प्रदायिक निर्णय के विरोध में जब गांधीजी ने यरवदा-जेल में आमरण अनशन रखा तब २५ मिनम्बर १९३० को बम्बई में सनातन हिन्दू-धर्म के महान् नेता ५० भद्रनमोहन भागवत के सभापतित्व में हिन्दुओं और हिन्दू नेताओं ने सर्व-सम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया—

“यह सम्मेलन यह निश्चय करता है कि भविष्य में हिन्दुओं में कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण अछूत नहीं माना जायेगा और अज्ञान या ऐस माने गये हें उन्हें सार्वजनिक कुआ, स्कूल, सड़क, और मन्दिर सार्वजनिक सम्पत्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में हमारे हिन्दुओं के समान अधिकार होगा । प्रथम सुयोग प्राप्त होने पर इस अधिकार का कानूनी स्वीकृति दी जायेगी । यदि पहले से ही इसे कानूनी स्वीकृति नहीं मिली, तो यह संसद या कानून के प्रथम कानूनों में सम्मिलित होगा ।

और यह भी निश्चय किया गया है कि समस्त हिन्दू नेताओं का यह वक्तव्य होगा कि वे समस्त शान्तिमय और वैध उपायों द्वारा दलित वर्ग पर लादी गयी समस्त सामाजिक अयोग्यताओं और भेद पर प्रवर्ण के संशोधन में प्रतिबद्ध वे निवारण के लिए शीघ्र प्रयत्न करें।

इस प्रस्ताव द्वारा समस्त हिन्दू नेताओं ने यह घोषणा की कि भविष्य में कोई भी हिन्दू अपने जन्म के कारण अछूत न माना जाएगा और साथ ही इस प्रस्ताव के दूसरे भाग द्वारा यह निश्चय किया गया कि दलित वर्ग पर जो सामाजिक प्रतिबन्ध तथा मन्दिर प्रवेश के सबंध में जो रुकावट है, उसे शान्तिमय तथा वैध उपायों द्वारा शीघ्र दूर करने का प्रयत्न किया जाय। शान्तिमय तथा वैध उपायों का अन्तर्गत धारा समा द्वारा कानून निर्माण भी शामिल है। इस प्रकार इन अयोग्यताओं के निवारण तथा मन्दिर प्रवेश की सुविधा देने के लिए वैद्रीय धारा समा तथा प्रान्तीय धारा समाओं का उपयोग किया जाना उचित है।

हरिजन नाम देकर हरिजन सेवा, आदि दशव्यापी आन्दोलन के सूत्रधार महात्मा गांधी हैं।

हरिजन सेवक-संघ नाम की एक अखिल भारतीय संस्था का कार्य ही इन अधिकार वंचित हिन्दुओं की तरह-तरह से सेवा करना तथा छुआछूत को मिटाना है, इसी शाखाओं के रूप में प्रत्येक प्रान्त में हरिजन सेवक संस्थाएँ कार्य कर रही हैं।

मुस्लिम जीवन

हिन्दू और मुस्लिम सामाजिक जीवन में स्पष्ट अंतर दिखायी देता है। मुसलमानों की आदर्श समाज व्यवस्था का मूलधार सामाजिक एकता की भावना है। मुस्लिम समाज में प्रत्येक मुसलमान बराबर है। यद्यपि मुसलमानों में हिन्दू समाज जैसी ३००० से भी ऊपर जातियाँ और अगणित उपजातियाँ नहीं हैं, तो भी मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो बड़े सम्प्रदाय हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक सम्प्रदाय और जातियाँ हैं। उत्तराधिकार विरासत, वसीयत, विवाह वक्फ आदि के सबंध में

मुसलमानों की व्यवस्था मुसलिम-कानून के अनुसार होती है। मुसलमानों में हिन्दू सयुक्ताकुटुम्ब-प्रथा जैसी कोई सत्वा नहीं है। सम्मिलित रहने में वे सम्मिलित कुटुम्ब नहीं कहला सकते।

उत्तराधिकार

१

मुसलमानों में दा सम्प्रदाय प्रमुख है और उन दोनों के कानून भी भिन्न-भिन्न हैं। हनफी-कानून (सुन्नी-कानून) के अन्तर्गत उत्तराधिकारी तीन श्रेणियों में विभाजित हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों के हिस्से कानून द्वारा निर्धारित हैं जा निम्न प्रकार हैं—

(१) पिता (२) पितामह (३) पति (४) पत्नी (५) मा (६) पितामही (७) पुत्री (८) पोत्री (९) सहोदर भ्राता (१०) सहोदर बहन इत्यादि।

इन सबके हिस्से निर्धारित हैं। इनको देने के बाद दूसरी श्रेणी के उत्तराधिकारियों को हिस्सा मिलता है। पुत्र और पति दूसरी श्रेणी में आते हैं। परन्तु अबस्था इसप्रकार की गयी है कि पुत्र व पत्नी के लिए बाकी हिस्सा बच रहता है। शिया-कानून के अनुसार उत्तराधिकारियों को ३ भागों में बाँटा गया है—प्रथम श्रेणी में रक्त-सम्बन्ध रखनेवाले वारिस आते हैं जैसे माता-पिता और उनकी सन्तान, पितामह और पितामही तथा भाई और बहन और उनकी सन्तान, चाचा तथा मामा और उनकी सन्तान, पितामह और पितामही तथा भाई और रतन और उनकी सन्तान, चाचा तथा मामा और उनकी सन्तान, पति-पत्नी विवाह-अभ्यर्थ में उत्तराधिकारी हैं। मुसलमानों का उत्तराधिकार कानून इतना जटिल और पेचीदा है कि उसे समझना एक समस्या है।

सम्पत्त्याधिकार की दृष्टि से मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति हिन्दू-महिलाओं से बड़ी उत्तम और श्रेष्ठ है। मुस्लिम महिलाओं को अपने हिस्से पर पूर्ण अधिकार होता है। मुसलमान अपनी सम्पत्ति को वसीयत में भी दे सकता है। परन्तु किसी वारिस के नाम वसीयत उस समय तक बंध नहीं मानी जाती जबतक कि वसीयत करनेवाले की मृत्यु के बाद

दूसरे वारिस अपनी सम्पत्ति न दद। मुसलमान एक तिहाई से अधिक सम्पत्ति वसीयत द्वारा नही द सकता। यह एक तिहाई भाग विधवा-वधू के साथ तथा बच्चों का अदा करने के बाद जा रहे उमरा हिम्मा माना जाता है। मुसलमान को अपनी सम्पत्ति दान करने का अधिकार है। वह अपनी सारी सम्पत्ति अपने वारिस को भी दान कर सकता है।

विवाह

विवाह को मुसलमानों में धार्मिक मस्कार नहीं माना जाता। वह केवल एक समझौता है जिसका उद्देश्य सन्तानोत्पादन और धन का कानूनी अधिकार-युक्त बनाना है। मुसलमानों में विवाह १५ वर्ष की आयु में किया जा सकता है। परन्तु यदि किसीका विवाह उसकी सम्पत्ति के बिना किया जाये और विवाह के समय उसकी उम्र १५ वर्ष की हो तथा विभाग भी सही हो तो ऐसा विवाह अवैध होगा। विवाह के लिए एक पक्ष की आर से प्रस्ताव होना चाहिए और दूसरे पक्ष द्वारा उसे स्वीकृति दी जानी चाहिए। यह भाग्य दो साक्षियों के सामने होना चाहिए। प्रस्ताव और उसकी मजूरी एक ही मित्र में होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव एक घर दिया गया हो और उसकी स्वीकृति एक या दो दिन बाद दी जाये तो यह उचित नहीं। विवाह के लिए किसी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक दायरे की आवश्यकता नहीं है। एक मुसलमान एक समय में एक साथ चार पत्नियाँ रख सकता है। मुसलमान अपनी मा, माता नहीं पुत्री पौत्री प्रपौत्री बहन चाची तथा मामी के साथ विवाह नहीं कर सकता। वह अपनी सास अम्मी पत्नी की पुत्री अपने पिता की स्त्री या अपने पुत्र की वधू से भी विवाह नहीं कर सकता। परन्तु दो भाइया या बहनों की सन्तानों में परस्पर विवाह हो सकता है।

गिरा कानून दो प्रकार के विवाहों को स्वीकार करता है एक अस्थायी और दूसरा अस्थायी। एक मुसलमान पुरुष मुस्लिम इसाई यहूदी या पारसी स्त्री के साथ अस्थायी विवाह कर सकता है। परन्तु शिया स्त्री किसी गैर मुस्लिम पुरुष से अस्थायी विवाह नहीं कर सकती। यह अस्थायी विवाह क्या है? अस्थायी विवाह के लिए यह जरूरी है कि

सहगमन की अवधि नियत कर दी जाये—यह एक दिन, एक मास या एक साल या अधिक समय के लिए हो सकती है और दूसरी बात यह है कि महर निर्धारित कर दिया जाये। जबकि महर निर्धारित नहीं किया जाये तब तब अस्थायी विवाह वैध नहीं हो सकता।

प्रत्येक मुस्लिम स्त्री को विवाह के समय निर्धारित दहेज (Dower) वर की ओर से भेंट किया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। एक तो सुहागरात से पूर्व देना होता है और दूसरा तलाक या मृत्यु के समय उसके वारिस को देना पड़ता है।

तलाक

मुसलमानों में तलाक की प्रथा है। विवाह-सम्बन्ध-विच्छेद तीन प्रकार से हो सकता है—

- (१) पति-द्वारा अपनी इच्छानुसार,
- (२) पति-पत्नी की परस्पर सम्मति से,
- (३) पति या पत्नी की प्रार्थना पर न्यायालय के निर्णय से।

मुस्लिम पति को जिसका दिमाग सही है तथा जिसकी उम्र १५ साल की है अपनी पत्नी को अपनी इच्छा से बिना कोई कारण बताये तलाक देने का अधिकार है।^१ यह वास्तव में स्वेच्छा की परंपरा है।

पति-पत्नी परस्पर सम्मति से तलाक दे सकते हैं। परन्तु पत्नी को अपनी ओर से तलाक देने का अधिकार केवल निम्न स्थिति दगाओ में ही प्राप्त है। ये दगाएँ निम्न प्रकार हैं—

(१) पति की नपुंसकता, परन्तु नपुंसकता विवाह के समय होनी चाहिए और उसके बाद भी बरकरार रही हो और तब उसे उसका ज्ञान न हो।

(२) यदि पति ने पत्नी पर ब्याभिचार का भ्रम दोगारोपण किया हो।

मुस्लिम स्त्री केवल उपर्युक्त दो आधारों पर ही तलाक के लिए न्यायालय से प्रार्थना कर सकती है ।

यदि उसका पति व्यभिचार करता है, उपपत्ती रगता है, या उसकी परवरिश नहीं करता है, तो भी पत्नी के लिए विवाह-सम्बन्ध को तोड़ने का अधिकार नहीं है । इस सम्बन्ध में मुस्लिम स्त्री का भाग्य ऐसा नहीं है कि हिन्दू महिला उससे ईर्ष्या करे ।

मुस्लिम महिलाओं में परदे की बड़ी भयंकर कुप्रथा है । इस परदे की प्रथा ने स्त्रियों को विलास की सामग्री बना दिया है । परदे की प्रथा के कारण न स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार व प्रसार हो सकता है और न वे सामाजिक या राजनीतिक आन्दोलन में पुरुषों का हाथ बढ़ा सकती हैं ।

विवाहों के अवसरों पर दहेजों का रिवाज भी मुसलमानों में बहुत अधिक है ।

मुसलमानों में हिन्दू-समाज की तरह जाति-भेद भी है । जो लोग मुसलमान बनाये जाते हैं, वे अक्सर हिन्दुओं के दलितवर्ग के व्यक्ति ही होते हैं । वे मुसलमान होकर भी मुस्लिम समाज में 'दलित' ही बने रहते हैं । उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता ।

ईसाई, पारसी आदि जीवनों का यद्यपि भारतवर्ष में अस्तित्व है, जिसका परिचय धार्मिक जीवन में दिया गया है । पर उनका भारतीय सस्कृति में कोई विशेष स्थान नहीं है ।

नागरिकों का स्वास्थ्य

मुक्तपूर्वक जीवनयापन के लिए स्वास्थ्य अत्यन्त आवश्यक है। यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है।' हममें से प्रत्येक अपने अनुभव से यह जानता है कि यदि हमारे शरीर में कोई कष्ट और पीड़ा हो तो उसका हमारे चित्त और मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है, वह खिन्न और दुखी रहता है।

भारतवर्ष में जनता में स्वास्थ्य के प्रति बड़ी उपेक्षा की भावना देखी जाती है। जनता मुन्दर स्वास्थ्य वा न मूल्य समझती है और न आवश्यकता। फिर उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करना तो दूर रहा। यही कारण है कि हमारे देश में जन्म और मृत्यु की औसत संख्या अन्य देशों से बहुत बढ़ी-चढ़ी है। बाल-मृत्यु तथा प्रसूताओं की भीषण मृत्यु-संख्या बड़ी भयानक है और हृदय को कँपा देनेवाली है।

स्त्री-पुरुषों की मृत्यु संख्या का अनुपात

मृत्यु-संख्या वा अनुपात प्रति १०० जन्म इस प्रकार है—

आयु	बालक	बालिकाएँ
■	२४.८७	२०.२१
१	९.१८	८.६५
२	५.६४	५.०६
३	३.९२	३.४०
४	२.७४	२.३३
५	१.९२	१.६५
६	१.४५	१.२५
७	१.१५	१.०१
८	.९४	.८८
९	.८२	.८२

भारत की मृत्यु-संख्या (आयु के अनुसार अनुपात)

आयु	प्रतिशत बालक	प्रतिशत बालिकाएँ
१०	७९	८१
११	८१	८४
१२	८४	८८
१३	८८	९३
१४	९३	१०२
१५	९८	११५
१६	१०४	१३०
१७	११०	१४०
१८	११६	१५६
१९	१२१	१६६
२०	१२७	१७६

दूसरे देशों की तरह भारत में भी बालक बालिकाओं से अधिक पैदा होते हैं। अर्थात् भारत में बालिकाओं की प्रतिशत जन-संख्या के लिए बालकों की जन-संख्या १०८ है। इंग्लैण्ड में बालकों की ऐसी जन-संख्या १०५ है। इसी कारण ९ वर्ष की आयु के भीतर बालकों की मृत्यु-संख्या का अनुपात बालिकाओं की मृत्यु संख्या के अनुपात से अधिक रहता है।

परन्तु १० वर्ष की आयु से बालिकाओं की प्रतिशत मृत्यु-संख्या एकदम बढ जाती है और बालकों की प्रतिशत मृत्यु संख्या से आगे निकल जाती है।

भारतवर्ष में ५५ वर्ष की आयु के बाद पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा मृत्यु-संख्या अधिक होती है। युरोप में भी यही बात है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ दीर्घजीवी होती हैं। ग्रेट ब्रिटेन में ८० वर्ष से ऊपर की आयुवाले मनुष्यों में पुरुषों से स्त्रियाँ दोगुनी हैं। सन् १९३२ में १०० वर्ष के ऊपर आयुवाले १८ मनुष्य मरे। इनमें केवल ३ ही पुरुष थे, शेष स्त्रियाँ थीं।

सन्	जन्म	अनुपात प्रति १०००	मृत्यु	अनुपात प्रति १०००
१९३१	९१,३५,८९०	३४३	६५,१५,०९९	२४.९०
१९३२	९०,५४,५०६	६६७८	५८,०५,६६९	२१.८५
१९३३	९६,७८,८७६	३६.४३	६०,९६,७८७	२२.९५
१९३४	८२,८८,८९७	३३.७	६८,५६,२४४	२३.००
१९३५	९६,९८,७९४	३४.९	६५,७८,७११	२३.६

उपर्युक्त १० वर्षों की मृत्यु और जन-संख्या के अकों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जन्म और मृत्यु-संख्या में समीपति होती रही है।

सन् १९३० की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति १००० जन्म पीछे १८०.८३ बालक-बालिकाओं की मृत्यु का अनुपात है। इन दस वर्षों में इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। भारत में बाल-मृत्यु अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही अधिक है। नगरों में और विशेषतः बड़े-बड़े नगरों में मृत्यु का अनुपात तो और भी अधिक है। ५ वर्ष तक की आयु के बालकों की मृत्यु संख्या एक लाख जन्म पीछे ४५ हजार है।

भारत की जन-संख्या में वृद्धि

भारत की जन-संख्या में उत्तरात्तर वृद्धि होती जा रही है। जन-संख्या की वृद्धि के सम्बन्ध में निम्नलिखित अकों से इस वृद्धि का अनुपात ज्ञात हो जायेगा —

सन्	भारत की जन-संख्या	वृद्धि की संख्या
१८९१	२८,७३,१४,६७१	
१९००	२९,४३,६१,०५६	+ ७०,४६,३८५
१९११	३१,५१,५६,३९६	+ २,०७,९५,३४०
१९२१	३१,८९,८२,४८०	+ ३८,३६,०८४
१९३१	३५,२८,३७,७७८	+ ३,३८,५५,२९८

इस वर्ष (१९४१ में) जो मनुष्य-गणना हुई है, उसके अनुसार भारत की जन-संख्या प्रायः ४० करोड़ हो गयी है। इस प्रकार १०

वर्षों में प्रायः ५ करोड़ जन-संख्या की वृद्धि हुई।

जन-संख्या में यह वृद्धि वास्तव में एक बड़ी विकट समस्या है। भारत में भीषण दरिद्रता की छाया में जनता की संख्या में वृद्धि वास्तव में एक ऐसी समस्या है जो समाज-शास्त्रियों के लिए एक आश्चर्य है। भारत में इतने भीषण रोगों, भयंकर बीमारियों तथा बालमृत्यु-संख्या के बावजूद भी यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है और यदि उसी क्रम से संख्या में वृद्धि होनी रही तो इस बढ़ती हुई संख्या के पालन पोषण की समस्या बड़ा विकट रूप धारण कर लेगी।

प्रसूति-काल में मृत्यु

भारत में बहुत छोटी आयु में विवाह हो जाने से स्त्रियाँ छोटी आयु में ही गर्भधारण करने लगती हैं। शारीरिक अवस्था भी गर्भधारण के पूर्णतः अपेक्षणीय होती है इसलिए यहाँ प्रसूति-काल में ही माताएँ रोगिणी बन जाती हैं और शीघ्र ही मृत्यु के मुख में चली जाती हैं।

बालमृत्यु सम्बन्धी अक्ष देखने से यह भलीभाँति प्रमाणित हो जाता है कि १६ वर्ष की अवस्था तक बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की मृत्यु अधिक संख्या में होती है। परन्तु इस आयु के बाद जब वे गर्भधारण करने लगती हैं तो उनकी मृत्युसंख्या का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा घट जाता है। १५ से ४० वर्ष की अवस्था में स्त्रियों की मृत्यु अधिक होती देखी गयी है। इसके कई कारण हैं—(१) बाल-विवाह (२) कम आयु में शरीर की दुर्बल अवस्था में गर्भधारण (३) प्रसूति-काल में दुर्बल अवस्था (४) स्वच्छ वायु, प्रकाश और स्थान का अभाव (४) पोष्टिक भोजन का अभाव।

प्रसूति काल में माताओं की मृत्यु के सम्बन्ध में १९३३ में सर जान मिगाड ने जाँच की थी। उनके अनुसार प्रसूताओं की मृत्यु के अंक १७५ प्रति हजार हैं।

उनका कथन है कि १००० बालिका माताओं में १०० माताओं की मृत्यु तो प्रसूति-काल में ही हो जाती है और भारतवर्ष भर में

लगभग २ लाख माताएँ प्रतिवर्ष बच्चों के जन्म होने के समय प्रसूति-गृह में मर जाती हैं ।

सन् १९३८-३९ में कलकत्ता में अविल भारतवर्षीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था (All India Institute of Hygiene and Public Health) की ओर से एक साल तक प्रसूताओं की मृत्यु के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की गयी थी । ८८७ प्रसूताओं की मृत्यु के कारणों की जाँच की गयी । इनमें से ७०१ प्रसूताओं की मृत्यु का कारण प्रत्यक्ष रूप से गर्भ-प्रारण सम्बन्धी था और १८६ प्रसूताओं की मृत्यु का कारण वे रोग थे जो गर्भप्रारण से सम्बन्ध रखते हैं । प्रसूताओं में रक्त का अभाव, विषमय गर्भपान, प्रसूति सम्बन्धी विषाक्रमण और प्रसूति के बाद यथमा ना आक्रमण ही प्रमुख कारण हैं जो उनकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं । इनमें ४०% मृत्यु सरस का कारण यथा था । और २३.०% मृत्यु-मरणा का कारण रक्त का अभाव था ।

जीवन-काल का औसत

संसार के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध देशों का आयु का औसत (वय. में) इस प्रकार है—

सन्	देश	पुरुष	स्त्री
१९३१	भारत	२६ ९१	२६ ५६
१९२६	जर्मनी	५५ ९३	५८ ८२
१९२३	फ्रांस	५२ १९	५५ ८७
१९२२	ग्रेट-ब्रिटेन	५५ २०	५९ ५८
१९२०	इटली	६९ २५	७० ३५
१९२७	रूस	८१ ९३	६२ ३३
१९२०	जापान	८० ०६	८३ २०
१९२५	स्वीडन	६० ३२	६२ ९५
१९००	डेनमार्क	५४ २५	५८ ५५

भारत में औसत आयु २६ वर्ष है । परन्तु जर्मनी और इंग्लैंड में ५५

वर्ष से भी अधिक औषध आयु है। कितना महान् अनन्तर है। 'जीवेम शरदं शतम्' का माय प्राण ग्राह करनेवाली आर्थ-सतति का यह पतन कितना भयावह है।

सन् १९३१ में भारत में प्रान्तों के अनुसार औसत आयु इस प्रकार है—

प्रान्त	स्त्री	पुरुष
बंगाल	२८ ९१	२४ २१
बम्बई	२७ ८४	२६ ३७
मद्रास	२८ ७१	३० ०४
पंजाब	२८ ०५	२६ ५७
संयुक्तप्रान्त	२४ ५६	२५ ०९
बिहार-उड़ीसा	२८ ८८	२६ ९०
- मध्यप्रान्त	२८ १०	२८ २१

सन्नामक रोगों की वृद्धि और भीषणता

भारतवर्ष में मलेरिया, हैजा, इन्फ्लुएन्जा, चेचक, मोतीझरा, प्लेग तथा यक्ष्मा आदि भयंकर सन्नामक रोगों की दिन पर दिन वृद्धि हो रही है। सरकार की ओर से अभी तक इन रोगों के निवारण के लिए कोई प्रभावशाली कार्यक्रम बनाकर काम नहीं किया गया। प्रतिवर्ष मलेरिया से भारतवासी सबसे बड़ी संख्या में मर जाते हैं, परन्तु अभी तक उसके प्रतिकार का कोई उपाय नहीं किया गया। आजकल राजयक्ष्मा रोग भारतीय ग्रामों और नगरों में बड़े व्यापक रूप में फैल रहा है। इस रोग की दिन पर दिन वृद्धि के कारण केवल मृत्यु की संख्या में ही वृद्धि नहीं होनी बल्कि यह महा भयानक रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य का बड़ा घातक भी बन रहा है।

सन् १९३५ की जन-गणना के अंकों के अनुसार समस्त ब्रिटिश भारत में ६५ ७८,७११ स्त्री पुरुष तथा बच्चे प्रतिवर्ष मरे और उसका व्योरा इस प्रकार है —

पागड़	१ २०,२०८
गूंगे पहरे	० ३०,८९५
कोडी	१,४७,९११
अधे	६,०१,३७०

इस प्रकार कुल ११ लाख असाहिज थे। यदि इन सब असाहिजा को इकट्ठा किया जाये तो कलकत्ते के बराबर नगर बस जायेगा, जो ब्रिटिश साम्राज्य में लन्दन के बाद दूसरा विशाल नगर है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि असाहिज कितने अधिक हैं।

अस्वास्थ्य के कारण

भारतवर्ष में अस्वास्थ्य के निम्नलिखित कारण देखने में आये हैं—

जल-वायु का प्रभाव—भारतवर्ष के अनेक भागों की जल वायु स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त और अनुकूल नहीं है। अनेक भागों में वर्षा की अधिकता के कारण मच्छर आदि रोगों के जीवाणु अधिक पैदा हो जाते हैं जिनसे रोगों में वृद्धि हो जाती है। भारत के अधिकांश भाग में गरमी अधिक पड़ती है और उसका भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग पंजाब तथा सीमाप्रांत और पहाड़ी प्रदेशों में रहते हैं, उनका स्वास्थ्य उत्तम है, पर जो बंगाल तथा मद्रास प्रान्तों में रहते हैं वे अस्वस्थ और शरीर से अत्यन्त दुबल हैं।

स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों के प्रति अवहेलना—भारतवासियों में और विशेषतः अशिक्षित तथा गरीब जातियों में स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन नहीं किया जाता। शारीरिक स्वास्थ्य तथा गृह और वास-पास के वातावरण को सुदृढ़ रखने की ओर नागरिकों का ध्यान त्रिकुल नहीं है। भारत में सनातन रागा का प्रकोप जो प्रतिवर्ष भयंकर रूप में होता है और जिसमें लाखों मनुष्य मर जाते हैं, उसकी वृद्धि का कारण भी जनता का अज्ञान है। ग्रामीण और नगरों में ऐसे लोगों की संख्या सबसे अधिक है जो रोगों के कीटाणुओं के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते। इसी कारण वे छतछान का भी ध्यान नहीं रखते। स्वास्थ्य तथा

के पेट में जाते हैं तो उन्हें भी हैजा होजाना है ।

प्रत्येक व्यक्ति जहाँ अपने शरीर, वस्त्र, गृह आदि की शुद्धता और सफाई रखे वहाँ उसका यह भी मतव्य है कि वह अपने पड़स तथा बस्ती या ग्राम की सफाई तथा स्वास्थ्य के लिए नियमों का पालन करे ।

भय और अध विश्वास—भारतवासियों के अस्वास्थ्य का एक छिपा रह य है धार्मिक अध विश्वास तथा भिष्या भय । मनुष्य में ही क्या प्रायेव प्राणी में आत्म रक्षा तथा स्वजाति रक्षा की प्रबल भावना है । इसी कारण उसमें भय का भी भाव है । मनुष्य अपनी तथा स्वजाति की रक्षा के लिए अनेक जानवरों व चीजों से भयभीत रहता है—घाँस, बिच्छू, शेर, बिजली आदि ।

यह ठीक है और आत्म रक्षा के लिए ऐसी छतरनाक चीजों तथा जीवों से आनी रक्षा करना बुद्धिमानी है । परन्तु अज्ञान-वश लोग ऐसे कल्पित भय के शिकार बने रहने हैं कि जिनका इस जगत् में कोई अस्तित्व नहीं । भूत, चुड़ैल, देवी देवता, काली, भवानी आदि ऐसे कल्पित जीव हैं जिनकी स्वार्थी लोगों ने अपनी जीविका के हेतु कल्पना करली है । इस प्रकार के अज्ञान से लोग किसी भयकर बीमारी से आक्रान्त होजाने पर देवी-देवता की, भूत प्रेत की पूजा करते हैं—जात (याना) को जाते हैं और देवता को मनाने के लिए न जाने क्या क्या मूर्खता पूर्ण दुष्कर्म करते हैं । परन्तु अज्ञान के कारण उन्हें यह पता नहीं चलता कि ये सब भिष्या पाखण्ड हैं । इस प्रकार भूत प्रेतों की पूजा में लगकर न रोगी के राग की चिकित्सा करायी जाती है और न उसे किसी डाक्टर या वैद्य को दिखाया जाता है । फलतः असावधानी के कारण उसकी मृत्यु होजाती है । नवयुवकी स्त्रियाँ भी कामोन्माद के कारण हिस्टीरिया राग का आक्रमण होजाता है । मूर्खों स्त्रियाँ समझती हैं कि यह चुड़ैल का चक्कर है और फिर उसका उपचार करती हैं ।

(१) प्रसव क्रिया का अवंतानिक ढंग

माताओं और बालकों की मृत्यु सत्या में वृद्धि का मूलकारण है

गर्भवती स्त्रियों का गिरा हुआ स्वास्थ्य तथा भूर्त्ता दाइयों द्वारा प्रसव क्रिया का सम्पादन । वच्चे जनाने का काम ग्रामों और नगरों में अतिशय तथा गैरार दाइयों द्वारा किया जाता है । वे अपने स्वास्थ्य के नियमों के प्रति अज्ञान के कारण प्रसव के समय शुद्धि का ध्यान नहीं रखती । फलतः प्रसूत-काल में स्त्री के गर्भाशय में विष का संचार होजाता है । इस प्रकार प्रसूनाएँ रोगी होकर मर जाती हैं । इस और कई प्रान्तों की सरकारों ने म्युनिंसिपल बाडों-द्वारा शिक्षित धानियों (Midwives) तथा परिचारिकाओं (Nurses) की व्यवस्था करदी है जो गिरा किसी कीस के प्रसव क्रिया का सम्पादन करती हैं । प्रत्येक बड़े नगर में स्वस्थ-केन्द्र तथा प्रभूता केन्द्र (Maternity Centers) खुल गये हैं, तो भी इस दिशा में अभी बहुत-कुछ करने की जरूरत है । ग्रामों में भी ऐसी ही व्यवस्था हो जानी चाहिए ।

(२) परदा-प्रथा

भारतवर्ष के समुक्तप्रान्त, बिहार, राजस्थान, मध्य- भारत तथा उड़ीसा और कुछ देशी राज्यों में मुसलमानों तथा हिन्दुओं में परदे की बड़ी बुरी प्रथा आज भी प्रचलित है । बंगाल, पंजाब, मद्रास, बम्बई, आसाम तथा महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में स्त्रियों में परदे का विस्तृत रिवाज नहीं है । भारत में परदे के कारण स्त्रियों को हर समय घर की जेल में बन्द रहना पड़ता है । वे न शुद्ध हवा पा सकती हैं और न टहलकर अपने स्वास्थ्य को सुधार सकती हैं । परदे के विरुद्ध जबसे आन्दोलन छिडा है और जबसे राष्ट्रीय आन्दोलन ने जोर पकडा है तबसे इस दिशा में कुछ सुधार हुआ भी है । प्रसन्नता की बात है कि शिक्षित समाज में से परदा विदा होता जा रहा है ।

(३) शुद्ध तथा पोटिक साधन-पदार्थों का अभाव

अस्वास्थ्य का एक बड़ा प्रमुख कारण है शुद्ध साधन-पदार्थों का अभाव । आजकल के बाजार में प्रायः कोई भी साधन वस्तु शुद्ध रूप में नहीं

मिळती। आटा, चायू, दाल आदि सड़े-गले मिलते हैं। मिठाइयाँ मिलावट के घी की या खराब तेल की होती हैं और दूध आदि तरल पदार्थ शुद्ध नहीं मिलते। जय राष्ट्र के नागरिकों को ये शुद्ध भौतिक पदार्थ खाने के लिए न मिलेंगे तो फिर उनका स्वास्थ्य अच्छा कैसे बनेगा ? म्युनिसिपल बोर्डों तथा जिला बोर्डों की ओर से शुद्ध-भोजन में मिलावट के विरुद्ध कानून चलाये गये हैं, परन्तु कर्मचारियों और अधिकारियों की उपेक्षा तथा अवहेलना के कारण इनका ठीक ठीक पालन नहीं हो रहा है।

(४) असयत जीवन तथा मादक-द्रव्यों का प्रयोग

भारतवर्ष में जीवन को सदाचारी बनाने की ओर दूसरे देशों की अपेक्षा जितना ही अधिक उपदेश दिया जाता है उतना ही कम उस पर आचरण किया जाता है। समाज में व्यभिचार गुप्त व्यभिचार, बलात्कार तथा वेश्यावृत्ति का चक्र समूचे समाज के स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। भारत में बढती हुई दुष्कृतियाँ तथा अपराध इसका स्पष्ट प्रमाण हैं। रहा-सहा स्वास्थ्य मादक-द्रव्यों के प्रयोग द्वारा नष्ट हो रहा है। भारत के नगरों में मिल और कारखाना के पास ही मादक-द्रव्यों की दूकानें हैं जिन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। मजदूर लोग ८—१० घण्टे काम करने के बाद अपनी थकावट मिटाने को शराब, ताड़ी या अफीम आदि का सेवन करते हैं। सन् १९३७ में जब ७ प्रान्तों में कांग्रेस ने मद्य-पद ग्रहण किया, तब महात्मा गांधी की प्रेरणा तथा आदेश से कांग्रेस मंत्रियों ने अपने अपने प्रान्तों में मादक-द्रव्यों के निषेध (Prohibition) के लिए उद्योग किया था। और मद्रास बम्बई, सयुक्त प्रान्त, बिहार उड़ीसा, व मध्यप्रदेश में शराबबन्दी कुछ चुने हुए विशेष जिलों व नगरों में की गयी थी।

महात्माजी का यह कार्यक्रम था कि ३ वर्षों में समस्त देश में पूर्ण रूप से शराबबन्दी हो जायेगी, परन्तु नवम्बर १९३९ में युद्ध के कारण कांग्रेसी मन्त्री-मण्डली ने पद-त्याग कर दिया और यह कार्य आगे न बढ़ सका। वर्तमान सरकार उसी पुराने कार्य को उसी मर्यादा में कर

रही है। बम्बई की हाईकोर्ट की ओर से जल्दमे यह निर्णय हुआ है कि शराबबन्दी की व्यवस्था अवैध है, तब बम्बई नगर में पुनः मद्य निषेध व्यवस्था भंग हो गयी है।

(५) अस्वास्थ्यग्रह भवन

ग्रामा और नगरा में भवन का निर्माण बहुत ही ध्वस्तानिक ढंग से किया जाता है। सम्पत्तिशाली शिक्षित वर्ग के लोग और बम्बई, कच्छता अहमदाबाद जैसे नगरा के सेठ-ब्यापारी अपने आराम के लिए तांगुले स्थानों में जंगले तथा कोठियाँ बनवाते हैं, परन्तु उनके कारखानों व मिलों में काम करनेवाले मजदूरों के लिए बड़ी गन्दी और अस्वास्थ्यकर कोठरियाँ होती हैं। उन्हें ८ फीट लम्बी चौड़ी कोठरियाँ ४ से ८ तक की मग्गा में गुजर करनी पड़ती हैं।

नगरा के भवन एक दूसरे से इतने सटे हुए हुए हैं कि उनमें शुद्ध हवा और प्रकाश का प्रवेश स्वतन्त्र रूप से नहीं हो पाता।

(६) आर्थिक दुर्दशा और दरिद्रता

भारतवासियों के हीन स्वास्थ्य का एक प्रधान कारण उनकी आर्थिक दुर्दशा और भयानक गरीबी तथा बेकारी भी है। जून १९४१ में भारत-मन्त्री श्री एमरी ने पार्लमेंट में भाषण करते हुए भारत के सम्बन्ध में कहा—“भारत समृद्धिशाली है। केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के पास अधिक राज-कोष है।”

परन्तु इस कथन में सचाई का रेश भी नहीं है। भारत की समृद्धि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत-भर्रा ने प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारों की बत्ती हुई आमदनी पर अपनी दृष्टि डालकर यह निष्कर्ष निवाड लिया है कि भारत समृद्धिशाली है। परन्तु उन्होंने नहीं दिल्ली और लखनऊ, बम्बई, कच्छता, मद्रास, लाहौर आदि नगरा के सरकारी मजदूरों के आदिमोह पर विचार करने का कष्ट नहीं किया।

देश की जनता की समृद्धि का पता निम्नलिखित के मान भवन में

निवास करनेवाले सम्पत्ति-जीवियों से नहीं लग सकता । इसके लिए तो भारत के ग्रामों का भ्रमण आवश्यक है । आप किसी भी ग्राम में चले जाएँ वहाँ आपको दरिद्रता का ताण्डव दिख ही देगा और उसके चारों ओर खड़े दीवंगे रोग, चिन्ता, बेकारी और दैन्य ।

सन् १९३८ में तत्कालीन अर्थ मन्त्री सर जेम्स ग्रिग ने अपने बजट भाषण में कहा था कि— ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय आय १६ अरब रुपये है । यदि इस बयन को सत्य मान लिया जाये तो ब्रिटिश भारत में प्रत्येक व्यक्ति को औसत वार्षिक आमदनी ५३ रुपये ५ आने ४ पाई होती है । यदि इस आय में से केन्द्रीय, प्रान्तीय सरकारों तथा स्थानीय बौद्धों को दिये जानेवाले टैक्सों को कम कर दिया जाये जो अनुमान से ८ रुपये ५ आने ४ पाई होने हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की वार्षिक आमदनी ८५ रुपये पड़ती है । इस प्रकार ४ रुपये मासिक से भी कम आमदनी पड़ती है ।^१

क्या यह भारत की समृद्धि का प्रमाण या उसकी भीषण दरिद्रता का चिह्न है ?

(७) स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्था

सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा तथा सफाई की व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व प्रत्येक प्रान्त की सरकार पर है । प्रत्येक प्रान्त में एक स्वास्थ्य-विभाग होता है । इसका प्रधान अधिकारी तो मंत्री होता है, परन्तु विभाग सम्बन्धी व्यवस्था का दायित्व इंडियन सिविल सर्विस के सेक्रेटरी पर रहता है । प्रत्येक प्रान्त में स्वास्थ्य विभाग का एक डाइरेक्टर होता है जिसके नियन्त्रण में स्वास्थ्य विभाग का कार्य संचालित होता है । यह विभाग अपना कार्य स्थानीय बोर्डों (चुंगियों तथा जिला बोर्डों) के द्वारा सम्पादन करता है । इस विभाग के स्थानीय कर्मचारी स्थानीय

^१ भारत मंत्री ऐमरी के भाषण पर सर इब्राहीम रहमतुल्ला खाँ का वक्तव्य—'लीडर' (१९ जून १९४१) ।

बोर्ड के नियन्त्रण में रहते हैं। स्थानीय बोर्डों का शासन-प्रबन्ध वैसे ही असन्तोषजनक रहता है। इनके सदस्य तथा चेयरमैन राजनीतिक धालों का आश्रय लेकर नागरिक जीवन के साथ खिलवाड़ करना ही अपना मनोरंजन या व्यापार समझते हैं।

मही कारण है कि इन बोर्डों के नियन्त्रण में रहने के कारण स्वास्थ्य-विभाग के स्थानीय अधिकारी भी मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। प्रत्येक नगर में एक हैलथ आफिसर तथा कई सेनीटरी इंस्पेक्टर होते हैं। इनका यह कार्य है कि वस्तियों में भ्रमण कर सफाई की व्यवस्था करें। परन्तु देखा यह गया है कि ये अफसर वयों में भी किसी घन्टी में निरीक्षण करने नहीं आते और न सेनीटरी इंस्पेक्टर ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।

स्वास्थ्य-विभाग की ओर से मेहनतों के रहन-सहन तथा उनके सफाई-कार्य में सुधार करने के लिए इस विभाग की ओर से कोई कार्य नहीं किया गया है। कलकत्ता, बम्बई आदि बड़े नगरों में तो कुछ प्रबन्ध किया भी गया है।

स्वास्थ्य-विभाग की ओर से नगरों में बाढिनाशों तथाकों, स्वास्थ्य-गृहों तथा जलाशयों की व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु इस ओर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है।

स्वास्थ्य सुधार के उपाय

हमने स्वास्थ्य-हीनता के जिन कारणों पर ऊपर विचार दिया है, उनके निवारण द्वारा ही स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यदि उपर्युक्त कारणों के निवारण के लिए समस्त नागरिक मिलकर स्वास्थ्य-विभाग के सहयोग से प्रयत्न करें, तो कोई कारण नहीं कि भारतवासियों के स्वास्थ्य में सुधार न हो सके।

सांस्कृतिक जीवन

शिक्षा साहित्य, भाषा और कला संस्कृति के अंग हैं। अब भारत के सांस्कृतिक जीवन पर विचार करने में इन पर विचार करना आवश्यक है।

शिक्षा

प्राचीन काल में शिक्षा

अज सभी विद्वान् एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य मानव की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का साम-जस्यपूर्ण विकास और उत्कर्ष है। आज भारत में जो शिक्षा-प्रणाली प्रचलित है, उससे राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। इसलिए उसके प्रति बड़ा असंतोष पैदा हो रहा है और उसमें सुधार और सशोधन के लिए उद्योग किया जा रहा है। अब भारत में शिक्षा पर विचार करते समय यह उपयोगी होगा कि हम अपनी प्राचीन वैदिक शिक्षा-प्रणाली का तो अवलोकन करें ही उसकी विशिष्टताओं पर भी विचार करने का प्रयास करें।

पुराने समय में शिक्षा का आधार आध्यात्मिक था। समस्त ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, साहित्य आदि का धर्म से घनिष्ठ संबंध था। धर्म आज-कल जैसी सांसारिक जीवन से अलग देवमन्दिरों में तीर्थों या मठों तक ही परिमित रहनेवाली चीज नहीं थी। धर्म मच्च अर्थों में सामाजिक जीवन का आधार था। उस समय गुरुकुल थे। गुरुकुल का अर्थ है आचार्य, शिक्षक या अध्यापक का परिवार। उसके सदस्य गुरुकुल के छात्र होते थे, जो 'ब्रह्मचारी' कहे जाते थे, क्योंकि गुरु उन्हें 'ब्रह्म' (ज्ञान) की ओर ले जाने की साधना में पथ प्रदर्शन करता था। इनमें बालक और बालिकाएँ निशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुकुल के संचालन में सहयोग और आर्पित सहायता देना गृहस्थ का पवित्र कर्तव्य होता

था। फलस्वरूप गुरुकुल आश्रित चिन्ता से मुक्त होकर अपने आचार्यों द्वारा ग्रह्यचारियों को सम्यक् ज्ञान देने थे।

वैदिक साहित्य में आचार्यों की जो महत्ता है उसका एकमात्र कारण यह है कि आचार्यों ग्रह्यचारी का धर्म पितृ है, वह उसे आचार को शिक्षा देता है, उसका आध्यात्मिक मस्कार करता है। माना-पिता ही उसके शरीर का पालन पोषण मात्र ही करते हैं, परन्तु आचार्यों के हाथ में इससे भी गुरुतर कार्य—चरित्र का निर्माण—जिसके ऊपर उसका मारा जीवन निर्भर है। चरित्र-निर्माण में शारीरिक और आत्मिक पवित्रता की साधना होनी है। इस प्रकार वैदिक शिक्षा शुद्धि का समन्वय थी। अनुशासन द्वारा शरीर की शुद्धि, शिक्षण द्वारा पशुत्वों की शुद्धि, ज्ञान द्वारा बुद्धि या मन की शुद्धि और ध्यान तथा मनन द्वारा आत्मा की शुद्धि।

वैदिक शिक्षा-प्रणाली में अनुपासन पर स्वाध्याय में अधिक ध्यान दिया जाता था। सरल और तपस्वी जीवन पर जाग्रह था। वैयक्तिक और सामूहिक आचार, स्वाध्याय-भक्त्यी तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन तत्परता से होता था।

प्राचीन-काल में सार्वजनिक-शिक्षा अधिकांश में मौखिक रूप में हुआ करती थी, आजन्म की तरह पुस्तकें इकट्ठी नहीं। धार्मिक शिक्षण द्वारा उस सार्वजनिक शिक्षा को आध्यात्मिक रंग दिया गया और धर्म और कला में सामंजस्य स्थापित करके सस्मृति का निर्माण हुआ। ईसा की सातवीं शताब्दी में जब विद्यापीठा, मठ और मन्दिरों द्वारा इस सार्वजनिक शिक्षा का प्रसार हुआ तो उस सस्मृति का विस्तार हुआ। रामायण में भी शिक्षा का एवं प्रचार हुआ। ग्राम-पाठशालाएँ स्थापित की गयीं। हरिवीर्तन और नाटकों द्वारा धर्म और सस्मृति का प्रसार हुआ।

त्रियों की शिक्षा

वैदिक काल में और उसके बाद के युग में त्रियों को भी पुष्पों के बराबर ही शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था।

वैदिक युग में गुरुकुल में धार्मिक शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता था परन्तु अथ उपयोगी विद्याओं की उपेक्षा नहीं की जाती थी। विज्ञान, मनोविज्ञान (योग), गणित, ज्योतिष, भौतिकशास्त्र, रसायन, चिकित्साशास्त्र, नृत्य, कला, संगीत आदि सभी विषयों को गुरुकुल के पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त था।

बौद्ध काळ में तत्त्वशिक्षा और नागरिक के विश्वविद्यालय अथ संस्कृति के क्षेत्र थे। भारत से ही नहीं विदेशों से लोग गणित, ज्योतिष, दशन और चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इन विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय सम्मिलित थे—

धर्म (वेद और जातक), दशन (अध्यात्मशास्त्र और तर्कशास्त्र), विज्ञान (चिकित्सा तथा तन्त्र विद्या) व्याकरण, कला, धनुर्विद्या मृगया। राजपुरुषों और लोकनेताओं के लिए अर्थशास्त्र और राजनीति-शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। धर्म, विज्ञान, दशन की शिक्षा का भी समुचित प्रबंध था।

गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की नीचे लिखी विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं—

(१) कुटुम्ब की भावना (ब्रह्मचारी को 'कुल का सदस्य माना गया है, और आचार्य का कर्तव्य उसके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के लिए पूरी व्यवस्था करना है।)

(२) समाज के प्रत्येक बालक-बालिका के लिए निःशुल्क शिक्षा निःशुल्क भोजन वस्त्रादि की व्यवस्था।

(३) सब ब्रह्मचरियों के साथ समान व्यवहार और इस प्रकार उनमें सच्चे बंधुत्व का विकास।

(४) ब्रह्मचर्य का अनिवार्य पालन, शरीर का कष्ट-सहन या अभ्यस्त बनाना तथा तपस्या का जीवन।

(५) चरित्र निर्माण।

'आचार्य शब्द का अर्थ होता है आचार का आदर्श स्थापित करनेवाला शिक्षक।'

१ प्रा० सत्यव्रत : 'गुरुकुल शिक्षापद्धति।

आज जबकि भारत में शिक्षा के पुनर्संगठन पर विचार हो रहा है वर्तमान शिक्षा के दोषों के परिहार के लिए विचार करने के साथ-साथ उसमें अपने गुणों के समावेश करने का प्रयत्न करें जो हमारी वैदिक सभ्यता की रक्षा के लिए आवश्यक है तथा जिसमें राष्ट्र का भी हित हो सकता है।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली

आज भारत में जो शिक्षा-प्रणाली प्रचलित है उसकी सभी शिक्षा-विज्ञी और लोकनेताओं ने घोर निंदा की है। इस प्रणाली में कई बड़े दोष हैं:—पहला यह है कि वह न तो शिक्षा और जीवन में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करती है और न जीवन की आवश्यकताओं पर ही ध्यान देती है।

यद्यपि वर्तमान शिक्षा-पद्धति के दोषों को सभी विद्वान् स्वीकार करते हैं, तथापि इससे कोई इंकार नहीं करता कि इसने देश को रड़ी सेवा की है। इस प्रणाली ने भारत में ब्रिटिश शासन को शिक्षित सामक ही प्रदान नहीं किये है प्रत्युत भारत में राष्ट्रीय और राजनीतिक नवचेतना और जागरण में भी विशेष योग दिया है। नवीन शिक्षा ने भारत में विद्वान्, वैज्ञानिक और महान् दार्शनिकों को पैदा किया है जिन्होंने न केवल भारत का ही मस्तक ऊंचा किया है प्रत्युत अन्तर्राष्ट्रीय-जगत में भी अपना विशेष स्थान प्राप्त किया है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि भारत में जो विद्वान्, वैज्ञानिक और महापुरुष हुए हैं और जो इस समय मौजूद हैं, उनके निर्माण में केवल पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को ही श्रेय है। उनकी महानता में उनके विशिष्ट व्यक्तित्व, उच्च सस्कार और अपूर्व प्रतिभा ने भी पर्याप्त योग दिया है। फिर भी आज हम यह अनुभव करते हैं कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में परिवर्तन की जरूरत है।

दूसरा यह कि इसका लक्ष्य राष्ट्रीयता से दूर है। वास्तव में इसका विकास भारत में अंग्रेजी शासकों की सुविधा और शासन-संचालन के

उद्देश्य से किया गया था और इस उद्देश्य की पूर्ति में इसने बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है।

तीसरा यह है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाकर भारतीय भाषाओं के विकास और जनता पर ध्यान नहीं दिया गया। मातृभाषा में शिक्षा न होने से भी विद्यार्थियों का बहुमूल्य समय अंग्रेजी भाषा की सीखने में व्यतीत होता है।

चौथा यह कि यह शिक्षा सैद्धान्तिक ही है व्यावहारिक नहीं। इसलिए जब विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज का छाड़कर सत्तार में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें व्यावहारिक जीवन में बड़ी असफलता का सामना करना पड़ता है।

पाँचवाँ और सबसे बड़ा दाव यह है कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली आर्यसंस्कृति के विरुद्ध है। वह चरित्र निर्माण और सदाचार की संबंधी उपेक्षा करती है। ज्ञान वृद्धि के लिए वह पर्याप्त सुयोग प्रदान करती है, परन्तु छात्रों की मानसिक, शारीरिक एवं आत्मिक शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास नहीं करती। वह राष्ट्रीयता एवं एकात्मता की भावना के प्रादुर्भाव के लिए भी कोई ध्यान नहीं देती और उ छात्रों में नागरिकता की भावना का प्रादुर्भाव ही करती है।

भारत में विश्व-विद्यालय

भारत में सबसे पहले सन् १८५७ में बलभत्ता, बम्बई और मद्रास में तीन विश्व-विद्यालय स्थापित किये गये थे। विश्व-विद्यालय दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के वे हैं जो अपने अन्तर्गत कॉलेजों की परीक्षा का प्रबन्ध करते हैं। उनकी ओर से कॉलेजों में शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं होता। प्रत्येक कॉलेज जो ऐसे विश्व विद्यालय से सम्बन्धित होता है, उसके द्वारा निर्धारित पाठ्य-क्रम के अनुसार शिक्षा का प्रबन्ध करने में स्वतन्त्र है। दूसरे प्रकार के विश्व विद्यालय वे हैं जिनके अन्तर्गत कॉलेजों का प्रबन्ध स्वयं विश्वविद्यालय की कार्य-कारिणी बोर्डिंग और गवर्नर के अधीन होता है। पहले प्रकार के विश्व विद्यालयों में आगरा, बम्बई,

कलकत्ता आदि विश्वविद्यालय हैं। दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालयों में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय हैं। भारतवर्ष के विश्वविद्यालय बर-बर स्थापित हुए यह नीचे लिखी सारिणी से स्पष्ट हो जायेगा।

विश्वविद्यालय	सन्	विश्वविद्यालय	सन्
१. कलकत्ता वि०वि०	१८५७	१०. अलीगढ़ मुसलिम	१९२०
२. मद्रास	१८५७	११. रघून	१९२०
३. बम्बई	१८५७	१२. लखनऊ	१९२०
४. पंजाब	१८८२	१३. अनमलाई	१९२०
५. इलाहाबाद	१८८७	१४. ढाका	१९२१
६. बनारस, हिन्दू	१९१६	१५. दिल्ली	१९२२
७. पटना	१९१७	१६. नागपुर	१९२३
८. मैसूर	१९१६	१७. आन्ध्र	१९२६
९. हैदराबादउरामानिया	१९१८	१८. आगरा	१९२७

इन विश्वविद्यालयों में भाषा-साहित्य, इतिहास, राजनीति, वर्गन, मनोविज्ञान, ज्योतिष, रसायन, भूगर्भ, भौतिक-विज्ञान, व्यापार-वाणिज्य, अर्थ-शास्त्र, जीव-शास्त्र, वनस्पति-विज्ञान, चिकित्सा, इन्जिनियरी, कृषि, कानून आदि की उच्चशिक्षा का प्रबन्ध है।

अन्य शिक्षा-संस्थाएँ

सन् १९३५ की भारत सरकार की शिक्षा-विभाग की रिपोर्ट के अनुसार समस्त भारत में २ लाख ५६ हजार २६३ स्कूल तथा कालेज हैं। इनमें कुल १ करोड़ ३५ लाख ६ हजार ८६५ छात्र शिक्षा पा रहे हैं। कुल जनसंख्या का ५% भाग शिक्षा पा रहा है। १९३५ के अंक ये हैं—

संस्थाएँ	छात्र-संख्या	छात्रा-संख्या
कालेज	१,०९,३१५	२,४९३
हाई स्कूल	९,४४,९२२	९८,९७५
मिडिल स्कूल	११,७७,०६५	१,४६,०५२

प्राइमरी स्कूल	८६,३९,४०५	१४,५०,२६७
स्पेशल स्कूल	२,३९,१८१	१८,०९५

विविध शिक्षा-संस्थाओं पर सरकारी व्यय का अनुपात निम्न प्रकार है—

विश्वविद्यालय और कॉलेज	१४.७%
हाई स्कूल और मिडिल स्कूल	२४.१%
प्राइमरी स्कूल	३४.३%
कन्या-शिक्षा	१३.९%
प्रबन्ध और निरीक्षण	८.८%

दलित जातियों में शिक्षा

दलित जातियों में शिक्षा का अत्यन्त अभाव है। सन् १९३२ के पूना-पैक्ट के अनुसार अब प्रत्येक प्रान्त के सरकारी बजट में इनकी शिक्षा के लिए पृथक् रूप से रकम निश्चित कर दी जाती है और वह केवल उन्हीं के स्कूलों, शिक्षा, छात्र-वृत्तियों, पुस्तकालय तथा निरीक्षण आदि पर व्यय की जाती है। ब्रिटिश भारत में सन् १९३४-३५ में दलित वर्ग के छात्रों की कुल संख्या १२ लाख ६ हजार १९३ थी। इनमें छात्राओं की संख्या भी शामिल है। शिक्षा में मद्रास प्रान्त सबसे आगे है और सयुक्त-प्रान्त सबसे पिछड़ा हुआ।

जो स्कूल विशेष रूप से इन जातियों के लिए स्थापित हैं, वे सन् १९३५ में ९,३९३ थे।

वर्धा-शिक्षा-पद्धति

जब सात प्रान्तों में कांग्रेस का शासन स्थापित हुआ तो महात्मा गांधी ने 'हरिजन' द्वारा राष्ट्र के सर्वतोमुख सुधार के लिए ग्रामोद्योगों में उन्नति, खादी-प्रचार, मादक-द्रव्य-निषेध आदि के सम्बन्ध में अपनी योजनाएँ प्रस्तुत कीं जिनपर कांग्रेसी सरकारों ने अमल किया। साथ ही उन्होंने शिक्षा में सुधार करने के सम्बन्ध में अगस्त, १९३७ में 'हरिजन' में कई विचारोत्तेजक लेख लिखे, जिनसे जनता और नेताओं का ध्यान शिक्षा के पुनः संगठन की ओर आकर्षित हुआ। फलतः वर्धा में २२-२३ अक्टूबर

१९३७ को राष्ट्रीय-शिक्षा-विचारदो का एक सम्मेलन आमन्त्रित किया गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अपने उपर्युक्त लेखों के आधार पर भाषण दिया और शिक्षा के मुद्दे पर विस्तारपूर्वक अपने विचार व्यक्त किये। इनपर विचार-विनिमय के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया—

(१) राष्ट्रव्यापी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ७ वर्ष तक हो ऐसी व्यवस्था की जाये; शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो; इस अवधि में महात्मा गांधी के मन्तव्यानुसार शिक्षा रचनात्मक उद्योग द्वारा हो जाये। सम्मेलन को यह आशा है कि इस शिक्षा-पद्धति द्वारा धीरे-धीरे अध्यापकों का चेतन भी प्राप्त किया जा सकेगा।

इस शिक्षा-सम्मेलन ने जामिया मिलिया, दिल्ली के प्रिंसिपल डा० जाकिरहुसैन की अध्यक्षता में वर्धा-शिक्षा-कमेटी की नियुक्ति भी की जिसे प्राथमिक शिक्षा के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार ७ वर्षों के लिए पाठ्य-क्रम तैयार करने का कार्य सौंपा गया।

बुनियादी तालीम

उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सात साल के निम्न बुनियादी तालीम (Basic Education) की व्यवस्था की है।

बुनियादी तालीम की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) स्कूल में प्रत्येक बालक की अपनी रुचि के अनुसार एक आधारभूत उद्योग चुनना चाहिए जिसकी व्यवस्था स्कूल के द्वारा की गयी हो। इस उद्योग के आधार पर बालक की शिक्षा दी जाये। इसके साथ ही साथ उसे दो सहायक उद्योगों का भी चुनाव करना चाहिए, जैसे कनाई और बागवानी। १० वर्ष की अवस्था तक इन उद्योगों की शिक्षा केवल शिक्षा के मूल्य की दृष्टि से दी जाये, औद्योगिक दृष्टि से नहीं। जो बालक भविष्य में उद्योग में निपुणता प्राप्त करना चाहें उन्हें अन्तिम दो सालों में औद्योगिक ढंग पर शिक्षा देने की व्यवस्था की जायेगी। लड़कियों की घरेलू धर्मों की शिक्षा दी जायेगी और अन्तिम दो वर्षों में दूरियों के पालन तथा देख-रेख की शिक्षा दी जा सकेगी है।

(२) 'समाज-सेवा (ग्राम-स्वास्थ्य, प्रचार, दुष्प्राल में सेवा, रोग तथा वाढ से पीडितों की सेवा, स्थानीय मेला की व्यवस्था, सम्मेलनों में स्वयं-सेवक का कार्य, इन्डरगार्टन दर्जों की व्यवस्था में सहयोग, स्त्री-समाज-सघ तथा सेवासघ,) प्रवृत्ति-निरीक्षण, भ्रमण, खेल, व्यायाम आदि ।

(३) शिक्षा में कार्यशीलता के सिद्धान्त की स्वीकृति; इसका अर्थ यह है कि बालकों की स्वामाबिक तथा रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन और बालकों की बौद्धिक, सामाजिक तथा शारीरिक शक्तियों के विकास के लिए पूर्ण सुयोग दिया जाये ।

(४) राज्य को प्रत्येक बालक के लिए ७ वर्ष की आयु से १४ वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ।

(५) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी तथा 'हिन्दुस्तानी' का सामान्य ज्ञान अनिवार्य होगा । पिछले दो वर्षों में अंग्रेजी केवल उनको पढ़ायी जायेगी जो आगे हाई स्कूल या कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हों ।

(६) पाठ्य-क्रम में आधुनिक शिक्षा-सम्बन्धी आदर्शों के प्रकाश में परिवर्तन किया जाये ।

(७) नागरिकता की तैयारी के उद्देश्य से पाठ्य-क्रम बनाया जाये, केवल इस लिहाज से नहीं कि प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा का आधार है ।

(८) पाठ्यक्रम में सामान्य नागरिक शास्त्र और सामान्य विज्ञान को स्थान दिया जाये ।

(९) भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से पढ़ाया जाये, राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सामयिक घटनाओं का भी ज्ञान आवश्यक है ।

(१०) चरित्र निर्माण को शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाये । सदाचार की शिक्षा सामाजिक एवं मनोविज्ञान की दृष्टि से दी जाये, विशुद्ध धार्मिक दृष्टि से नहीं ।

(११) मनोवैज्ञानिक प्रणाली द्वारा स्कूल के वातावरण को शुद्ध तथा

अनुकूल बनाया जाये। अध्यापक और छात्रों में सहकारिता का भाव हो।

(१२) वार्षिक परीक्षाएँ छटा दी जायें और स्कूलों में रिकार्ड द्वारा ही श्रेणी चढ़ायी जाये।

(१३) बारह वर्ष की आयु में छात्र की मनोवैज्ञानिक परीक्षा की जाये और उसकी रुचि तथा प्रवृत्ति की जाँच की जाये तथा उसके मरक्षक को सूचनाएँ दी जायें।

(१४) स्कूल के वातावरण, कार्य-प्रणाली तथा शिक्षा में राष्ट्रीय तथा अहिंसान्तमक दृष्टिकोण सामने होना चाहिए।

इसमें सन्देह नहीं कि यह शिक्षा की एक क्रान्तिकारी योजना है। इससे राष्ट्र का हित होगा, क्योंकि यह राष्ट्र-हित की दृष्टि से ही तैयार की गयी है। महात्माजी शिक्षा को स्वाश्रयी (Self supporting) बनाना चाहते हैं। उनका यह मकल्प प्रारम्भिक दशा में पूरा होगा अथवा नहीं, यह अभी से निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। जब इस योजना के अनुसार समस्त भारत में प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध हो जायेगा, तब इसमें जो दीर्घ परीक्षण काल में माहूम होंगे, उनके निवारण के लिए भविष्य में प्रयत्न किया जा सकेगा। परन्तु इसमें तनिक भी शक नहीं कि वर्षों शिक्षा-योजना ही एक ऐसी योजना है, जो आज १५० वर्षों के ब्रिटिश शासन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय हित की दृष्टि से रखी गयी है और जिसपर समुक्तप्रान्त, मध्यप्रान्त, बम्बई आदि कई प्रांतों में अमल भी होने लगा है।

भाषा और लिपि

हिन्दी-राष्ट्रभाषा

भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है परन्तु आज वह किसी भी प्रान्त की बोल-चाल की भाषा नहीं है। हाँ, यह निर्विवाद है कि भारत की अधिकांश प्रान्तिक भाषाएँ हिन्दी, बगल, मराठी, गुजराती उर्दू, सिन्धी, पंजाबी, राजस्थानी और उड़िया संस्कृत से उत्पन्न और विकसित हुई हैं और भेष ब्राह्मण—नामिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड पर भी संस्कृत का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब प्रान्तीय

भाषाभाषा में हिन्दी ही सबसे अधिक बाली और पढ़ी लिखी जाती है।

सन १९३१ में भारत की जनसंख्या ३५,२९,८६ ८७६ थी। इनमें देशी रियासतों की संख्या भी शामिल है जो ८ करोड़ से ऊपर है।

हिन्दीभाषी प्रान्त

भारत के संयुक्तप्रान्त, बिहार उड़ीसा पंजाब, मध्यप्रान्त वरार दिल्ली, अजमेर मरवाड़ा और कुछ हिन्दीभाषी रियासतें हैं, जिनका कुल जनसंख्या सन १९३१ ई० के अनुसार १७ करोड़ ६३ लाख ७० हजार, ४५२ है।

अहिन्दी भाषी प्रान्त

बंगाल मद्रास, बम्बई सिन्ध कुश्, पश्चिमोत्तर सामाप्रान्त, बलूचिस्तान, आसाम ब्रह्मा तथा कुछ अहिन्दीभाषी रियासतें हैं जिनकी जनसंख्या १७ करोड़ ४८ लाख ७२ हजार ९०२ है।

इस प्रकार हिन्दी भाषाभाषियों और इतर भाषा भाषियों की जनसंख्या प्रायः बराबर है। इसलिए हिन्दी भाषा ही राष्ट्र की भाषा बहलानेयोग्य है। परन्तु मुसलमानों की ओर से यह दावा पेश किया जा रहा है कि उर्दू ही राष्ट्र भाषा हो सकती है। इस प्रकार भाषा के इस राष्ट्रीय प्रश्न पर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार करने की पद्धति शुरू हो गयी है। आजकल सामान्यभाषा और राष्ट्र भाषा—इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में किया जाने लगा है। इस प्रकार इसमें भ्रान्तिपूर्ण विचारों का प्रचार होने लगा है। सामान्य भाषा क्या है? यह वह भाषा है जो प्रत्येक प्रान्त में बोल चाल में काम आती है और जिस थोड़ा बहुत सभी समझ सकते हैं और दोनों सबत हैं। सामान्य भाषा पर स्थानीय भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे बलूचिस्तान के बाजारा में बोली जानेवाली भाषा उस भाषा में मिलती है जो बम्बई के बाजारा में बोली जाती है। बलूचिस्तान की बाल चाल की भाषा में बंगला के अधिक शब्द होते हैं। इसी प्रकार बम्बई की बालचाल की भाषा में गुजराती के शब्द अधिक होते हैं। इस सब

म श्री रामनाथ 'मुमन' न लिखा है—

“यह भाषा अन्तर्प्रतीय वातावात, रत्न, व्यापार और बड़े बड़े उद्योग-व्यापार के लड़े हा जाने स बनी है। इसे किसी सस्था न नहा बनाया, न इसके बनान में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, हिन्दी प्रचार-सभा या कांग्रेस का हाथ है। यह भाषा उत्तर भारत (मुख्यतः संयुक्तप्रान्त, मध्यभारत तथा बिहार) के उन गरीब प्रवासियों की राष्ट्र की दन है, जो गरीबी क कारण अपना घरबार छोडकर नीकरी की तलाश में दूर-दूर के सूबा में गये और वहाँ महन्त मजदूरी करके पट पालने लगे। इनमें स किसी ने वापस ठाने का काम किया, कुछ स्टेशन पर कुली बने, कुछ आफ्रिका में चपरासी बने, कुछ का मिलों, रेलों क कारवाना और दुकानों में काम मिला। कुछ न दरदानी को, कुछ पुलिस और ट्राम की नीकरी में भरती हुए कुछ इक्का-तीका हाकने लगे। बहुतों ने ग्वाले, नार्ड, ग्माई का काम संभाला, और बहुतों न छोटे-छोटे घरे अपनाये। ये गिम्ति न थे और जहाँ गये वहाँ अपनी बोली और रीति रिवाज साथ र गये। जिस हिन्दी के घर में यह कहा जाता है कि वह अधिकांश भारतीयों द्वारा समझी जाती है वह भी सामान्य बोली है। इसका न काद निश्चित व्याकरण है और न आजतक कोई पुस्तक इस भाषा न लिखी गयी।

अतः यह स्पष्ट है कि भारत में प्रचलित ‘सामान्य भाषा’ राष्ट्रभाषा नहा है। जा ऐसा मानते हैं वे भारी भ्रम म ह।

वह न राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ राष्ट्रीय नेताओं न राष्ट्रभाषा निर्माण क प्रश्न का प्रस्तुत किया। उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत में राष्ट्रीय नवचेतना और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए यह जरूरी है कि नारन व सभी प्रान्तों म एकता स्थापित की जाये। एवना उसी समय स्थापित हो सकती है जब कि विचार विनिमय के लिए एक अन्तर्प्रतीय भाषा हा। अंग्रेजी भाषा एभी भाषा है जिस सभी प्रांतों में पडा और बोला जाता है पर वह स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों तथा अंग्रेजी बड़े समुदायों तक ही सीमित है—जनता की भाषा नहीं

है। इसलिए राष्ट्र का संदेश जनता तक पहुँचाने के लिए ऐसी भाषा की जरूरत है जिसे सभी प्रान्त के लोग समझ सकें।

आज से २० वर्ष पहले महात्मा गांधी ने यह विचार प्रकट किया कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। उन्होंने कहा है—

“मैं उस भाषा को हिन्दी कहता हूँ जिसे उत्तर के हिन्दू-मुसलमान लिखते पढ़ते हैं—चाहे उसे देवनागरी में लिखें या उर्दू लिपि में। इस परिभाषा पर कुछ आपत्ति भी की जा सकती है। यह कहा जा सकता है कि हिन्दी और उर्दू दो भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं। यह युक्ति-सगत तर्क नहीं है। भारत के उत्तरी भाग में हिन्दू-मुसलमान एक ही भाषा बोलते हैं। साक्षर वर्गों ने भेदभाव पैदा कर दिया है। विद्वान् हिन्दुओं ने हिन्दी को संस्कृतमयी बना दिया है। इसलिए मुसलमान उसे समझ नहीं सकते। लखनऊ के मुसलमानों ने उसमें फारसी का अधिक समावेश करके उसे हिन्दुओं के लिए कठिन बना दिया है। ये एक ही भाषा की दो आवश्यकताएँ हैं। जनता की बोली में इनका कोई स्थान नहीं है। उत्तर की भाषा को चाहे आप हिन्दी कहें या उर्दू, एक ही बात है। उर्दू लिपि में लिखने से वह उर्दू है और नागरीलिपि में लिखने से वह हिन्दी है।”

महात्मा गांधी आज तक इसी विचार के पोषक रहे हैं और वह इस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। अहिन्दीभाषी प्रान्तों में महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही हिन्दी-भाषा का प्रचार शुरू हुआ। आज से १० वर्ष पूर्व दक्षिणभारत में हिन्दी-प्रचार-समा की स्थापना की गयी, जो तबसे अब तक हिन्दी-प्रचार का कार्य बड़े अच्छे ढंग से कर रही है। जब महात्मा गांधी और उनके सहयोगी राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दी प्रचार में योग देना आरम्भ कर दिया और यह नियम भी बना दिया कि कांग्रेस में जो भाषण दिये जायें वे हिन्दी भाषा में हो, तो मुस्लिम नेताओं की ओर से आक्षेप होने लगे। मुसलमानों ने यह

संस्कृत के शब्द हों और न फारसी के, हमारा काम नहीं चल सकता। हमें न केवल पारिभाषिक शब्दों के लिए, बल्कि ऐसे शब्दों के लिए भी जो हमारे गहरे चिंतन के यथार्थ प्रतिबिम्ब हो सकें, संस्कृत अथवा अरबी की शरण लेनी होगी।”

अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के शिमला-अधिवेशन में सभापति-पद से हिन्दी के विद्वान और अनुभवी पत्रकार श्री बाबूराव विष्णु पराडकर ने भी राष्ट्रीय भाषा के सम्बन्ध में अपने अभिभाषण में कहा था—

“मौलाना अबुल कलाम आजाद जिसे सर्वप्रान्तीय व राष्ट्रीय भाषा बनने की अधिकारिणी समझते हैं वही यदि यह ‘हिन्दुस्तानी’ है तो मैं निःसंशय चित्त से साहित्य-सम्मेलन को सलाह दूंगा कि वह निर्भीकता के साथ स्पष्ट शब्दों में इसका विरोध करे।” “हिन्दुस्तानी के नाम पर यह जो अनर्थ हो रहा है, उससे केवल हिन्दी की ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए मैं कहता हूँ कि हमारी राष्ट्रभाषा का नाम हिन्दी होना चाहिए और उसकी प्रवृत्ति भी हिन्दी यानी हिन्द की होनी चाहिए।”

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और राष्ट्रभाषा

उपरोक्त विवाद पर निर्णयात्मक विवेचन करने के लिए इस क्षण के मूल को देखना होगा। महात्मा गांधी के सभापतित्व में इंदौर में होनेवाले हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के चौबीसवें अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ था—

“इस सम्मेलन को मालूम हुआ है कि राष्ट्रभाषा के स्वरूप के संबंध में हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न प्रान्तों में कुछ चलतफहमी फैली हुई है और लोग उसके लिए अलग-अलग राय रखते हैं। इसलिए यह सम्मेलन घोषित करता है कि राष्ट्रभाषा की दृष्टि से हिन्दी का वह स्वरूप मान्य समझा जाये जो हिन्दू-मुसलमान आदि सब धर्मों के प्राणीय और नागरिक व्यवहार करते हैं, जिसमें रुढ़ सब सुलभ अरबी, फारसी, अंग्रेजी या संस्कृत शब्दों या मुहावरों का बहिष्कार न हो और जो नागरी या उर्दू

लिपि में लिखी जाती हो।”

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के शिमला-अधिवेशन में सम्मेलन की नियमावली में संशोधन किये गये और १९ सितम्बर सन् १९३८ की संशोधित नियमावली के अनुसार उद्देश्य धारा २ (क) और (ख) में इस प्रकार निर्धारित किया गया—

“(क) हिन्दी-साहित्य के सब अंगों की पुष्टि और उन्नति का प्रयत्न करना,
(ख) देशव्यापी व्यवहारों और कार्यों को सुलभ करने के लिए राष्ट्रलिपि देवनागरी और राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार बढ़ानेका प्रयत्न करना,
(ग) हिन्दी भाषा को अधिक सुगम, मनोरम, व्यापक और समृद्ध बनाने के लिए समय समय पर उसके अभावों को पूरा करना और उसकी शैली और श्रुतियों के संशोधन का प्रयत्न करना।”

यद्यपि सम्मेलन के उद्देश्यों में ‘हिन्दी राष्ट्रभाषा’ का उल्लेख है— उसमें ‘हिन्दुस्तानी’ का उल्लेख नहीं है, तथापि इंदौर के उपर्युक्त निश्चय में ‘हिन्दुस्तानी’ शब्द न होने हुए भी ‘हिन्दुस्तानी’ का स्वरूप यही विद्यमान है जिसे आज महात्मा गांधी ‘हिन्दुस्तानी’ कहते हैं।

इन्दौर-सम्मेलन के बाद ‘हिन्दुस्तानी’ भाषा का प्रचार बढ़ता रहा। जुलाई सन् १९३७ में जब कांग्रेस, मग्न-मण्डली ने शासन-भार संभाला तब हिन्दुस्तानी प्रांतीय सरकारों द्वारा भी स्वीकार कर ली गयी। हिन्दी साहित्यिकों के सामने ‘हिन्दुस्तानी’ का व्यवहार्य स्वरूप ‘रीडरो’ में आया तो हिन्दी-साहित्य-सेवियों को उसे देखकर घोर निराशा हुई और उसका फल यह हुआ कि पत्र-पत्रिकाओं द्वारा उसका घोर विरोध किया जाने लगा। सितम्बर १९३८ के शिमला-अधिवेशन में ‘आज’ के मशहूरी विद्वान् संपादक तथा सम्मेलन के अध्यक्ष श्री वावूराव विश्वु पराडकर ने अपने भाषण में विचारपूर्वक हिन्दुस्तानी भाषा की आलोचना की और उसका विरोध करने के लिए सम्मेलन की सलाह भी दी। सम्मेलन के इस अधिवेशन में हिन्दी भाषा की सुगम बनाने के सम्बन्ध में जो निश्चय किया गया वह इस प्रकार है—

“इस सम्मेलन के विचार में हिन्दी के आधुनिक साहित्य-निर्माण के

लिए ऐसी भाषा उपयुक्त है जिसका परम्परागत सम्बन्ध सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से है जिसकी शक्ति कबीर, तुलसी, सूर मलिक मुहम्मद जायसी, रहीम, रसखान और हरिश्चन्द्र की कृतियों से आयी है, जिसका मूलाधार देशी और तद्भव शब्दों का भण्डार है, और जिसके पारिभाषिक शब्द प्राकृत अथवा सस्कृत के क्रम पर ढाले गये हैं किन्तु जिसमें रुढ़, सुलभ और प्रचलित विदेशी शब्दों का भी स्थान है।'

पहले दिये गये इन्दौर-सम्मेलन और शिमला सम्मेलन के निश्चयों में मौलिक अन्तर है। इन्दौर के निश्चय के अनुसार 'हिन्दी का यह स्वरूप मान्य है जिसे हिन्दू मुसलमान आदि सब धर्मों के प्रामीण और नागरिक व्यवहार करते हैं।'

और शिमला के निश्चय के अनुसार 'हिन्दी के आधुनिक साहित्य-निर्माण के लिए ऐसी भाषा उपयुक्त है जिसका परम्परागत सम्बन्ध सस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से है, जिसकी शक्ति हिन्दी के प्राचीन कवियों तथा साहित्यकारों की रचनाओं से आयी है।

ये दोनों निश्चय परस्पर विरोधी हैं। पर धीरे धीरे सम्मेलन में हिंदुस्तानी विरोधी तत्त्व का बहुमत होता गया। अपने पिछले पूना-अधिवेशन में उसने इस बात को कुछ कुछ स्पष्ट कर दिया है। पूना का प्रस्ताव यह है—

'सम्मेलन की नियमावली के निषम (ख) में आये हुए 'राष्ट्रभाषा' शब्द के स्पष्टीकरण के लिए सम्मेलन के इन्दौरवाले अधिवेशन का जो निश्चय दिया गया है, उसका निम्नलिखित रूप हो—

'इस सम्मेलन को भाठूम हुआ है कि 'राष्ट्रभाषा' के स्वरूप के सम्बन्ध में हिंदुस्तान के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में कुछ गलतफहमी फैली हुई है और लोग उसके लिए अलग अलग राय रखते हैं। इसलिए यह सम्मेलन घोषित करता है कि 'राष्ट्रभाषा' की दृष्टि से हिन्दी का यह स्वरूप मान्य समझा जाये जो हिन्दू, मुसलमान आदि सब धर्मों के प्रामीण और नागरिक व्यवहार करते हैं, जिसमें रुढ़, सर्वमुक्त अरबी, फारसी, अंग्रेजी या मस्कृत शब्दों या मूहाविरा का बहिष्कार नहीं होता और

जैसा कि लिखा जा चुका है दोनों दलों का सगड़ा मूल में राष्ट्र-भाषा के नाम और स्वरूप पर है। काना बालेत्कर तथा उनके समर्थकों का ओर राष्ट्रभाषा को

(१) 'साहित्यिक हिन्दी' या 'उर्दू-ए-मुअल्ला' बनाने पर नहीं है और

(२) उसे वे कांग्रेस द्वारा किया स्वीकृत 'हिन्दुस्तानी' नाम से ही पुकारना राष्ट्र के लिए हितकर मानते हैं।

दूसरी ओर उत्तरभारत के हिन्दीभाषी उसे

(१) 'संस्कृत, प्राकृत के क्रम पर' ढालना चाहते हैं और

(२) उसे वे 'हिन्दी' नाम से ही पुकारना चाहते हैं।

इस बार जो हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अग्रीहर-अधिवेशन के चुनाव में सघर्ष रहा, वह इसी मतभेद का लक्षण था। अग्रीहर के अधिवेशन में जो मन बहुमत में है, वह अवश्य अपने निर्णय को कड़े से बड़े शब्दों में प्रकट करेगा, ऐसी सम्भावना है।

परन्तु राष्ट्रभाषा का प्रश्न अकेले हिन्दीवालों का ही नहीं है उसे अखिल भारतीय दृष्टि से देखना चाहिए। हमारी दृष्टि में भाषा की पवित्रता जैसी कोई चीज है ही नहीं। आधुनिक हिन्दी में कई विदेशी भाषाओं (पुर्तगाली, फ्रेंच, जर्मनी) के शब्द इस बुरी तरह से मिल गये हैं कि उन्हें निकालना मुश्किल है। इसी प्रकार देशभाषाओं के शब्द भी मिलेंगे। हाँ, यह मिलावट बलात् नहीं होनी चाहिए। भाषा 'बलालार' को सहन नहीं कर सकती। वह अन्य भाषा के शब्दों से मधुर समन्वय ही कर सकती है जिसे कोई नहीं रोक सकता।

राष्ट्र-लिपि की समस्या

महात्मा गांधी और राष्ट्रीय महासभा देवनागरी और उर्दू दोनों लिपियों को राष्ट्र-लिपि स्वीकार करने के पक्ष में हैं। देन का सबसे विशाल जन-समुदाय देवनागरी लिपि को पसन्द करता है। सन् १९३१ की जन-संख्या के अनुसार प्रति १० हजार मनुष्यों में ४,०५६ मनुष्य देवनागरी-लिपि में लिखी जानेवाली भाषाएँ व्यवहार में लाते हैं।

लगभग १७ करोड़ व्यक्ति हिन्दी भाषा-भाषी हैं। उनके अनिश्चित बंगला, गुजराती, मराठी और गुरुमुखी लिपियाँ भी देवनागरी लिपि से बहुत अधिक मिलती-जुलती हैं। जन-गणना रिपोर्ट में यह पता चलता है कि प्रति १०,००० मनुष्या में २,६६२ मनुष्य ऐसे हैं जो नागरी-लिपि के विविध रूपों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रति १०,००० मनुष्या में ६,७१८ मनुष्य ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में देवनागरी-लिपि का व्यवहार करते हैं। मद्रास में तामिल-भाषा में सभ्यता का बाहुल्य है। अब उन्हें भी एक रूप में देवनागरी लिपि का प्रयोग करना पड़ता है।

सन् १९३८ में हरिपुरा कांग्रेस में श्री मुभागचन्द्र बसु ने राष्ट्रपति पद में अपने भाषण में राष्ट्र-लिपि के रूप में रोमन-लिपि का समर्थन किया था। और उनके समर्थक भी इस देश में बहुत हैं। परन्तु रोमन-लिपि राष्ट्र-लिपि बन नहीं सकती। जब भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी है तब उसकी लिपि रोमन कैसे हो सकती है? फिर भारत में अंग्रेजी जानने-माने मुश्किल से १००० में १ है। इससे भिदा वह अवज्ञानिक भी है। उर्दू-लिपि तो महा जटिल, क्लिष्ट, अस्पष्ट, दुर्बल और ध्वनिशास्त्र की दृष्टि से अपूर्ण है। फिर उसकी कोई साम्प्रतिक या साहित्यिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। उर्दू जाननेवाला भी मरुता बहुत ही कम है। वह एक-दो प्रान्तों में ही अधिक है और छापने, लिखने, पढ़ने और पढ़ाने में कठिन है।

देवनागरी लिपि ही ऐसी है जो सबसे व्यवहार के योग्य है। वह पूर्णतः वैज्ञानिक और मर्यादपूर्ण है। हाँ, इसकी विविध वर्ण-मयोजन-प्रणाली और मात्रा-गणना तथा विविधरूप वर्णों की बहुतायत इसे प्रेम, टाटपराइश आदि के लिए, पूर्ण सुगम होने से रोक्ती है, जिन्हें दूर

जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाना है, वही लिखा जाता है ।

साहित्य

मसार में सज्जे प्राचीन आर्य जाति है और इसी कारण सज्जे प्रार्थना आर्य-संस्कृति तथा साहित्य है ।

पाश्चात्य विद्वानों ने मुबनकट से यह स्वीकार किया है कि आर्य-संस्कृति तथा साहित्य मसार में सज्जे प्राचीन है । सृष्टि के आदि में परमात्मा ने चार ऋषियों को जो अपना ज्ञान दिया, वह वेद के नाम से प्रसिद्ध है । वेद ईश्वरीय ज्ञान है । उसकी रचना किसी मानव ने नहीं की । इसीलिए वह अनादि है और उसका नाश भी नहीं होता । वैदिक युग में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद—इन चार वेदों का ही आदर था और जन-समाज इनके अनुसार ही अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करता था । ये चार वेद ही वैदिक काल का साहित्य, धर्म-पुस्तक और कला-कृति थे । सामवेद का ऋषियण गायन करने थे । उसे समीत का जन्मदाता कहा जाता है ।

कुछ काल के बाद इन वेदों की ऋषियों-मुनियों ने व्याख्याएँ करना शुरू किया । अतः उपनिषदों तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों की रचना हुई । इसके बाद दर्शन-शास्त्रों की रचना की गयी । इस युग का जो साहित्य आज उपलब्ध है वह आध्यात्मिक-धार्मिक ही है । उस समय भारतीय कला का विकास वैसा हुआ था इसका आज कोई प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है ।

ब्राह्मण-ग्रन्थों के निर्माण के समय जनता की रक्षि, कला-कृति तथा नरस साहित्य की ओर होने लगी । जनता काव्य और कविता में आनन्द लेने लगी । उस समय जन-समाज की मान्यताएँ मसृज्य थीं । अतः इस काल के ग्रन्थों का निर्माण ससृज्य में किया गया । मबने प्राचीन काव्य-ग्रन्थ जिनका वर्णन इतिहास में आज उपलब्ध है, महर्षि वाल्मीकि की 'रामायण' है ।

‘रामायण की रचना के बहुत वर्षों के पश्चात् महर्षि व्यास न जय काव्य की रचना की। इसमें महाभारत का काव्यमय वर्णन है। पीछे से इसी ग्रन्थ का नाम महाभारत प्रसिद्ध हो गया।

भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। इस ग्रन्थ में भारतीय नाट्य कला के सिद्धान्त बताये गये हैं। नाटक के लिए उपयोगी तथा आवश्यक सभी बातों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। सबसे पहला नाटक भास कवि ने इसी ग्रन्थ के सिद्धान्तों के अनुसार लिखा।

ईसा की पाँचवीं शताब्दी में महाकवि कालिदास का जन्म हुआ। कालिदास संस्कृत के महाकवि थे और वाल्मीकि के बाद वही सबसे महान् कवि माने गये हैं। आज ससार में कालिदास की कला-कृतियों का जो आदर और सम्मान है वह इसीलिए है कि उन्होंने ऐसे अमर साहित्य की सृष्टि की जो युगो तक जनता के हृदय को प्रभावित करता रहगा।

महाकवि कालिदास के अतिरिक्त और भी कई प्रसिद्ध काव्यकार हुए जिनकी अमर कृतियों के कारण आज संस्कृत साहित्य ससार की भाषाओं के सम्मुख खड़ा हो सकता है और संस्कृत भाषा में ऐसे रत्न भरे पड़े हैं जिनके कारण वह विश्व साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त कर सकती है।

हिन्दी-साहित्य

बौद्ध काल तक भारत में साहित्य रचना की भाषा और सभ्यत जनता की मातृभाषा संस्कृत रही। परन्तु बौद्ध-काल में पाली भाषा का अधिक प्रचार हो गया। इसी कारण इस युग की बौद्ध-साहित्यिक तथा धार्मिक कृतियाँ पाली भाषा में मिलती हैं। पाली भाषा के बाद भारत में प्राकृत भाषा का अधिक प्रचार बढ़ा। परन्तु जबसे भारत में विदेशी आक्रमणकारियों ने प्रवेश आरम्भ किया तबसे यहाँ की भाषाविषयक एकता भंग हो गयी और प्रान्तीय भाषाओं का जन्म होने लगा। ११वीं या उसके शताब्दी में आस पास ही हिन्दी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, तमिल, तगूर, मलयालम और मराठी आदि भाषाओं का विकास हुआ।

हिन्दी-साहित्य का इतिहास सन् ११९१ से आरम्भ होता है जब कवि चन्दबरदाई ने 'पृथ्वीराज रागो नामक' काव्य की रचना की। इस प्रकार हिन्दी-साहित्य आज ९०० वर्षों से उत्तरी भारत की जनता में अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करता रहा है। आज हिन्दी का साहित्य अत्यन्त समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है। एक युग था जब बंगला साहित्य भारतीय साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। परन्तु सरस्वती तथा रवीन्द्रनाथ के युग के समाप्त हो जाने पर उसने कोई प्रगति नहीं की।

हिन्दी साहित्य सदा प्रगतिशील रहा है और आज भी वह प्रगति के पथ पर है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी 'रामचरितमानस' जैसी अमर कृति से हिन्दी को सदैव के लिए उच्च आसन पर बिठा दिया। 'रामचरितमानस' वास्तव में ऐसी उच्चकोटि की कला-पूर्ण रचना है जिसमें सम्पूर्ण मानव-जीवन की बड़ी सरस व्याख्या की गयी है। उसमें राम के प्रति गोस्वामीजी ने भक्ति की जैसी मनाहर अभिव्यक्ति की है वैसे किसी भी साहित्य में मिलना दुर्लभ है, साथ ही उन्होंने जनता के हृदय को भी बड़ी मामिकता के साथ स्पर्श किया है। यह जनता का अपना साहित्य है। आज भारतवर्ष में 'रामचरितमानस' का बड़ा आदर है और उसकी चीपाइयाँ एक अपठ क्लृप्तान के मुख से भी सुनायी पड़ती हैं। हिन्दी-साहित्य का यह सबसे लोकप्रिय काव्य है। अत्यन्त भाषाओं में भी तुलसीदास की इस अमर कृति का अनुवाद हो गया है।

आधुनिक काल में श्री मैथिलीशरण गुप्त हिन्दी के सबसे बड़े कवि हैं। उनकी रचनाएँ जनता में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। श्री मुमिषानन्दन पन्ना, श्री सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, श्री रामकुमार वर्मा, श्री महादेवी वर्मा आदि हिन्दी काव्य-जगत की आधुनिक भावना धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी कविताएँ विश्व-साहित्य में स्थान पाने योग्य हैं।

उपन्यास क्षेत्र में प्रेमचन्द ने जैसा नाम पाया है वैसे हिन्दी के किसी दूसरे लेखक ने नहीं पाया। प्रेमचन्द हिन्दी-मनोरंजन की एक मूल्यवान् विधि हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों तथा कहानियों के द्वारा हिन्दी-साहित्य को

जो रत्न प्रदान किये हैं, उनसे वह तो गौरवान्वित हुआ ही है, इतन विश्व-साहित्य को भी एक मूल्यवान् दान मिला है।

हिन्दी साहित्य में श्री जयशंकर 'प्रसाद' ने नवीन नाटका की रचना करके यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी नाटक आधुनिक नाट्य-कला में किसी भी भाषा के साहित्य से पीछे नहीं है। उन्होंने अपनी नाट्य-कला के द्वारा भारतीय आर्य-संस्कृति तथा कला का जो पुनरुज्जीवन किया है, वह उनकी साहित्य और समाज को एक स्थायी देन है।

बंगला साहित्य के श्री बंकिमचन्द्र, श्री सरत्चन्द्र और श्री रवीन्द्रनाथ अमर रत्न हैं। यदि बंगला साहित्य में कुछ भी न रहे तो भी रवीन्द्रनाथ उसे अमर बनाने के लिए काफी हैं। डॉ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर आज इस सप्ताह में नहीं हैं और उनका युग भी बीत चुका, परन्तु उन्होंने जिन कला-कृतियों का निर्माण किया है वे विश्व साहित्य की अमर रचनाएँ हैं। सप्ताह भर में उनका भाग है। वे बंगला के ही महाकवि, नाटककार और उपन्यासकार नहीं थे, प्रसूत इस युग के सबसे महान् कवि थे। वह मानवता के महान् उपासक और आर्य संस्कृति के आचार्य थे।

गुजराती साहित्य, मराठी-साहित्य तथा तामिल तेलगू और उर्दू-साहित्य ने भी बड़ी उन्नति की है। पर स्थानाभाव-वश यहाँ इनके सम्बन्ध में विवेचन अभिप्रेत नहीं है।

कला

भारतीय कला के आदर्श

ललित कलाओं में साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्र कला, मूर्ति-कला, और वास्तुकला का स्थान है। इनमें से साहित्य के विषय में हम ऊपर विवेचन कर चुके हैं। संगीत, नृत्य आदि अन्य कलाओं के सम्बन्ध में विचार करने में पहले यह उचित होगा कि हम भारतीय कला की विशेषताओं, आदर्शों तथा लक्ष्य के विषय में विचार करें, कारण कि ये आदर्श और लक्ष्य केवल साहित्य तक ही परिमित नहीं। प्रसूत दूसरी ललित कलाओं में भी उनकी स्पष्ट परस्पर सम्बन्ध है।

आज भारतवर्ष में, साहित्यिक जगत में एक युग में, आदर्शवाद तथा यथार्थवाद की लेकर एक बड़ा वाद-विवाद खड़ा हो गया है। कला में यथार्थ का चित्रण होना चाहिए—संसार को हम जैसा देखते हैं, उसका ज्यों का त्यों चित्रण हो कला है, ऐसा यथार्थवादी का मत है। दूसरी ओर आदर्शवादी का मन यह है कि संसार में बुराई-मलाई सभी को हम देखते हैं, परन्तु यह सभी यथार्थ नहीं—सत्य नहीं। इसलिए हमें जो वास्तव में सत्य है—आदर्श है, उसीका चित्रण करना चाहिए। एक मत के अनुसार कला में इन दोनों का समन्वय ही उचित मार्ग है।

यहाँ इन दोनों वादों की समीक्षा अभिनेत्र नहीं है। हमें तो यह देखना है कि ये दोनों वाद भारतीय-कला के आदर्शों के वहाँ तक अनुकूल हैं। यह हम ऊपर ही कह चुके हैं कि भारत में कला का उद्देश्य धर्म-देवों की कला-साहित्य की अपेक्षा मित्र है। भारतीय और विगेनन आर्य-जीवन का लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार कला की प्राप्ति। इन्हीं की धार्मिक भाषा में पुरुषार्थ कहा गया है। मानव-जीवन का लक्ष्य है इन चारों की सिद्धि। वन इन्हीं चरम लक्ष्य को दृष्टि में रखकर समस्त भारतीय साहित्य तथा कला का निर्माण हुआ है। इस प्रकार कला, भारतीय की दृष्टि में, पाश्चात्य देशों की तरह, मनोरंजन का साधन नहीं है, प्रत्युत वह जीवन को मुक्ति-व्ययन से मोक्ष की ओर ले जाने का एक मार्ग है—साधन है। जिस प्रकार योग-साधना द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य-साधन और कला की उपासना द्वारा भी ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है।

भारतीय आर्य साहित्य में धर्म से मुक्ति की ओर जाने के लिए जो भावना अंतर्भूत है, उसका हमारे धार्मिक सिद्धान्तों में गहरा स्वरूप है। संसार भर में आर्यों (हिन्दुओं) के मित्राचार्य और कौटिल्य पुनर्जन्म तथा कर्म-फल के सिद्धान्तों से विश्वास नहीं करनी। पाश्चात्य देशों में तो इसी जन्म में मनुष्य को भोग-विश्रान्त का जीवन बिताकर अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करनी है। उनकी जतना का परलोक-जीवन

जा रत्न प्रदान किय है उनसे वह तो गौरवाचित हुआ हा है, इसमें विश्व साहित्य को भी एक मूल्यवान दान मिला है।

हिन्दी साहित्य में श्री जयशंकर प्रसाद ने नवान नाट्य कला की रचना करके यह सिद्ध कर दिया है कि हिन्दी नाटक आधुनिक नाट्य कला में किसी भी भाषा के साहित्य से पीछे नहीं है। उन्होंने अपनी नाट्य कला में द्वारा भारतीय आय-सस्कृति तथा कला का जो पुनर्जन्म किया है वह उनकी साहित्य और समाज को एक स्थायी देन है।

वगला साहित्य के श्री बकिमधद्र श्री शरतचन्द्र और श्री रवीन्द्रनाथ अमर रत्न हैं। यदि वगला साहित्य में कुछ भी न रहे तो भा रवीन्द्रनाथ उस अमर बनाने के लिए काफी हैं। डा० रवीन्द्रनाथ ठाकुर आज इस ससार में नहीं हैं और उनका युग भी बीत चुका परन्तु उन्होंने जिन कला कृतियों का निर्माण किया है वे विश्व साहित्य की अमर रचनाएँ हैं। ससार भर में उनका मान है। वे वगला के ही महाकवि, नाटककार और उपासक हैं। ये प्रत्युत इस युग के सर्वम महान कवि हैं। वह मानवता के महान उपासक और आय सस्कृति के आचम्य हैं।

गुजराती साहित्य, मराठी साहित्य तथा तामिल तेलगू और उर्दू साहित्य में भी बड़ी उन्नति की है। पर स्थानाभाव वश महा इनके सम्बन्ध में विवेचन अभिप्रेत नहीं है।

कला

भारतीय कला के आदर्श

सलिल कलाओं में साहित्य, संगीत नृत्य चित्र-कला मूर्ति-कला और वास्तुकला का स्थान है। इनमें से साहित्य के विषय में हम ऊपर विवेचन कर चुके हैं। संगीत नृत्य आदि अन्य कलाओं के सम्बन्ध में विचार करने से पहले यह उचित होगा कि हम भारतीय कला की विशिष्टताओं आदर्शों तथा लक्ष्य के विषय में विचार करें। कारण कि ये आदर्श और लक्ष्य केवल साहित्य तक ही परिमित नहीं हैं। प्रकृत दूसरी शक्ति कलाओं में भी उनका स्पष्ट चरित्र हमें मिलता है।

आज भारतवर्ष में, साहित्यिक जगत में एक युग से, आदर्शवाद तथा यथार्थवाद की लेकर एक बड़ा वाद-विवाद खड़ा हो गया है। कला में यथार्थ का चित्रण होना चाहिए—ससार को हम जैसा देखते हैं, उसका ज्यों का त्यों चित्रण ही कला है, ऐसा यथार्थवादी का मत है। दूसरी ओर आदर्शवादी का मत यह है कि ससार में बुराई-भलाई सभी को हम देखते हैं, परन्तु यह सभी यथार्थ नहीं—सत्य नहीं। इसलिए हमें जो वास्तव में सत्य है—आदर्श है, उसी का चित्रण करना चाहिए। एक मत के अनुसार कला में इन दोनों का समन्वय ही उचित मार्ग है।

यहाँ इन दोनों वादों की समीक्षा अभिप्रेत नहीं है। हमें तो यह देवना है कि ये दोनों वाद भारतीय-कला के आदर्शों के कहीं तक अनु-कूल हैं। यह हम ऊपर ही कह चुके हैं कि भारत में कला का उद्देश्य अन्य देशों की कला-साहित्य की अपेक्षा भिन्न है। भारतीय और विशेषतः आर्य-जीवन का लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार फलों की प्राप्ति। इन्हीं की धार्मिक भाषा में पुस्तार्थ कहा गया है। मानव जीवन का लक्ष्य है इन चारों की सिद्धि। बस इसी चरम लक्ष्य की दृष्टि में रखकर समस्त भारतीय साहित्य तथा कला का निर्माण हुआ है। इस प्रकार कला, भारतीय की दृष्टि में, पाश्चात्य देशों की तरह, मनोरंजन का साधन नहीं है, प्रत्युत यह जीवन की मुक्ति-वधन से मोक्ष की ओर ले जाने का एक मार्ग है—साधन है। जिस प्रकार योग-साधना द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है, उसी प्रकार साहित्य-साधन और कला की उपासना द्वारा भी ब्रह्मानन्द की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है।

भारतीय आर्य साहित्य में वधन से मुक्ति की ओर जाने के लिए जो भावना आंतर्भूत है, उसका हमारे धार्मिक सिद्धान्तों से गहरा संबंध है। ससार भर में आर्यों (हिन्दुओं) के सिवा साधक और कोई जाति पुनर्जन्म तथा कर्म फल के सिद्धान्तों में विश्वास नहीं करती। पाश्चात्य देशों में तो इसी जन्म में मनुष्य की भोग विलास का जीवन बिनाकर अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करनी है। उनकी जनता का परलोक-जीवन

तथा पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं। इसलिए जो कुछ इस जीवन में कर लिया जाये वही सायंक है, परलोक से हमारे आर्या का कोई सम्बन्ध नहीं। परन्तु भारतवर्ष में यह सिद्धान्त प्राचीन काल से प्रचलित है कि मनुष्य तीन प्रकार के कर्म के बन्धन में है। सचित कर्म—जिन कर्मों को वह कर चुका है प्रारब्ध-कर्म—जिन कर्मों को वह भोग रहा है, क्रियमाण—जिन कर्मों को वह अब कर रहा है तथा जिनका फल भविष्य में भोगना पड़ेगा।

मनुष्य मृत्युपर्यन्त कर्म करता रहता है, कुछ कर्मों का फल वह अपने इस जीवन में भोग लेता है और शेष कर्मों के भोगने के लिए उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। यदि मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या व साधना करे और उसमें उसे सफलता मिल जाये तो वह कुछ नियत काल के लिए जन्म मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

इस प्रकार हम भारतीय साहित्य तथा कला में इस विश्वास की स्पष्ट झलक पाते हैं। यदि आप किसी भारतीय नाटक को देखें तो आपको यह मालूम हो जायेगा कि वह सुखान्त ही है। यदि कोई दुष्ट जन किसी साधु पुरुष के शुभ कार्या में बाधा डालता है, अथवा वह उस पुरुष की हत्या कर देता है, तो भारतीय नाटककार अपने नाटक में उस साधु पुरुष के साथ पूर्ण सहानुभूति रखेगा और उस दुष्ट पात्र को अन्त में दण्ड दिलायेगा। यदि उसे बिना दण्ड दिये छोड़ दिया जायेगा तो इससे भारतीय विश्वास को बड़ी ठेस लगेगी और वास्तव में होता भी ऐसा ही है।

इस प्रकार भारतीय कला का आदर्श है मुक्ति की साधना। इसके अनुसार जो-जो सिद्धान्त ठीक हैं, उनका भारतीय कला में निर्वाह वाछनीय है। यथार्थवादी जिसे सत्य समझते हैं, वह वास्तव में सत्य नहीं है, यदि वह अपने आन्तरिक चक्षुआ से सत्य की खोज करे और सत्य का दर्शन करे तो उसे प्रकट होगा कि जिस अश्लील तथा कामुक चित्र के चित्रण को वह यथार्थ मानता है, वह तो सत्य से दूर है।

पुनर्जन्म तथा कर्म फल के सिद्धान्तों की गहन व्याख्या से एक बहुत-

ही अवाञ्छनीय प्रभाव जनता के हृदय पर पड़ा है—वह यह कि आज समाज में यदि किसी ब्राह्मण की उच्च स्थिति है, तो वह उसके अपने कर्मों के कारण है और यदि आज किसी दीन-दलित जन की दुर्दशा है तो वह उसके कर्मों का फल है। इसलिए समाज की जैसी स्थिति विद्यमान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि आज नारी-जाति की हीन दशा है, तो वह उनके कर्मों का फल है, यदि आज मजदूर पूँजीपतियों के अत्याचारों के शिकार हैं तो अपने प्रारब्ध के कारण, और यदि आज किसान वर्ग पीड़ित है तो अपने कर्मों के फल से। इस प्रकार की विचारधारा ने भारतीय समाज का बड़ा अनिष्ट किया है और जनता में भाग्यवाद तथा नैराश्य को जन्म देकर उसे अपग और शक्तिहीन बना दिया है। प्रत्येक सुधार-आन्दोलन में इस विश्वास ने बड़ी ठेस पहुँचायी है।

यह विश्वास सर्वथा गलत है। मनुष्य के कर्मों का फल मिलता है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता नहीं है। मनुष्य पूर्वजन्म में जो कार्य करता है, वही आपे उसके प्रारब्ध-कर्म बन जाते हैं। इसलिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से सुयोग मिलना चाहिए जिससे वह अपना प्रारब्ध-निर्माण सही भाँति कर सके।

आधुनिक भारतीय साहित्य पर समाजवादी विचारधारा, गांधीवादी आदर्शवाद तथा डॉ० रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रहस्यवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा है। दश युग के साहित्य की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(१) राष्ट्रीय जीवन की भाँति साहित्य में भी स्वातन्त्र्य प्रियता का दर्शन हमें मिलता है। कविता का छन्द शास्त्र के बन्धन मुक्ति के प्रयत्न में भी यह स्वाधीनता-प्रेम ही है।

(२) साहित्य आज किसी एक वर्ग की आवाज़ की पूर्ति का साधन नहीं रहा है। यह अब जनता का साहित्य बन गया है। उसमें नैतिकता का लोक कल्याण की भावना की प्रतिष्ठा फिर से नये ढंग से हो रही है।

(३) आज का साहित्य जीवन के अधिक निकट हो गया है और उसमें

जीवन की विविध समस्याओं पर आधुनिक ढंग से प्रकाश डाला गया है।

(४) आज के साहित्य में मानवता के आन्ध को महत्वपूर्ण स्थान पुनः प्राप्त हो गया है। समाज तथा व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए उसमें प्रेरणा है।

(५) अन्तिम और महत्वपूर्ण विगपता है अंतर्राष्ट्रीय भावधारा का सुदूर समन्वय।

भारतीय कला के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों तथा भारत के पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक विद्वानों की यह धारणा है कि वह यथार्थ का चित्रण नहीं करती और न उसमें स्वाभाविकता ही है। परन्तु वास्तव में यह धारणा सर्वथा निराधार है। भारतीय कला में कहा भी कृत्रिमता दृष्टिगोचर नहीं होती और किसी के चित्रण में स्वाभाविकता तो उसकी निजी विगपता है। भारतीय कलाकार प्रकृति के बाह्य रूप से ही आकर्षित होकर अपनी कृति की रचना नहीं करता वह उसके अन्तर में प्रविष्ट होकर अपनी अन्तर्दृष्टि से उसकी सच्चाई की खोज करता है और इस खोज के बाद जो उसे यथार्थ का दर्शन होता है उसका वह चित्रण करता है। अर्थात् गुणाचार्य ने जो मुद्रा के आचार्य माने जाते हैं अपनी गुणनीतिसार पुस्तक में लिखा है—

‘किसी मूर्ति के स्वरूप की पूर्ण और स्पष्ट झलक मानसिक लोचनों के समक्ष उपस्थित करने के लिए मूर्तिकार को चिंतन करना चाहिए और इस चिंतन पर ही उसकी सफलता निर्भर है। और दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं — यहाँ तक कि दृश्य वस्तु का निरीक्षण भी जो इस उद्देश्य को पूरा कर सके।’ इसके आगे वह लिखते हैं — कलाकार का मूर्त की प्राप्ति चिंतन और साधना द्वारा ही सुलभ है। यह आध्यात्मिक दृष्टि ही उसके लिए सर्वथोष्ठ और सबसे सच्चा मानदण्ड है। उसे इसी पर निर्भर करना चाहिए दृश्य वस्तुओं के बाह्य इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकरण पर नहीं।

इस प्रकार भारतीय कला में दृश्य वस्तुओं का वह चित्रण नहीं है जो लोचनों का विषय है प्रयुक्त उसे तो कलाकार का अंतर्दृष्टि ही

अनुभव कर सकनी है और उसे वैसा ही चित्रित करनी है। इसलिए कवि पहले योगी और दार्शनिक है; क्योंकि उसकी कला का जन्म ध्यान, योग और साधना के द्वारा ही सम्भव है।

संगीत-कला

प्राचीन काल में संगीत-कला का भारत में बड़ा प्रचार था। ऋषि-गण यज्ञ तथा अन्य उत्सवों पर साम-गान से जनता का मनोरंजन करते थे। सामवेद को संगीत का आदि-स्रोत माना जाता है। ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी में भारत मुनि ने अपने नाट्य-शास्त्र की रचना की। यह नाट्य-शास्त्र ही भारतीय संगीत पर सबसे पुराना ग्रंथ है जो आज प्राप्य है। नाट्य-शास्त्र में मुख्यतः नाटकों के सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया है; परन्तु इसमें संगीत-कला के विषय में भी विवेचन किया गया है। इसके बाद ११वीं शताब्दी में काश्मीर के शारंगदेव ने 'संगीत-रत्नाकर' नामक ग्रंथ लिखा। संगीत-कला पर यह बड़ी प्रामाणिक पुस्तक है और उस समय से अबतक संगीतज्ञों तथा संगीताचार्यों ने इसमें प्रेरणा प्राप्त की है। चौदहवीं सदी में छोबन कवि ने राजतरंगिणी की रचना की। यह भी संगीत-कला की भीमासा करती है। अकबर के शासन-काल में खानदेश में पुठरीक बिठ्ठल का जन्म हुआ। उन्होंने सद्-राग-चन्द्रोदय, रागमाला, रागमञ्जरी और नर्तन-निर्णय ग्रन्थ लिखे। सत्रहवीं शताब्दी में अहोनाथ ने 'संगीत-पारिजात' की रचना की। इसी काल में गढ़ देश के राजा महाराजा हृदयनारायण देव ने भारतीय संगीत पर 'हृदय-प्रकाश' नामक एक बड़ी उत्तम पुस्तक लिखी। शाहजहाँ के शासन-काल में भाव भट्ट ने संगीत पर तीन पुस्तकें लिखी—अनूपसंगीतरत्नाकर, अनूपकुपा और अनूप-विलास। इसके बाद हमें इन कला पर कोई रचना प्राप्त नहीं होती। आधुनिक काल में श्री बी० एन० भालगण्डे ने संस्कृत में दो ग्रन्थ संगीतशास्त्र पर लिखे हैं—मध्य संगीतम् और अभिनव रागमञ्जरी। ये दोनों भारतीय संगीत पर अन्तिम ग्रन्थ हैं। इसके बाद कोई भी ग्रन्थ नहीं लिखा गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत-कला का भारत में बड़ा प्रचार रहा और उसके आचार्यों ने समय समय पर उसके सिद्धांतों का निरूपण किया। प्राचीन भारत में संगीत-कला का प्रयोग केवल मनोरंजन कभी नहीं रहा। संगीत का लक्ष्य था जीवन की व्याख्या करना और उसके लिए संगीत को अनुकूल बनाने में ऋषि मुनियों ने प्रकृति के मनो भावा, वैचित्र्य तथा सौंदर्य का अध्ययन किया और उसके आधार पर भारतीय संगीत कला की प्रतिष्ठा की। संगीत कला के आचार्यों को इसका पूर्ण ज्ञान था कि वायुमण्डल की किस स्थिति में किस प्रकार की संगीत-ध्वनि तथा लय उपयुक्त होती है। ध्वनि पर मौसम का प्रभाव पड़ता है। यह आजकल बेतार के तार तथा रेडियो विज्ञान ने स्पष्ट कर दिया है। इसी प्रकार प्रवास और अघकार का भी ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। इसे प्राचीन संगीताचार्य भली भाँति जानते थे।

भारतीय गायन कला में भाव, रस तथा स्वाभाविकता और समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक कला में कलाकार के भावा तथा अनुभूति की अभिव्यक्ति होना अनिवार्य है। संगीत इसका अपवाद नहीं है। भावों की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से होनी चाहिए। इसीलिए रसों का आश्रय लिया गया है। भारतीय कला में नवरस प्राचीनकाल से माने जाते हैं—शृंगार, करुण, शांत, वीर, हास्य, अद्भुत, भयानक, रौद्र और भीमत्स। इन्हीं के अनुसार राग रागिनियाँ भी होती हैं। शृंगार रस के लिए भैरवी बंगाली, बरारी, संधयी, गौरी और श्री राग हैं। करुण के लिए जोगिया भैरव मालकोश, पूरिया इत्यादि हैं। प्रत्येक संगीतज्ञ को इसका पूरा ज्ञान होता है कि किस राग का किस रस से संबंध है।

भारत में ६ मुख्य ऋतुएँ हैं—वसन्त ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त, शरद् और शिशिर। इन ऋतुओं के साथ नीचे लिखे ६ विनोद रागा का समोह किया गया है —

राग	ऋतु	मास
हिन्दोल	वसन्त	चैत्र वैशाख
दीपक	ग्रीष्म	ज्येष्ठ आषाढ

मेर	वर्षा	श्रावण-भाद्रपद
भैरव	हेमन्त	आश्विन-कार्तिक
श्री	हेम	अग्रहन-पौष
मालकोश	शिशिर	माघ-फाल्गुन

संगीतज्ञों ने एक दिन-रात्रि को एक वर्ष मानकर संगीत के लिए उसका ६ अस्तुओं में विभाजन किया है। इस प्रकार प्रत्येक काल भाग के लिए भी एक-एक राग निर्धारित किया गया है—

भैरव	प्रातः ४ बजे से ८ बजे तक,
हिंडोल	प्रातः ८ से १२ तक,
मेघ	मध्याह्न-काल १२ से ४ तक,
श्री	सायंकाल ४ से ८ तक,
दीपक	रात्रिकाल ८ से १२ तक,
मालकोश	मध्यरात्रि १२ से प्रातः काल ४ तक,

भारतवर्ष में प्राचीन काल से दो प्रकार का संगीत प्रचलित है—
मौखिक (vocal) और वाद्य-यन्त्र द्वारा (Instrumental music)। तबला, सितार, वीणा, हारमोनियम, जल-तरंग, सरोज, पखावज, बादलिन आदि वाद्य-यन्त्रों द्वारा गायन किया जाता है। आधुनिक समय में संगीत-कला के पुनरुज्जीवन तथा उसके प्रचार में दो महानुभावों ने सबसे अग्रगण्य भाग लिया। वे हैं महाराष्ट्र के संगीताचार्य पं० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर और संगीत-कला विस्तारद श्री भातखण्डे।

प्राचीन प्रणाली के संगीत में बम्बई के संगीत-समर्थ श्री अल्लादिया खाँ और श्री फैयाज खाँ हैं। लाहौर के प्रो० दिलीपचन्द बेदी भारत के सर्वश्रेष्ठ ख्याल-गायक हैं। प्रो० नारायणराव व्यास तथा श्री वी० एन० पटवर्धन प्राचीन संगीत के आचार्य हैं। उस्ताद अल्लाउद्दीन खाँ भारत में सर्वश्रेष्ठ सरोज-गायक हैं। तबला में आबिदुल्लाह अन्तर्राष्ट्रीय रघाति के कला-विस्तारद हैं। इलाहाबाद के श्री गगनचन्द्र चट्टोपाध्याय, जो पल्लवराव के नाम से प्रसिद्ध हैं, बादलिन के सर्वश्रेष्ठ गायक हैं।

इस प्रकार आज भारत में संगीत कला के पुनरुज्जीवन के लिए जो

प्रयत्न हो रहा है, वह प्रशंसनीय है। इस कार्य में भारत विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के प्रोफेसर तथा विद्यार्थीगण बड़ी रुचि के साथ भाग ले रहे हैं। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों तथा हाई स्कूलों में संगीत-कला के शिक्षण के लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है। जहाँ-तहाँ प्रतिवर्ष संगीत-सम्मेलन होने हैं। इन अवसरों पर संगीत प्रतिभागिताओं का आयोजन किया जाता है जिनमें छात्र-छात्राएँ समान रूप से भाग लेते हैं। विश्वविद्यालयों तथा हाई स्कूलों में संगीत-शिक्षा के लिए भी व्यवस्था है तथा इस विषय में परीक्षा का भी प्रयत्न है। इस कला के पुनरुद्धार के लिए शिक्षित पुरुषों तथा स्त्रियों का सहयोग आवश्यक है। आज के सम्य-समाज में संगीत को घृणा की वस्तु नहीं समझा जाता। शिक्षित तथा सम्माननीय परिवारों की कुमारियाँ तथा महिलाएँ भी इस कला का अपना रही हैं।

नृत्य-कला

नृत्य-कला का संगीत-कला से घनिष्ठ सम्बन्ध है। संगीत के समान नृत्य भी भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है। एक समय था जबकि नृत्य-कला भारत में उत्कर्ष की चरमसीमा पर पहुँच चुकी थी।

प्राचीन भारत में नटराज नकर और उनकी पत्नी पार्वती, महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन आदि नृत्य-कला में आचार्य माने जाते थे। अर्जुन ने अपने अज्ञात-वास के समय राजा विराट की कन्या उत्तरा को नृत्य-कला की शिक्षा दी थी।

परन्तु कालान्तर में नृत्य-कला भारत से लुप्त होगयी और जन-समाज तथा सम्य-समाज में इसे घृणा की वस्तु समझा जाने लगा। वेद्यों ने संगीत तथा नृत्य-कला को अपनाया और इसके द्वारा वे नागरिकों के लिए आकर्षक बनने में साधक हुई। जब ये कलाएँ इनके द्वारा संरक्षित होने के कारण क्लृप्त और दूषित हो गयी, तब सम्य-समाज में संगीत और नृत्य के प्रति और भी अधिक घृणा पैदा हो गयी। परन्तु ऐसी दशा में भी स्त्रियों ने ग्रामों और नगरों में संगीत और

नृत्य की परम्परा को कायम रखने में एक गीमा तब याग दिया ।

दश म राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन और राजनीतिक गवचेतना में स्फूर्ति पाकर कला प्रेमिया ने संगीत तथा नृत्य-कला के पुनरुज्जीवन के लिए फिर से प्रयत्न किया । १० १५ वर्षों में ही इस क्षेत्र में कलाकारों ने बड़े मनोयोग से कार्य किया है । जिसका फल आज प्रयत्न दीख पड़ता है । आज नृत्यकला का संगीत से भी कहीं अधिक आदर है । बड़े बड़े मुम्बई तथा अन्य परिवारों की कुमारिकाएँ, सांत्विकाएँ और स्त्रियाँ आज नृत्य-कला को सीख रही हैं ।

भारतीय नृत्य के तीन भेद हैं — (१) नाट्य (२) नृत्य और (३) नृत्त ।

नाट्यमें नर्तक या नर्तकी रंगमंच पर नाटक के अंग पात्रों के साथ नृत्य करता या करती है । नृत्य में राग, ताल और भाव तीनों की आवश्यकता होती है, परन्तु उसमें भाव का ही प्रभाव होता है । और इसमें नर्तक या नर्तकी ऐतिहासिक या पौराणिक काल के किसी भी नायक या नायिका के जीवन की किसी सामान्य घटना को अभिव्यक्त करता या करती है । नृत्य में ताल की प्रधानता होती है । स्वर और ताल के साथ गावना पड़ता है । नृत्त दो प्रकार का होता है — (१) ताण्डव (२) लास्य । शिवजी के नृत्त को ताण्डव तथा पार्वती के नृत्त को लास्य कहा जाता है । इसी कारण पुण्ड्र ताण्डव करते हैं और स्त्रियाँ लास्य करती हैं ।

नृत्य में भाव, रस, राग, ताल और अभिनय होता है । नर्तक में भी भाव होते हैं वह उन्हें किसी न किसी रस द्वारा स्वर और ताल के साथ अपने अभिनय द्वारा व्यक्त करता है ।

भावा का अभिनय चार प्रकार से किया जाता है — (१) आंगिक (२) सात्विक (३) वाचिक और (४) वाह्य ।

१ आंगिक अभिनय में नर्तक मुद्रा प्रदर्शन अर्थात् अंग और विशेष रूप से हाथों के संकेतों द्वारा भाव प्रदर्शन करता है ।

२ सात्विक अभिनय में नर्तक आँसू, कपन, स्वरभेद, भय, मूर्च्छा, मुस्मान, आदि शारीरिक अवस्थाओं के द्वारा भाव प्रदर्शन करता है ।

३ वाचिक अभिनय म शब्द या ध्वनि द्वारा भाव प्रदर्शन किया जाता है ।

४ वाह्य अभिनय में वस्त्रालंकार तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है ।

भारतवर्ष में आजकल दो प्रकार के नृत्य सभ्य अधिक प्रचलित हैं— कथक और कथाकली । कथक लास्य नृत्य है और कथाकली ताण्डव ।

कथक नृत्य

इस नृत्य में नृत्य लय और ताल में बंधा होना है । इस नृत्य में अधिकांश में शृंगार रस से परिपूर्ण मनाभावों की अभिव्यक्ति की जाती है । नृत्य में पग, हस्त, गर्दन, भ्रू, और खास एक दूसरे से मिलकर तान म चलते हैं । उत्तरी भारत में इस नृत्य का अधिक प्रचार है ।

कथाकली-नृत्य

इस नृत्य का दक्षिण भारत और विशेष रूप में केरल प्रान्त में बड़ा प्रचार है । परन्तु यह अब समस्त भारत में लोकप्रिय हो गया है । इस नृत्य में मुद्रा के प्रदर्शन द्वारा नृत्य किया जाता है । इसमें हाथ, हथेली और उँगलियों के भिन्न संकेतों द्वारा भावा का प्रदर्शन किया जाता है । एकाकी कर-मुद्राएँ और संयुक्त कर मुद्राएँ कुल ६० हैं जिनका नृत्य में प्रयोग किया जाता है । इन दोनों प्रकार की कर मुद्राओं द्वारा ५०० से अधिक शब्द व्यक्त किये जा सकते हैं । परन्तु मुख्यतः ५ एकाकी मुद्राओं और कुछेक संयुक्त मुद्राओं का प्रयोग सामान्यतया किया जाता है ।

कुछ नृत्य कला के आचार्यों के अनुसार कथाकली में लास्य तथा ताण्डव दोनों प्रकार के भेद होते हैं । अर्थात् ताण्डव में वीर तथा भयानक और रौद्र रस की अभिव्यक्ति की जाती है और लास्य में शृंगार भक्ति तथा करुण रस की ।

आजकल भारतीय नाट्य कला के आचार्यों, संसार प्रसिद्ध नृत्य कला विद्वान् श्री उदयशंकर भारत में नृत्य कला के पुनरुज्जीवन के लिए उद्योग

कर रहे हैं। उन्होंने यूरोप और अमरीका में वर्षों तक अपनी कला का प्रदर्शन करके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। अलमोडा की एक उपत्यका में, प्रकृति की मनोरम गोद में उन्होंने भारत-संस्कृति-केन्द्र (India Culture Centre) की स्थापना करके नृत्य के पुनरन्वर्धन के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिया है।

स्वयं श्री उदयशंकर के शब्दों में "इस केन्द्र में सम्मिलित होनेवाले कलाकार गतिमय सत्कार को देखने, उसकी रंग बिरंगी रूपरेखा को परखने और सजीव मूर्ति-रूप में उसे व्यवस्त करने तथा उसकी गाना प्रकार की कोमल और भावपूर्ण भगियों को साकार रूप से दृष्टिगोचर करने और कराने की शिक्षा दी जायगी। इसके पाठ्य-क्रम तथा अभ्यास की नींव शास्त्रोक्त रीति से होते हुए भी शरीर की सहज सुन्दर भाव-भंगी के आधारभूत होंगे। छात्रों में सक्रिय कल्पना शक्ति की वृद्धि के लिए उन्हें कुछ खास तरह के ऐसे अभ्यास बताये जायेंगे, जिनसे वे चित्त की एकाग्र और भावुकता को बढ़ाने में समर्थ होते हुए अपनी भूलें और कमियाँ स्वयं समझ सकें।

यह तो है संस्कृति-केन्द्र का लक्ष्य। अब कला के विषय में कलाकार उदयशंकर के विचार भी मननीय हैं—

"यद्यपि कलात्मक दिग्दर्शन वास्तविक जीवन में भिन्न होता है, परन्तु वह आधारित रहता है जीवन पर ही। भारत में हम कला की त्रिविध दृष्टिकोण से देखते हैं। इनमें एक है मुद्राओं की सहायता से कला का दिग्दर्शन कराना। इसमें वास्तविक से, जो रंगमंच पर किया जाता है, अधिक अर्थसूचक होता है और यही रस की अनुभूति है। पृथ्वी के ऊपर के बुलबुलों की भांति नहीं बल्कि समुद्र के स्थायी अन्तर्लोक की भांति होता है। दर्शक और कलाकार का वास्तविक समागम तभी सम्भव है जब कि कलाकार रस के इस स्थायी लोत का मुर छेड़ सके और उसे समवेत रसिक-मण्डली तक पहुँचाने में समर्थ हो सके। सिर्फ टेकनीक याद करने से काम न चलेगा। कलाकार का समूचा जीवन कलामय बनाना होगा जिससे वह सजीव मूर्तिकला को

रखन कर सके और तभी यह आध्यात्मिक विकास तथा भावना में प्रवेश कर सकेगा।^१

श्री उदयगकर, वास्तव में, आर्य सस्कृति और कला के एक महान् उदायक ह। उन्होंने भारत की मृतप्राय नृत्यकला को पुनर्जन्म दिये करके उसमें मौलिकता तथा नवीनता की स्थापना की है। नृत्य भारत में अश्वमेधा तथा कामुकता का बोधक बन गया था पर उन्होंने उसे अपनी साधना तथा सिद्धि द्वारा एक दैवी कला के रूप में फिर म उपस्थित किया है।

भारत में नृत्य कला का प्रचार दिनादिन बढ़ता जा रहा है। कुमारी वनकलता, कुमारी अमलानन्दी, श्री साधना बोस, रुक्मिणीदेवी, श्री रागिनीदेवी (अमरीकन महिला) और श्रीमती मीनाक्षी रामाराय ने इस कला में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। और भारत के लिए विशेष गौरव की बात यह है कि भारत से बाहर इन कलाकारों के प्रदर्शनों से प्रभावित होकर अमरीका व यूरोप में भारतीय नृत्य अधिक लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। आज से प्राय ३०-३५ वर्ष पूर्व अमरीका में मिस हय सेंट डेनिस, ने जो अमरीका में हिन्दू नृत्यकला की आवाज मानी जाती है, अपने भारतीय नृत्या से लोगो की धृष्टा और प्रशंसा प्राप्त की। वर्तमान समय में ला मेरी नाम की अमरीकन महिला अमरीका में भारतीय नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही है।

चित्रकला

चित्र-कला भी भारत में प्राचीन काल से ही प्रतिष्ठित है। या तो चित्र कला के सश्रव में अनेक प्राचीन सस्कृत ग्रन्थों में उल्लेख मिलना है, परन्तु विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रमूत्र अध्याय में उसका विस्तृत और सरस वर्णन है। डा० स्टेला कामरिस ने अंग्रेजी भाषा में इस अध्याय का अनुवाद किया है। च० आनन्द कुमार स्वामी ने भी इसका अनुवाद

किया है। श्री नान्हालाल चमनलाल मेहता आई सी एस के मतानुसार 'चित्र, नृत्य और चित्रकला का महत्त्व समझने के लिए 'चित्रसूत्र' इतने महत्त्व का ग्रन्थ है कि उसका हिन्दी में किसी योग्य उपनिषद् द्वारा प्रामाणिक अनुवाद तुरन्त कराना चाहिए।' १

उपर्युक्त ग्रन्थ के आरम्भ में मार्कण्डेय मुनि ने लिखा है—'विना तु नृत्यशास्त्रेण चित्रसूत्रमुदुविदम्।' नृत्य शास्त्र के अध्याय के बिना 'चित्र सूत्र' समझना कठिन है।

सन् १९०९ में बालुस्थल के नरेश सोमेश्वर के भूपति ने 'मान-मोलास' नामक ग्रन्थ में चित्रकला का विवेचन किया और १६ वीं सताब्दी में श्री कुमार ने 'दिग्दर्शन' नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें चित्रकला का उल्लेख है।

वात्स्यायन के 'वामसूत्र' ग्रन्थ में चित्र के ६ ध्येय बताये गये हैं जो ये हैं

- १ रूपभेद (आकृतिभेद) २ प्रमाण ३ भाष ४ लावण्य-योजना
- ५ सादृश्य और ६ वर्णिक भग (रंगों का विधान) ।

भारतीय चित्रकला के अन्तर्गत ४ प्रकार के चित्रों का उल्लेख मिलता है

१ भित्ति-चित्र—ये चित्र भवना, मन्दिर और यज्ञशालाओं की दीवारों पर बनाये जाते हैं। अजन्ता की गुफा में इसी प्रकार के चित्र हैं।]

२. चित्रपट—ये चित्र कपड़े या कागज पर बनाये जाते हैं।

३ चित्र-फटक—ये चित्र पत्थर या लकड़ी पर बनाये जाते हैं।

४ धूलि-चित्र—ये चित्र रंगों से पृथ्वी पर बनाये जाते हैं। आज-कल समुद्रप्रान्त तथा अन्य प्रान्तों में विवाह आदि शुभ अवसरों पर स्त्रियाँ रंगों से पृथ्वी पर चित्र बनाती हैं। उसे 'चौक पूरना' या 'माची' कहते हैं।

चित्रकला द्वारा चित्रकार अपने मनोभावों को इस रीति से अभि-

व्यक्त करता है कि चित्र को देखनेवाले के हृदय में भी वैसी भावना का उदय हो जाता है और इस प्रकार चित्रकार तथा दर्शक के बीच आध्यात्मिक संबंध स्थापित हो जाता है।

ऐतिहासिक महापुरुषों के जीवन की घटनाओं, विशेष ऐतिहासिक घटनाओं तथा प्राकृतिक दृश्यों के संरक्षण के लिए चित्रकला सर्वोत्कृष्ट साधन है। प्राचीन काल में धार्मिक कृत्यों और विवाहादिक अवसरों पर भी इसका प्रयोग किया जाता था। उसकी उपयोगिता असंदिग्ध है।

भारतवर्ष में चित्रकला का विकसित करने तथा उसके संरक्षण का पूरा श्रेय हिंदू चित्रकारों को है। आज जिस हम लोग मुगल चित्र-कला कहते हैं उसके निर्माण में भी हिंदू चित्रकारों का ही हाथ है। हाँ यह शब्द उस चित्रावली के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो मुगल काल में तैयार की गयी थी।

भारत में मुसलमान चित्र-कला का विरोध रहे हैं। इसके कारण का उल्लेख करते हुए श्री महता ने अपने ग्रंथ में लिखा है—

कुरान के पाँचवें अध्याय में लिखा है कि शराब, धूम्र, प्रतिमा विधान, भविष्यकथन, ये सब शैतान के काम हैं। इन चीजों से मुसलमानों को बचना चाहिए। यद्यपि इसमें चित्रकला के लिए कोई निषेध नहीं परंतु हदीस के अनुसार कयामत के दिन चित्रकार को घोर नरक में स्थान मिलेगा, क्योंकि उसने मनुष्य कृत वस्तुओं में प्राण संचार करने का दुस्साहस किया है। सर टामस आरनाल्ड के मतानुसार यह तिरस्कार इसलिए संभव हो सकता है कि शुरु में इस्लाम धर्म के अनुयायी यहूदी थे जिनके मन में पुरानी प्रतिमाओं व चित्रों के प्रति बहुत ही दुर्भाव व तिरस्कार पैदा हुआ।^१

इस धार्मिक अंधपरम्परा का होना हुआ भी हम देखते हैं कि मुगल बादशाहों ने चित्र-कला का प्रासादन दिया। आजकल भी सितमा कला जिसमें चित्रकला को प्रमुख स्थान प्राप्त है का विकास में मुस्लिम अभि

नेताजी तथा अभिनेत्रिया का पूरा हाथ है। ऐसे भी बहुत से चित्र मिलेंगे जिन्हें मुख्य चित्रकारों ने बनाया है।

अजन्ता की गुफाओं की चित्र-कला

निजाम राज्य हैदराबाद में औरंगाबाद से ५० मील दूर पर अजन्ता प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ चट्टान में खोदकर ३२ गुफाएँ बनायी गयी हैं। जिनमें २९ विहार और ३ चैत्य हैं। अजन्ता की इन गुफाओं में आज से प्रायः दो हजार वर्ष पूर्व चित्र बनाये गये थे। अजन्ता की तरह एलोरा में भी चित्र कला की शोभा दक्षनीय है। परन्तु इन दोनों में अन्तर यह है कि अजन्ता की कला विषुद्ध बौद्धकला है और एलोरा की कला में बौद्ध, जैन और हिन्दू कलाओं का मिश्रण है। इन चित्रों से तत्कालीन जन्ता के रीति रिवाजों, मस्ति और धार्मिक-जीवन का पूरा पता लग जाता है। इन विहारों में महात्मा बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं को कलाकारों ने बड़े धार्मिक तथा प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। वास्तव में ये भारतीय कला के आश्चर्य-जनक प्रतीक हैं, जो आज भी उसकी सर्वश्रेष्ठता को पुनः-पुनः कर बनाते हैं।

श्री अम्बनीन्द्रनाथ ठाकुर ने चित्र कला में जो युगांतर उपस्थित किया है तथा स्व० श्री शारदाचरण उकील ने जिस परम्परा को चलाया है उसमें इस कला में बड़ी उन्नति हुई है। आजकल बदलाव बहुत, अभितकुमार हालदार आदि अच्छे चित्रकार हैं।

वास्तु-कला

प्राचीन भारत में जहाँ आर्य जाति ने बस कला का य उन्नति की वहाँ वास्तु (मकान निर्माण) कला में भी आश्चर्यजनक उन्नति की थी। प्राचीन संहित साहित्य तथा विशेषतः रामायण और महाभारत के अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से विदित हो जाता है कि आर्यों की अपन निजाम स्थापन करने, यन् शान्ता, धर्मशान्ता तथा अन्य आर्थिक मकान आदि बनाने में वास्तु कला के सिद्धांतों ने काम लेने का। धानु के भी मकान

बनाये जाने थे। इन्द्रप्रस्थ में महाभारत-कालीन भवनो के जो भग्नावशेष आज मौजूद हैं, उनसे भी यह प्रमाणित हो जाता है कि पहले कलाकार मकान बनाने में ऐसी सामग्री का प्रयोग करते थे जो आज की अपेक्षा अधिक मजबूत होती थी।

मौर्य-काल में वास्तु-कला समृद्धि पर थी। पाटलिपुत्र में सुन्दर भवन थे। लकड़ी का काम भी बड़ा कलापूर्ण था। भारहुत, सांची, और अमरावती के स्तूप बौद्ध वास्तु-कला के सुन्दर नमूने हैं। कनिष्क तथा ह्विष्क ने भी कई दर्शनीय इमारतें बनवायी थी। गुप्त-काल में बनारस तथा मथुरा के कई मन्दिरों का निर्माण किया गया था। हर्ष के शासन काल में नालंद में बड़े भव्य मकान बनाये गये। बनारस, मथुरा और कन्नौज में हिन्दू तथा बौद्ध मन्दिर बन गये थे।

एलोरा का कैलास-मन्दिर वास्तु-कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मुस्लिम शासन-काल में भी वास्तु-कला की बड़ी उन्नति हुई। मुगल-काल में बादशाहों के लिए बड़े बड़े राज-प्रासाद तथा गढ़ और मस्जिदें बनायी गयीं। इस समय हिन्दू-वास्तुकला को संरक्षण न मिलने के कारण वह लुप्त-सी हो गयी। सन् १२३१ में कुतुबमीनार बनायी गयी जिसकी ऊँचाई २४० फीट है।

अकबर ने फतहपुर-सीकरी में दोस्त सलीम चिश्ती की दरगाह, और जागरा तथा इलाहाबाद में किले बनवाये। मुगल-काल की वास्तु-कला का सर्वोत्तम आश्चर्यजनक कृति है सम्राट् शाहजहाँ का अपनी बेगम का कब्र पर बनवाया हुआ ताजमहल, जो ससार की सुन्दर इमारतों में गिना जाता है।

मूर्ति-कला

भारत में मूर्ति-कला की भी बड़ी उन्नति हुई है। प्राचीन काल में हिन्दू देवी-देवता तथा अपने इष्टदेवों की अत्यन्त सुन्दर मूर्तियाँ बनाने थे। ये पत्थर, धातु, लकड़ी या हाथी दाँत की होती थीं। बौद्ध तथा जैन-काल में भी मूर्ति-कला का पर्याप्त विकास हो चुका था।

नागरिक जीवन और कला

नागरिक जीवन को सर्वश्रेष्ठ और समाजोन्मुखी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे संस्कृति के ढाँचे में ढाला जाये। संस्कृति का अर्थ है—परिष्कार और स्कार। मानव-जीवन को सुसंस्कृत बनाने के लिए कला ही सर्वोत्तम साधन है। प्रत्येक युग में जब मानव समाज ने अभ्युदय प्राप्त किया तब ऐसा वह कला के विकास द्वारा ही कर सका। वास्तव में मानव एकता और विश्व-बन्धुत्व की स्थापना करने में कला का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। जब-जब समाज ने विखुद कला की साधना की तब-तब उसने शान्ति, समृद्धि और मानव-एकता को प्राप्त किया और जब-जब समाज कला के नाम पर विनाशिता और कामुकता में लीन होगया, तब-तब उसे पतनोन्मुख होना पड़ा है। इतिहास इसका ज्वलन्त प्रमाण है। इसकी सिद्धि के लिए भारतीय इतिहास से दो प्रमाण दे देना उचित होगा।

मौर्य-काल में समाज कितना प्रगतिशील था और जनता में कितनी सुख-समृद्धि थी। उस काल में मानव समाज में विखुद कला की पूजा की जाती थी। परन्तु मुगल काल में जब कला को राजाओं तथा नवाबों के राज-वासालों में परिमित कर—जनता के बीच से उसे पृथक् कर—उनके मनोरंजन तथा विनाशिता का साधन बना दिया गया तब हिन्दू-कला के पतन के साथ भारतीय जीवन और चरित्र का भी पतन हो गया। यही कारण है कि हम मौर्य-कालीन चित्रकला में भक्ति-भावना की झलक पाते हैं—उसमें जीवन के वधन से मुक्ति पाने की साधना का स्पष्ट आभास मिलता है। परन्तु मुगल काल की कला में हम कामुकता, निम्न कोटि के भृंगार और विनाशिता की छाया पाते हैं। कारण स्पष्ट है कि मौर्य-काल में कला जन-समाज में एवना स्थापित करने के लिए थी, परन्तु मुगल-शासन में वह अपने इस उच्च ध्येय से भ्रष्ट कर दी गयी और एक वर्ग-विशेष ने मनोरंजन की साधन बन गयी।

कला का लक्ष्य मानवता को मुक्ति की ओर ले जाना है। वह मानव-जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम करती है। वह समाज में एकता

की प्रतिष्ठा के लिए एक सर्वोत्कृष्ट साधन है ।

वर्तमान काल में हम जो विश्व-मस्तिष्क तथा समाज-ज्वला के विनाश का भयानक दृश्य देख रहे हैं उसका कारण है मज्बी कला की उपामना की उपेक्षा । वैज्ञानिकों ने बड़े चिन्तन तथा परिश्रम के बाद जिन नवीन-नवीन आविष्कारों तथा वैज्ञानिक चमत्कारों का आविर्भाव मानव-वल्याण के लिए किया था, उनका प्रयोग आज मानवता के विनाश के लिए हो रहा है !

कला और विज्ञान इन दोनों का मानव-जीवन के उत्कर्ष में महान् स्थान है । जिस प्रकार मनुष्य-शरीर में मस्तिष्क और हृदय का स्थान है, उसी प्रकार मानव-जीवन में विज्ञान और कला का स्थान भी है । विज्ञान मानव-मस्तिष्क की उपज है और कला का सबध हृदय से है । विज्ञान विचार-प्रधान है—वह सत्य की जाँच करता है और कला भावना-जगत में उस सत्य की प्रतिष्ठा करती है । एक का विकास तथा उत्कर्ष दूसरे पर निर्भर है । एव की अशुद्धि का प्रभाव दूसरे पर अनिवार्य है । यदि हृदय किसी तरह विकारपूर्ण हो जाये तो उसका प्रभाव मस्तिष्क पर पड़े बिना न रहेगा और फलतः सम्पूर्ण शरीर उस विकारपूर्ण हृदय से प्रभावित हो जायेगा । इसी प्रकार यदि मानव-जीवन में कला अपने उद्देश्य या लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाये तो विज्ञान भी उसमें प्रभावित हुए बिना न रहेगा ।

आज ससार में जो भीषण ताण्डव हो रहा है और जिसके फलस्वरूप मानवता का सहार हो रहा है, उसका मूल कारण यही है कि पाश्चात्य देशों ने कला को भ्रष्ट कर उसे अपने विलास का साधनमात्र बना लिया है । इसी कारण आज वहाँ कला और विज्ञान दोनों में कोई सबध नहीं रहा है । कला-शून्य जीवन में विज्ञान आज कल्याण के म्यान पर सर्व-नाश की चर्पा बर रहा है ।

अतः सारांश यह है कि नागरिक-जीवन में कला—विशुद्ध कला को फिर से उसी उच्चासन पर बिठाया जाये जिसमें वह मानव-समाज में एकता की स्थापना कर सके ।

संस्कृति

संस्कृति क्या है ?

'संस्कृति' शब्द संस्कृत में बना है। संस्कृत का अर्थ है शुद्ध किया हुआ, परिमार्जित, परिष्कृत, सँवारा हुआ। संस्कृत विशेषण है और संस्कृति सजा है। अतः संस्कृति का अर्थ हुआ सृष्टि, परिमार्जन तथा परिष्कार। मानव-समाज ने सामाजिक जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनानेवाली जो एक प्रवृत्ति है, उसी का नाम संस्कृति है। प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक सर मॉरिस ग्रायर ने अपने एक भाषण में संस्कृति के मन्त्र में जो विचार प्रकट किये हैं उनमें इसका अर्थ और भी स्पष्ट हो जायेगा।

'मैं यह कहना चाहूँगा कि सच्ची संस्कृति का मुख्य मिशनक महानुभूति है, दिखावा अथवा उसका दावा नहीं। पाश्चित्य का नाश, फला का ज्ञान तथा मनुष्य के पुष्पक में परिचय 'संस्कृति' बनाने है, ऐसा मैं नहीं समझता, पर संस्कृति जिसमें बनती है वह वह वृत्ति है जो इन सबके मित्र जाने में उत्पन्न होती है। सच्ची संस्कृतिवाले मनुष्य में मूल्य आँकने और ठीक-ठीक नापतौल की योग्यता मिलती है। जो ऐसा मनुष्य के दृश्य में किसी ऐसा विचार का ही नहीं मन्त्र कि वह वह नहीं है जो दूसरे मनुष्य है, या जो मानवता सबसे व्याप्त है उसे भूत जाये।'

संस्कृति के सम्बन्ध में योग्य विद्वान् ने जो अपना मूल्य प्रकाशित किया है, उसमें शायद ही किसी सच्चे मुसलमान व्यक्ति का मतभेद हो। आत्मिक में संस्कृति का प्रयोजन मानव समाज की एकता ही है। एक संस्कृत पुष्प के लिए सब मानव समान हैं। यह न जानि के भेद-भाव को मानता है और न धर्म के भेद को। संस्कृति मानव-एकता का अनुभव कराती है। यह मनुष्य को यह सिखाती है कि सब मानव बराबर हैं, कोई मानव किसी दूसरे से भिन्न नहीं।

आर्य-संस्कृति के आदर्श

मानव शरीर के तीन मुख्य भाग हैं—मिर्, हृदय और घड़। नसिका के भी तीन महत्त्वपूर्ण कार्य हैं—अनुभूति, भाव और इच्छा।

इसी प्रकार मस्कृति क भी जिसका मानव जीवन के विकास और मानसिक उत्थप स सम्प्रच है तीन अग है । उसका दर्शन और विज्ञान, उसका धर्म और कला और उसका कर्मकाण्ड । इस तरह मस्कृति में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीना का समन्वय है ।

आर्य मस्कृति क दार्शनिक पहलू पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका सत्रस प्रधान लक्ष्य लाकसग्रह—मानव माय का कल्याण है । उसकी दृष्टि में केवल मानव ही नहीं सभी प्राणी समान हैं । वह जाति, रग तथा मत के भेदभाव का नहीं मानती ।

आर्य सस्कृति का आदर्श यह है कि मानव विश्व में धर्म, अर्थ और काम की साधना द्वारा अभ्युदय का प्राप्त करना हुआ नि श्रेयस की सिद्धि के लिए पुरपार्य करे । यह तो निर्विवाद है कि आर्य सस्कृति आध्यात्मिक है, उसमें आत्मा-कर्म का सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है । परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह भौतिक उत्थति का विरोध करती है ।

आर्य-मस्कृति के अनुसार मानव का यह धर्म है कि वह धर्मद्वारा अर्थ की प्राप्ति करे—वह अपनी जीविता धर्म-पुनन कार्या ॥ ही कमाये । उसे इसके किए अयम का आश्रय न लेना चाहिए । यह है आर्य सस्कृति का दशन शास्त्र ।

आर्य सस्कृति का भक्ति पक्ष सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का साम-जस्यपूर्ण समन्वय है । सरस्वती का अर्थ है विद्या, ज्ञान विज्ञान, लक्ष्मी का अर्थ है धन सम्पत्ति और दुर्गा का अर्थ है शक्ति । मानव का अपने जीवन में इन तीनों की आवश्यकता है । वह पहले सरस्वती की पूजा करे अर्वात् ज्ञान विज्ञान की शिदा प्राप्त करे, उससे वह लक्ष्मी की पूजा करने में समर्थ होग । वह ज्ञान विज्ञान द्वारा उद्योग धन्यो में उत्थति करके धन पैदा कर सकेगा और इस तरह अन्त में उसे शक्ति प्राप्त हागी । यह शक्ति केवल पाशविक ही नहीं हागी, कयाकि उसके मूल में ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा होगी । वह शक्ति केवल 'आर्थिक' नहीं होगी कयोकि उसमें आध्यात्मिकता का अश भी हागा ।

आर्य-सस्कृति का तीसरा पक्ष है—कर्मकाण्ड । ज्ञान और भक्ति के बाद

कर्म जाना है। आर्य-मस्ति का सारा कर्मकांड परवर्ति के योगदान के एक मूल में निहित है। यह मूल है—यम नियम का। अहिंसा, सत्य, अग्नेय, ब्रह्मचर्य और अजरिह ये पाँच 'यम' हैं और मोक्ष, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति ये पाँच 'नियम' हैं। जो मसार में मुक्त जीवन बिनाना चाहता है और उसके बाद पारलौकिक शान्ति की दृष्टि करता है, उसे इन दस नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए।

संसार में यही आर्य-मस्ति का मौलिक स्वल्प है। आज के हिन्दू-समाज में, यद्यपि हम इन आदर्शों की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं पाते, तथापि यह तो निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि आज भी हिन्दू-जीवन इन आदर्शों के अनुसार आचरण करता अर्थात् परम मानता है।

आर्य-संस्कृति की प्रवृत्तियाँ

आर्य-मस्ति का अनुशीलन करने पर आर्य-जीवन की कई विशेषताएँ व्यक्त होती हैं।

आर्य-मस्ति की प्रथम और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि वह पारलौकिक आनन्द, शान्ति या मुक्ति का जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानकर मानव को भोगवाद से पद-पद पर सतर्क रहने की चेष्टा करती है। यह शरीर तथा जड़ जगत् नागवान् है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आत्मा का— जो अजर है, अमर है, अजन्मा है तथा अनादि है—इस भोगवाद से पतित हो जाने से बचना चाहिए। इसीलिए हिन्दू-जीवन में तपस्या, व्रत, दान, दक्षिणा आदि का विशेष महत्त्व है।

आर्य-मस्ति में व्यक्ति का उच्च स्थान है, परन्तु वह समाज से ऊँचा नहीं है। वर्ण-व्यवस्था से बहिर समाजवादी प्रवृत्ति का पूरा निर्देश मिलता है। समाज के हित के लिए मनुष्य को अपने हित का बलिदान करने की शिक्षा आर्य-मस्ति का प्रमुख अंग है।

आर्य-मस्ति अपनी समाजवादी प्रवृत्ति के कारण ही त्याग पर अधिक जोर देती है। वह भोगवाद का आत्मिक तथा आध्यात्मिक अभ्युदय में बाधक मानती है।

आर्य-सस्कृति में धर्म ओनप्रोन है। वह समाजनीति अर्थनीति, और राजनीति सभी में विद्यमान है। वह वास्तव में जीवन की एक मूल प्रेरक शक्ति है।

आर्य सस्कृति में हम मामजस्य की भावना पाते हैं। हम चाहें भाषा का लें, चाहे साहित्य को चाहें कला को चाहे सामाजिक जीवन को— सभी क्षेत्रों में महयोग की भावना मिलेगी। मघप और वगदाद के लिए आर्य सस्कृति में कोई स्थान नहीं है।

अरबी और मुस्लिम सस्कृति

भारत में अरबी सस्कृति का प्रवेश मुसलमानों के आगमन से हुआ। अरबी सस्कृति धार्मिक, सैनिकवादी और राजनीतिक है। यह एबेस्वरवादी और मूर्ति-पूजा विरोधी है। अरबी सम्यता में प्रचार की भावना ओन प्रोत है। अरबी सस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता है धार्मिक प्रवृत्ति। हिन्दू सस्कृति के समान ही मुस्लिम सस्कृति में धर्म और ईश्वर की भावना ओनप्रोन है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर धर्म का प्रभाव है। इस्लाम के शानूनो का आधार भी कुरान ही है जो मनुष्य-वृत्त नहीं है। मुसलमानों की जीवनचर्या भी इस प्रकार निर्धारित की गयी है कि वे ईश्वर और धर्म को विस्मृत नहीं कर सकते। दिन में पाँच बार नमाज पढ़ना तथा दुश्गार को मसजिद में सम्मिश्रित रूप से नमाज पढ़ना उनकी धार्मिकता का एक प्रमाण है।

मुस्लिम सस्कृति में बीर पूजा को ऊँचा स्थान प्राप्त है। बीर-पूजा का अर्थ इस हद तक लगाया गया है कि जो काफिरा के साथ धर्म-युद्ध में अपना बलिदान करदे तो वह सीधा स्वर्ग को जाना है।

मुस्लिम सस्कृति में दानशीलता भी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। मुसलमान दान दक्षिणा देना तथा इस्लाम की उन्नति के लिए मसजिद बनवाना तथा धर्म प्रचार के लिए दान देना अपना कर्तव्य समझते हैं।

मुस्लिम सस्कृति में स्त्री की पवित्रता तथा उसके सतीत्व की रक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था है। मुसलमान अपनी स्त्रियों को कठे

परदे में रखन है और मुस्लिम कानून में भी ऐसी व्यवस्था की गयी है कि मुस्लिम स्त्री विधर्मी के साथ विवाह नहीं कर सकता। मुस्लिम पुरुष तो ईसाई, पारसी या ग़रूदी के साथ शादी कर सकता है।

मुस्लिम सभ्यता में मानवीय एकता तथा समानता पर अधिक जोर दिया गया है। सब मनुष्य परमात्मा की दृष्टि में समान हैं। मनुष्य का मनुष्य के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।

मुस्लिम सभ्यता में परिवर्तन

हम उन अरबी सभ्यता की जा विशेषताएँ उपर बतानी हैं जो आदिम अवस्था की विशेषताएँ हैं। जब मुसलमान आने अरब देश का छाड़ कर विश्व में इस्लाम के विस्तार के लिए गए तब उनकी सभ्यता पर तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा और उसमें परिवर्तन हो गये।

मुस्लिम सभ्यता में जो परिवर्तन हो गया, उसका वर्णन श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने इस प्रकार किया है—

‘मुसलमान को यह सिखाया जाता है कि ‘हमारा ही मरहब दुनिया में सबसे अच्छा है, यही एक ईश्वर तक पहुँचने का सबसे बेहतर रास्ता है। जो खुदा को नहीं मानता वह काफिर है, काफिर खुदा का मुन्किर—ईश्वर विमुख—है, इसलिए वह मार डालने के लायक है। जो एक भी काफिर को बीने इस्लाम में लाता है वह खुदा की मेहर हासिल करता है—जिस तरह हो सके इस्लाम को बढ़ाओ। इसी उद्देश्य में मुस्लिम सभ्यता और मुसलमानों के स्वभाव में पायी जानेवाली अनर्थाव हितावृत्ति असहिष्णुता का बीज है। मुसलमानों का यह उग्र हिंसक स्वभाव चाहे तत्कालीन अरब की परिस्थिति के कारण बना हो, चाहे पैगम्बर साहब के कुछ उपदेशों का दुरुपयोग करने के कारण बना हो—आज के समय जगत में यह अक्षेप्योप्य एव अक्षम्य है।’^१

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि आधुनिक मुस्लिम सभ्यता में

१ श्री हरिभाऊ उपाध्याय स्वामीजी का बलिदान और हमारा कर्तव्य, पृ० ८४

असहिष्णुता की अधिकता है। यह धर्मों की मौलिक एकता में विश्वास नहीं करती। इसीलिए वह दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु नहीं है। यही कारण है कि भारत में धर्म की आड़ में साम्प्रदायिक संघर्ष दैनिक जीवन का अंग बन गये हैं।

सच तो यह है कि भारत के मुसलमानों का दृष्टिकोण इस्लामी रंग में इतना अधिक रंगा हुआ है कि वह आज न स्वधर्मानुयायी अन्य देशों की स्थिति को समझने या अवलोकन करने का कष्ट करता है और न मसाले की परिस्थिति तथा परिवर्तन को समझने का प्रयास ही।

आज पृथ्वी तथा टर्की जैसे स्वाधीन मुस्लिम राष्ट्रों में मुस्लिम सभ्यता में कितना कायापलट हो गया है। परन्तु भारत के मुसलमान नेना इमारत विचार करने का कष्ट नहीं करते। आज तुर्की में प्रजातन्त्र शासन प्रणाली है। और वहाँ शासन का आधार शरियत नहीं है जिसका मुख्य स्रोत कुरान है। टर्की के मौलिक विधान में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि—

“सरकार बिना किसी शर्त या बाधा के राष्ट्र की है। राज्य की शासन-प्रणाली इस आधार पर स्थित है कि जनता कार्य-कुशलता के साथ शासन करती है।”

मोविपट मस के १२ से अधिक राज्यों में जिनमें मुसलमानों की संख्या अधिक है, मुस्लिम-कानून में जो कायापलट हो गया है वह अच्छी तरह देखा जा सकता है। यहाँ तक कि मोविपट सच और टर्की के वक्फ की संपत्ति की राज्य प्रबंध तथा सामाजिक सुधार के कार्यों में व्यय किया जाता है। आज इन दोनों में शिक्षा कुरान के अनुसार नहीं दी जाती और न केवल मकतब ही शिक्षा के केन्द्र हैं। आज उनमें पाश्चात्य ढंग से शिक्षा की व्यवस्था है। तुर्की में तो सहशिक्षा—लड़के-लड़कियों को माय-माय एक ही स्कूल में पढ़ने की भी सुविधा है। तुर्की में परदा-प्रथा का सर्वथा त्याग कर दिया गया है। नमाज भी पाँच बार नहीं पढ़ी जाती। टर्की मसाले के मुस्लिम राष्ट्रों में पहला है जिमने बहुविवाह

की प्रथा को उठा दिया है। आज वहाँ मुस्लिम केवल एक ही पानी से शादी कर सकता है। अब वह एक साथ चार पत्नियाँ नहीं रख सकता।

आर्य-संस्कृति पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव

जब एक जाति दूसरी जाति के सम्पर्क में आती है तो स्वाभाविक रूप से उन दोनों में संस्कृतियों का आदान-प्रदान होता है। भारत में कई सदियों तक मुसलमानों का शासन रहा। उस समय भारत का राजवंश इस्लाम होने के कारण उसका हिन्दू-संस्कृति पर भी बहुत प्रभाव पड़ा।

हिन्दुओं में जो कट्टरपंथी थे उन्होंने इस्लाम के प्रभाव से अपनी रक्षा करने के लिए सामाजिक उन्नयन की ओर भी बड़ा बनाने का उद्योग किया और जातिपति के नियमों का बड़ी कठोरता के साथ पालन किया जाने लगा।

वे मुसलमानों को प्लेब्स कहने लगे और उनके सम्पर्क तथा सङ्ग में बचने के लिए बड़े सतर्क रहने लगे। अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए ही सामाजिक बहिष्कार की प्रथा शुरू हुई है।

इस्लाम के सम्पर्क में आने का प्रभाव यह हुआ कि हिन्दू समाज में जातिवाद की कुप्रथा में अधिक भयंकर रूढ़ि धारण कर लिया और अपवित्रता का भी पालन बड़ी सतर्कता से किया जाने लगा। मुसलमानों से छूतछात की जाने लगी और जो लोग मुसलमानों के सम्पर्क में रहने लगे उनमें भी कट्टरपंथी छूतछात करने लगे। इस प्रकार वे हिन्दू-समाज के लिए 'अस्पृश्य' बन गये।

हिन्दुओं की सामाजिक व्यवस्था पर भी मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ा। हिन्दू-समाज में ऐसे अनेक सुधारक और धार्मिक नेता गये महारामा पैदा हुए हैं जिनके उपदेशों में इस्लाम के उपदेशों की अलग स्पष्ट ही सीख पड़ती है। रामानन्द, कबीर, नानक, चैतन्य, बालगोविन्द आदि ऐसे कितने ही सन्त पैदा हुए जिन्होंने जाति-प्रथा के विरुद्ध प्रबल प्रचार किया और हिन्दू-समाज में समता के आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए उपदेश दिये।

१. हेनरी ई० एलेन 'इस्लाम एण्ड सम मॉडर्न प्रोग्रेस इन इंडिया' ('हिन्दुस्तान रिप्यू', जुलाई १९३४)

भारत में मुस्लिम सस्कृति के प्रभाव से हिन्दुओं में परदा-प्रथा का विकास हुआ। मुसलमानों से अपनी मा-बहन की रक्षा करने के लिए उन्हें परदे में रखा जाने लगा। इस तरह परदा हिन्दू-समाज का एक रिवाज बन गया।

मुसलमानों के आगमन से पहले हिन्दुओं की पाशाक बँसी थी जैसी हम राजपूत काल के चित्रों में देखते हैं वे सिर पर पगड़ी बाँधते थे और दाढ़ पर एक बड़ा लम्बा चोगा सा पहनते थे जो घुटना से भी नीचे तक होता था। धोती तो बहुत ही पुरानी पोशाक है।

मुसलमानों का अनुकरण करके हिन्दू भी कुर्ता, पायजामा, अचकन शेरवानी आदि पहनने लगे। स्त्रियाँ के आभूषण में भी नये-नये नकशा का अनुकरण किया गया।

मुसलमान बादशाह तथा नवाब अपनी विशासिता के लिए बदनाम थे। मुगल-दरबार में अभिचार और पाप लीला का केन्द्र बन गया था। ऐसी दशा में हिन्दू महिलाओं का सनीव सकट में था। नवयुवतिप्रा और कुमारियों का अपहरण और उनके साथ बलात्कार सामान्य घटना थी। इसी कारण हिन्दुओं में बाल-विवाह तथा अनमेल विवाह का रिवाज चर पडा।

हिन्दुओं के नैतिक जीवन पर भी मुस्लिम सस्कृति का बड़ा प्रभाव पडा। समाज में मदिरा-पान और विशासिता अधिक बढ़ गयी। अज्ञान तथा धर्म के वास्तविक स्वरूप की भूठ जाने के कारण सैकड़ों प्रकार के भ्रम विश्वास ने यहाँ अपनी जड़ जमा ली। अबतक तो हिन्दू देवी देवता की ही पूजा होती थी। परन्तु अब अज्ञानी हिन्दू स्त्री पुरुष मुसलमान फकीरा, मुल्लाओं और मौलवियों से तावीज, गण्टे और दवा लाने लग गये। यह अन्ध विश्वास यहाँ तक बढ़ा कि मुसलमानों के पीर, मदार, सैयद और कत्रा के पत्थरों तक की पूजा होने लगी।

मुसलमानों का शासन-काल में अरबी और फारसी का राजभाषा का पद मिला। भारत के उत्तरी प्रान्तों में मुसलमानों का शासन अधिक काल तक रहा। आगरा, देहली तथा लखनऊ मुगलकाल में राजधानी रह चुके हैं। फिर भारत के उत्तर में मुसलमानों का प्रचार

कम हो गया और उसके दक्षिणी प्रान्ता में उसका प्रचार बढ़ गया। हिन्दू जनता में हिन्दी भाषा का प्रचार बढ़ने लगा। इस काल में जो साधु-सन्त पैदा हुए, उन्होंने अपनी पुस्तकें हिन्दी भाषा में लिखीं। फारसी और अरबी भाषा का प्रयोग करनेवाले मुसलमान जब हिन्दुओं के सम्पर्क में आते थे तो वह अपनी भाषा में संस्कृत, हिन्दी तथा बोलचाल के सरल शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था जिससे वह हिन्दुओं के लिए बोधगम्य हो सके। यही भाषा धीरे-धीरे विकसित होकर 'उर्दू' हो गयी।

भारतीय वास्तु कला, संगीत, काव्य, साहित्य तथा भाषा पर भी मुसलमानों की संस्कृति का प्रभाव पड़ा, परन्तु इन क्षेत्रों में मुस्लिम संस्कृति का जो प्रभाव पड़ा वह ऐसा नहीं था कि जिससे आर्य-संस्कृति के आदर्शों पर कोई आघात पहुँचा हो।

मुस्लिम संस्कृति पर आर्य संस्कृति का प्रभाव

केवल आर्य संस्कृति पर ही मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि मुस्लिम-संस्कृति भी आर्य-संस्कृति से प्रभावित हुई। भारतीय वेदान्त और एकेश्वरवाद का अनेक मुस्लिम सन्तों तथा दार्शनिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा और इस प्रकार प्रभावित होकर उन्होंने मुसलमानों में कई ऐसे मतों की स्थापना की जो शान्ति और मानवता एवं सहिष्णुता में विश्वास करते हैं।

मुगल सम्राट अकबर के नवरत्ना में शेख अबुलफजल प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान् और इतिहासकार हुआ है। उसने एक फारसी इतिहास-ग्रन्थ 'आइने अकबरी' लिखा है। शेख अबुलफजल यद्यपि सूफ़ीमत का अनुयायी था, परन्तु उसपर वेदान्त और गीता का बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसने लिखा है—

‘मुझपर यह बात रोशन हो गयी है कि आमतौर पर लोगों का यह कहना कि हिन्दू लोग उस अद्वितीय परमेश्वर के साथ औरों को भी शरीक करते हैं, सत्य के अनुकूल नहीं। यद्यपि किसी-किसी बात की व्याख्या और उसकी युक्तियों के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है, तथापि

हिंदुओं की ईश्वरभक्ति और उनका एकेश्वरवाद दोनों मेरे हृदय में निविदा जम गये हैं। सब मेरे लिए यह आवश्यक हो गया है कि मैं उन लोगों की अध्यात्मविद्या, उनके दर्शनशास्त्र, आत्म-संयम की उत्तरोत्तर अवस्थाएँ और उनसे अनेक रस्मोरिवाज पर खूला प्रकाश डालूँ ताकि उनके विरुद्ध द्वेष के भाव कम हो और सांसारिक लोगों की तलवारें खून सहाने से रुकें, भीतरी और बाहरी झगड़े शांत हो जायें और विरोध और शत्रुता के कटकों की जगह परस्पर मित्रता का हरा भरा उद्यान दिखायी देने लगे ताकि सबसे शास्त्राय और धर्म-धर्मा के लिए जलसे हो सकें और ज्ञान विज्ञान की खोज के लिए सभाएँ की जा सकें।'

शेख अबुलफजल सन्ना अद्वैतवादी था और सर्वधर्मसमन्वय अथवा सब धर्मों की मौलिक एकरता में उसका पूर्ण विश्वास था। वह अहिंसा का उपासक था। 'आईने अकबरी में उसने लिखा है—

'तरह-तरह के भोजन मनुष्य के लिए मौजूद हैं, केवल अज्ञान और क्रूरता के कारण मनुष्य पशुओं को बघट देने पर तुल हुए हैं और उनको मारकर खा जाने से अपने हाथों को नहीं रोकते। मालूम होता है अहिंसा के सौम्य की किसी की भी आँख नहीं देख पाती। सबने अपने को पशु के लिए कबिस्तान बना रखा है।''

कहने का आशय यह है कि हिन्दू-संस्कृति का मुसलमानों के रहन सहन, विचार प्रणाली, भाषा, साहित्य, कला आदि सभी पर प्रभाव पड़ा है।

भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव

जब एक जाति दूसरी जाति को पराजित करके उसकी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का अपहरण करती है तो वह अपनी विजय को दृढ़ और स्थायी बनाने के लिए पराजित जाति की संस्कृति, धर्म, साहित्य,

भाषा और मनोवृत्ति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा करती है। नैतिक विजय के अभाव में राष्ट्रीय विजय का स्थायी होना असम्भव है। विदेशी शासन से बढ़कर जातीय चरित्र को भ्रष्ट करनेवाली और कोई भी वस्तु ससार में नहीं है। गुलामी जातीय चरित्र के पतन का कार्य और कारण दोनों ही हैं। नैतिक पतन के कारण जानियाँ गुलाम बनती हैं और गुलामी के कारण उनका नैतिक पतन होता है।

अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कंपनी ने जब भारतवर्ष की स्वतन्त्रता छीनी तो उसे भी अपनी राष्ट्रीय विजय को स्थायी बनाने के लिए भारतवर्ष पर नैतिक विजय प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अंग्रेजों को यह अनुभव हुआ कि जबतक हम भारत के सामाजिक जीवन का सर्वनाश न कर देंगे तबतक भारत सदैव के लिए हमारी गुलामी में न जा सकेगा। इसलिए भारत की नैतिक विजय प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी शासकों ने भारतीय सामाजिक जीवन और नैतिक जीवन पर अपना नियंत्रण रखना शुरू किया।

कम्पनी ने भारतीय बच्चों की शिक्षा के लिए कई स्कूल और कालेज खोले जिनमें भारतीय भाषा और साहित्य के साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा दी जाने लगी। इन नवीन शिक्षा-संस्थाओं में ब्राह्मण 'आचार्य' का स्थान अंग्रेज 'प्रिंसिपल' ने लिया। भारत की प्राचीन वैदिक शिक्षा-मर्यादा का उच्छेद किया गया और उससे म्यान में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य भारतीयों में ऐसी मनोवृत्ति पैदा करना था जिससे वे अपने को अंग्रेजों से धर्म, इतिहास, दर्शन, ज्ञान-विज्ञान, सम्यक्ता तथा सृष्टि में होने समझते रहें और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा न हो सके। कंपनी के शासकों को ऐसे छोटे धर्मचारियों की भी आवश्यकता थी जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते हों। इन का उद्देश्यो से भारत में अंग्रेजी साहित्य, भाषा और विचारधारा का प्रचार किया गया।

इससे अनिश्चित जब भारत में 'ईस्ट इण्डिया कंपनी' का शासन प्रवर्धित था, उसे भारत में अंग्रेजी राज्य को स्थायी बनाने तथा शासन-

प्रबन्ध की सुविधा के लिए ऐसे भारतीया की आवश्यकता पड़ी जो छोटी-छोटी सरकारी नौकरियों पर नियुक्त किये जा सकें। यह युक्ति सोची गयी कि कम वेतन पर भारतीया को छोटी-छोटी नौकरियाँ दी जायें। इससे उनमें रिसवतखोरी बढेगी तथा उनका चरित्रिक पतन भी होगा। वे इसके लिए अपने देशवासिया को ही दोष देंगे।^१

जो अग्रज भारतवासियों को नौकरियाँ देने का समर्थन करते थे उनके दो पक्ष थे। एक पक्ष था कहना था कि भारतवासिया को केवल प्राचीन भारतीय साहित्य, भारतीय विज्ञान और सस्कृत, फारसी अरबी तथा देशी भाषाएँ पढ़ानी चाहिए, उन्हें पश्चिमी विचारों की हवा भी न लगने देनी चाहिए, क्योंकि भारतवासियों को जब यूरोप के इतिहास का ज्ञान होता है और वे पश्चिम के राष्ट्रीय विचारों के सम्पर्क में आते हैं, तो मुट्ठीभर विदेशियों के द्वारा उन्हें अपने देश का शासित होना भूलने लगता है और वे स्वभावतः अपनी मातृभूमि के भस्तक से गुलामी के कलक को मिटा देने की बात सोचने लगते हैं।

दूसरे पक्ष का यह विचार था कि भारतवासिया के चरित्र को जब तक यूरोपियन साधे में न ढाला जायेगा, तबतक हमारे चरित्र के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं उत्पन्न हो सकता, जो हमारे शासन के स्थायित्व के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अन्यथा वे हमको काफिर, म्लेच्छ और विदेशी समझते रहेंगे, और जब अवसर पायेंगे तब हमें अपने देश से बाहर भगाने की चेष्टा करेंगे। इसके विपरीत यदि उन्हें अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी विज्ञान और अंग्रेजी सभ्यता

१ "If we are to have corruption, it is better that it should be among the natives than among ourselves, because the natives will throw the blame of the evil upon their countrymen they will still retain high opinion of our superior integrity and our character which is one of the strongest supports of our power will be maintained
—Sir Thomas Munro Governor of Madras

की शिक्षा दी जाये, तो वे बड़ी प्रसन्नतापूर्वक हमारे पूर्वजों के गुणों का अध्ययन करेंगे, उनके चरित्र से शिक्षा ग्रहण करेंगे और उनके अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करेंगे। ऐसी अवस्था में वे अपना विरोध करने के बदले, हमारी आज्ञा का पालन करने में अपना गौरव समझेंगे तथा हमारी सस्कृति का अनुकरण करके हमारे राज की अपना बहो-भाग्य मानेंगे। इस नीति का स्पष्टीकरण लॉर्ड मैकाले के सन् १८३५ के मिनिट से हो जाता है जिसमें लिखा है—

“हमें भारत में ऐसे मनुष्यों की एक श्रेणी पैदा कर देने का शक्ति-भर प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों भारतवासियों के बीच, जिनपर हम शासन करते हैं, बुझापिये का काम करें। इन लोगों को ऐसा होना चाहिए कि वे केवल रण और रक्त की दृष्टि से भारतीय हों, किन्तु रुचि, विचार, भाषा और बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज।”

इससे सिद्ध होता है कि भारत पर पाश्चात्य सस्कृति, भाषा, साहित्य, सभ्यता, रीति-रिवाज, रहन-सहन की प्रणाली आदि लादने के लिए किस प्रकार सगठित रूप से भयंकर आयोजन किया गया। और हम देख रहे हैं कि हिन्दुस्तानियों में आज हाथ मिलाना, विदेशी भाषा में ही बोलने की गौरव की बात समझना, टी-वार्टी, एट-होम, डिनर, डान्स आदि आमोद-प्रमोद मनाना, डबलरोटी, बिस्कुट चाय, केक, विदेशी शराब आदि पीना, स्त्री-पुरुषों की वेशभूषा में अंग्रेज जाति का अनुकरण करना, सिविल मैरिज और डाइवोर्स (तलाक) का आश्रय लेना आदि अच्छी-बुरी प्रथाएँ आ गयी हैं और भारतीय सस्कृति को मिटाती जा रही है।

इस प्रकार भारत की सस्कृति, सभ्यता, भाषा, साहित्य, विचारधारा, आदर्शों पर ही यूरोपीय सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ा प्रत्युत यहाँ के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक आदर्शों पर भी इंग्लैण्ड की सभ्यता ने अपनी छाप डाली है

आर्थिक जीवन

आर्थिक स्थिति

भारत आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा देश है। यद्यपि भारत के सम्यग्र में यह कहा जाता है कि वह सबसे धनी देश है, तथापि यहाँ की जनता इतनी गरीब है कि करोड़ों की भरपट अन्न तक नहीं मिलता। सन् १९३१ में भारत की कुल जनसंख्या ३५ करोड़ थी। सन् १९२१ से ३१ तक जासख्या में १०% की वृद्धि होकर १९४१ में जनसंख्या लगभग ३९ करोड़ हो गयी है। भारतवासियों की जनसंख्या का ९०% भाग ग्रामों में है और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा कृषि से जुड़े हुए उद्योग हैं। भारत में इस अनेक धन कृषि की दशा भी अच्छी नहीं है। किसानों को उससे कोई लाभ होना तो दूर, भरपेट खाने तक को नहीं मिलता और सर एम विन्नेस्वरेया के अनुसार औसत भारतवासी की मासिक आमदनी ६ रुपये है। निधन वगैरे आय तो और भी कम है। सन् १९२९ के व्यापारिक संकट के कारण कृषि से आय और भी कम हो गयी है।

भारत में जीवन का मान-दण्ड इतना अधिक गिरा हुआ है कि उसकी किसी भी देश से तुलना नहीं की जा सकती। एक अंग्रेज लेखक के अनुसार इंग्लैंड में स्वास्थ्य विभाग के भर्ती न अंग्रेज बेकारों के भोजन की तालिका बनायी है जो भारत की जनता के लिए कौतुक मानी जायेगी। ग्रामों में प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी दो-तीन रुपये मासिक है। उनपर ऋण का भार इतना अधिक है कि प्रति कुटुम्ब पर २५० रुपये पड़ता है। ग्रामों की सबसे बड़ी समस्या बच्चे घास फूस के शोषण में रहती है, जो न बीत से उनकी रक्षा कर सकते हैं और न गर्मी से। न वे हवादार हैं और न उनमें प्रकाश का ही प्रवेश हो सकता है। निवास के लिए वे सर्वथा अस्वास्थ्यप्रद हैं। रात दिन खेतों पर मेहनत

करने पर भी वे सदैव अन्न के लिए चिंतित रहते हैं। उनके शरीर पर मोटे कपड़े तक नहीं होते।

फिर, इस भयंकर गरीबी में अज्ञान का अखण्ड राज है। ९०% जनता निरक्षर है, ९४% मनुष्यों को अक्षर ज्ञानमात्र है और शेष व्यक्ति शिक्षित हैं।

भारत का क्षेत्रफल १८ करोड़ वर्गमील है। इसमें ४० करोड़ व्यक्ति रहते हैं जो समस्त ससार की जनसंख्या का $\frac{1}{4}$ भाग है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में एक वर्गमील में औसतन १९५ व्यक्ति रहते हैं। परन्तु कितने ही प्रान्ता में ऐसे स्थान भी हैं जहाँ इससे चार या पाँच गुनी अधिक आबादी एक वर्गमील में रहती है। यूरोप में एक वर्गमील में १२७ व्यक्ति और अमरीका में एक वर्गमील में ४१ व्यक्ति रहते हैं। इस दृष्टि से भारत में बड़ी घनी आबादी है। किन्तु जन्म-मृत्यु की दृष्टि से हमारा देश ससार के दूसरे देशों से हीन है। सन् १९३१ में भारत में मृत्यु-संख्या का औसत १००० में २४५ था और जन्म-संख्या का ३३। उस समय ब्रिटेन की मृत्यु संख्या १२५, जर्मनी की ११ और अमरीका की ११३ थी। भारतीय जीवन का औसत मान भी बहुत ही कम है। सन् १९३१ की मनुष्य-गणना के अनुसार भारतीय की औसत आयु २६७ वर्ष है, जबकि इंग्लैंडवासी की ५७६, अमरीकावासी की ५६४, जर्मन की ५९०४, फ्रांसीसी की ५० और जापानी की ४४५ वर्ष है।

औद्योगिक स्थिति

भारत की कुल ३५ करोड़ की जन-संख्या में १५ करोड़ ३९ लाख अर्थात् $\frac{2}{3}$ व्यक्ति कार्य करने और जीविका कमाते लायक थे। इनमें से १५ करोड़ २० लाख उपयोगी उद्योग धन्धों व व्यवसायों में लगे हुए थे शेष १८ लाख ४४ हजार अनुपयोगी धन्धों में। यह नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जायेगा।

व्यवसाय

कार्य करने योग्य व्यक्तियों की संख्या

कृषि, मछली पकड़ना व शिकार—१० करोड़, ३२ लाख, ९४ हजार ४३९

उद्योग-धन्यो और खानों में काम—	१ करोड़, ५६ लाख, ९७ हजार, ९५३
व्यापार और यातायात—	१ करोड़, २ लाख, ५५ हजार, ३
सरकारी नौकरियाँ और सेना—	१८ लाख, ३६ हजार, ७५८
वकील, डाक्टर और कलाकार—	२३ लाख, १० हजार, १४१
घरेलू नौकर	— १ करोड़, ८ लाख, ९८ हजार, २७७
अन्य विविध पेशे	— ७७ लाख, ७८ हजार, ६४२
अनुपयोगी धन्ये	— १८ लाख, ४४ हजार, ६४२

ब्रिटिश भारत में लगभग २८ करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती है। प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में १०२ एकड़ भूमि आती है। इस भूमि पर हर वर्ष कृषि द्वारा २० अरब, ३२ करोड़ रुपये की पैदावार होती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में ६४ रुपये की सामग्री आती है। यही सख्या अमरीका में १७५, कनाडा में २१३, जापान में ५७ और इंग्लैंड में ६२ रुपये है। कृषि की आमदनी की दृष्टि से भारत इंग्लैंड और जापान से कुछ अच्छा है, परन्तु उद्योगों में वह बहुत पिछड़ा हुआ है। अन्य औद्योगिक देशों में जनसख्या का अधिक भाग उद्योग-धन्यो में लगा हुआ है और बहुत ही कम भाग खेती पर निर्भर है, परन्तु दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश में उद्योग धन्यो में बहुत कम लोग लगे हुए हैं। औद्योगिक पैदावार का औसत प्रति व्यक्ति अमरीका में ७२१, ब्रिटेन में ४१२, कनाडा में ४७० और जापान में १५८ रुपये है। भारत में यह औसत केवल १५ से २० रुपये है।

व्यापारिक स्थिति

भारत की व्यापारिक स्थिति भी अत्यन्त शोचनीय है। आर्थिक सकट के पूर्व, सन् १९३३ करोड़ रुपये। इस प्रकार प्रति व्यक्ति है। अन्य देशों में प्रति व्यक्ति है। भारत में ५९७, भारत का आयात-व्यापार करोड़ रुपये का था। वा व्यापार होता है। प्रकार

में ९० रुपये। यह दशा तो आज से ११ वर्ष पहले की है। तबसे अब तो व्यापार और भी कम हो गया है। इस समय भारतीय व्यापार का औसत प्रति व्यक्ति ७.६ रुपये है।

राष्ट्रीय आय की दृष्टि से भी भारत दूसरे देशों में बहुत पिछड़ा हुआ है। भारत की प्रति वर्ष की औसत आय बतलाना बड़ा कठिन है; क्योंकि इसके हिसाब में कौन-कौन से विषय लेने चाहिएँ, इस सबब में विद्वानों में मतभेद रहा है। अलग-अलग वर्षों में उन्होंने जो अनुमान निकाले हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करते समय उन वर्षों में वस्तुओं के भावों की ध्यान में रखा गया होगा। इस सबब में अभी तक जो-जो अनुमान किये गये, वे क्रमशः नीचे दिये जाते हैं :

वर्षाशास्त्री	वर्ष	प्रति-व्यक्ति वार्थिक आय	रुपये	आना	पाई
दादाभाई नीरोजी	१८७०	२०	०	■	
वैमरिंग ब्राबूर	१८८२	२७	०	०	
विलियम डिग्बी	१८९८	१८	९	०	
विलियम डिग्बी	१९००	१७	४	०	
लाहं वर्जन	१९००	३०	४	०	
अटिक्सन	{ १८७५,	२५	०	०	
	{ १८९५	३४	०	■	
	१९११	{ ५०	०	०	
		{ ८०	०	०	
प्रो. वाडिया और श्रीजीसी	१९१०-१४	४४	५	६	
श्री विश्वेश्वरया	१९१९	४५	०	०	
प्रो० शाह और श्रीसम्बाता	१९२१-२२	६७	०	०	
प्रो० बी जे. काळे	१९२१	४०	०	०	
श्री प्रफुल्लचन्द्र घोष	१९२५	४६	०	०	
विन्डले शिरास	{ १९२१	१०७	०	०	
	{ १९२२	११६	०	०	

फिन्डले शिरास	१९२६	१०८	०	०
"	१९२९	१०९	०	०
"	१९३०	८४	०	०
"	१९३१	६३	०	०
"	१९३२	५८	०	०

सर विश्वेश्वरैया का मत है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति की औसत वार्षिक आय ८२ रुपये माननी चाहिए ।^१ अवश्य ही ये अंक जिस वर्ष फसल अच्छी हुई होगी उस वर्ष के हैं । वर्तमान मन्दी के युग में उसका $\frac{1}{4}$ अर्थात् करीब ५५ रुपये औसत मानना चाहिए ।^२

इस आय की तुलना यदि दूसरे देशों के औसत व्यक्ति की आय से की जाये तो भारत की दरिद्रता का अनुमान सहज ही हो जायेगा ।

देश	सन	प्रति व्यक्ति वार्षिक आय रुपये आना पाई
ब्रिटिश भारत	१९३७	५५ ० ०
इंग्लैंड	१९३१	१०२६ ० ०
ऑस्ट्रेलिया	१९२४	१३२३ ० ■
संयुक्तराज्य अमेरिका	१९३२	१२०१ ८ ■
फ्रान्स	१९२८	५५३ ८ ०
चेकोस्लोवाकिया	१९२५	४७२ ८ ■
डेनमार्क	१९२७	७४२ ८ ०

भारतवर्ष में सबसे विशाल समस्या गरीब जनता की है । धनी और लक्ष्मण तो बहुत ही थोड़े हैं । कृषि का सबसे अधिक बोझ गरीब जनता पर ही पड़ता है ।

१ श्री विश्वेश्वरैया 'प्लेण्ड इकॉनॉमी फॉर इण्डिया'

२ श्री प्रो जठर और बेरी 'इण्डियन इकॉनॉमिक्स (२), (१९३७)'

भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति पर औसत कर इस प्रकार है—

वर्ष	रुपये आना पाई	वर्ष	रुपये आना पाई
१९२२-२३	५ ४ ५	१९२७-२८	५ ५ ०
१९२५-२६	५ ६ ७	१९३२-३३	५ ० ६

इस प्रकार ५५ रुपये वार्षिक औसत आय में से ५ रुपये व्ययित् आय का ११ भाग वरों में दे देना पड़ता है ।

भारत की भयंकर गरीबी और दरिद्रता के सबध में भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री रेमजे मैकडानल्ड ने लिखा है—

“ .. ५ करोड़ तक कुटुम्ब (जिसका मतलब हुआ १५ से लेकर २५ करोड़ तक मनुष्य) साढ़े तीन आने की माय पर अपना गुजारा करते हैं । 'हिन्दुस्तान की दरिद्रता केवल कल्पना नहीं बल्कि वस्तु-स्थिति है । सर्वथा सम्पन्न-काल तक में कर्जस्थी शक्की का मोटा पाठ किसान के गले में लटका रहता है । ग्रामों में घूमने पर ऐसे ककाल दिखायी पड़ते हैं जो दिन-रात के परिश्रम से चकनाचूर हो गये हैं और जो भूखे पेट मन्बिर में जाकर खिन्नबदन होकर परमेश्वर की उपासना करते हैं । ”

श्री आर्याविन ने अपनी पुस्तक 'भारत का बाग' (Garden of India) में भारत के मजदूरों की स्थिति के बारे में लिखा है—

“अनाज में से ककर की तरह निकाले हुए अधनगे-भूखे लोग गाँव गाँव में सर्वत्र दिखायी पड़ते हैं । उनके पास मवेशी न होने के कारण जीविका का कोई साधन नहीं है । कुदाली से खोदी हुई जमीन के सिवा उनकी जीविका की और कोई वस्तु नहीं है । उन्हें दो सेर के भाव का बिल्कुल हलका अनाज अथवा डेढ़ या दो आने रोज की मजदूरी मिलती है और यह नगण्य मजदूरी भी पूरे वर्ष भर नहीं मिलती । क्षुधा पीड़ित और बहुधा वस्त्र-हीन स्थिति में ये लोग सर्दियों के दिनों में चौरों और पशुओं में अपनी रक्षा करके किस तरह जी सकते हैं, यह एक आश्चर्य ही है । ”

भारत के आर्थिक साधन

भारत में आर्थिक साधन इतने विपुल हैं कि यदि उनका राष्ट्रीय हित के लिए ठीक अच्छी तरह उपयोग किया जाये तो वह बहुत ही थोड़े समय में पाश्चात्य देशों के बराबर समृद्ध देश बन सकता है। आश्चर्य है कि जिस भारतभूमि में जनता को सुखी और ऐश्वर्यशाली बनाने की पूरी क्षमता है, उसकी गोद में आज ४० करोड़ नर-नारी महादरिद्रता और बेकारी में अपना जीवन बिता रहे हैं।

संसार में जितना जूट पैदा होता है उसका उत्पादक भारत ही है। संसार में सबसे अधिक चावल चाय और शक्कर भारत में पैदा होती हैं। तम्बाकू मगनीज और कई पैदा करने में संसार में भारत का स्थान दूसरा है। तेल निकालनेवाली चीजें पैदा करनेवालों में भारत का स्थान तीसरा है। पेट्रोल पैदा करनेवाले देशों में १३ वाँ, लकड़ी पैदा करनेवाले देशों में १५ वाँ, कोयला पैदा करनेवाले देशों में ११ वाँ, फौलाद पैदा करनेवाले देशों में ११ वाँ रबर पैदा करनेवाले देशों में ७ वाँ, सोना पैदा करनेवाले देशों में ११ वाँ और चाँदी पैदा करनेवाले देशों में उसका ९ वाँ स्थान है।

भारत में पोर्टलैंड सीमेंट बड़े ऊँचे दर्जों का बनता है, जिसकी बराबरी अंग्रेजी स्टैंडर्ड भी नहीं कर सकता। रसायनों में क्लोरिन, फास्टिक सोडा ऐश बनाने के लिए भी बड़े-बड़े कारखाने खुले हुए हैं। भारत में ताँबा भी खानें हैं जिनमें से घरेलू बतन बनाने के लिए ताँबा निकलता है। बिजली के बल बनाने के लिए भारत में पर्याप्त साधन हैं। बिजली के तार भी भारत में बनाये जाते हैं। लाख भारत में बहुत पैदा होती है। नल तथा टर्बुविम बनाने के लिए भी पर्याप्त साधन हैं। हाँ, शीशा भारत में पैदा नहीं होता। वह उस ब्रह्मा से मँगाना पड़ता है। रंगों के बनाने के लिए उसे विदेशों से चीजें मँगानी पड़ती हैं।

यहाँ हम भारत की पैदावारों का संसार की पैदावारों से अनुपात दिखलाने का प्रयत्न करेंगे।

धातु या पंदावार ससार का प्रतिशत धातु या पंदावार ससार का प्रतिशत

बोक्साइट	०.४	जूट	९८.७
कच्चा क्रोम	५.३	गेहूँ	६.६
कच्चा ताँबा	०.५	चावल	४३.५
कच्चा लोहा	१.९	भक्का	१.६
कच्चा मैंगनीज	१७.९	जौ	५.४
मौयला	१.९	कॉफी (कहवा)	१.७
पेट्रोल	०.१	चाय	४२.०
मैंगनीसाइट	०.९	शक्कर	१८.७
पोटाश	०.१	तम्बाकू	१९.६
सोना	१.०	रेप-बीज	७३.६
रबड़	१.०	बिनीला	१४.२
रई	१२.३	मूँगफली	५०.९
ऊन	२.५	बलसी	१३.०
रेसम	०.१	सीसामम	५९.८

आर्थिक साधनों में भारत में श्रम-शक्ति भी महत्वपूर्ण है। अभी-तक भारत की मानव-शक्ति का भी इस दिशा में अच्छी तरह उपयोग नहीं हो सका।

भारत का आर्थिक संगठन

हमारे देश का आर्थिक संगठन अत्यन्त विषम है, वह आर्थिक समता या आर्थिक न्याय पर आधारित नहीं है। ग्रामों में समस्त भूमि के स्वामी जमींदार और किसान हैं जो किसानों से बड़ी-बड़ी रकमें लगान के रूप में वसूल करते हैं और उसका एक अंश सरकारी कोष में मालगुजारी के रूप में अदा करते हैं। ग्रामों में जमींदारों और ताल्लुकेदारों का किसानों के न केवल आर्थिक जीवन पर ही बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर भी पूरा नियन्त्रण है। किसानों को जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों की दया-दृष्टि के भरोसे रहना पड़ता है। जमींदार किसानों को

खेती के लिए भूमि देते हैं, साहूकार खेती के लिए कर्ज देते हैं और व्यापारी उनकी पैदावार को खरीदते हैं। प्रायः इन तीनों का गुट्ट सा रहता है।

नगरों में बड़े-बड़े कारखाने हैं जिनके स्वामी बड़े बड़े सेठ पूँजीपति महाजन और बैंकर हैं। ये कारखाने कपड़ों के रूप में हैं। इनमें ग्रामी से दारो में आये हुए बंकर मजदूर काम करते हैं। उह पूरी और पर्याप्त मजदूरी तक नही मिलती। काम भी अधिक लिया जाता है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल का कोई प्रबंध नहीं होता। रहन सहन भी बड़ी अस्वास्थ्यप्रद होती है। पूँजीपति इनके परिश्रम से मात्रामाल होते हैं परन्तु इनका उचित भाग तक इन्हें नहीं दिया जाता। फलतः औद्योगिक मजदूरों में भीषण अशान्ति और असन्तोष रहता है। जगह-जगह मजदूरों के सगठन भी बन गये हैं जो अपने सुधार के लिए काम करते रहते हैं। समाजवादी और साम्यवादी नेता इनमें प्रचार तथा सगठन का कार्य करते रहते हैं।

आज कल देश में आर्थिक समस्या के संबंध में दो प्रकार के विचार प्रचलित हैं। एक वर्ग का विचार है कि आर्थिक प्रणाली को स्वावलम्बी बनाया जाना चाहिए। देश में तैयार हो जानेवाली चीज़ों के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। वे ग्रामों में उद्योग धंधों तथा घरेलू व्यवसाय की उत्थिति पर अधिक जोर देते हैं। उनका कहना है कि खादी का प्रचार बढ़ाया जाये और सब लोग हाथ का कता-बुना कपड़ा ही पहनें। जमींदारी ज्वा की त्याग्यम रहे और वे अपने को किसानों का ट्रस्टी मानें। इस विचारधारा के प्रवक्ता तथा प्रमुख समर्थक महात्मा गांधी तथा दूसरे गांधीवादी नेता हैं।

दूसरे वर्ग के लोग वे हैं जो देश के आर्थिक जीवन का निर्माण औद्योगीकरण और बड़े-बड़े उद्योग धंधों के सगठन से करना चाहते हैं। वे जमींदारी प्रथा और पूँजीवाद को आज के युग में अनावश्यक समझते हैं। पं० जवाहरलाल नेहरू, श्री सुभाषचंद्र बोस, श्री मानवेन्द्रनाथ राय, आचार्य नरेन्द्रदेव आदि नेता देश में पाश्चात्य देशों जैसा औद्योगीकरण चाहते हैं। वे ग्रह उद्योग, खादी या ग्रामोद्योग को देश के लिए आर्थिक जीवन का स्थायी अंग ही मानते हैं।

में ये ग्रामोद्योग केवल सक्रमण-काल के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं ।^१

भारत की गरीबी के मूल कारण

भारत की भयंकर गरीबी के मूल कारणों में सबसे प्रधान राजनीतिक पराधीनता और उसके फलस्वरूप आर्थिक पराधीनता है । भारतीय जनता की आर्थिक नीति का पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथ में है । भारतीय जनता को उसमें हस्तक्षेप करने का कुछ भी अधिकार नहीं है । व्यापारिक संपन्न व्यापारिक नीति, सटकर सरलण, व्यापारिक कर्पनिया पर नियंत्रण, विनिमय की दर आदि सभी पर ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण है ।

दूसरा प्रमुख कारण है भारत में निरक्षरता और शिक्षा का अभाव । जनता के अशिक्षित होने के कारण उनमें ज्ञान विज्ञान से लाभ उठाने की प्रवृत्ति का अभाव रहता है । फलतः वह उद्योग-व्यवसायों का वैज्ञानिक ढंग से उनत बनाने में विफल रहते हैं ।

तीसरा प्रमुख कारण है भारत में कृषि की प्रधानता । कृषि प्रधान होने से भारत बच्चा माल तैयार करने पर तो साख ध्यान देता है, परन्तु वह इस कारण, औद्योगिक प्रगति में पिछड़ा हुआ है ।

भारत के सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सर एम विश्वेश्वरैया का कथन है कि भारतवासियों को अपना जयघोष यह बनाना चाहिए—‘उद्योगवादी बनो’ । उन्होंने काशी विश्वविद्यालय के दीक्षान्त-समारोह भाषण (१९३७) में कहा था—

“पिछली शताब्दी से कनाडा में अन्न पैदा करनेवाले मजदूरी की सख्या बराबर घटती आ रही है और यह सख्या ७५% से घटकर आज १७% हो गयी है । स्वीडन में भी खेती का काम करनेवालों की सख्या में भारी कमी हो गयी है । वहाँकी एक बहुत बड़ी सख्या उद्योग, व्यवसाय, शिल्प और व्यापार में लग गयी है । पचास वर्षों से हर देश में यही प्रवृत्ति देखने

में आरही है, जैसा कि रूस, जर्मनी और जापान में प्रत्यक्ष है। भारत के अक्सर कृषि-प्रधान देश कहा जाता है, परन्तु जनता को यह साफ-सा नहीं बतलाया जाता कि उसकी सुरक्षा कृषि की अपेक्षा उद्योग और नौकर पर निर्भर है। उद्योगों को प्रोत्साहन देना प्रगतिशील देशों में नीति नीति स्वीकार की गयी है। परन्तु यहाँ उसकी अपेक्षा की जाती है।”

गरीबी का चौथा कारण यह है कि भारत में उत्पादन और उसके वितरण न्यायोचित ढंग से नहीं किया जाता। खेती की पैदावार की बिक्री की भी कोई अच्छी पद्धति नहीं है। इस कारण किसानों को कम मूल्य पर सस्ते दामों में अपना माल बेचना पड़ता है। भारत में कृषि की पद्धति भी जनता की गरीबी का एक प्रधानकारण है। भूमि का वितरण भी सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर नहीं है।

जबतक भारत पूर्णतः उद्योगवादी राष्ट्र नहीं बन जाता तबतक भारतीय व्यापार के संरक्षण की अत्यन्त आवश्यकता है और जबतक सरकार भारत के उद्योग धर्मों का संरक्षण नहीं करेगी, तबतक औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति होना संभव नहीं।

श्री देवीप्रसाद खेतान का मत है कि भारत सरकार द्वारा शक्कर व्यवसाय को १५ वर्ष के लिए संरक्षण मिलने का असर यह हुआ है कि पाँच वर्ष में ही भारत शक्कर के व्यवसाय में स्वावलम्बी हो गया है। शक्कर-व्यवसाय की उन्नति से १५ करोड़ रुपये विदेशों में जाने से बच गये। इनमें से ८ करोड़ रुपये तो किसानों को मिल जाते हैं।^१ विलगत १० वर्षों में भारत में सूती वस्त्र-व्यवसाय, शक्कर, दिमासलाई, कागज, अण्डे, गुड़ आदि व्यवसायों ने आश्चर्यजनक उन्नति की है, जो नीचे दी हुई तालिका से प्रकट होती है—

१ कानपुर के इन्स्टीट्यूट ऑफ़ शूगर टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सन् १९३९-४० में १२, ४१, ७०० टन शक्कर बनायी गयी। इससे पहले साल में ६, ५०, ८०० टन शक्कर बनायी गयी। भारत में इस समय १४५ शक्कर मिल काम कर रहे हैं।

इन वर्षों में भारत की प्रायः १०० करोड़ की आय हुई है।

व्यवसाय	सन् १९२५-२६	सन् १९२५-२६
दियारालाई	१२ करोड ६० लाख दर्जन	२९ करोड ४० लाख दर्जन
कागज	२८ हजार टन	४८ हजार टन
सूती कपड़ा	१९५ करोड़ ४० लाख गज	३५७ करोड़ १० लाख गज
हाथयूना कपड़ा	११६ करोड गज	१६६ करोड गज
शक्कर	३ लाख २१ हजार टन	११ लाख ६६ हजार टन
गुड़	१५ लाख टन	६७ लाख ५० हजार टन
लौहा	३ लाख २० हजार टन	अप्राप्त

भारत की जनता की गरीबी के कारण आर्थिक के अतिरिक्त सामाजिक भी है। भारत में ऐसी सामाजिक कुप्रथाएँ प्रचलित हैं जिनके कारण भी जनता को अपने धन का बहुत बड़ा भाग व्यर्थ खर्च करना पड़ता है। इन सामाजिक प्रथाओं में सबसे हानिप्रद प्रथाएँ हैं—बाल-विवाह, विवाहों में धन का अपव्यय, मृत-भोज, श्राद्ध तथा तीर्थ-यात्रा में महन्ती, साधुजी और पुजारियों को दान-दक्षिणा, शराबखोरी, जुआ, बेध्यागमन इत्यादि।

ये सामाजिक बुराईयाँ न केवल आर्थिक दृष्टि से ही हानिप्रद हैं, बल्कि नैतिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी घातक हैं। इनका कुप्रभाव केवल फिजूलखर्ची करनेवाले तक ही सीमित नहीं रहता सारे कुटुम्ब, ग्राम और समाज पर भी पड़ता है।

कृषि

भूमि-प्रणालियाँ

भारत में दो प्रकार की भूमि-प्रणालियाँ (Systems of Land Tenures) प्रचलित हैं। एक जमींदारी और दूसरी रयतवारी। जमींदारी प्रणाली विशेषतः बंगाल, बिहार, संयुक्त-प्रान्त और उत्तरी मद्रास में प्रचलित है। इसके अनुसार जमींदार भूमि के स्वामी होते हैं और वे उसकी मालगुजारी सरकार को देने के लिए बाध्य हैं। जमींदार

अपनी भूमि किसानों को जोतने-चोने के लिए दे देते हैं और उसके एवज में उनसे लगान वसूल करते हैं। इस लगान का एक नियत भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में दे दिया जाता है और शेष उनके हिस्से में आता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार का जमींदार ही से सीधा सम्बन्ध होता है। किसानों से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इसलिए जमींदार के किसानों पर होनेवाले अत्याचार में वह हस्तक्षेप नहीं करती।

रयतदारी भूमि-प्रणाली भारत के शेष भाग पंजाब, बम्बई, सिन्ध, मध्यप्रान्त, सीमाप्रान्त, दक्षिण-मद्रास आदि में प्रचलित है। इस प्रथा के अनुसार भूमि के स्वामी किसान ही होते हैं। प्रत्येक किसान को सीधे सरकार को मालगुजारी देनी पड़ती है। उनके और सरकार के मध्य में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता जो भूमि का स्वामी कहलाये।

बन्दोबस्त

किसान अपनी जोत का जो लगान जमींदार या सरकार को देता है, उसपर समय-समय पर पुन विचार किया जाता है। इसके लिए जो जायंदाही की जाती है उसे बन्दोबस्त कहते हैं। भारत में दो तरह के बन्दोबस्त हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी बन्दोबस्त में लगान हमेशा के लिए स्थिर कर दिया जाता है, जो किसान से नहीं बल्कि जमींदार से वसूल किया जाता है। सन् १७९५ में अवध और मद्रास में स्थायी लगान निश्चित कर दिया गया था। शेष सारे देश में अस्थायी बन्दोबस्त की प्रथा जारी है। सरकार के सर्वे-विभाग द्वारा की गयी सर्वे के आधार पर तीस तीस वर्ष में प्रत्येक जिले की जमीन की पूरी जाँच होती है। प्रत्येक गाँव की पैमायश होती है, नकसे बनते हैं, हर एक किसान के खेत को उसमें पृथक् पृथक् बताया जाता है। उनके अधिकार का एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें जमीनों का लेन-देन आदि लिखा जाता है। इस रजिस्टर को 'वाजिबुल अर्ज' (Record of Rights) भी कहते हैं। यह सब जाँच करके उसके अनुसार लगान कायम करने का काम भारत सरकार की सिविल सर्विस के विशेष अफसरों

द्वारा होना है जिन्हें 'सेटिलमेण्ट ऑफसर' कहा जाता है।

लगान की दर

भारत में जमीन पर जो लगान लिया जाता है, उसकी एक निश्चित दर नहीं है। यह स्थायी बन्दोबस्तवाले प्रान्तों में एक प्रकार की है और अस्थायी बन्दोबस्तवाले सूबों में दूसरे प्रकार की। फिर जमींदार तथा रयतद्वारी प्रान्तों में भी लगान की दरें भिन्न-भिन्न हैं। वे जमीन की किस्म और उसके अधिकार आदि के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। बंगाल में १६ करोड़ रुपये जमींदार लगान में किसानों से वसूल करते हैं, परन्तु चूंकि वहाँ स्थायी बन्दोबस्त प्रचलित है, इसलिए सरकार उसमें से केवल ४ करोड़ रुपये मालगुजारी के रूप में ले लेती है। अस्थायी बन्दोबस्तवाले प्रदेशों में जमींदारों से अधिक-से-अधिक लगान का ५० फी सदी सरकार वसूल करती है। किसी-किसी प्रान्त में वह इससे भी कम वसूल करती है।

जमींदारी प्रथा की उत्पत्ति और विकास

वेद-काल में भारत में जमींदारी-प्रथा नहीं थी। राजा और प्रजा का सीधा सम्बन्ध था। प्रजा राजा को लगान देती थी। उस सत्तपुग में समस्त भूमि चार प्रकार की थी—(१) वास्तु भूमि, (२) कृषि भूमि, (३) गोचर भूमि, (४) वन्य भूमि। वास्तु-भूमि का स्वामी विज्ञान होता था।

रामायण-काल में भी हमें जमींदारी प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता। स्मृति-काल तथा महाभारत-युग में भी जमींदारी प्रथा नहीं थी। बौद्ध-काल में भी जमींदारी प्रथा नहीं मिलती। सब कृषक जमीन के मालिक थे।^१ मौर्य-काल में ग्रामों में स्थानीय स्वशासन था। सब

१. प्रो० सन्तोषकुमार दास : 'प्राचीन भारत का साम्प्रतिक इतिहास'

२. रामदास गोड : 'हमारे गाँवों की कहानी'

ग्राम स्वतंत्र थे। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम-पंचायत होती थी इस पंचायत का जो मुखिया होता उसे ग्रामपति कहते थे। परन्तु वह आज कल के जमींदार का पूज्य नहीं है। जमींदारी का कोई रिवाज नहीं था। सब किसान अपने खेतों के मालिक थे।^१ पठान और मुगल काल में भी जमींदारी प्रथा नहीं थी।

मुगल-काल में भी सद्धान्तिक रूप से राज्य ही समस्त भूमि का स्वामी था, परन्तु भूमि की पैदावार किसान और सरकार के बीच में बांटने की व्यवस्था थी। लगान वसूल करनेवाले लोग किसानों से लगान वसूल करके सरकारी कोष में जमा कर देते थे। इस प्रकार लगान वसूल करने वाले व्यक्तियों का एक वर्ग बन गया जो सरकार की आर से नियुक्त किये जाते थे और उन्हें सरकार से वेतन मिलता था। ये लगान वसूल करनेवाले सरकारी कर्मचारी होते थे। जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा और शासन-व्यवस्था अस्तव्यस्त होने लगी तो ये लगान वसूल करनेवाले स्वतंत्र होते गये और उन्होंने सरकार की कमजोरी का लाभ उठाकर अपने पद को मीरुसी बना लिया। सरकार की सत्ता मालगुजारी की आमदनी पर निर्भर थी। लगान वसूल करने वालों की स्वच्छंदता के कारण सरकार को बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़ा। अन्त में सरकार ने यह निश्चय किया कि लगान वसूल करनेवाले रेब्यू फार्मर कहलायेंगे। अर्थात् वे निर्धारित सालाना मालगुजारी सरकार को देंगे और उन्हें यह स्वतंत्रता दे दी जायगी कि वे रीयत से मनमाना लगान वसूल करें। सबसे पहले बंगाल प्रान्त में यह प्रणाली जारी की गयी। यह मुगल-साम्राज्य काल में शुरू हुई और सारे [भारत में व्याप्त हो गयी।^२

आज के युग में यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में जमींदारी प्रथा किसानों के लिए बड़ी दुखदायिनी है और यह निश्चित

१ रामदास गोड 'हमारे गांवों की कहानी

२ डा० जेड ए अहमद द एंग्लो-इण्डियन प्रॉब्लम इन इंडिया

हैं कि जबतक इस प्रश्न का परित्याग नहीं किया जायेगा, तबतक किसानों की न सामाजिक उन्नति हो सकती है और न उनका आर्थिक सुधार ही सम्भव है। देश में एक ऐसा प्रबल लोकमत तैयार हो गया है जो जमींदारी के दोषों की गंभीर भाँति अनुभव करता है और उनके निवारण के लिए भी उत्साह कर रहा है।

बंगाल की सरकार ने नवम्बर १९३८ में सर फामिस एल्ट की अध्यक्षता में बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन यह जाँच करने के लिए नियुक्त किया था कि बंगाल में प्रचलित भूमि प्रणालियाँ कौन-कौन सी हैं, उनका जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, स्वामी बन्दावस्त के क्या गुण व दोष हैं ? और क्या यह उचित होगा कि सरकार जमींदारियाँ खरीद ले और सीधे किसानों से मालगुजारी वसूल करे ?

मई १९४० में प्रकाशित इस कमीशन की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी है कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि वह समस्त जमींदारों की भूमि मुआविजा देकर खरीद सके। अनुमान दिया गया है कि जो मुआविजा जमींदारों को दिया जायेगा वह ७७ करोड़ ९० लाख रुपये होगा।

जब ईस्ट इण्डिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी अपने हाथ में ली तब वहाँ रेवेन्यू फार्मर बहुत बड़ी समस्या में थे। उनमें और किसानों में कोई भेद ही नहीं मालूम पड़ता था। लार्ड कानिंगहम ने यह अनुभव किया कि रेवेन्यू फार्मर सरकारी बोध में मालगुजारी जमा करने-वाला एक विशेष वर्ग है। इसपर अपना प्रभुत्व रखना चाहिए। ये हमारे राजमन्त्र बने रहें, क्योंकि इनके द्वारा सरकार रकम पर भी अपना पूरा नियंत्रण रख सकेगी। अतः अंग्रेजी राज्य में उन्हें भूमि पर पूरा स्वामित्व दे दिया गया। इस प्रकार जमींदारी प्रथा कायम हो गयी।

संयुक्तप्रान्त में जमींदार और उनके अधिकार

संयुक्तप्रान्त में २० लाख म ऊपर जमींदार हैं। कमार्य में ४ लाख

जमींदार स्वयं खेती करते हैं। १२ लाख जमींदार ऐसे हैं जो एक रुपये से कम मालगुजारी देते हैं। इसलिए वे तो नाममात्र के ही जमींदार हैं। १०० रुपये तक मालगुजारी देनेवाले जमादारा की संख्या ४½ लाख है। १०० रुपये से अधिक मालगुजारी देनेवाले जमींदारों की संख्या १ लाख ६२ हजार और इनमें से ११०० जमींदार ५००० रुपये या इससे अधिक लगान देते हैं। और केवल २०३ जमींदार २०,००० रुपये या इससे ज्यादा मालगुजारी देते हैं। इस प्रकार २० लाख जमींदारों में अधिकांश किसान ही हैं। केवल १ लाख ६२ हजार जमींदार ऐसे हैं जिनका गुजारा मुख्यतया जमींदारी की आमदनी से होता है। इसके साथ ही यह भी जान लेना जरूरी है कि जमींदारा पर प्रायः ९० करोड़ का ऋण है।

अंग्रेजी राज के आरम्भ में किसानों का भूमि पर अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। जमींदार भूमि के स्वामी बन गए परन्तु किसानों को भूमि पर स्थायी रूप से जोतने बोलने तक का अधिकार नहीं मिला। जमींदार जब चाहे तब बाश्तनार को खेत से बंदखल कर सकता था। बाद में जब किसानों के लिए कृषि कानून बनाये गए तब किसानों के अधिकारों की व्याख्या की गयी। इसी समय से जमींदारों ने अपने लिए खेती के निमित्त भूमि सुरक्षित रखना शुरू कर दिया। यही सुरक्षित भूमि सीर कहलाने लगी। पहले सीर से अभिप्राय उस भूमि से था जिसे जमींदार स्वयं अपने लिए जोतता बोता था परन्तु समय समय पर कृषि कानूनों द्वारा सीर की परिभाषा में परिवर्तन होता रहा। अन्त में सीर का नाम उस भूमि को दिया गया जो जमींदारों के निजी प्रयोग के लिए सुरक्षित होती थी और जिसपर किसानों को मोरूसी अधिकार प्राप्त नहीं होता था। जब जमींदार की जमींदारी बिक जाती थी, तो उसके साथ उसकी सीर नहीं बिकती थी।

इस प्रकार सीर जमींदारों का एक महत्वपूर्ण अधिकार बन गया। अवध लगान कानून १९२१ तथा आगरा कृषि कानून १९२६ के अनुसार उस सब भूमि पर जमींदारों को सीर का अधिकार प्राप्त है जिसे वे स्वयं या उनके नीकर बमजदूर जोतते-बोते थे और जो भूमि उपयुक्त कानूनों

के बनने से १ वर्ष पहले खुदकास्त दर्ज थी। अब उन्हें यह भी अधिकार प्राप्त हो गया है कि किसी भी १० साल की खुदकास्त को वे सीर दर्ज करा सकते हैं, परन्तु अपनी जमींदारी की भूमि के १०% से अधिक भाग में उन्हें सीर का अधिकार प्राप्त न हो सकेगा। अर्थात् जो ०० एकड़ भूमि का जमींदार है वह १० एकड़ से अधिक में इस प्रकार अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। सन् १९३५-३६ में आगरा प्रान्त में ४९ ३६ लाख एकड़ और अवध में ७ २४ लाख एकड़ जमीन सीर थी।

संयुक्तप्रान्त में किसान और उनके अधिकार

सन् १९३१ में खेती करने और खेती से जीविका कमानेवालों की ससया इस प्रकार थी—

कुल कृषक	१७, ७६, ५४, ३१
जमींदार (जो खेती नहीं करते)	२६, ०६, १०
जमींदार (जो खेती करते हैं)	१, ७९, ५५, ३६
बास्तकार (जो खेती करते हैं)	१२, ०१, १६, २१
कास्तकार (जो खेती नहीं करते)	१९, ३८, ७७
सेतिहर मजदूर	३, ४१, ९१, ८५
माली आदि	३, २१, ३९

सन् १९३५-३६ में संयुक्तप्रान्त में ३५, २७, ८०, ०० एकड़ भूमि पर कृषि होनी थी और ९६ लाख एकड़ भूमि व्यर्थ पड़ी हुई थी। कृषियोग्य भूमि में ३३, ७६, ६२५ एकड़ भूमि पर जमींदारों की सीर है और २८, १५, १४५ एकड़ भूमि पर उन्हें खुद कास्त का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार ६१ लाख से ऊपर एकड़ भूमि पर जमींदारों की सीर व खुदकास्त है। १२, ५९, ६४१ एकड़ भूमि ऐसी है जो किसानों के पास है और जो लगान से बरी है।

• संयुक्तप्रान्तीय कृषि-वानून १९३९ के अनुसार संयुक्तप्रान्त में ७ प्रकार के किसान मजूर किये गये हैं जो निम्नलिखित हैं—

(१) हकदारान कब्जा मुस्तकिल

- (२) शरह मुअइन कास्तकार
- (३) अवध में विशेष अधिकारवाले कास्तकार
- (४) साकितुल मिलनियत कास्तकार
- (५) नये मोरूसी कास्तकार
- (६) दखीलदार कास्तकार
- (७) गैरदखीलदार कास्तकार

प्रथम तीन प्रकार के कास्तकार अवध और पूर्वी जिलों में हैं जिनमें स्थायी बंदोबस्त प्रचलित है। हकदारान कब्जा मुस्तकिल जमींदार और किसान के बीच उस समय से चले आये हैं जब स्थायी बंदोबस्त हुआ था। इनका लगान स्थायी रहता है और इनका अधिकार मृत्यु के बाद इनके वारिसा को मिलता है। वे चाहें तो अपने अधिकार को बेच सकते हैं, रहन रख सकते हैं या हिस्से कर सकते हैं।

दूसरी श्रेणी के कास्तकारों के लगान की दर भी नियत है। इनका अधिकार भी मोरूसी है।

तीसरी श्रेणी के कास्तकार केवल अवध में हैं। ये वे कास्तकार हैं जिनका पट्टा विशेष इकरारनामे या सन् १८८६ के अवध लगान-कानून से पहले न्यायालय के निर्णय से हुआ है। मोरूसी कास्तकारों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे सब इन्हें भी प्राप्त हैं।

चौथी श्रेणी के साकितुल मिल्कियत कास्तकार वे हैं जो जमींदार, अदना मालिक या हकदारान कब्जा मुस्तकिल के अपनी जमींदारी तथा भूमि के बेचने, रहन करने या दान करने के बाद भी सीर व खुद-कास्त पर अपना अधिकार रखते हैं। परन्तु शर्त यह है कि बेचने, दान करने या रहन रखन से तीन साल पहले से वह उसे जोतता हो।

पाँचवीं श्रेणी मोरूसी कास्तकारों की है। ये तीन प्रकार के हैं—

(१) वह व्यक्ति जो सन् १९२६ के आगरा-लगान-कानून के अन्तर्गत कानूनी कास्तकार हो और उसके वारिस,

(२) वर्तमान कानून के अन्तर्गत जो कास्तकार मजूर किया गया

हो, परन्तु वह सीर वा काश्तकार न हो और न शिकमी काश्तकार (Subtenant) हो।

(३) प्रत्येक व्यक्ति जिसने इस कानून के अन्तर्गत मौससी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं।

छठी श्रेणी दखीलदार काश्तकारों की है। ये वे काश्तकार हैं जिन्हें पहले लगान कानून के अन्तर्गत दखीलदार काश्तकारों के अधिकार प्राप्त थे।

जो काश्तकार उपर्युक्त किसी श्रेणी में नहीं हैं वे गैरदखीलदार काश्तकार हैं।

अन्तिम श्रेणी के काश्तकारों को छोड़कर शेष काश्तकारों की सभी श्रेणियाँ को नीचे लिखे अधिकार प्राप्त हैं—

(१) हकदारान कब्जा मुस्तकिल और धरह मुजइमन काश्तकार दोनों को अपनी जमीन पर पूरा अधिकार है। वे उसे बेच सकते हैं, रहन पर सकते हैं और उनके वारिस भी उसे उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकते हैं।

(२) अवध के छास काश्तकार, साबिनुल मुस्विबत काश्तकार, दखीलदार, मौससी तथा गैर-दखीलदार काश्तकारों को जमीन बेचने या रहन रखने का अधिकार नहीं है। यह केवल वारिसों को ही प्राप्त हो सकती है।

(३) प्रत्येक काश्तकार को जोत पर अपनी जमीन दूसरे काश्तकार को उठा देने का अधिकार है। परन्तु यह अधिकार शिकमी काश्तकार तथा सीर के काश्तकारों को नहीं है।

(४) काश्तकार को लिखित पट्टा प्राप्त करने का अधिकार है।

(५) हकदारान कब्जा मुस्तकिल, धरह मुजइमन काश्तकार, अवध में दखीलदार काश्तकार, या छास अधिकारवाले काश्तकार अपनी जमीन पर कोई भी सुधार कर सकते हैं^१। शेष काश्तकारों का भी

^१ ऐंटी के सम्बन्ध में काश्तकारों को निम्नलिखित सुधार करने का अधिकार है—

सब प्रकार के सुधार करने के अधिकार ह। परन्तु वे निम्नलिखित सुधार जमींदार की लिखित आज्ञा के बिना नहीं कर सकते जबतक कि ऐसा रिवाज ग्राम में प्रचलित न हो जिससे उन्हें अधिकार प्राप्त हो जाये—

(अ) जोत के पास ही आराम या सुविधा के लिए मकान बनाना

(ब) खेती के काम के लिए तालाब बनाना ।

(६) गैर-दखीलदार काश्तकार को जमींदार की आज्ञा के बिना जोत में कोई भी सुधार करने का अधिकार नहीं है ।

(७) काश्तकारों को अपनी जमीन पर पेड़ लगाने का अधिकार है ।

(८) काश्तकार को लगान बढ़ा करने पर जमींदार से उसके हस्ताक्षर सहित रसीद पाने का अधिकार है ।

(९) कृषि वर्ष के अन्त होने से ३ मास पहले तक काश्तकार को जमींदार से ब्याज का हिसाब प्राप्त करने का अधिकार है ।

(१०) बकाया लगान के लिए जो काश्तकार अपनी कुल काश्त या उसके किसी हिस्से से बेदखल किया जायेगा उससे बकाया लगान चाहे

१ अपनी जोत पर अपने या मवेशी के लिए मकान या गोशाला बनाना ।

२ जोत की तरक्की के लिए कोई भी काम करना, जिनमें निम्न लिखित काम शामिल ह—

१ खेती के लिए कुआ बनाना या पानी जमा करने के लिए प्रबंध करना,

२ बाढ़ तथा पानी से फसल की रक्षा के लिए नालियाँ बनाना,

३ जमीन की सफाई करना, घेरा लगाना तथा उसे समतल बनाना

४ जोत के समीप आराम के लिए मकान बनाना,

५ खेती के लिए तालाब बनाना

६ उपर्युक्त कामों को फिर से बनाना ।

उसकी डिग्री हुई हो या न हुई हो, वसूल करने का ज़मींदार को हक न होगा।

(११) यदि कोई वास्तुकार अपनी ज़ीन से बंदखल कर दिया गया हो तो उसे उस गाँव में उसके रहने के मकान से बंदखल न किया जा सकेगा।

इस क़ानून में संयुक्तप्रान्त के ३४ लाख से ऊपर खेतिहर मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इन खेतिहर मजदूरों की दशा अत्यन्त भयंकर है। शहरों में, मिला में काम करनेवाले मजदूरों के लिए, मजूरी, पाम के पटे तथा छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में क़ानून बन गये हैं परन्तु खेतों पर काम करनेवाले किसानों के सम्बन्ध में अभी तक कोई क़ानून नहीं है। उनसे दिन-रात काम लिया जाता है और दो या ठाई आने मजदूरी दे दी जाती है। अक्सर यह मजदूरी भी नहीं मिलती। प्रायः ज़मींदार बंगार में ही उनसे काम लेते हैं। फसल काटने के समय मजदूरी कुछ बड़ा दी जाती है। सिपा को दो आने रोज़ से अधिक मजदूरी नहीं दी जाती। खेतिहर मजदूर वास्तव में गुलामी की दशा में हैं। वे अधिकांश में उस वर्ग में से हैं जिसे 'दमित' कहा जाता है।^१

वैसे तो समस्त भारत में खेतों पर काम करनेवाले मजदूरों की अवस्था बुरी है परन्तु बिहार और गुजरात प्रान्त में तो उनकी दशा गुलामी की तरह है। गुजरात में इन्हें हाली और बिहार में भूमिया कहा जाता है।

हाली खेतों पर काम करनेवाले मजदूर हैं जो अपनी भर्जी से मजदूरी पर काम नहीं करते; परन्तु उन्हें बड़े-बड़े ज़मींदारों द्वारा स्थायी रूप से पुश्तनी नोकर बनाकर रखा जाता है और उनसे खाने तथा रहने का प्रत्यक्ष ज़मींदारों द्वारा ही किया जाता है। वे अपने काम को छोड़कर दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। इस प्रकार इन हालियों और अमरीया के खेतों पर काम करनेवाले उन गुलामों में कोई अन्तर नहीं है, जो गृहपूँड से पूर्ण अमरीया में पाये जाने में। अब, अन्तर बेचल इतना

ही है कि अदालतें इन मजदूरों तथा इनकी मजदूरी पर जमींदारों का निरपेक्ष स्वामित्व नहीं स्वीकार करती। ये कानूनी रूप से स्वतन्त्र हैं पर वस्तुतः गुलाम हैं।*

किसानों का कर्जा

किसान न केवल गरीब, नासमझ और अत्याचार-पीडित ही हैं, बल्कि उनके सिर पर कर्जों का बड़ा बोझ भी है जिससे वे दबे जा रहे हैं। सन् १९३० में प्राविन्दयल बैंकिंग इन्क्वायरी कमिटी ने किसानों के कर्जों का जो अनुमान लगाया था, यद्यपि वह सर्वांश में सत्य नहीं है, तो भी उससे यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि किसानों पर कर्जों का कितना भारी बोझ है। प्रत्येक प्रान्त में किसानों पर कर्जा करोड़ रुपयों में इस प्रकार था—

बम्बई-सिन्ध	८१	बिहार-उड़ीसा	१५५
मद्रास	१५०	आसाम	२२
बंगाल	१००	केन्द्रीय प्रदेश	१८
समुद्रप्रान्त	१२४	ब्रह्मा	५०.५
पंजाब	१३५	कुर्ग	३५ ५५ लाख
मध्यप्रान्त-बरार	३६.५		

उद्योग-व्यवसाय

विगत अर्द्धशताब्दी में, विशेष रूप से विगत महायुद्ध के बाद से, भारत में उद्योग-धन्धों की पर्याप्त उन्नति हुई है। एक समय था जब भारत में उँगलियों पर गिनी जाने लायक मिले थीं और उनमें जो माल तैयार होता था वह विदेशी माल के मुकाबिले बहुत ही घटिया था। इस समय (सन् १९४०-४१) ब्रिटिश भारत में कुल रजिस्टर्ड कारखानों की संख्या १०,७८२ है। ९,७४३ कारखाने चले जिनमें ६,०८६ कारखाने सालभर काम करते रहे और ३,६५७ ऋतु-विशेष में।

१ जे० एम० मेहता । 'ए स्टडी ऑव रूलर इकनॉमी ऑव गुजरात'

कारखाने

रुई की धुलाई, कपड़े की धुलाई, चूँच बनाने, मोटरकारों की मरम्मत करने, इञ्जीनियरिंग, छपाई, जिल्दसाजी और चावल के उद्योगों में काफी उन्नति हुई है। मोझे, तेल, ग्लास, सीमेंट, ईंट, टाइल, चाय और चमड़ा बनाने के उद्योगों का भी पर्याप्त विस्तार हुआ है।

इन कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या सन् १९३८ में १७,३८,००० थी। यह अवस्था की संख्याओं में सबसे अधिक है। रुई के उद्योग में ५,१२,००० और जूट के उद्योग में २,९५,००० मजदूर लगे हुए हैं। जिनमें २४१,००० स्त्री-मजदूर और १०,७४२ बालक हैं।

पैदावार

महापृष्ठ के बाद भारतीय उद्योग-धन्यों में जो प्रगति हुई उसका अनुमान निम्नलिखित विवरण से मली मानि लग जाता है :

भारत में विदेशों से आनेवाला माल

वस्तुएँ	सन् १९१३-१४	सन् १९३८-३९
मूती घस्त्र	५३,२०,५१,०००	२२,६६,२०,०००
छोटा य इम्पात	१०,८८,५०,०००	६,६७,२०,०००
ऊनी कपड़ा	३,२४,६०,०००	२,८१,९०,०००
पाँच का सामान	१,६१,९२,०००	१,०५,१२,०००
सम्पाकू	५०,७४,०००	४०,२७,०००
सीमेंट	५०,७७,०००	१०,०५,०००
गव्वर	१२,९०,५०,०००	४५,४८,०००
मिट्टी का सामान	५२,१९,०००	३९,१९,०००
गिनीने	४०,०५,०००	३७,३०,०००
दिवागलाई	१,५३,३१,०००	२३,५०,०००
साबुन	६१,८७,०००	२० ४६,०००
छाने	४१,९४,०००	१४,८७,०००
	८८,२,९१,००० २०	३६,२४,२४,००० २०

सन १९३८ ३९ में भारत से निम्नलिखित माल विदेशों में भेजा गया :

चीजें	रुपये	चीजें	रुपये
कच्चा जूट	१३ ३९,६७,०००	खाने-पीने की चीजें	५९,३२,०००
तैयार जूट	२६,२६ ११,०००	रगने तथा चमड़ा	
कच्ची रुई	२४,६६,६५ ०००	बनाने की चीजें	५९,११,०००
तैयार रुई	७,११,७९,०००	खाद	३७,२२,०००
चाय	२३,४२,४७,०००	मोम	३६,२५,०००
बीज	१५,०९,२२,०००	दवाइयाँ	२७ ८३,०००
अनाज आटा दाल ७ ७४,१२,०००		सुअर के बाल	२६ ३२ ०००
चमड़ा	५ २७,५८ ०००	शक्कर	२४,१८ ०००
धातु	४,९१,०२,०००	हड्डियाँ	२३,७१ ०००
ऊन	३,८४,९५ ०००	लकड़ी	२३,६६,०००
कच्चा चमड़ा	३ ८४,६७ ०००	बृश तथा झाड़न	१५,७१ ०००
खली	३,०१,२० ०००	इमारती सामान	१४,७५ ०००
तम्बाकू	२,७५ ६७ ०००	पोशाक	१२ ६२,०००
फल-तरकारी	२,२६ ८६ ०००	गन्धक	१०,८९ ०००
कोयला व कोक	१,३६ २५ ०००	चारा	८,९६ ०००
लाख	१,२६ ६५ ०००	जानवर (जीवित)	८ २३,०००
भोहर	१,१४,१२,०००	रस्सी	८,१२,०००
तेल	१,०३,३९,०००	रेशम	४ २६,०००
ताँबा	९६ ०१,०००	टैलो	३,२७,०००
मसाले	७३,६६ ०००	सींग	२,३६,०००
कहवा	७५ ११,०००	वस्त्रियाँ	२,०००
गाँजा	७१,९८ ०००	अफीम	१,०००
कच्ची रबड़	७१ ५८,०००	दूसरी चीजें	५,८० ७७,०००
मछलियाँ	६९ २९,०००		
			१,६२,९२ ५५ ००० रुपये

भारत के आयात-निर्यात का तुलनात्मक अध्ययन निम्नलिखित अंकों से किया जा सकता है—

वर्ष	आयात (रुपयों में)	निर्यात (रुपयों में)
१९३५	१,१५,३५,७०,१४४	१,४७,२५,०६,८२०
१९३६	१,३२,२८,६४,६५३	१,५१,६६,९७,४९७
१९३७	१,२५,२४,०५,४२५	१,९६,१२,४६,२८६
१९३८	१,३४,४२,३२,३८५	१,६०,५२,३६,९९४
१९३९	१,७३,७८,७६,०८९	१,८०,९२,४२,२२१

व्यायष्ट स्टॉक कम्पनियों की पूँजी

भारत में इस समय विविध उद्योग-धन्धों में कपनियों की जो पूँजी लगी हुई है, उसका अध्ययन यह बताता है कि देश में उद्योग-धन्धों में बढ़ती हो रही है। १९३६-३७ के अंकों के अनुसार भारत के बेकिंग, बीमा, जहाजी, रेलवे तथा ट्रामवे कपनियों, रई, जूट, ऊनी तथा रेशमी मिल, रई व जूट के प्रेस, आटे के मिल, चाय, दूसरे मिल, कापड़ा धरकर आदि उद्योग-धन्धों और व्यवसायों की भारत में रजिस्टर्ड कम्पनियों में २ अरब ९७ करोड़ ९३ लाख ४४ हजार रुपये की और विदेशों में रजिस्टर्ड कम्पनियों में ७ अरब २५ करोड़ ३९ लाख २ हजार पाँच की पूँजी लगी हुई है।

मजदूरों की दशा

भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास में पूँजी और उत्पादन के अन्य साधनों का तो महत्त्व है ही मानव की श्रम-शक्ति का महत्त्व भी कम नहीं है। पूँजीपति और मिल-मालिक, साम्प्रदाय में, मजदूरों की इस श्रम-शक्ति से ही मालामाल होते हैं। अब मजदूरों का उद्योग में विशेष स्थान है। जबसे उद्योग-धन्धों में प्रगति होने लगी है, तबसे मिल में काम करनेवाले मजदूरों की समस्या भी विवट होती जा रही है।

मजदूरों की मजदूरी, काम करने के घण्टे, उनके साथ मालिकों का व्यवहार, उनके रहने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबन्ध, उनके

बालका की शिक्षा तथा स्वास्थ्य रखा की व्यवस्था अपाहिज तथा वृद्ध मजदूरों की वृद्धावस्था में सहायता छुट्टियाँ के नियम, वेतन-वृद्धि तथा भत्तों के नियम आदि ऐसे प्रश्न हैं जिनका अभी तक समुचित समाधान नहीं हो सका है। यही कारण है कि आज मजदूरों में घोर असंतोष और असान्ति है। उनके पास अपनी शिकायतों के दूर कराने के लिए केवल एक ही साधन है और वह है—हड़ताल।

मजदूरों के पारिवारिक (मजदूरी) का प्रश्न बड़ा विकट है। बड़े-बड़े औद्योगिक नगरों में मिलों और कारखानों में काम करनेवाले मजदूर अक्सर ग्रामों से आते हैं। अपने परिवारों को अपने ग्राम में छोड़कर वे शहरों में मजदूरी करने जाते हैं। ऐसे भी मजदूर हैं जो अपनी स्त्री बच्चों को साथ ल आते हैं। कारखाना में उन्हें वेतन कम मिलता है और इस पर उन्हें शहर के खर्चीले जीवन का सामना करना पड़ता है। शहरों में मकानों का किराया अधिक होता है। एक एक कोठरी सी, कोठरी में चार-चार उ छ स्त्री-पुरुष रहते हैं। एक एक कोठरी में जिसका क्षेत्रफल १२×१२ वर्गफीट होता है कभी कभी दो-दो तीन-तीन मजदूरों को सपरिवार रहना पड़ता है। खाना खाने बैठने, सोने आदि के लिए ऐसे छोटे-छोटे कमरों का एक भाग ही उन्हें मुश्किल से मिलता है।

अहमदाबाद और बम्बई में मजदूरों के रहने के लिए चालें बनायी गयी हैं जिनका किराया उन्हें देना पड़ता है। ये चालें इतनी गंदी तथा अस्वास्थ्यकर हैं कि इनमें पशुओं को बाँधना भी अयाय होगा।

मिल मालिकों की ओर से अथवा म्यूनिसिपल बोर्डों ने शहरों में मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाने का प्रयत्न किया है। परन्तु अभी तक इधर जो प्रयत्न हुआ है वह सतोषप्रद नहीं है। संयुक्तप्रान्त में ४५४ क्वार्टर बनाये गये हैं। य अधिकांश में शक्करमिलों की तरफ से बनाये गये हैं। मद्रास में मजदूरों के लिए कम किराये पर क्वार्टर बनाये गये हैं। कुछ साल पहले डेवरुपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा बम्बई में मजदूरों के लिए चालें बनायी गयी थी। अब उनमें सुधार किया गया है और उनमें

मजदूरों को रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। २०७ चालों में से १९२ में अब मजदूर रहने लगे हैं। इन चालों में ६३,००० मजदूर रहते हैं। अहमदाबाद में म्यूनिसिपल बोर्ड ने १५६ क्वार्टर मजदूरों के लिए बनवा दिये हैं। बंगाल में २० मिला ने अपने मजदूरों के लिए मकान बनवा दिये हैं। अजमेर-मेरवाड़ा, बिहार-उड़ीसा, मध्यप्रदेश-बरार, देहली तथा सीमाप्रांत में मजदूरों के लिए अभी कोई योजना नहीं बनायी गयी है।

कानपुर के मजदूरों की दशा की जाँच के लिए ३० अगस्त १९३७ को सयुक्तप्रान्त की सरकार ने एक जाँच-कमेटी बनायी थी। इस कमेटी के सामने काज़ुपुर की मजदूर-सभा की ओर से एक बकनव्य दिया गया जिसमें मजदूरों के विषय में लिखा है—

“मिलों में प्रधान निरीक्षक के कपन से विदित होता है कि सयुक्त-प्रान्त में, जहाँ का मुख्य व्यावसायिक केन्द्र कानपुर है, कपड़ों की मशीनों पर काम करनेवाले मजदूर को ३३ रुपये और सूत कातने की मशीन पर काम करनेवाले मजदूर को २५ रुपये मासिक मिलते हैं। पंजाब, दिल्ली और बंगाल में इससे अधिक मजदूरों नहीं मिलती। यम्पई की चुनौ हुई १९ मिलों की जाँच करने से पता चलता है कि वहाँ मजदूरों को ४० रुपये १२ आने २ पैसे से ५४ रुपये ७ आने तक मजदूरी मिलती है।”

मजदूर-जाँच-समिति का यह विश्वास है कि सयुक्तप्रान्त में वस्त्र-व्यवसाय की काफी उन्नति हुई है और उसने यह सिफारिश की है कि कानपुर के मजदूरों की मजदूरी में १० से १२ प्रतिशत वृद्धि कर दी जाये। कमेटी ने मजदूरों को पाँच श्रेणियों में विभाजित कर दिया है और उनकी मजदूरी में इस प्रकार वृद्धि करने की सिफारिश की है

श्रेणी	वृद्धि	कुल घेतन
१३) से १९) रु० तक	२३ आने प्रति रु०	अधिक से अधिक २१।।)
१९) से २५) „ „	२ आने „	„ „ २७।।)
२५) से ३२) „ „	१३ आने „	„ „ ३५।)
३२) से ४०) „ „	१ आने „	„ „ ४१।।)

४०) से ५९) रु० तक ३ आना प्रति रु० अधिक से अधिक ६०॥)

मजदूरों को ४ श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिनका वेतन क्रमशः ४०) रुपये से अधिक ३०) से ४०) तक, १५) से ३०) तक और १५) रुपये तक है और उन मजदूरों का औसत आय व्यय रूपमा में इस प्रकार है

श्रेणी	आय	व्यय	बचत	घाटा
पहली	५३-८-५	५३-५-९	०-२-८	०-०-७
दूसरी	३५-२-२	३७-५-११	०-०-०	२-३-९
तीसरी	२०-११-२	२२-२-३	०-०-०	१-६-११
चौथी	१२-१०-२	१५-५-६	०-०-०	२-११-४

३०) वेतन पानेवाले मजदूर का औसत व्यय इस प्रकार होता है—

	सपरिवार	अकेला
आटा	१)	२)
बाल	१॥)	१)
शाक सब्जी	१)	॥)
नमक	१२)	३)
मसाले	१)	॥)
खबर मिठाई	१)	
दूध घी	२॥)	
अन्य खाद्य पदार्थ	१)	॥)
लकड़ी तेल	३)	२)

मजदूरों के हित के लिए कानून

मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए प्रांतीय सरकारों ने कुछ कानून हाल में बनाये हैं जिनमें से निम्नलिखित कानून उल्लेखनीय हैं—

(१) प्रसूता-सहायक-कानून—इससे कारखानों व मिलों में काम करनेवाली स्त्री मजदूरों के लिए प्रसव से पूर्व और उसके बाद निर्धारित समय के लिए सबेसन अवकाश देने की व्यवस्था की गयी है।

(२) मजदूर-रक्षण-कानून—इसके अनुसार मजदूरों को अपने कल्याण के लिए हाथ ठेक करने तथा आन्दोलन करने का अधिकार प्राप्त है।

(३) मजदूर विवाद-कानून—इसके अनुसार मिल-मालिकों तथा मजदूरों के पारस्परिक झगड़ों को शान्तिपूर्वक निपटाने की व्यवस्था की गयी है।

(४) मजदूर-क्षतिपूर्ति कानून—कार्यकाल में किसी मजदूर की मृत्यु हो जाये या उसे कोई शारीरिक हानि पहुँचे तो इससे उसे मुआवजा देने की व्यवस्था की गयी है।

: १६ :

राष्ट्रीय जीवन

शासन पद्धति

आजकल भारत का शासन सन् १९३५ के भारत-सरकार-कानून के अनुसार चल रहा है। इस कानून से पहले सभी भारत सरकार-कानून केवल ब्रिटिश भारत में ही लागू होते थे लेकिन इस शासन विधान का सबध प्रान्ता और देशी राज्यों दोनों से है। इस विधान के दो प्रमुख भाग हैं। एक भाग में सघ शासन की योजना है और दूसरे भाग में प्रान्तीय शासन की।

भारतीय सघ-शासन

भारतीय सघ राज्य के दो प्रधान अंग निर्धारित किये गये हैं—
(१) गवर्नर के प्रान्त और (२) देशी राज्य। इसमें चीफ कमिश्नर के प्रान्त भी शामिल हैं।

भारतीय शासन में गवर्नर जनरल और वायसराय ये दो अलग अलग पद हैं। गवर्नर-जनरल सम्राट की ओर से भारतीय सघ का सर्वोच्च शासक होगा। वायसराय की हैसियत से वह उन देशी नरेशों का नियंत्रण करेगा जो सघ राज्य में शामिल न होंगे और उन विषयों का भी जो सम्राट उसे सौंप दे। गवर्नर जनरल की नियुक्ति के समय सम्राट की ओर से एक आदेश जारी होगा जिसके अनुसार वह भारत का शासक होगा। वायसराय को नियुक्त

भारत के प्रान्तों में शासन होना था, केन्द्र में भी उसी पद्धति की स्थापना की गयी है।

सेना, ईसाई-धर्म, पर-राष्ट्र-नीति और पिछड़े प्रदेशों का शासन 'सुरक्षित विषय' कहे गये हैं। इन विषयों का शासन-प्रबन्ध गवर्नर जनरल भारत-मन्त्री के नियन्त्रण में स्वेच्छानुसार करेगा। वह अपनी सुविधा के लिए सुरक्षित विषयों के प्रबन्ध में सहायता के लिए तीन परामर्शदाता नियुक्त कर सकेगा। इस प्रकार उपर्युक्त सुरक्षित विषय और अपनी विशेष जिम्मेदारियों को छोड़कर सघ-शासन के अन्य विषयों का राज-प्रबन्ध गवर्नर-जनरल मन्त्रि-मण्डल के परामर्श से करेगा। मन्त्रि-मण्डल में १० सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति गवर्नर-जनरल के द्वारा होगी।

गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं—

(१) भारतवर्ष या उसके किसी भाग में शान्ति-भंग करनेवाले खतरो का निवारण;

(२) संध-शासन की आर्थिक स्थिरता और साक्ष का सुरक्षित रखना;

(३) अल्प-संख्यक जन समुदायों के उचित हितों की रक्षा करना;

(४) सरकारी नौकरियों के सदस्यों और उनके अधिकारों की शासन-विधान द्वारा दिये गये अधिकार दिलाना और उनकी रक्षा करना;

(५) व्यापारिक और जातिगत भेदभाव-संबन्धी उन नियमों पर अमल करना जिनकी व्यवस्था विधान के पाँचवें भाग के तीसरे अध्याय में की गयी है,

(६) ग्रहण और इंग्लैंड के बने हुए आयात-माल के संबंध में ऐसे कामों की रोकना जिनके कारण इस माल के साथ भेद-भाव की नीति का व्यवहार होता हो;

(७) देशी रियासतों और उनके नरेशों के अधिकारों व भयंदा की रक्षा करना;

(८) इस बात का प्रवचन करना कि अपने विवेक एवं व्यक्तिगत निर्णय द्वारा किये जानेवाले कार्यों के संपादन में अन्य किसी संबंधित विषय से बाधा न पड़े।

उपर्युक्त विषयों के शासन में गवर्नर जनरल अपनी नीति और बायों के लिए भारतमन्त्री के प्रति उत्तरदायी होगा और अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार बाय-सपादन करेगा। गवर्नर-जनरल पर भारतमन्त्री का नियन्त्रण है। इसके अतिरिक्त उसपर किसी भारतीय सभ सस्या या जनता का नियन्त्रण नहीं है और न वह सभ के प्रति उत्तरदायी ही है। वह भारत का सर्वोच्च है।

मधीय व्यवस्थापक मण्डल में सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नर-जनरल, कौंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ असेम्बली शामिल हैं। कौंसिल ऑफ स्टेट में २६० सदस्य होंगे। इनमें से १५६ ब्रिटिश भारत के और १०४ देशी राज्यों के होंगे। चुनाव साम्प्रदायिक प्रणाली के आधार पर होगा। उसके अधिकांश सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होगा। हिन्दू, सिख तथा मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव उन्हींके सम्प्रदायों के निर्वाचकों द्वारा होगा। बड़े देशी राज्यों को अकेले एक सदस्य और छोटी रियासतों को कई मिलकर एक प्रतिनिधि मनोनीत कर भेजने का अधिकार होगा। एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, भारतीय ईसाई और दलित जातियों के प्रतिनिधि परोक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इनके चुनाव में वे ही व्यक्ति मतदाता होंगे, जो प्रांतीय व्यवस्थापक-मण्डल के सदस्य होंगे। इस कौंसिल का कार्य काल ९ वर्ष का होगा। एक तिहाई सदस्य ३ साल के लिए, १/३ के लिए और शेष एक तिहाई ९ साल के लिए होंगे। १ और ३ साल में एक बार अधिवेशन अवश्य होगा।

असेम्बली का जीवन काल ५ वर्ष होगा। उसकी अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। असेम्बली के सदस्यों का चुनाव परोक्ष रूप से प्रांतीय असेम्बली के सदस्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर होगा।

उपर्युक्त सघीय व्यवस्थापक मण्डल के तीन अधिकार होंगे। (१) शासन निरोक्षण (२) नियम-निर्माण और (३) आर्थिक।

गवर्नर-जनरल के सुरक्षित विषयों, विशेष उत्तरदायित्वों और व्यक्तिगत निर्णयों के कामों को छोड़कर, मघीय-मन्त्रि-मंडल हस्ताक्षरित विषयों के शासन में सामूहिक रूप से मघीय व्यवस्थापक-मण्डल के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रत्येक सदस्य को नियमानुसार मन्त्रियों से उनके कार्यों के बारे में प्रश्न पूछकर उत्तर माँगने का अधिकार होगा। वे शासन विभाग की आलाचना करते हुए स्पष्ट प्रस्ताव भी रख सकेंगे। कानून बनाने की सुविधा के लिए शासन विधान द्वारा समस्त विषय प्रांतीय और सघीय दो श्रेणियों में विभाजित कर दिये हैं। मघीय व्यवस्थापक मण्डल को सम्पूर्ण सघीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा।

कौंसिल ऑफ स्टेट तथा असेम्बली दोनों का एक-एक निर्वाचित अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तथा प्रधान उपप्रधान होगा।

प्रत्येक कानून दोनों मण्डलों की स्वीकृति से बनाया जायेगा। गवर्नर-जनरल कानून बनाने के लिए दोनों का संयुक्त अधिवेशन भी आमंत्रित कर सकेगा। उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी 'बिल' ऐक्ट नहीं बन सकेगा। गवर्नर-जनरल का स्वच्छानुसार आर्डिनेंस जारी करने तथा कानून बनाने का भी अधिकार होगा। आवश्यकता पड़ने पर वह सारे शासन विधान को स्थगित कर उसकी वागडोर अपने हाथ में ले सकेगा।

भारतीय सघ के प्रांतों व राज्यों के पारम्परिक सभा, विधान-संघी निर्णय तथा व्याख्या के लिए एक सघीय-न्यायालय होगा। इस न्यायालय में कोई भी मामला नियमानुसार निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा सकेगा और अपील भी की जा सकेगी। प्रांता में या देशी राज्या

में यदि किसी अधिकार के संघर्ष में झगडा होगा तो सघीय न्यायालय को निर्णय देने का अधिकार होगा ।

संक्षेप में यह भारत के वैदेशीय शासन की रूप रेखा है । विधान के अनुसार-संघ शासन की स्थापना के लिए दो शर्तों की पूर्ति आवश्यक है

(१) कम से कम इतने देशी राज्य सघ में शामिल होने के लिए तैयार हो जायें जो कौंसिल ऑफ स्टेट में ५२ सदस्य भेज सकें और जिनकी जन संख्या समस्त देशी राज्यों की जन-संख्या की आधी हो ।

(२) प्रथम गत की पूर्ति के पश्चात्, यदि ब्रिटिश पार्लमैट की दोनों सभाएँ सम्राट से सघ राज्य स्थापित करने की प्रार्थना करें, तो सम्राट इस आशय की घोषणा करेंगे कि अमुक तिथि से सम्राट के अधीन सघ शासन स्थापित किया जाये ।

जब सन् १९३५ में ब्रिटिश पार्लमैट ने भारत का शासन विधान स्वीकृत किया तभी से भारत के वायसराय लार्ड लिनलिथगो द्वारा देशी राज्या को सघ में शामिल कराने के लिए प्रयत्न हो रहा था । परन्तु नरेशाने अपनी स्वीकृति नहीं दी थी । इतने ही में सितम्बर १९३९ में इंग्लैंड और जर्मनी में युद्ध छिड़ गया और सरकार ने भारतीय सघ की स्थापना के प्रयत्न को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया ।

भारतीय लोकमत ब्रिटिश पार्लमैट द्वारा प्रस्तावित इस सघ-योजना के विरुद्ध शुरू से ही है । विधान का अस्वीकार्य घोषित कर चुकी है और शासन की स्थापना न होने देने के लिए भी न

विधान का अस्वीकार्य
शासन की स्थापना
भी सघ

सब के बाल में भारत का केन्द्रीय शासन किस प्रणाली पर होगा ? इस सत्रमण-काल में सपरिषद् गवर्नर जनरल सघीय शासन-विभाग का काम करेगा और केन्द्रीय व्यवस्थापक-मण्डल सघीय व्यवस्थापक-मण्डल का । गवर्नर-जनरल की सारी जिम्मेदारियाँ नये विधान के अनुसार होंगी । यह भारत-मंत्री के आधीन होगा । फेडरल पब्लिक सर्विस कमिशन, फेडरल रेलवे ऑथारिटी तथा फेडरल कोर्ट की स्थापना हो चुकी है । शासन विभाग में परिवर्तन पार्लमेट द्वारा अथवा मार्टर-इन-कौंसिल द्वारा ही हो सकेगा ।

प्रान्तीय शासन-प्रणाली

भारत में दो प्रकार के प्रान्त हैं (१) गवर्नर के प्रान्त और (२) चीफ कमिशनर के प्रांत । गवर्नरों से शासित ११ प्रांत हैं—बंगाल, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, आसाम, सिंध, सीमा-प्रान्त और मध्यप्रांत तथा चीफ कमिशनरों के प्रान्त हैं—ब्रिटिश बिनो-चिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा, दिल्ली कुर्ग, अण्डमान निकोबार और पप-पिपलोदा ।

सन् १९३५ के विधान के अनुसार केवल उपर्युक्त ११ गवर्नरों के प्रांतों में ही उत्तरदायी शासन की स्थापना की गयी है । इसीको 'प्रान्तीय स्वराज' कहा जाता है । गवर्नर-जनरल की भूमिति गवर्नरों का भी निम्नलिखित के समान आदेश-पत्र मिलता है । इस आदेश-पत्र में यह बतलाया जाता है कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं ? गवर्नर उस व्यक्ति के परामर्श से अपने मंत्रियों को नियुक्त करेगा जिसके साथ, उसके विचारों में, प्रांतीय व्यवस्थापिका-सभा (असेम्बली) का बहुमत हो । यह अल्पसंख्यक जन-समुदायों के प्रतिनिधियों को जहाँ-तक सम्भव होगा, मिलाने की काशिश करेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि समस्त मंत्रि-मंडल में व्यवस्थापक-मंडल को विश्वास हो । वह मंत्रि-मण्डल के समुक्त उत्तरदायित्व पर जार देगा । प्रांतीय गवर्नर अपने शासन-मन्त्री अधिकारों का उपयोग मंत्रियों के परामर्श से तब तक

करेगा जबतक उसके विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने में कोई बाधा न पड़े। विशेष उत्तरदायित्वों को पूरा करने में बाधा पड़ने पर वह मंत्रियों के परामर्श से प्रतिकूल व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य संपादन करेगा।

प्रत्येक प्रान्त के शासन में गवर्नर की सहायता करने और उस परामर्श देने के लिए एक मंत्रि मंडल होना है। मंत्रि मंडल के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। किसी प्रान्त में ३ मंत्री हैं, किसी में १०, किसी में ६। मंत्रियों की नियुक्ति व्यवस्थापक मंडल में बहुमत-दल के नेता के परामर्श से गवर्नर द्वारा की जाती है। उन्हीं बहुमत-दल का नेता प्रधान मंत्री होता है। प्रत्येक मंत्री का व्यवस्थापक मंडल का सदस्य होना आवश्यक है।

गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं—

(१) प्राप्त या उसके किसी भाग में शांति भंग करनेवाले पत्रों को दूर करना,

(२) अल्प संख्यक जनसमुदायों के उचित हिता की रक्षा करना,

(३) सरकारी नौकरियों के सदस्यों और उनके आधिता की शासन-विधान द्वारा दिये गये अधिकारों को दिलाना और उनके उचित अधिकारों की रक्षा करना,

(४) इंग्लैंड और ब्रह्मा के बने हुए आयात माल के संबंध में ऐसे कामों की रोकना जिनके कारण इस माल के साथ भेदभाव संबंधी नीति का व्यवहार होता है,

(५) प्रान्त के जिन भागों को नये शासन विधान के अनुसार पृथक् घोषित किया जाये उनके शासन तथा सुव्यवस्था का प्रबंध करना,

(६) दक्षी राज्यों के अधिकारों और उनके नरेशों के अधिकारों और मर्यादा की रक्षा करना

(७) गवर्नर-जनरल के उन आदेशों पर अमल करना जो वह अपने व्यक्तिगत निर्णय अथवा विवेक के द्वारा किये गये कार्यों के लिए जारी करे।

उपर्युक्त विषय का शासन प्रान्तीय गवर्नर स्वेच्छानुसार करते हैं। इस प्रकार प्रान्तों में आज भी पूर्ण उत्तरदायी शासन-प्रणाली जारी नहीं है। उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त और भी कार्य हैं जिन्हें गवर्नर अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय से करते हैं और जिनके लिए वे प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते।

गवर्नरों के अधिकार

गवर्नरों को तीन प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं—शासन-सबधी (Executive), व्यवस्था-सबधी (Legislative) तथा आर्थिक (Financial)।

(१) शासन-सम्बन्धी अधिकार—

- (१) मन्त्रि मण्डल की नियुक्ति,
- (२) मन्त्रि-मण्डल के अधिवेशन का सम्पादन,
- (३) एडवोकेट जनरल की नियुक्ति तथा पदव्युक्ति,
- (४) आभूषण के दमन के लिए विशेष व्यवस्था,
- (५) मन्त्रि मण्डल के कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाना,
- (६) वैधानिक शासन-पद्धति के अमल होने पर अपने विवेक के अनुसार घोषणा द्वारा उसके अन्तर्गत उल्लिखित सारे काम अपने विवेक या इच्छानुसार कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार, हाई-कोर्ट के अधिकारों के अतिरिक्त, किसी भी प्रान्तीय शासन-स्था के अधिकारों को स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की घोषणा की सूचना भारत मंत्री द्वारा पार्लमेंट को देनी पड़ती है। छ मास बाद इसका कार्यकाल पार्लमेंट की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। इस घोषणा के अनुसार शासन अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक किया जा सकता है।^१

१ यूरोपीय युद्ध के प्रदन पर कांग्रेसी मन्त्रि-मण्डलों द्वारा त्याग पत्र दे देने के बाद नवम्बर सन १९३९ से भारत के उन प्रान्तों (मद्रास, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा सीमाप्रान्त) में गवर्नरों द्वारा परामर्शदाताओं की सहायता से शासन हो रहा है। प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल स्थगित कर दिये गये हैं।

(२) व्यवस्था सवधी अधिकार—

(१) व्यवस्थापक सभाआ के अधिवेशन आमत्रित करने तथा विसर्जन करने का अधिकार,

(२) व्यवस्थापक मडल भग करने का अधिकार,

(३) दोना सभाआ के सयुक्त अधिवेशन आमत्रित करना

(४) सदस्या या मत्रिया का त्यागपत्र मजूर करना,

(५) प्रान्तीय व्यवस्थापक मडल द्वारा पास कानूना पर स्वीकृति देना या न देना गवनर-जनरल के लिए सुरक्षित रगना,

(६) किसी भी कानून के मसविदे को पुनर्विचार न लिए पुन व्यवस्थापक सभा में भजना

(७) आडिनेंस जारी करना

(८) गवनर के कानून बनाना और जारी करना

(३) धार्मिक अधिकार—

(१) प्रान्तीय व्यय की सारी माँगें गवनर की सिफारिश पर प्रांतीय व्यवस्थापक सभा में पेश की जाती ह । व्यय के दो भाग हैं—

(अ) प्रांतीय व्यय का वह भाग जिसका उल्लेख विधान में किया गया है ।

(ब) वह व्यय जिसकी माँग प्रथम भाग के अनिरिकष पैग की जाती है ।

अमुक भाग प्रथम भाग की है या द्वितीय की—इसका निणय गवनर पर निर्भर है । प्रथम भाग की माँग पर व्यवस्थापक सभा का मत देने का अधिकार नहीं है । द्वितीय भाग की माँग पर सभा की राय जरूरी है ।

प्रान्तीय व्यवस्थापक-मडल

नये विधान के अनुसार भारत के केवल छ प्रान्त कर्नाल, मद्रास बम्बई सयुक्तप्रान्त बिहार और आसाम में व्यवस्थापक मडल के अन्तगत दो सभाएँ हैं जो कौंसिल और असेम्बली कहलाती ह । साथ ५ प्रान्तों में केवल एक व्यवस्थापक सभा है जो असेम्बली कहलाती है । प्रांतीय कौंसिलें स्थायी संस्थाएँ ह और उनका कायकाल ९ वर्ष का है । प्रति

तीसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य नये चुने जाने हैं। उसके संगठन का आधार साम्प्रदायिकता है। असेम्बली की रचना भी साम्प्रदायिक है।

व्यवस्थापक-मण्डल के अधिकार तीन प्रकार के हैं—(१) शासन-नियंत्रण (२) कानून निर्माण (३) आर्थिक।

(१) शासन नियंत्रण—

प्रान्तीय गवर्नर अपने विवेक और व्यक्तिगत निर्णय के कामों को छोड़कर जो सब कार्य अपने मन्त्रि-मण्डल की सहायता एवं परामर्श से करते हैं। गवर्नर के द्वारा किये जानेवाले उन कार्यों पर जिन्हें वे अपने व्यक्तिगत निर्णय या विवेक से करते हैं प्रान्तीय व्यवस्थापक-मण्डल का कोई अधिकार नहीं है। व्यवस्थापक-मण्डल का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी विभाग की नीति व कार्य के संबंध में प्रश्न पूछ सकता है और मन्त्रियों को ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना होता है। शासन-नीति के विरोध के लिए व्यवस्थापक सभा के अधिवेशन को स्थगित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर मन्त्रि-मण्डल को त्याग-पत्र देना पड़ता है।

१ प्रान्तीय कौंसिलों का संगठन इस प्रकार है—

प्रांत	सामान्य मु०	यूरो०	हि०ईसाई	अर्सेवली	द्वारा गवर्नर द्वारा योग	नियुक्त	नियुक्त
मद्रास	३५	७	१	३	...	८ से १०	५६
बम्बई	२०	५	१	३ से ४	३०
बंगाल	१०	१७	३	...	२७	६ से ८	६५
सयुक्तप्रांत	३४	१७	१	६ से ८	६०
बिहार	९	४	१	...	१२	३ से ४	३०
असम	१०	६	०	३ से ४	२२

प्रान्तीय असेम्बलियों का संगठन इस प्रकार है—

प्रति

कृ० उदय

दिना

दिल्ली के सुदीक्षित

रक्षण

पुस्तकी जातिनी व

प्रदेश

विषय

सुसज्जित

पुस्तकी वृद्धि

पुस्तकी वृद्धि

दि० ईसाई

व्यापार वृद्धि

मार्च

जुलाई

विषयवर्गीकृत

मार्च

मद्रास
बंगाल
बम्बई
समुद्रप्रांत
पंजाब
विहार
मध्यप्रांत
असम
सीमाप्रांत
उड़ीसा
सिन्ध

२१५
१७५
२५०
२२८
१७५
१५२
११२
१०८
५०
६०
६०

१२६
१२६
१२६
१२६
१२६
१२६
१२६
१२६
१२६
१२६
१२६

०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०

(२) नियम निर्माण—

प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल को उन समस्त निर्धारित विषयों पर बानून बनाने का अधिकार है जो प्रान्तीय सूची के अन्तर्गत विषयों में उल्लिखित हैं।

(३) आर्थिक अधिकार—

मन्त्रि मण्डल प्रति वर्ष आर्थिक वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व सरकारी आय-व्यय का व्योरा व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष स्वीकृति के लिए रखता है। निम्नलिखित मुद्दों पर असेम्बली और कौंसिल में बहस की जा सकती है, परन्तु उनपर मत देने का उन्हें अधिकार नहीं है—

१ गवर्नर का वेतन, भत्ते और उसके कार्यालय का वह खर्च जिसकी व्यवस्था सपरिषद सम्मेलन द्वारा की गयी हो,

२ प्रान्तीय सरकारी ऋण सम्बंधी खर्च,

३ मन्त्रियों तथा एडवोकेट जनरल का वेतन और भत्ता,

४ हाईकोर्ट के जजों का वेतन व भत्ता,

५ पुष्प प्रदेशों के शासन का व्यय,

६ किसी न्यायालय के नियमों के अनुसार चुकायी जानेवाली रकम,

७ कोई और खर्च जो शासन विधान और प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल द्वारा इस प्रकार का घोषित किया गया हो।

स्थानिक स्वायत्त शासन

प्रत्येक गवर्नर का प्रान्त कई भागों में विभक्त होता है—प्रान्त का सबसे बड़ा भाग कमिश्नरी कहलाता है। एक प्रान्त में कई कमिश्नरियाँ होती हैं। कई जिलों को मिलाकर एक कमिश्नरी बनती है। कमिश्नरी का शासन कमिश्नर के आधीन होता है। वह इण्डियन सिविल सचिव (आई० सी० एस०) का सदस्य होता है। वह मालगुजारी तथा भूमि सम्बंधी मामलों का नियंत्रण करता है। वह जिला के शासन का भी निरीक्षण करता है तथा स्थानिक बोर्डों का नियंत्रण भी उसीके अधीन होता है।

प्रत्येक जिले का शासन प्रबन्ध कलेक्टर के हाथ में होता है। वह जिले का प्रमुख शासक है। मुख्यतः उसके अधिकार मालगुजारी, शासन प्रबन्ध, न्याय और निरीक्षण-सम्बन्धी हैं। मालगुजारी वसूखरना कलेक्टर का प्रमुख काम है (जो कि नाम से ही स्पष्ट है)। जिले के शासन की देखभाल, जनता में शान्ति-व्यवस्था तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा आदि उसके आनुपंगिक कार्य हैं। कलेक्टर जिले का प्रधान मजिस्ट्रेट भी होता है। शासन प्रबन्ध के अतिरिक्त वह मुकद्दमा के फंसले करता है तथा डिप्टी कलेक्टरों के फंसल की अपील सुनता है। जिले के प्रत्येक सरकारी विभाग के निरीक्षण करने का अधिकार कलेक्टर को है। वह भी इन्चियन सिविल सचिव का सदस्य होता है। कुछ डिप्टी कलेक्टर भी कलेक्टर बना दिये जाते हैं। सिविल सर्जन जेन सुपरिन्टेण्डेन्ट, पुलिस सुपरिन्टेण्डेन्ट आदि उसके कार्य में योग देते हैं।

प्रत्येक जिले में कई तहसीलें होती हैं। इन्हें परगना भी कहते हैं। प्रत्येक परगना या कई परगने का एक अफसर होता है जो डिप्टी कलेक्टर कहलाता है। डिप्टी कलेक्टर प्रान्तीय सिविल सचिव का सदस्य होता है। डिप्टी कलेक्टर के कार्य भी कई प्रकार के हैं। अपने परगने के शासन प्रबन्ध की देख रेख उसका प्रमुख कार्य है। वह फौजदारी और मालगुजारी के मुकद्दमे लेता है तथा तहसीलदारों के फंसलों की अपील भी सुनता है। प्रत्येक डिप्टी कलेक्टर जो परगना का अफसर होता है, प्रथम दर्जे का मजिस्ट्रेट होता है। प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार और उसकी सहायता के लिए एक नायब-तहसीलदार होता है।

म्यूनिसिपल बोर्ड

सामान्य तथा औद्योगिक नगरों के प्रबन्ध के लिए चार प्रकार की स्थानीय संस्थाएँ होती हैं—(१) कॉर्पोरेशन (२) म्यूनिसिपैलिटी (३) पोर्ट-ट्रस्ट (४) इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट।

मद्रास बम्बई कलकत्ता, कराँची आदि बड़-बड़े नगरों में म्यूनिसिपल बोर्डों को 'कॉर्पोरेशन' और उसके अध्यक्ष को मेयर कहते हैं।

म्युनिसिपलिटि का शासन एक समिति के हाथ में होता है, जिसे 'म्युनिसिपल बोर्ड' कहते हैं। इस बोर्ड का चुनाव मतदाताओं द्वारा साम्प्रदायिक आधार पर होता है। निर्वाचन की सुविधा के लिए प्रत्येक गहर की कई बाड़ों (वार्डों) में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक बाड़ से सामान्यतया जनसंख्या के आधार पर १ से ३ तक सदस्य चुने जाते हैं। कुछ म्युनिसिपल बोर्डों में महिलाओं तथा दलित वर्गों के प्रतिनिधि सरकार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं।

म्युनिसिपल बोर्ड के उम्मीदवारों की योग्यताएँ—बोर्ड के उम्मीदवारों की योग्यताएँ एकसी हैं। सयुक्तप्रान्त में प्रत्येक म्युनिसिपल मतदाता जो अंग्रेजी, हिन्दी या उर्दू पढ़ लेता हो, जो म्युनिसिपल नीकर न हो, जो म्युनिसिपल बोर्ड के किसी ठेके का ठेकेदार या हिस्सेदार न हो, जो वैतनिक मजिस्ट्रेट या पुलिस का अफसर न हो, या सरकारी कर्मचारी न हो म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य चुना जा सकता है।

निर्वाचन—पहले चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची तैयार होती है। एक निश्चित तारीख तक प्रस्तावकगण उम्मीदवारों का (नाम पता सहित) प्रस्ताव और अनुमोदन आवेदनपत्रों द्वारा पेश करते हैं और निश्चित तिथि को रिटनिंग अफसर उनकी जाँच करके उन्हें स्वीकृत या रद्द करता है। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ ५०) दाखिल करने पड़ते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के दिन सरकार छुट्टी घोषित करती है। फिर प्रत्येक बाड़ में पक्षियों द्वारा उम्मीदवारों के मत लिखे जाते हैं।

पदाधिकारी—जब इस प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो सबसे पहली बैठक में उसके अध्यक्ष (चेयरमैन) और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं।

बोर्ड में कुछ वेतनभोगी म्युनिसिपल पदाधिकारी भी होते हैं। जिनमें से मुख्य हैं—एक्जीक्यूटिव आफिसर, हेल्थ ऑफिसर, म्युनिसिपल इंजीनियर, वाटर वर्क सुपरिण्डेण्डेंट, एजुकेशन सुपरिण्डेण्डेंट। इन उच्च पदाधिकारियों और अन्य छोटे कर्मचारियों की नियुक्ति बार्ड

करता है और सुचारु रूप से काम चलाने के लिए अर्थ-समिति, शिक्षा-समिति, जल-व्यवस्था-समिति, पब्लिक वरस कमिटी आदि उपसमितियाँ निर्वाचित करता है।

म्युनिसिपल बोर्ड अपने काम संचालन में एक बड़ी सीमा तक स्वतंत्र है परन्तु कमिश्नर और सरकार का उनपर नियंत्रण होता है। नागरिक जीवन को अधिक-से-अधिक सुखी बनाना ही इनका मुख्य लक्ष्य है। वे जनता की प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियमाँ का पालन कराते हैं भोजन की शुद्धि और पवित्रता की रक्षा कराते हैं, मकान आदि बनाने के लिए मजूरी देते हैं और अपने नगरवासियों पर अनेक तरह के कर भी लगाते हैं।

ज़िला-बोर्ड

ज़िले के प्रबंध के लिए प्रायः प्रत्येक जिले में एक बोर्ड होता है, जिसे प्रांतीय सरकार बनाती है। भारत में कुल २७७ जिला बोर्ड हैं। इनकी भी रचना, संगठन, काम प्रणाली, अधिकार इत्यादि म्युनिसिपल बोर्ड के समान ही है और चुनाव भी साम्प्रदायिक प्रणाली के आधार पर होता है।

संयुक्त-प्रान्त में ग्राम-पंचायते निम्नलिखित फौजदारी-दीवानी सगडों की जाँच करती और फँसले देती हैं—

- (१) २५ रुपये तक के रुपये-पैसे के मुकद्दमे;
- (२) साधारण मार-पीट या १० रुपये तक की चोरी या १० रुपये तक की हानि या जानबूझकर अपमान करने के फौजदारी मुकद्दमे;
- (३) जानबूझकर जानवर पकड़ने और स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों पर ध्यान न देने के मुकद्दमे।

ग्राम-पंचायतों को फौजदारी के मामलों में १० रुपये, मवेशियों के मामलों में ५ रुपये और स्वास्थ्य-सम्बन्धी मामलों में १ रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार है, परन्तु मुचलके की कार्रवाई करने पर जमानत लेने अथवा कैद की सजा देने का अधिकार नहीं है।

पंचायतों के शासन-सम्बन्धी-कार्य निम्नलिखित हैं—

ग्रामी में सड़के बनाना, रास्ते बनाना, नये कुएँ बनाना, तालाबों और कुओं की सफाई, स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातों की देखभाल; ग्रामबालों की शिक्षा, उनके खेल-तमाशों का प्रबन्ध, स्मशान-भूमि की व्यवस्था आदि। लेकिन बंगाल के 'यूनिपन बोर्ड' के अधिकार क्षेत्र में सफाई, मार्ग-जनिक हित के काम आदि की भी देखभाल होती है।

राष्ट्रीय नवजागरण

राष्ट्रीयता का उदय

पृथ्वीराज के पतन के बाद से ही मुस्लिम शासन की जड़ जमी, जो मुगल साम्राज्य के निर्मूल होने पर उखड़ी; किन्तु उसको निर्मूल करनेवाली भी एक विदेशी सत्ता ही थी। मुगल खानदान के सदियों लम्बे शासन-काल में ही अंग्रेजों ने भारतवर्ष में अपना सिक्का जमाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था। सन् १६०८ में व्यापार के लिए आये हुए अंग्रेजों ने मूरत नगर में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनायी। इसके तीन माल बाद इंग्लैंड के राजा ने सर टामस रो को जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त करके भेजा। इसी समय से भारत में

अंग्रेजी व्यापार की जड़ जम गयी। धीरे-धीरे तराजू के माथ-साथ तन्-वार का राज्य भी जमने लगा।

मुगल शासन काल और कम्पनी के घामन-काठ में भारतीय जनता पतन की नीमा तब पहुँच चुकी थी। राजनीतिक पराधीनता के साथ-साथ भारतवासियों में सामाजिक तथा धार्मिक पतन के लक्षण भी साफ-साफ दिखायी देने लगे। दस्तकारियों और ग्रामीणों के मास के साथ-साथ संस्कृति, कला तथा साहित्य का भी ह्रास होने लगा। हिन्दू लोग ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित होने लगे और अपनी भाषा, साहित्य और धर्म का परित्याग कर विदेशी (ईसाई) धर्म, संस्कृति तथा भाषा को अपनाने लगे।

एक ओर भारतीय जीवन में इस अवाछनीय परिपक्वता ने हिन्दू समाज के सामने एक भयानक समस्या ला दी, दूसरी ओर कम्पनी के शासन मनमाने ढंग से जनता का शोषण करने लगे। सन् १८५७ में जो भारतीय विद्रोह (गदर) हुआ वह इसी दुःशासन के प्रति विद्रोह था। यह भारत का अन्तिम सशस्त्र विद्रोह था जिसमें राजा-रंक सभी ने भाग लिया था।

इस प्रकार भारत में राष्ट्रीयता के उदय का बीज यहाँ के विदेशी शासन की दमन और शोषण-नीति में ही छिपा हुआ है।

हमारे आचार-विचार, धर्म, संस्कृति आदि की भावनाओं को बङ्गने-वाली हानिकारक पाश्चात्य शिक्षा का एक लाभ यह भी हुआ कि भारतीयों में पश्चिम के नवीन राजनीतिक आदर्शों तथा मिद्वान्तों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति हुई। भारतवासी विदेशों में अध्ययन के लिए गये और वहाँ के स्वतन्त्र वातावरण में उन्होंने नयी प्रेरणाएँ पायीं। विदेशों में स्वतन्त्रता और समानता का जैसा स्वरूप उन्होंने देखा, स्वदेश में तात्पर्य

स्थापना की। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर और श्री केशवचन्द्रमेन ने उनके कार्य में सहयोग दिया। बम्बई में प्रार्थना-ममाज स्थापित हुआ। न्यायमूर्ति रानाटे, सर रामकृष्ण भट्टारकर और सर नारायण चन्द्रावरकर ने बम्बई में हिन्दू-ममाज-सुधार आन्दोलन की नींव डाली। श्री ईश्वरचन्द्र विद्या-नागर ने विधवा-विवाह आन्दोलन का श्रीमण्डल किया। श्री ध्यारीचरण मरपार ने मद्य-निषेध-आन्दोलन द्वारा जनता के स्वास्थ्य-निर्माण में योग दिया। महर्षि दयानन्द ने 'आर्य-समाज' की स्थापना करके उसके द्वारा ज्ञान-प्रचार से अधविश्वासी या रुढ़ियों को छिन्न-भिन्न करने का काम किया। स्वामी दयानन्द ने अपने ग्रन्थ "मत्तार्थ-प्रकाश" में लिखा है कि "विदेशी राज्य में चाहे जड़ कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य, चाहे उसमें कितनी ही सुटियाँ क्यों न हों, अच्छा होता है।" आर्य-समाज ने भारत में धार्मिक जाति के नाश-साथ सामाजिक सुधार तथा राजनीतिक स्वाधीनता का भी मार्ग दिखाया।

मद्रास प्रान्त में धियोमॉर्फिकल सोसायटी (व्याधिया-समाज) की स्थापना हुई। इसकी महालिवा श्रीमती क्लायस्टकी और उनके सह-योगी कर्नल आल्कर ने राष्ट्रीय जागरण में प्रमुख योग दिया। श्रीमती वासन्तीदेवी (ऐनी बीमेंट) ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। प्राचीन भारतीय मरुति के पुनरुद्धार के लिए समाज ने पर्याप्त उद्योग किया। रामकृष्ण परमहंस और उनके योग्य निष्ठास्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त का भारत में ही नहीं विदेशों में, और विशेषतः से अमरीका में भी प्रचार किया।

यद्यपि मूलतः ये आन्दोलन धार्मिक थे, किन्तु उनका एकमात्र लक्ष्य विदेशी जाति द्वारा शासित प्रजा में नवचेतना तथा नवजागरण की भावना उत्पन्न करना ही था। इन आन्दोलनों ने भारतवासियों के हृदय पर पुनः यह छाप लगा दी कि आर्य-मरुति ही सर्वश्रेष्ठ है, वेदिक धर्म ही प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ धर्म है, भारत या प्राचीन इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है आदि। इन विचारधारा में जनता में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई।

धार्मिक पुनरुत्थान के साथ-साथ कला, साहित्य तथा ओलोगिक

क्षेत्रों में भी राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार होने लगा। साहित्यकारों ने अपने नाटकों, काव्यों, कहानियों, उपन्यासों और लेखों द्वारा जनता में देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता के भाव भरना शुरू किया।

राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना

जब भारत में हिमाचल से लेकर बंगालाकुमारी और सिन्धु से लेकर ब्रह्मातम्व राष्ट्रीय भाषना का जागरण हो गया तो एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की आवश्यकता अनुभव होना स्वाभाविक ही था। फलतः बंगाल में सन् १८५१ में 'ब्रिटिश भारतीय सभा' (British Indian Association) की स्थापना हुई।

यम्पई तथा पूना में भी 'बाम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन' तथा 'पूना सार्वजनिक सभा' खोली गयी। सन् १८७६ में बंगाल में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में 'इंडियन एसोसिएशन' की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य बंगाल और सामान्यतया समस्त भारत में राजनीतिक आन्दोलन करना था। श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उत्तरी भारत में भ्रमण करके अपने ओजस्वी व्याख्यानो तथा भाषणों द्वारा राजनीतिक चेतना उत्पन्न की। सन् १८७७ में देहली में राज-दरबार हुआ। इसमें भारत के सभी प्रसिद्ध नेता तथा राजा-महाराजा सम्मिलित हुए। ऐसा कहा जाता है कि इस सुविशाल दरबार की देखकर श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के हृदय में एक अखिल भारतीय संस्था स्थापित करने का विचार आया और जब सन् १८८१ में कलकत्ता के एलर्ट हाल में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ तो उसमें श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने एक अखिल भारतीय संस्था स्थापित करने पर जोर दिया। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय महासभा की स्थापना के लिए सबसे पहले किसके हृदय में विचार पैदा हुआ, परन्तु यह तो निश्चित है कि देश में ऐसी संस्था की स्थापना के लिए वातावरण पहले से तैयार था। इंडियन सिविल सर्विस के अवकाश प्राप्त सदस्य श्री एलेन ऑक्टोविन ह्यूम ने इस दिशा में आगे पग बढ़ाया और २३ मार्च १८८५ में पूना में प्रथम राष्ट्रीय सभा (Indian National Union) बुलायी।

राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) की स्थापना

पूना में हैजे के प्रकोप के कारण उपर्युक्त निश्चय के अनुसार सभा न हो सकी। इसलिए प्रथम अधिवेशन बम्बई में ता० २८ दिसम्बर १८८४ को हुआ। इसमें देश के ७२ प्रमुख नेता शामिल हुए। इस अधिवेशन में केवल ९ प्रस्ताव स्वीकार किये गये। इन प्रस्तावों का सारांश इस प्रकार है—

भारत में शासन-प्रबन्ध की जांच की जाये, भारत-मन्त्री की कौंसिल भग कर दी जाये; धारा-सभाओं में सुधार किये जायें; आई० सी० एस० की परीक्षाएँ भारत और लन्दन में साथ-साथ हों; सेना-व्यय में कमी की जाये तथा भारत में ब्रह्मा को न मिलाया जाये।

कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कश्मिर्ता में बाबाभाई नौरोजी के समारोहित्व में हुआ। इसमें ४४० प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रारम्भ में दो-तीन वर्षों तक सरकारी अफसर तथा अंग्रेज कांग्रेस के कार्य में सहयोग देते रहे, परन्तु बाद में सरकारी अफसर इसके विरोधी हो गये।

वंग-भंग और स्वदेशी आन्दोलन

कुछ वर्षों तक कांग्रेस के कार्यक्रम में कोई रचनात्मक प्रवृत्ति नहीं रही। वह एक सुधारवादी वैधानिक संस्था थी। जनता से भी उसका सम्पर्क नहीं के बराबर था। उसके नेता उच्च-मध्यमवर्ग के धनी और उच्च-शिक्षित जन थे। लार्ड कर्जन की दमन-नीति और बंगाल के विभाजन से जनता में असन्तोष उठ खड़ा हुआ। इसके फलस्वरूप जनता राजनीतिक आन्दोलन में दिलचस्पी लेने लग गयी। पूना में महामारी के प्रकोप के अवरोध के लिए जो उपाय काम में लाये गये, वे इतने कठोर थे कि जनता उनके कारण बड़ी पीड़ित थी। वंग-भंग का उद्देश्य सरकार ने बताया यह कि इससे शासन-प्रबन्ध में सुविधा मिलेगी; परन्तु वास्तव में इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय जागरण को निधिल कर देना था।

सरकार पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत बनाकर एक

महात्मा गांधी ने रोलट-कानून के विरोध में सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू किया। उनके आदेशानुसार ६ अप्रैल १९१९ को समस्त भारत में हड़ताल की गयी और सार्वजनिक उपवास रखा गया। पंजाब में घोर दमन हो रहा था। वहाँसे गांधीजी को निमंत्रण मिला। ८ अप्रैल १९१९ को जब वे मयुरा होवर रेल द्वारा पंजाब के लिए जा रहे थे, तब पलवल स्टेशन पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और बम्बई ले जाकर छोड़ दिया। अमृतसर के जलियाँवाला बाग और अहमदाबाद में हत्याकांड हुए और वहाँ मार्शल-लों (फौजी-कानून) जारी किया गया। नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से देश में अशांति की आग मुलगती गयी।

दमन तथा शासन-सुधार

भारत में अंग्रेजी शासन की यह एक विशेषता रही है कि यह दमन के साथ-साथ शासन सुधार की योजनाएँ भी तैयार करके उदार-दली भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उद्योग करती रही है। एक ओर १३ अप्रैल १९१९ को अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा पर, जिसमें कोई २०,००० स्त्री-पुरुष मौजूद थे, जनरल डायर ने १५० सैनिकों से गोली चलवा दी, जिसमें ४०० व्यक्ति मारे गये तथा लगभग २००० व्यक्ति घायल हुए और दूसरी ओर भारत के वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड तथा भारत-मंत्री मि० माण्टेग्यू भारत में शासन-सुधार के लिए योजना तैयार कर रहे थे।

जब अमृतसर में दिसम्बर १९१९ में कांग्रेस का अधिवेशन होनेवाला था, तो उससे २-३ दिन पहले २४ दिसम्बर को ब्रिटिश सम्राट की ओर से भारत के शासन विधान पर स्वीकृति के हस्ताक्षर कर दिये गये।

हो सकी। भारत सरकार ने दमन के लिए भारत-रक्षा-कानून बनाया। यह युद्ध-काल में जारी रहा और युद्ध के बाद भी इसे जारी रखा गया। स्थिति पर विचार करने के लिए जस्टिस रोलट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गयी जिसने यह सिफारिश की कि दमन जारी रखा जाये।

कांग्रेस के दानों दणों में मतभेद इतना अधिक बढ़ गया था कि उनका मिलकर काम करना असम्भव था। नरम-दल के कांग्रेसी शासन-मुद्धारों को कार्यान्वित कर प्रान्तों में पदग्रहण करना चाहते थे और गरम-दल इससे विरुद्ध था। अन वम्बई में नरम-दल के लोग कांग्रेस से अलग हो गये और उन्होंने उसी वर्ष बलकत्ता में अखिल भारतवर्षीय उदार-मण (All India Liberal Federation) की स्थापना की।

असहयोग-आन्दोलन

सन् १९२० में महात्मा गांधी ने 'असहयोग आन्दोलन' का श्रोगणेश किया। बलकत्ता-कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग की नीति का स्वीकार किया। विद्याविषय ने सरकारी स्कूला का बहिष्कार किया, धनीला ने न्यायालय का बॉयकाट किया, व्यापारियों ने विदेशी पण्यों का बहिष्कार किया तथा कांग्रेस जनों ने धारासभाओं से त्याग-पत्र दे दिये। प्रान्तीय कांग्रेस कमिटियाँ को अपने-अपने प्रान्त में व्यक्तिगत सत्याग्रह संचालन करने की आज्ञा मिली। सबसे पहले गुजरात के बारडोली और आनन्द स्थाना में आन्दोलन किया गया।

इसी समय 'खिलाफत आन्दोलन' भी बड़े जोर से चलने लगा। मौलाना मुहम्मदअली और मौलाना शौकतअली गांधीजी के दाहिने हाथ थे। कांग्रेस में मुसलमाना की सग्या भी बढ़ गयी। १ फरवरी १९२२ को गांधीजी ने वायसराय की इस आगय का एक पत्र लिया कि एक सप्ताह में सरकार अपनी नीति में परिवर्तन कर दे अन्यथा बारडोली में सत्याग्रह किया जायेगा। यह पत्र वायसराय के पास नहीं पहुँचा कि गोरखपुर में चोरीचोरा को दुर्घटना से सारे दश में क्षोभ पैदा होगया। चोरीचोरा के पुलिस घाने पर कांग्रेस भीड़ ने आश्रमण करके उसमें आग लगादी। १३ मार्च १९२२ को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये। उनपर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया और उन्हें ६ वर्ष कैद की सजा दी गयी। इसके बाद कांग्रेस-आन्दोलन में शिथिलता आगयी और कांग्रेस-जन बौमिल प्रवेश के लिए लालायित हो उठे।

स्वराज-दल का जन्म

दिसम्बर १९२२ में गया में देशबन्धु श्री चित्तरजन दास के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस में इस समय दो दल थे— एक परिवर्तनवादी और दूसरा अपरिवर्तनवादी।

परिवर्तनवादी कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम में परिवर्तन चाहते थे। ये कांग्रेस द्वारा कौंसिल-प्रवेश का कार्यक्रम स्वीकार कराने के पक्ष में थे। स्वर्गीय श्री चित्तरजनदास, प० मोतीलाल नेहरू, श्री श्रीनिवास अयंगर, हकीम अजमल ख़ाँ, श्री चिट्ठल भाई पटेल आदि परिवर्तनवादी थे और श्री राजगोपालाचार्य, ए० अंसारी आदि नेता अपरिवर्तनवादी थे। गया-कांग्रेस में पिछले दल का बहुमत था। इसलिए कौंसिलवादियों की इसमें पराजय हुई। सितम्बर १९२३ में मीराना अबुलकलाम आजाद के सभापतित्व में देहली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें कौंसिल-प्रवेश का कार्य-क्रम स्वीकार किया गया। इस प्रकार कांग्रेस के अन्तर्गत स्वराज-दल की स्थापना की गयी। कांग्रेसवादी प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारासभाओं में सदस्य चुने गये। बंगाल की धारा-सभा में देशबन्धु चित्तरजनदास के नेतृत्व में स्वराज-दल ने कार्य किया। केन्द्रीय धारासभा में प० मोतीलाल नेहरू स्वराज-दल के नेता चुने गये। इस प्रकार अगले सत्याग्रह (१९३०) तक कांग्रेसवादी सदस्य कौंसिलों के भीतर कार्य करते रहे। वे असहयोग की जिस नीति को स्वीकार करके कौंसिलों में गये उसका पालन न कर सके। इसमें शक नहीं कि विरोधी दलों के रूप में इन्होंने अवरोध-नीति का काफी प्रयोग किया।

सन् १९२७ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय शासन-मुधारों की जाँच के लिए एक साही कमीशन सर जान साइमन की अध्यक्षता में नियुक्त किया जिसमें ७ अंग्रेज सदस्य थे। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नियुक्त नहीं किया गया। अतः कांग्रेस ने कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया। इसमें कांग्रेस की पूरी सफलता मिली।

'स्वाधीनता-दिवस' मनाया गया। इस अवसर पर सार्वजनिक सभाओं में एक प्रतिज्ञा पढी गया। तबसे प्रति वर यह राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस-समिति ने १७ फरवरी १९३० को सत्याग्रह-आन्दोलन शुरू करने का निश्चय किया। गांधीजी सचालक नियुक्त हुए। मार्च १९३० को महात्मा गांधी ने वायसराय लार्ड इर्विन के समक्ष अपने पत्र में निम्नलिखित ११ माँगे रखी भादक-द्रव्य-निषेध, एक रुपया १६ पैस के दरार माना जाये, मालगुजारी में ५०% बमी की जाये, सरकारी कर्मचारियों के वेतनों में ५०% बमी हो, सामुद्रिक तटकर-सरक्षण कानून बनाया जाये, राजनीतिक बन्धियों को रिहा कर दिया जाये, सन् १८१८ के रेग्यूलेशन ३ तथा दण्ड-विधान की धारा १०४ अ (राज द्रोह) का रद्द कर दिया जाये, निर्वासित भारतीयों को भारत में आने की आज्ञा दी जाये, खुफिया विभाग या तो बन्द कर दिया जाये या भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया जाये, स्वदेशी वस्त्र-व्यवसाय के सरक्षण के लिए विदेशी वस्त्र व्यवसाय पर अधिक कर लगाया जाये, आत्म-रक्षा के निमित्त अस्त्र-शस्त्रों के रखने की आज्ञा दी जाये।

वायसराय ने इन माँगों में से एक को भी स्वीकार नहीं किया। अतः १२ मार्च १९३० को गांधीजी ने नमक-कानून भंग करने सत्याग्रह आरम्भ कर दिया।

यह सत्याग्रह आन्दोलन पूरे एक वर्ष तक जारी रहा। इसमें हजारों की संख्या में कांग्रेसवादियों को जेल-यात्रा करनी पड़ी। अतः में सर तेजबहादुर सप्रू तथा श्री मुकुन्दराव जयकर के प्रयत्नों से लार्ड इर्विन और गांधीजी में ५ मार्च १९३१ को समझौता हो गया। इसे 'गांधी-इर्विन समझौता' कहा जाता है। इसके अनुसार सत्याग्रह स्वगित कर दिया गया, ब्रिटिश मालका बहिष्कार बन्द कर दिया गया, कांग्रेस कानूनी सस्था घोषित कर दी गयी, समस्त कांग्रेसी बन्दी रिहा कर दिये गये, व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने की सुविधा मिल गयी, परन्तु नमक कर कायम रहा।

गोलमेज-परिषद्

गांधी इर्विन समझौते का भंग कई प्रान्तों में किया गया। कांग्रेस ने

किया। उनकी जीवन-रक्षा के लिए देश भर में प्रार्थनाएँ की गयीं तथा बम्बई और पूना में दलित जातियों तथा हिन्दू नेताओं का सम्मेलन हुआ जिसके अध्यक्ष पं० मदनमोहन मालवीय थे। इसमें परस्पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया और २५ सितम्बर को गांधीजी ने व्रत छोड़ा। इसके बाद गांधीजी यरवदा जेल से 'हरिजन आन्दोलन' का संचालन करने लगे।

८ मई १९३३ में गांधीजी ने पुनः आत्म-तुष्टि के लिए व्रत रखा। गांधीजी जेल से मुक्त कर दिये गये। मुक्ति के बाद गांधीजी ने राष्ट्रपति से यह सिफारिश की कि सत्याग्रह-आन्दोलन १६ मास के लिए स्थगित कर दिया जाये। अतः आन्दोलन स्थगित हो गया।

१२ जुलाई १९३३ को पूना में कांग्रेस-जनों का एक सम्मेलन स्थिति पर विचार करने के लिए हुआ। इसमें यह निश्चय किया गया कि समझौते के लिए गांधीजी वायसराय से मिलें। परन्तु वायसराय ने इस स्वीकार नहीं किया। १ अगस्त को गांधीजी ने पुनः रास गाँव में सत्याग्रह करने का विचार किया। परन्तु वह पहले ही गिरफ्तार कर लिये गये। ४ अगस्त १९३३ को वह छोड़ दिये गये और उन्हें कहा गया कि यरवदा से बाहर रह। गांधीजी ने यह आज्ञा नहीं मानी, अतः उन्हें ६ ठे में फिर गिरफ्तार कर लिया गया और १ वर्ष की सजा दी गयी। जेल में हरिजन कार्य सम्बन्धी सुविधाओं के न मिलने पर उन्होंने फिर १६ अगस्त से व्रत रखा। २३ अगस्त को उनकी हालत बहुत नाजुक हो गयी, और उन्हें मुक्त किया गया। तब उन्होंने यह प्रण किया कि मैं ४ अगस्त १९३४ तक कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे जेल जाना पड़े। तबसे वह अपना सारा समय हरिजन-सेवा में लगाने लगे।

विधानवाद की ओर

देहली में ३१ मार्च १९३४ को डा० असारी के सभापतित्व में कांग्रेस-जनों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि स्वराज-दल की पुनः स्थापना की जाये। यह भी निश्चय किया गया कि

केन्द्रीय प्रागुत्पादों के चुनावों में भाग लिया जाये। मई १९३४ में रांची में कांग्रेसवादियों का एक दूसरा सम्मेलन हुआ। इसमें पहले सम्मेलन के प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। १८ व १९ मई १९३४ को पटना में कांग्रेस-कार्य-समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन हुए, जिनमें सभासद-प्रान्दोलन को स्थगित करने तथा कौमिल-प्रवेश का कार्यक्रम स्वीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार किये गये।

तत्पश्चात् दिनांक १९३४ में कांग्रेस ने केन्द्रीय चुनावों में भाग लिया और उसे आजादी का मन्त्र बना लिया।

नया शासन-विधान और कांग्रेस

मई १९३५ में जो नया शासन-विधान बनाया गया था उसे कार्यान्वित करने के लिए तैयारियाँ होने लगीं। मई १९३६ के मध्य में मान से ही चुनाव-प्रणाली शुरू हो गया। भारत के ११ प्रान्तों में से ७ में प्रागुत्पादों के चुनावों में कांग्रेस भाग ले रही थी।

समुद्रप्रान्त, बम्बई, मध्यप्रान्त, मद्रास, बिहार, उड़ीसा में और बाद में मीना-प्रान्त में कांग्रेस का बहुमत हो गया। इन प्रान्तों में कांग्रेस शासन-भार को सहाय करने में समर्थ थी। अतः कांग्रेस में ही प्रचार के दल पैदा हो गये। एक दल मन्त्रिमंडल ग्रहण करने के पक्ष में था और दूसरा दल विरोध में।

जब दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में यह सहाय के प्रश्न पर विचार किया गया, तो ऐसा प्रतीत होता था कि इस विषय पर कांग्रेस में तीव्र मतभेद हो जायेगा, परन्तु महात्मा गांधी ने पद-सहाय का प्रस्ताव अपने प्रभाव में इस दल के साथ स्वीकार करा दिया, कि मन्त्रिमंडल अपने विवेकाधिकारों को प्रयोग में करने का आश्वासन दे दें। ऐसा आश्वासन न मिलने के कारण, कांग्रेस ने ३ मार्च तक मन्त्रिमंडल नहीं बनाया। अन्त में स्थिति का राष्ट्रीयकरण हो जाने पर मार्च १९३७ में ६ प्रान्तों में कांग्रेस के मन्त्रिमंडल बने, बाद में

सीमाप्रान्त और आसाम में भी मन्त्रि-मण्डल बनाये गये । इस प्रकार ८ प्रान्तों में कांग्रेस का शासन स्थापित हो गया ।

कांग्रेस सच शासन का विरोध तथा विधान का अन्त करने के लिए धारा-सभाओं में गयी थी । इस कार्य में उसे वहाँ तक सफलता मिली, यह नहीं कह जा सकता, परन्तु इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पीसिला में जाकर कांग्रेस अपने वास्तविक कार्यक्रम और लक्ष्य से दूर हटकर 'शासन-संचालन' में तल्लीन हो गयी । हाँ, कुछ रचारात्मक कार्य अवश्य आरम्भ हुआ, जिसमें कई लोकोपकारी मुद्धार हुए—मादक द्रव्य-निषेध, ग्राम-मुद्धार, जेल मुद्धार तथा मिथा-मुद्धार ।

कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलों का पद-त्याग

१ सितम्बर १९३९ को यूरोप में इंग्लैण्ड और जर्मनी में महायुद्ध छिड़ गया । भारत के वायसराय ने यह घोषणा कर दी कि इस यूरोपीय युद्ध में भारत भी ब्रिटेन के साथ है । ऐसी घोषणा करने का विधान के अनुसार वायसराय को पूरा अधिकार था । परन्तु कानूनी दृष्टि से अधिकार होने पर भी नैतिक दृष्टि से यह उचित था कि भारत को युद्ध में सम्मिलित करने से पहले भारतीय नेताओं से परामर्श किया जाता । इस स्थिति से भारतीय लोकमन बड़ा विदुब्ध हो गया और कांग्रेस भारत-सरकार की इस नीति से असन्तुष्ट हो गयी ।

१४ सितम्बर १९३९ को कांग्रेस कार्य-समिति ने एक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया । इसमें कांग्रेस ने अंग्रेज सरकार से कहा कि वह युद्ध और शान्ति के उद्देश्यों की घोषणा करे । यदि यह युद्ध वास्तव में प्रजातन्त्र और स्वाधीनता की रक्षा के लिए है, तो क्या ब्रिटिश-सरकार इन सिद्धान्तों को भारत में भी लागू करना चाहती है ? इस घोषणा का सरकार ने कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दिया ।

कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि कांग्रेस पूर्ण - स्वाधीनता चाहती है अतः भारत को स्वाधीन राष्ट्र घोषित कर दिया जाये । भारत का शासन विधान निर्माण करने का अधिकार वयस्क

मताधिकार द्वारा चुनी हुई विधान-निर्मात्री-परिषद् (Constituent Assembly) को ही होना चाहिए ।

ब्रिटिश सरकार ने भारत में 'ओपनिवेशिक स्वराज' की स्थापना को अपना अन्तिम अग्र्य घोषित कर दिया है, जैसा कि वह पिछली बार भी कई बार घोषित कर चुकी है । उसने इस बार यह और जोड़ दिया है कि ओपनिवेशिक स्वराज शीघ्र से शीघ्र दिया जायेगा और वह सन् १९३० के वेस्टमिन्सटर-कानून (Westminster Statute) के दग का होगा । परन्तु अभी तक पार्लिमेंट ने इस सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की । यह भी निश्चय-पूर्वक नहीं कहा गया है कि ओपनिवेशिक स्वराज बख्श दिया जायेगा ?

८ अगस्त १९४० को वायसराय ने जो घोषणा की, उससे स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ । इस प्रकार भारत की इस वैधानिक समस्या को मुलझाने का लगातार दोनों ओर से प्रयत्न किया गया, परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली ।

युद्ध-विरोधी सत्याग्रह

समझौते के लिए एक साल तक घोर प्रयत्न करने के बाद महात्मा गांधी ने प्रकट किया कि जब आज स्वयम् इम्पैण्ड सकूट में है, तो भारत को उससे अपनी स्वाधीनता माँगना उचित नहीं है । एक भाषण में गांधीजी ने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि स्वाधीनता माँगने से प्राप्त नहीं की जा सकती । उसके लिए शक्ति की आवश्यकता है ।

तदनुसार स्वाधीनता के प्रश्न को अलग रखकर उन्होंने भाषण-स्वातन्त्र्य के प्रश्न पर अक्तूबर १९४० में देशव्यापी व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया । गांधीजी तथा कांग्रेस, जिसके यह अधिनायक हैं, वर्तमान युद्ध में इंग्लैंड को सहायता नहीं देना चाहती । साथ ही गांधीजी इस युद्ध में ब्रिटेन की हार भी नहीं चाहते । वह ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्न में किसी प्रकार की बाधा डालना नहीं चाहते । परन्तु वर्तमान युद्ध में भारत का भाग लेना या सहायता देना अनैतिक और हिंसात्मक मानते हैं । उनके

उनका विकासवाद में विश्वास है, क्रान्ति में विश्वास नहीं है और वे शान्तिमय साधनों द्वारा अपनी उन्नति चाहते हैं। विधान निर्मात्री परिषद् का तरीका भी उनकी विचारधारा के अनुकूल नहीं है। वर्तमान युद्ध में यद्यपि वे ब्रिटिश सरकार की भारत सम्बन्धी नीति से असन्तुष्ट हैं, तो भी सरकार को हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं। उदार दल के सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी नेताओं ने बम्बई में एक निर्दल-नेता-सम्मेलन का आयोजन किया था। सर तेजबहादुर सप्रू उसके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन के नरम प्रस्ताव तक तो भारत मन्त्री ने पसंद नहीं किया। इससे सर सप्रू तथा अन्य नेताओं को घोर निराशा हुई।

हिन्दू-महासभा की राजनीति

'हिन्दू महासभा की स्थापना २० वर्ष पूर्व हिन्दू-धर्म, सस्कृति तथा हिन्दुत्व की रक्षा के उद्देश्य से की गयी थी। प्रारम्भ में यह धार्मिक संस्था थी। इसका कार्यक्रम भी सामाजिक तथा धार्मिक था, परन्तु विगत १० वर्षों में वह एक राजनीतिक संस्था के रूप में बदल गयी है। भाई परमानन्द तथा वीर विनायक दामोदर सावरकर के शक्तिशाली नेतृत्व में हिन्दू महासभा का आन्दोलन अब अत्यन्त शक्तिशाली हो गया है। हिन्दू महासभा का लक्ष्य हिन्दू सस्कृति, हिन्दू धर्म तथा हिन्दू हितों की रक्षा करना तो है ही साथ ही साथ वह भारत की पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति को भी अपना लक्ष्य मानती है। अभी तक वह वैध और शान्तिमय उपायों द्वारा आन्दोलन करती रही है। दिसम्बर १९४० में मद्रास-अधिवेशन में महासभा ने ब्रिटिश सरकार को यह चुनौती दी थी कि वह ३१ मार्च १९४१ तक भारत का औपनिवेशिक स्वराज प्रदान कर दे, अन्यथा महासभा उसके विरुद्ध सीधी कार्रवाई (Direct-Action) शुरू कर देगी। परन्तु इस अवधि के बीत जाने पर भी हिन्दू-महासभा ने ऐसा आन्दोलन आरम्भ नहीं किया। हाँ, हैदराबाद में हिन्दू-हितों की रक्षा के लिए महासभा ने सत्याग्रह किया जिसमें उसे सफलता भी मिली।

उनका विकासवाद में विश्वास है। क्रांति में विश्वास नहीं है और वे शांतिमय साधनों द्वारा अपनी उन्नति चाहते हैं। विधान निर्मात्री परिषद का तरीका भी उनकी विचारधारा के अनुकूल नहीं है। वर्तमान युद्ध में यद्यपि वे ब्रिटिश सरकार की भारत सम्बन्धी नीति से असन्तुष्ट हैं तो भी सरकार को हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं। उदार दल के सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी नेताओं ने दिसम्बर में एक निम्नलिखित नेता सम्मेलन का आयोजन किया था। सर तेजबहादुर सप्रू उसके अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन के नरम प्रस्ताव तक को भारत मंत्री ने पसन्द नहीं किया। इससे सर सप्रू तथा अन्य नेताओं को घोर निराशा हुई।

हिन्दू महासभा की राजनीति

हिन्दू महासभा की स्थापना २० वर्ष पूर्व हिन्दू धर्म सस्कृति तथा हिन्दुत्व की रक्षा के उद्देश्य से की गयी थी। प्रारम्भ में यह धार्मिक संस्था थी। इसका कार्यक्रम भी सामाजिक तथा धार्मिक था। परन्तु विगत १० वर्षों में यह एक राजनीतिक संस्था के रूप में बदल गयी है। भाई परमानन्द तथा वीर विनायक दामोदर सावरकर के शक्तिशाली नेतृत्व में हिन्दू महासभा का आन्दोलन अब अत्यन्त शक्तिशाली हो गया है। हिन्दू महासभा का लक्ष्य हिन्दू सस्कृति हिन्दू धर्म तथा हिन्दू हितों की रक्षा करना तो है ही साथ ही साथ वह भारत की पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति को भी अपना लक्ष्य मानती है। अभी तक वह वैध और शान्तिमय उपायों द्वारा आन्दोलन करती रही है। दिसम्बर १९४० में मद्रास-अधिवेशन में महासभा ने ब्रिटिश सरकार को यह चुनौती दी थी कि वह ३१ मार्च १९४१ तक भारत का औपनिवेशिक स्वराज प्रदान कर दे अन्यथा महासभा उसके विरुद्ध सीधी कार्रवाई (Direct Action) शुरू कर देगी। परन्तु इस अवधि के बीत जाने पर भी हिन्दू महासभा ने ऐसा आन्दोलन आरम्भ नहीं किया। हाँ हैदराबाद में हिन्दू हितों की रक्षा के लिए महासभा ने सत्याग्रह किया जिसमें उम सफलता भी मिली।

भारतीय ईसाई और राष्ट्रीयता

भारतीय ईसाई भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। समस्त भारत के भारतीय ईसाइया की अग्रिम भारतीय सस्था 'अलि० भारतवर्षीय भारतीय ईसाई सम्मेलन' के नाम से प्रसिद्ध है। इसने वर्तमान अध्यक्ष डा० रामचन्द्र राव हैं। यद्यपि भारतीय ईसाई अपने को अल्पसंख्यक मानते हैं, तो भी इस आधार पर मुस्लिम-लीगवालों की तरह वे भारत की वैधानिक प्रगति तथा राष्ट्रीय-जीवन के विकास में बाधक बनकर अपने को बलवित्त करना नहीं चाहते।

भारतीय ईसाई-सम्मेलन भारत में पूर्ण स्वाधीनता और प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना चाहता है। सन् १९३८ में दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अग्रिम भारतवर्षीय ईसाई सम्मेलन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है कि भारतीय ईसाई गुरुदिन स्वानो के साथ सयुक्त-निर्वाचन-प्रणाली को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। दिसम्बर १९४० में लगनऊ में ईसाई सम्मेलन ने 'पाकिस्तान'-योजना की घोर निन्दा की और उसे देश के लिए घातक बतलाया। इससे प्रकट होना है कि वह साम्प्रदायिक निर्वाचन-प्रणाली से विरुद्ध है। ईसाई धर्म में राष्ट्रीयता की यह भावना भारत के लिए एक शुभ लक्षण है।

दलित-धर्म और उसकी राजनीति

भारत में हिन्दू-समाज के अन्तर्गत ६ करोड़ ऐसी जानियाँ हैं, जो दलित युग में भी राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक समान-अधिकारों से वंचित हैं। सन् १९१९ में जब मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना के अनुसार भारत में प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारा-सभाओं का गठन किया गया, तब वामसंख्य तथा प्रान्तीय गवर्नरों को यह आदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रान्त में दलित जातियों के एक-दो प्रतिनिधि नामजदगी द्वारा धारासभाओं में नियुक्त हों।

इसके अनुसार नियुक्तियाँ की गयीं। बाद में प्रत्येक प्रान्त के जिला-वालों तथा स्थानीय बोर्डों के बानूनों में गवरोचन किया गया और

द्वारा रद्द न करदी गयी हो, १० वर्ष तक कायम रहेगी।

६ सुरक्षित स्थानों के लिए दलित-वर्ग के लिए निर्वाचन प्रणाली, जिसका उल्लेख धारा १ से ४ तक है, उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि परस्पर समझौते द्वारा उसका अन्त न कर दिया जाये।

७ प्रान्तीय तथा केन्द्रीय धारासभाओं में दलित-वर्ग के लिए मताधिकार लोचियन रिपोर्ट के अनुसार होगा।

८ किसी भी व्यक्ति को केवल दलित-समुदाय का सदस्य होने के कारण स्थानीय बोर्डों के चुनावों में खड़ा होना या सरकारी नौकरियाँ में भरती होने के अयोग्य न माना जायेगा। इन दोनों में दलित-वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए प्रयत्न किया जायेगा, परन्तु प्रत्येक नौकरी के लिए निर्धारित योग्यता आवश्यक होगी।

९ प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा के लिए स्वीकृत कोष में से पर्याप्त धन दलित वर्ग की शिक्षा के लिए निर्धारित कर दिया जायेगा।

पूना समझौते की उपर्युक्त धाराओं पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इससे मुख्य उद्देश्य दो है। पहला तो यह कि सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए दलित-वर्ग की उन्नति के लिए पर्याप्त संरक्षण और सुविधाएँ मिलें और दूसरा यह कि दलित वर्ग हिन्दू-समाज से अभिन्न बन जाये।

इसमें सन्देह नहीं कि नये शासन-विधान में धारासभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मित्रों के कारण इन जातियों की अपनी उन्नति के लिए पर्याप्त सुयोग मिला, परन्तु वे उनसे वास्तविक लाभ न उठा सके। उन्हें राजनीति में, समाज नीति की भाँति, राजनीतिक दलों के शोषण का शिकार बनना पड़ा। वे ग्रामों में जमींदारों के आतंक के कारण अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रीति से न कर सके। भारत में उनके कुल १५१ सदस्यों में से १०२० सदस्यों को छोड़कर शेष सभी या तो निरक्षर हैं या अर्द्ध-साक्षर। यद्यपि लोक निर्वाचन क्षेत्र से सुयोग्य कार्यकर्ता और शिक्षित व्यक्ति इन जातियों में मिल सकते थे, परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

यद्यपि मद्रास, संयुक्तप्रान्त, बिहार—इन तीनों प्रान्तों में दलित-वर्ग के कांग्रेसी सदस्यों का बहुमत है, तो भी इन प्रान्तों के दलित-समुदाय की जनता में कांग्रेस के सदस्य बहुत ही कम हैं। कांग्रेसी उम्मीदवार के लिए मत प्राप्त कर लेना दूसरी बात है। यही कारण है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी इनके बहुत ही कम सदस्य हैं—पायद उगलियों पर गिनने लायक। इसका मुख्य कारण यह है कि अभी तक इन जानिया ने कांग्रेस के सन्देश को ग्रहण नहीं किया है।

दलित जातियों का कोई अखिल भारतवर्षीय दृढ़ और देशव्यापी संगठन नहीं है। इनके मुद्धार के लिए जो कुछ कार्य हो रहा है, वह प्रान्तीय आधार पर ही हो रहा है। प्रत्येक प्रान्त में अलग-अलग संगठन हैं। आवश्यकता है अन्तर्प्रान्तीय संगठन की।

दलित जातियों में प्रभावशाली नेतृत्व का भी अभाव है ही, पर उच्च शिक्षा का अभाव, अधिक पठिनाइयाँ, उच्च संस्कृति तथा प्रगतिशील विचार धारा का अभाव भी इनकी अवन्नता का एक मूल कारण है। इनके अतिरिक्त दलित जातियों पर ग्रामों में बड़े भीषण और अमानुषिक अत्याचार किये जाते हैं।

दलित जातियाँ, हिन्दू-समाज का ही अंग हैं, इसलिए हमारा वर्तमान है कि सामाजिक दृष्टि से इनकी समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न किया जाये। केवल राजनीतिक दृष्टि से इन्हें हिन्दू समाज का अंग मान लेने से न तो इनका बल्याण हो सकेगा और न वे राष्ट्र के उपयोगी अंग ही बन सकेगें।

सहायक ग्रन्थों की सूची

अंग्रेजी

1. Atharvaveda : Harward Oriental Series.
2. Old Testament (Bible.)
3. G.D.H. Cole : Review of Europe to-day (1933).
4. Leonard Woolf : Intelligent Man's Way to Prevent War (1933).
5. A. Drault : Social and Political Problems at the end of the 19th century.
6. Ramsay Muir : Nationalism and Internationalism
7. Beni Prasad : The State in Ancient India.
8. Beni Prasad : Theory of Government in Ancient India.
9. K. P. Jayaswal : Hindu Polity.
10. Freda and Bedi : India Analysed, Vol I.
11. W. B. Curry : The Case for Federal Union.
12. S. Mussolini : The Political and Social Doctrine of Fascism in Encyclopaedia Italiana (1932).
13. M. K. Gandhi : Mahatma Gandhi's Speeches and Writings.
14. Hobhouse : Elements of Social Justice.
15. H. J. Lasky : Liberty in the Modern State (1937).
16. K. T. Shah : Federal Structure (1938).
17. Shrinivas Iyengar : The Problem of Democracy in India (1939).
18. James Bryce : Modern Democracies.
19. K. M. Panikkar : Hinduism and the Modern World.
20. Prof. Wadia : Contemporary Indian Philosophy.
21. B. R. Ambedkar : Annihilation of Caste.
22. D. F. Mulla : Principles of Mohammadan Law.
23. B. P. Sitaramayya : History of the Congress.
24. Herr Hitler : My Struggle.

- 25 The Harijan, Poona
- 26 The Leader (19 6 1941)
- 27 The Hindustan Review (July 1934)
- 28, The Indian Information (Government of India, New Delhi)
- 29 League of Nations Statute of Court
- 30 League of Nations' Statistical Year Book, 1930 31
- 31 The Constitution of Socialist Soviet Russia

हिन्दी

- १ जवाहरलाल नेहरू मेरी कहानी
- २ मोहनदास करमचन्द गांधी हिंद स्वराज
- ३ रामदास गौड हमारे गाँव की कहानी
- ४ महाभारत
- ५ बैनीप्रसाद नागरिक शास्त्र
- ६ सबपल्ली राधाकृष्णन् गांधी अभिनन्दन-ग्रन्थ
- ७ हरिभाऊ उपाध्याय स्वामीजी का बलिदान और हमारा वर्तमान
- ८ नान्हालाल चमनलाल मेहता भारतीय चित्रकला
- ९ भगवानदास केला नागरिक शास्त्र
- १० मी० क० गांधी हमारा कलक
- ११ रामनारायण यादवेडु राष्ट्रसंघ और विश्व शान्ति
- १२ रामनारायण यादवेडु भारतीय शासन विधान
- १३ वर्धा शिक्षा-समिति की रिपोर्ट
- १४ 'सरस्वती (जनवरी, १९३७), प्रयाग
- १५ 'हरिजन सेवक', पूना
- १६ 'विश्वमित्र (अगस्त १९४०), कलकत्ता
- १७ 'कर्मयोगी (जनवरी, १९३७), प्रयाग

सस्ता साहित्य मण्डल के प्रकाशन

सर्वोदय-साहित्य माला

पुस्तक	लेखक	मूल्य
१ दिव्य-जीवन	स्वेट माडॅन	१८)
२ जीवन-साहित्य	काका कालेलकर	॥८)
३ तामिल वेद	ऋषि तिरुवल्लुवर	॥७)
४ भारत में व्यसन-व्यभिचार	वैजनाथ महोदय	॥८)
८ ब्रह्मचर्य-विज्ञान	जगन्नारायण देव शर्मा	॥८)
१४ द० अ० का सत्याग्रह	महात्मा गांधी	१॥७)
१६ अनीति की राह पर	"	१८)
१८ कन्या-शिक्षा	स्व० चन्द्रमोक्षर शास्त्री	७)
१९ कर्मयोग	अश्विनीकुमार दत्त	१८)
२० कलवार की करतूत	महात्मा टॉलस्टॉय	८)
२१ व्यावहारिक सभ्यता	गणेशदत्त शर्मा 'इन्द्र'	॥७)
२२ अधरे में उमाला	महात्मा टॉलस्टॉय	॥७)
२५ स्त्री और पुरुष	"	॥७)
२६ सक्राई	गणेशदत्त शर्मा 'इन्द्र'	१८)
२७ हम क्या करें ?	महात्मा टॉलस्टॉय	१७)
३१ जब अप्रेक्ष नहीं आये थे	स्व० दादाभाई नौरोजी	३)
३९ तरंगित हृदय	आचार्य देवतर्मा 'अभय'	॥७)
४१ दुखी दुनिया	राजगोपालाचारी	॥७)
४२ शिन्धा लाश	महात्मा टॉलस्टॉय	॥७)
४३ आत्मकथा	महात्मा गांधी	१), १॥७)
४५ जीवन विकास	सदाशिव नारायण दातार	१७), १॥७)
४७ फाँसी	विक्टर ह्यूगो	१८)
५० मराठा का उत्थान और पतन	गोपाल दामोदर तामसकर	२॥७)
५१ भाई के पत्र	रामनाथ 'मुमन'	१॥७)

५४ स्त्री-समस्या	मुकुटबिहारी वर्मा	१०
५८ इंग्लैंड में महात्माजी	महादेव देसाई	११
५९ रोटी का सवाल	प्रियस त्रिपाठक	१२
६० दैवी सपद्	रामनाथ मेहता	१३
६४ सधर्ष या सहयोग ?	प्रियस त्रिपाठक	१४
६५ गांधी विचार दोहन	किशोरलाल मशरूवाला	१५
६७ हमारे राष्ट्रनिर्माता	रामनाथ 'सुमन'	१६
६९ आगे बढ़ो	स्वेट मार्डन	१७
७० युद्ध वाणी	वियांगी हरि	१८
७१ कांग्रेस का इतिहास	पट्टाभि सीतारामैया	२०
७२ हमारे राष्ट्रपति	सत्यदेव विद्यालकार	२१
७३ मेरी कहानी	जवाहरलाल नेहरू	२२
७४ विश्व इतिहास की कलक		२३
७५ हमारी पुत्रियाँ कैसी हो ?	चतुरसेन शास्त्री	२४
७६ नया शासन विधान (प्रान्तीय स्वराज्य)	हरिश्चन्द्र गोयल	२५
७७ गाँवों की कहानी	स्व० रामदास गौड़	२६
७८ महाभारत के पात्र (दो भाग)	आचार्य नानाभाई	२७
७९ गाँवों का सुधार और संगठन	स्व० रामदास गौड़	२८
८० सतवाणी	वियांगी हरि	२९
८१ विनाश या इलाज ?	म्यूरियल लेस्टर	३०
८३ लोक-जीवन	काका कालेलकर	३१
८४ गीता प्रयन	किशोरलाल मशरूवाला	३२
८५ राजनीति प्रवशिका	हेरल्ड लास्की	३३
८६ हमारे अधिकार और कर्तव्य	कृष्णचन्द्र विद्यालकार	३४
८८ स्वदेशी और ग्रामोद्योग	महात्मा गांधी	३५
८९ सुगम चिकित्सा	चतुरसेन शास्त्री	३६
९० प्रेम में भगवान्	म० टालस्टॉय	३७
९१ महात्मा गांधी	रामनाथ सुमन	३८

९२. ब्रह्मचर्य	महात्मा गांधी	॥॥
९३. हमारे गाँव और किसान	भुखारसिंह	॥॥
९४. गांधी-अभिनन्दन ग्रन्थ	सर्वपल्ली राधाकृष्णन्	१॥, २॥
९५. हिन्दुस्तान की समस्याएँ	जवाहरलाल नेहरू	१॥
९६. जीवन-सन्देश	मलील जिन्नान	॥॥
९७. समन्वय	भगवान्दास	२॥
९८. समाजवाद पूँजीवाद	बर्नार्ड शॉ	॥॥
९९. मेरी मुक्ति की कहानी	म० टॉलस्टॉय	॥॥
१००. खादो मीमांसा	बालूमाई मेहता	१॥॥
१०१. बापू	धनश्यामदास बिडला	॥२॥, २॥
१०२. मधुकर	विनोबा	१॥
१०२. लडखडाती दुनिया	जवाहरलाल नेहरू	१॥
१०४. सेवाधर्म सेवामार्ग	कृष्णदत्त पालीवाल	१॥
१०५. दुनिया की शासन प्रणालियाँ	रामचन्द्र वर्मा	१॥॥
१०६. डायरी के पन्ने	धनश्यामदास बिडला	॥॥, १॥
१०७. तीस दिनों मालवीयजीके साथ	रामनरेश त्रिपाठी	२॥
१०८. युद्ध और अहिंसा	महात्मा गांधी	॥॥
१०९. महावीर बाणी	बेचरदास दोशी	१॥॥
११०. भारतीय संस्कृति	रामनारायण यादवेन्दु	१॥
१११. बिलरे विचार	धनश्यामदास बिडला	॥॥
११२. अहिंसा-विवेचन	किशोरलाल मशरूवाला	॥॥

नवजीवन-माला

१. गीता-बोध	२. भगवद्गीता	म० गांधी	७ ७
३. अनासक्तियोग	म० गांधी	सादी २॥ श्लोक सहित ३॥ सजित्	१॥
४. सर्वोदय	॥		७
५. नवयुवका से दो बातें	प्रियस क्रीपाटकिन		७
६. हिन्द-स्वराज्य	म० गांधी		३॥
७. छूतछात की माया			७

८ किमानो का सवाल	जेड ए अहमद
९ ग्राम-सेवा	म० गांधी
१० खादी और गादी की लड़ाई	विनोय
११ मधुमक्खी पान	
१२ गाँवों का आर्थिक सवाल	
१३ राष्ट्रीय गीत	
१४ खादी का महत्व	गुलजारीलाल नन्दा
१५ जब अंग्रेज नहीं आयें थे	
१६ सोने की माया	किशोरलाल मंगरूवाला
१७ सत्यवीर मुकरात	म० गांधी

सामयिक साहित्य माला

१ कागस इतिहास	(१९३५-१९३९)
२ दुनिया का रंगमंच	जवाहरलाल नेहरू
३ हम कहाँ हैं ?	
४ युद्ध-मकट और भारत	म० गांधी, राष्ट्रपति आदि के व्यक्तित्व
५ सत्याग्रह क्यों, नव और कैसे ?	म० गांधी
६ राष्ट्रीय पंचायत	महात्माजी, जवाहरलाल नेहरू, राजाजी
७ देशी राजाओं का दर्जा	प्यारे
८ यूरोपीय युद्ध और भारत	म
९ रचनात्मक क्राय क्रम	म

८ किसानों का सवाल	जड ए अहमद
९ ग्राम सेवा	म० गांधी
१० खादी और गादी की लड़ाई	विनोद
११ मधुमक्खी पालन	
१२ गाँवों का आर्थिक सवाल	
१३ राष्ट्रीय गीत	
१४ खादी का महत्व	गुलजारीलाल नन्दा
१५ जब अन्न नहीं आया था	
१६ सोने की भाषा	किशोरलाल मण्डवाला
१७ सत्यवीर मुकरात	म० गांधी

सामयिक साहित्य माला

१ काग्रस इतिहास	(१९३५-१९३९)
२ दुनिया का रगमच	जवाहरलाल नेहरू
३ हम कहाँ हैं ?	
४ युद्ध-संकट और भारत	म० गांधी, राष्ट्रपति आदि के कृत्य
५ सत्याग्रह क्यों, कब और कैसे ?	म० गांधी
६ राष्ट्रीय पचायत महात्माजी	जवाहरलाल नेहरू रामो
७ देशी राजाओं का दरजा	प्यारेलाल
८ यूरोपीय युद्ध और भारत	म० गांधी, जवाहरलाल
९ रचनात्मक कार्य क्रम	म० गांधी

विविध प्रकाशन

१ पण्डित मोतीलाल नेहरू	रामनाथ मुमन
२ पण्डित जवाहरलाल नेहरू	
३ सप्त सरिता	काका कालेलकर
४ चारा दाना और उसके खिलाने के उपाय	परमेश्वरीप्रसाद गुप्त
५ पशुओं का इलाज	परमेश्वरीप्रसाद गुप्त
६ उपनिषदों की कथाएँ	शंकर दत्तात्रय देव
७ आदश बालक	चतुरसेन शास्त्री